



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 46]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 नवम्बर 2019—कार्तिक 24, शक 1941

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश
और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की
अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम

भाग १

राज्य शासन के आदेश

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 नवम्बर 2019

क्र. एफ-1-40-2019-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्वारा श्री संजय तिवारी, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, इन्दौर रेंज (ग्रामीण), इन्दौर को London (U.K.) में M.C.T.P. प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त दिनांक 28 से 29 अक्टूबर 2019 तक, दो दिवस अर्जित अवकाश व दिनांक 26-27 अक्टूबर 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में परिवार सहित London (U.K.) की निजी विदेश यात्रा (Ex-India Leave) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है :—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।

2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे।

3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री संजय तिवारी, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पुलिस उप महानिरीक्षक, इन्दौर रेंज (ग्रामीण), इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री संजय तिवारी, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय तिवारी, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ-1-98-2018-ब-2-दो-संशोधित.—राज्य शासन विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 12 अक्टूबर 2019 को निरस्त करते हुए श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को United Nation Police Commander Course हेतु दिनांक 21 अक्टूबर से 1 नवम्बर 2019 तक भाग लेने के उपरान्त दिनांक 2 से 5 नवम्बर 2019 तक, चार दिवस अर्जित अवकाश के साथ Berlin Germany की विदेश यात्रा (Ex-India Leave) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है:—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
2. विदेश यात्रा के दौरान होने वाला सम्पूर्ण व्यय United Nation Police Division Berlin Germany द्वारा वहन किया जावेगा.
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.

(2) यात्रा से लौटने पर श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर बनी रहतीं.

भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2019

क्र. एफ-1(ए)185-1991-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री गोविन्द प्रताप सिंह, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (नक्सल विरोधी अभियान) पु. मु., भोपाल को दिनांक 15 से 18 अक्टूबर 2019 तक, चार दिवस अर्जित अवकाश एवं 10-20 अक्टूबर 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री गोविन्द प्रताप सिंह, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक (नक्सल विरोधी अभियान) पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री गोविन्द प्रताप सिंह, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गोविन्द प्रताप सिंह, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीदास, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर 2019

क्र. एफ-1(ए)60-2015-ब-2-दो.—राज्य शासन, द्वारा श्री संपत उपाध्याय, भापुसे (2013) पुलिस अधीक्षक, दक्षिण, भोपाल को दिनांक 13 से 27 सितम्बर 2019 तक, पन्द्रह दिवस पितृत्व अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री संपत उपाध्याय, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक, दक्षिण, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री संपत उपाध्याय, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संपत उपाध्याय, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. आर. भोंसले, उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 30 अक्टूबर 2019

फा. क्रमांक 5305-2019-इक्कीस-ब (एक).—(मेरिट क्रमांक 03), राज्य शासन, श्रीमती रेखा द्विवेदी पत्नी श्री राहुल वर्मा को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला भोपाल (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 18 अगस्त 1984 है.

फा. क्रमांक 5478-2019-इक्कीस-ब (एक).—(मेरिट क्रमांक 19), राज्य शासन, श्री शुभम नीमा पुत्र श्री दिनेश नीमा को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला मंदसौर (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 5 मई 1994 है.

फा. क्रमांक 5299-2019-इक्कीस-ब (एक).—(मेरिट क्रमांक 41), राज्य शासन, श्री राज पांडे पुत्र श्री राजेन्द्र पांडे को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला जबलपुर (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 7 मार्च 1994 है।

फा. क्रमांक 5307-2019-इक्कीस-ब (एक).—(मेरिट क्रमांक 42), राज्य शासन, श्रीमती पूजा भदौरिया पत्नी श्री हर्ष भदौरिया को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला इन्दौर (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 9 मार्च 1984 है।

फा. क्रमांक 5571-2019-इक्कीस-ब (एक).—(मेरिट क्रमांक 45), राज्य शासन, सुश्री प्रियंका सोलंकी पुत्री श्री देवेन्द्र सोलंकी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला इन्दौर (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 15 जनवरी 1996 है।

फा. क्रमांक 5386-2019-इक्कीस-ब (एक).—(मेरिट क्रमांक 47), राज्य शासन, श्री विशाल रिछारिया पुत्र श्री विश्वनाथ रिछारिया को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला नरसिंहपुर (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 6 अक्टूबर 1993 है।

फा. क्रमांक 5236-2019-इक्कीस-ब (एक).—(मेरिट क्रमांक 48), राज्य शासन, श्री विष्णु दुबे पुत्र श्री श्रवण कुमार दुबे को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने

तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला भोपाल (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 26 दिसम्बर 1995 है।

फा. क्रमांक 5233-2019-इक्कीस-ब (एक).—(मेरिट क्रमांक 51), राज्य शासन, सुश्री कीर्ति शुक्ला पुत्री श्री शीतला प्रसाद शुक्ला को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला भोपाल (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 1 मार्च 1988 है।

फा. क्रमांक 5365-2019-इक्कीस-ब (एक).—(मेरिट क्रमांक 53), राज्य शासन, सुश्री मोहिनी भदौरिया पुत्री श्री लोकेन्द्र सिंह भदौरिया को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला शिवपुरी (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 19 अगस्त 1993 है।

भोपाल, दिनांक 31 अक्टूबर 2019

फा. क्रमांक 5639-2019-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की स्थापना पर विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ करने हेतु उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री शिवकांत, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ग्वालियर की सेवाएं, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक एतद्वारा, माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है।

भोपाल, दिनांक 1 नवम्बर 2019

फा. क्रमांक 5634-2019-इक्कीस-ब (एक).—(मेरिट क्रमांक 10), राज्य शासन, सुश्री शाम्भवी सिंह पुत्री श्री शिवानन्द सिंह को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला रीवा (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 13 जुलाई 1992 है।

फा. क्रमांक 5608-2019-इक्कीस-ब (एक).—(मेरिट क्रमांक 21), राज्य शासन, सुश्री ऋचा द्विवेदी पुत्री श्री पवन कुमार द्विवेदी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला भिण्ड (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 28 जुलाई 1992 है।

फा. क्रमांक 5607-2019-इक्कीस-ब (एक).—(मेरिट क्रमांक 43), राज्य शासन, श्रीमती श्वेता गौतम पत्नी श्री आलोक राज गौतम को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला दमोह (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 27 नवम्बर 1986 है।

फा. क्रमांक 5498-2019-इक्कीस-ब (एक).—(मेरिट क्रमांक 52), राज्य शासन, श्री सतीश कुमार शुक्ला पुत्र श्री चक्रधर प्रसाद को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला रीवा (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 01 जुलाई 1984 है।

फा. क्रमांक 5366-2019-इक्कीस-ब (एक).—(मेरिट क्रमांक 54), राज्य शासन, सुश्री सोनम रघुवंशी पुत्री श्री घनश्याम रघुवंशी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला इन्दौर (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 28 मई 1995 है।

फा. क्रमांक 5297-2019-इक्कीस-ब (एक).—(मेरिट क्रमांक 58), राज्य शासन, सुश्री फाल्गुनी शर्मा पुत्री श्री मधुसूदन शर्मा को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला इन्दौर (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 25 फरवरी 1994 है।

फा. क्रमांक 5430-2019-इक्कीस-ब (एक).—(मेरिट क्रमांक 56), राज्य शासन, श्री पंकज बुटानी पुत्र श्री रमेश कुमार बुटानी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला देवास (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 03 अप्रैल 1985 है।

फा. क्रमांक 5343-2019-इक्कीस-ब (एक).—(मेरिट क्रमांक 59), राज्य शासन, सुश्री स्वाती रघुवंशी पुत्री श्री अजय रघुवंशी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला होशंगाबाद (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 28 अगस्त 1994 है।

फा. क्रमांक 5225-2019-इक्कीस-ब (एक).—(मेरिट क्रमांक 66), राज्य शासन, सुश्री अमृता मिश्रा पुत्री श्री महेश कुमार मिश्रा को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला सागर (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 01 जनवरी 1989 है।

भोपाल, दिनांक 4 नवम्बर 2019

भोपाल, दिनांक 1 नवम्बर 2019

फा. क्रमांक 5358-2019-इक्कीस-ब (एक).—(मेरिट क्रमांक 62), राज्य शासन, श्री कृष्णा वोहरा पुत्र श्री सुनील वोहरा को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला इन्दौर (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 20 मार्च 1993 है.

फा. क्रमांक 5370-2019-इक्कीस-ब (एक).—(मेरिट क्रमांक 74), राज्य शासन, सुश्री परिधि शर्मा पुत्री श्री उमाशंकर शर्मा को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला इन्दौर (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 20 नवम्बर 1994 है.

फा. क्रमांक 5268-2019-इक्कीस-ब (एक).—(मेरिट क्रमांक 78), राज्य शासन, सुश्री श्रद्धा पाण्डेय पुत्री श्री रामायण प्रसाद पाण्डेय को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला रीवा (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 16 नवम्बर 1994 है.

फा. क्रमांक 5599-2019-इक्कीस-ब (एक).—(मेरिट क्रमांक 82), राज्य शासन, सुश्री मोहसिना खान पुत्री श्री मोहम्मद अनीस खान को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 17 सितम्बर 1993 है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

फा. क्र. 1 (सी) 5546-एट्रोसिटीज-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (क्र. 33 सन् 1989) की धारा 14 के अंतर्गत स्थापित विशेष न्यायालय, जिला हरदा के लिए उक्त अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत, श्री सुखराम बामने, अधिवक्ता (नामांकन क्र. एम. पी./2410/09, दिनांक 19 सितम्बर 2009) को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है. श्री सुखराम बामने, अधिवक्ता की उक्त विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्ति आदेश दिनांक से 3 वर्ष की अवधि अथवा उनकी जन्म तिथि दिनांक 2 मार्च 1979 के आधार पर उनके द्वारा 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, इनमें से जो पहले हो, के लिये होगी तथा यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी.

श्री सुखराम बामने, अधिवक्ता, हरदा को ऐसे विशेष लोक अभियोजक के रूप में कार्य के लिये देय शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1(सी) एट्रोसिटी-इक्कीस-ब (दो), दिनांक 26 सितम्बर 2018 के अनुरूप देय होंगे एवं इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-मुख्य शीर्ष-2225-अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण (01) अनुसूचित जातियों का कल्याण (800)-अन्य व्यय-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जाति उपयोजना (सबस्कीम) योजना (5171)-विशेष न्यायालयों की स्थापना-31-व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियों की उपमद-003-अभिभाषकों को फीस के अंतर्गत विकलनीय होगा. जिसका भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गोपाल श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 2 नवम्बर 2019

पंजी क्र. 5567-2019-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन जिला-मुख्यालय, जबलपुर में नियुक्त नोटरी, श्री सुरेन्द्र दुबे का दिनांक 15 जुलाई 2018 को स्वर्गवास होने के फलस्वरूप उनके नोटरी नियुक्ति आदेश दिनांक 8 अप्रैल 1994 एवं नवीनीकरण आदेश दिनांक 8 अप्रैल 2013 को अपास्त करते हुए, श्री सुरेन्द्र दुबे का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. शुक्ल, अपर सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण, विंध्याचल भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 नवम्बर 2019

क्र. 832-फा. दो- 22-1-स्था.-2013.—मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण विनियम, 1985 के विनियम-34 (2) के अनुसरण में, एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा प्रकाशित वर्ष 2019 के कलैण्डर अनुसार उच्च न्यायालय के लिए अधिसूचित शीतकालीन विश्रामावकाश अवधि के दौरान, मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण में दिनांक 23 से 28 दिसम्बर 2019 तक कुल एक सप्ताह का शीतकालीन विश्रामावकाश रहेगा.

तथापि उक्त विश्रामावकाश अवधि में सार्वजनिक व सामान्य अवकाश दिवसों को छोड़कर, सामान्य कार्य दिवसों में अधिकरण का कार्यालयीन कार्य यथावत जारी रहेगा.

माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार,
उपेन्द्र कुमार सिंह, रजिस्ट्रार.

कार्यालय, कुलाधिपति, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

राजभवन, भोपाल, दिनांक 4 नवम्बर 2019

आदेश

क्र. एफ-1-3-2019-रा.स.-यू.ए.-1-3124.—मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, लाल जी टंडन, कुलाधिपति, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर एतद्वारा प्रो. कपिल देव मिश्रा, कुलपति, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म. प्र.) को उनका कुलपति पद का वर्तमान कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात् कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष की कालावधि के लिए रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर का कुलपति नियुक्त करता हूँ.

2. इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम-1 के अनुसार शासित होंगी.

लाल जी टंडन, कुलाधिपति.

आयुष विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 नवम्बर 2019

क्र. एफ 1-11-2019-1-59.—राज्य शासन, ड्रग्स एण्ड कास्मेटिक्स एक्ट, 1940 की धारा 33 एफ (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा डॉ. राहुल गुप्ता, व्याख्याता, द्रव्यगुण, शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, ग्वालियर को अपने वर्तमान कार्य के साथ शासकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, ग्वालियर के लिये शासकीय एनालिस्ट घोषित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कलावती उडके, अवर सचिव.

न्यायालय उपायुक्त (राजस्व) संभाग शहडोल एवं सक्षम प्राधिकारी

(म. प्र.) भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012

(क्रमांक 5 सन् 2013)

प्ररूप-घ

(नियम 6 देखिये)

शहडोल, दिनांक 27 सितम्बर 2019

क्रमांक 27/बी-121/ 2015-16, अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना दिनांक 13.07.2016 द्वारा राज्य सरकार ने मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन परियोजना के लिये ग्राम पांडखेर, पटवारी हल्का 63- घोरवे तहसील जैतपुर जिला शहडोल से ग्राम देवरी तहसील गोंहपारू जिला शहडोल के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजना हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 22.07.2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा पाइप लाइन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टेयर में)
1	2	3	4	5
शहडोल	जैतपुर	पांडखेर / 63-घोरवे	146/3, 146/7	0.137
			49/2, 49/3/ख	0.200
			213/2/घ, 213/4	0.467
			212/1, 212/2, 212/5, 212/6	0.300
			207/2/क, 207/2/ख	0.111

शहडोल, दिनांक 22 अक्टूबर 2019

प्ररूप-ख

क्रमांक /01/बी-121/2017-18, अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम कंचनपुर, पटवारी हल्का-कंचनपुर-67, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल में वेल क्रमांक SW#03-22 से TL-03 एवं Flow Line SW#06-24 से SW#05-23 के बीच मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्राजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, उपायुक्त राजस्व, शहडोल संभाग, शहडोल (म.प्र.) को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकारी के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
शहडोल	सोहागपुर	कंचनपुर/67	1465/2/1, 1465/2/2, 1465/2/3, 1465/2/4, 1465/2/5, 1465/2/6, 1465/3, 1465/4	0.040
			1468/1/1, 1468/1/2, 1468/1/3, 1468/1/4, 1468/1/5, 1468/1/6, 1468/2, 1468/3	0.526
			1513/1, 1513/2	0.020
			2150/1, 2150/2, 2150/3	0.035
			2149/1/1, 2149/1/2, 2149/2	0.614
			2143	0.177
			2144	0.178
			2142	0.224
			990/1, 990/2, 990/3, 990/4	0.010
			991	0.007
			992	0.010
			989/1, 989/2, 989/3	0.331

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
शहडोल	सोहागपुर	कंचनपुर/67	988/2, 988/3, 988/4/K, 988/4/Kh	0.046
			985/1, 985/2, 985/3	0.054
			986/1, 986/2	0.005
			984	0.039
			982	0.010
			981	0.010
			980/1, 980/2, 980/3/k, 980/3/kh	0.173
			979	0.042
			978	0.010
			975	0.057
			974/1, 974/2/1, 974/2/2, 974/2/3	0.068
			973	0.010
			971/1	0.010
			971/2	0.010
			969	0.126
			968/1, 968/2, 968/3, 968/4	0.010
			965	0.010
			966	0.045
			897/1, 897/2	0.087
			893	0.021

क्रमांक /01/बी-121/2018-19, अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम लालपुर, पटवारी हल्का-लालपुर-64, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल में वेल क्रमांक SW#08-22 C से SW#09-22 के बीच मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्राजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, उपायुक्त राजस्व, शहडोल संभाग, शहडोल (म.प्र.) को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकारी के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
शहडोल	सोहागपुर	लालपुर/64	1869	0.364
			1820/2	0.260
			1804/1, 1804/2, 1804/3, 1804/4	0.130
			1801/1/ख, 1801/2	0.090

क्रमांक /02/बी-121/2018-19, अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम सेंदुरी, पटवारी हल्का-सेंदुरी-60, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल में वेल क्रमांक SW#03-11 से SW#04-11 के बीच मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्राजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, उपायक्त राजस्व, शहडोल संभाग, शहडोल (म.प्र.) को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकारी के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
शहडोल	सोहागपुर	सेंदुरी/60	544/1, 544/2	0.024
			545	0.056
			559/1, 559/2	0.004
			558/1, 558/2	0.040
			557/1, 557/2, 557/3	0.048
			556/1, 556/2	0.104
			561	0.228
			555/1, 555/2	0.184
			516	0.048
			517	0.004
			515	0.028
			513/1, 513/2, 513/3, 513/4, 513/5, 513/6, 513/7	0.082
			514/1, 514/2	0.040
			497	0.064
			498/1, 498/2	0.048
			499/1, 499/2	0.064
			500/1, 500/2	0.080
			501/1, 501/2	0.164
			385/1	0.605
			385/2	0.275

क्रमांक /03/बी-121/2018-19, अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम पोंगरी, पटवारी हल्का-पोंगरी-61, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल में वेल क्रमांक SW#03-14 से SW#04-14 के बीच मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्राजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, उपायुक्त राजस्व, शहडोल संभाग, शहडोल (म.प्र.) को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकारी के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
शहडोल	सोहागपुर	पोंगरी / 61	760/1, 760/2, 760/3, 760/4, 760/5 803	0.040 0.056

क्रमांक /04/बी-121/2014-19, अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम कंचनपुर, पटवारी हल्का-कंचनपुर-67, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल में वेल क्रमांक SW#04-20 A से SW#05-21 बीच मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्राजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, उपायुक्त राजस्व, शहडोल संभाग, शहडोल (म.प्र.) को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकारी के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
शहडोल	सोहागपुर	कंचनपुर/67	291/1, 291/2, 291/3, 291/4, 291/5	0.230
			292	0.056
			347/1/ख, 347/2/क, 347/2/ख, 347/2/ग, 347/3	0.679
			296/1/क, 296/1/ख, 296/2	0.160
			297/1, 297/2	0.080
			303/1, 303/2	0.136
			348/2, 348/3	0.144

क्रमांक /05/बी-121/2018-9, अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम समदाटोला, पटवारी हल्का-पकरिया, तहसील बुढ़ार, जिला शहडोल में वेल क्रमांक SW#14-22 C से SW#15-22 एव SW#14-24 B से SW#14-24 के बीच मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्राजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, उपायुक्त राजस्व, शहडोल संभाग, शहडोल (म.प्र.) को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकारी के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
शहडोल	बुढ़ार	समदाटोला / पकरिया	12/2/1/1, 12/2/1/2, 12/2/2, 12/3, 12/4, 12/5, 12/6, 12/7, 12/8, 12/9, 12/10, 12/12, 12/14	0.380
			10	0.064
			9	0.032
			7/1 ख, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5 क, 7/5 ख, 7/6, 7/7, 7/8, 7/9	0.382
			5	0.056
			64/2, 64/3, 64/4, 64/5, 64/6, 64/499	0.220
			59	0.240
			58	0.052

क्रमांक /06/बी-121/2018-19, अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम जरवाही, पटवारी हल्का-जरवाही, तहसील बुढ़ार, जिला शहडोल में वेल क्रमांक SW#21-23 D से SW#21-24 के बीच मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्राजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, उपायुक्त राजस्व, शहडोल संभाग, शहडोल (म.प्र.) को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकारी के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
शहडोल	बुढ़ार	जरवाही / जरवाही	545	0.080
			530	0.324
			528/1, 528/2	0.136
			553	0.060
			554/1, 554/2	0.160
			942	0.040
			556/2	0.074

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. पाण्डेय, सक्षम प्राधिकारी उपायुक्त राजस्व.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 17 अक्टूबर 2019

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ 82/19-20 पत्र क्र0.../भू-अर्जन/19 दि0 17/10/2019
उप मुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर द्वारा सतना-रीवा बडी रेलवे लाईन (50 किमी)
का दोहरीकरण हेतु निम्नलिखित ग्रामों के भूअर्जन प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये थे-

ग्राम का नाम	तहसील का नाम	अर्जित रकबा
1	2	3
खारी	रामपुर बाघेलान	0.924 हे0
हिनौता पैपखार	रामपुर बाघेलान	1.014 हे.
बठिया	रामपुर बाघेलान	0.600 हे0
मनकहरी	रामपुर बाघेलान	1.253 हे0
सतरी कोठार	रामपुर बाघेलान	0.422 हे0
बम्हौरी	रामपुर बाघेलान	1.084 हे0

उपरोक्त ग्रामों के भूअर्जन प्रस्तावों में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 का प्रकाशन 28/09/18 को किया गया था इस प्रकार 28/09/2019 को 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है इस अवधि के भीतर अनुविभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन अधिकारी रामपुर बाघेलान द्वारा अवधि विस्तारित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 25 के प्रावधान अनुसार समुचित सरकार को ऐसी परिस्थितियों में 12 माह की अवधि बढ़ाने की शक्ति प्रदत्त की गई है। अस्तु भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 25 के प्रावधानों के अन्तर्गत उपरोक्त ग्रामों के अधिनिर्णय पारित किये जाने हेतु 02 माह की अवधि विस्तारित की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सतेन्द्र सिंह, कलेक्टर.

**कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी, भू-अर्जन एवं पुनर्वास
तहसील-रामनगर जिला-सतना (म. प्र.)**

क्र. 607-भू-अर्जन-कार्य-2019

रामनगर, दिनांक 23 अक्टूबर 2019

**प्रारूप-घ
(नियम-6 देखिए)**

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 396 दिनांक 29.08.2019 द्वारा, राज्य सरकार ने रामनगर सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम- धनवाही, तहसील-रामनगर जिला-सतना के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 02/08/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चरपा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	ग्राम-धनवाही, पटवारी हल्का-09 टेगना, रा.नि.म. बड़वार, तहसील-रामनगर	646/1	0.059	0.003
2		646/2	0.058	
3		598/1	0.684	0.019
4		598/2	0.684	
5		645/1	0.032	0.002
6		645/2	0.032	
7		645/3	0.032	
8		599/1	0.466	0.019
9		599/2	0.466	
10		599/3	0.466	
11		607	0.117	0.002
12		606/1	0.635	0.026
13		606/2	0.640	
14		600/1/क	0.024	0.003
15		600/1/ख	0.024	
16		600/2	0.045	
17		603/1	0.556	0.016
18		603/2	0.545	
19		539	0.150	0.003
20		538	1.016	0.020
21		512	0.647	0.024
22		513	0.348	0.009
23		504/1	0.316	0.015
24		504/2/क	0.083	

25	504/2/ख	0.004	
26	504/2/ग	0.083	
27	435	0.045	0.002
28	503/1	0.058	
29	503/2	0.059	0.009
30	442/1/क	0.084	
31	442/1/ख	0.084	
32	442/1/ग	0.085	0.023
33	442/1/घ	0.085	
34	442/2	0.334	
35	443	0.028	0.002
36	445/1/क	1.415	
37	445/2	0.129	0.015
38	446/1	0.012	
39	446/2	0.121	0.010
40	448	0.097	0.003
41	450	0.113	0.001
42	451/1	0.048	
43	451/2	0.049	0.011
44	452/1/क	0.170	
45	452/1/ख	0.044	0.007
46	452/2	0.215	
47	460/1	0.027	
48	460/2	0.009	0.003
49	459/1	0.264	
50	459/2	0.088	0.004
51	457/1	0.021	
52	457/2	0.021	0.002
53	456/1/क	0.042	
54	456/1/ख	0.042	
55	456/1/ग	0.041	0.013
56	456/2	0.063	
57	456/3	0.063	
58	454	0.049	0.003
59	228/1	0.130	
60	228/2/क	0.056	
61	228/2/ख	0.056	0.012
62	228/2/ग	0.057	
63	230/1	0.020	
64	230/2/क	0.010	0.006
65	230/2/ख	0.010	
66	232/1	0.017	
67	232/2	0.069	
68	232/3	0.018	
69	232/4	0.017	0.009

70		233	0.125	0.034
71		233/1	0.089	
72		233/2	0.089	
73		233/3	0.089	
74		209	2.630	0.015
75		209/1	0.322	
76		209/2	0.362	
77		209/3	2.025	
78		236/1	0.975	0.009
79		236/2	0.325	
80		236/3	0.325	
81		236/4	0.326	
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग—	81 किता	20.359	0.354
1		434	0.069	0.001
2		222/1	1.132	0.004
3		222/2	0.053	
4		222/3	1.012	
	(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग—	4 किता	2.266	0.005
		कुल 85 किता	22.625	0.359

क्र. 608-भू-अर्जन-कार्य-2019

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 386 दिनांक 29.08.2019 द्वारा, राज्य सरकार ने रामनगर सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम— दतवार, तहसील—रामनगर जिला—सतना के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 02/08/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	ग्राम-दत्तवार, पटवारी हल्का-9 टेगना, रा.नि.म.-बड़वार, तहसील-रामनगर	74/1	1.595	0.009
2		74/2	1.595	
3		75/1	0.032	0.002
4		75/2	0.032	
5		57	1.668	0.025
6		33/1	0.968	0.029
7		33/2	0.967	
8		36	0.125	0.002
9		30	1.177	0.023
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	9 किता	8.159	0.090
1		78	0.951	0.007
2		62	0.769	0.025
3		60	1.210	0.030
4		58	1.053	0.012
	(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-	4 किता	3.983	0.074
		कुल 13 किता	12.142	0.164

क्र. 609-कार्य-भू-अर्जन-कार्य-2019

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 385 दिनांक 29.08.2019 द्वारा, राज्य सरकार ने रामनगर सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम- टेगना, तहसील-रामनगर जिला-सतना के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 02/08/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	ग्राम-टेगना, पटवारी हल्का-09 टेगना, रा.नि.म.-बड़वार, तहसील-रामनगर	525/1	4.059	0.063
2		525/2	0.300	
3		518	0.709	0.026
4		517	0.089	0.004
5		510/1	0.559	0.024
6		510/2	0.554	
7		343/548/1	0.144	0.021
8		343/548/2	0.143	
9		343	0.113	0.002
10		344	0.434	0.022
11		345	0.024	0.004
12		346	0.166	0.001
13		349	0.121	0.008
14		350	0.061	0.004
15		351	0.065	0.007
16		282	0.194	0.012
17		281/1	0.243	0.009
18		281/2	0.010	
19		280	0.210	0.007
20		260	1.538	0.013
21		262	0.089	0.008
22		261	0.053	0.005
23		255/1	0.886	0.015
24		255/2	0.502	
25		256	0.093	0.008
26	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	257/1	0.410	0.019
27		257/2	0.270	
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	27 किता	12.039	0.282
1	(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-	241	0.583	0.003
		1 किता	0.583	0.003
		कुल 28 किता	12.622	0.285

क्र. 610-भू-अर्जन-कार्य-2019

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 391 दिनांक 29.08.2019 द्वारा, राज्य सरकार ने रामनगर सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम- मझियार, तहसील-रामनगर जिला-सतना के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 02/08/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	ग्राम-मझियार, पटवारी हल्का-09 टेगना, रा.नि.म.-बड़वार, तहसील-रामनगर	263/302	0.024	0.002
2		263/1	0.797	0.025
3		263/2	0.401	
4		279	0.113	0.002
5		238/1	0.313	0.018
6		238/2	0.153	
7		242/1	0.162	0.008
8		242/2	0.081	
9		243	0.729	0.025
10		223	0.206	0.010
11		222	0.393	0.016
12		216/1/1/क/1	0.190	0.017
13		216/1/1/क/3	0.065	
14		216/1/1/ख	0.510	
15		216/1/2	0.409	
16		216/1/क/1/क/1	0.068	
17		216/1/क/2	0.065	
18		216/1/ख/1	0.510	
19		216/2	0.214	
20		216/294/1/ख	0.060	0.013
21		216/294/1/ग	0.028	
22		216/294/2	0.142	

23		160	0.061	0.001
24		193	0.117	0.011
25		193/2	0.060	
26		191	0.134	0.002
27		192	0.089	0.009
28		199	0.154	0.002
29		200	0.849	0.032
30		201/1	0.025	0.003
31		201/2	0.024	
32		202/1	0.064	0.003
33		202/2	0.163	
34		207/1	0.027	0.004
35		207/2	0.026	
36		208/1	0.506	0.011
37		208/2	0.502	
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग—	37 किता	8.434	0.214
	(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग—	0 किता	0.000	0.000
	अ + ब का योग—	कुल 37 किता	8.434	0.214

क्र. 611-भू-अर्जन-कार्य-2019

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 390 दिनांक 29.08.2019 द्वारा, राज्य सरकार ने रामनगर सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम- खारा, तहसील-रामनगर जिला-सतना के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 02/08/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	ग्राम-खारा, पटवारी हल्का-02 खारा, रा.नि.म.-बड़वार, तहसील-रामनगर	364	0.379	0.006
2		362/4	0.056	0.004
3		362/6	0.084	0.006
4		365/1	0.113	0.002
5		365/2	0.110	0.001
6		372/2	0.040	0.006
7		373	0.194	0.004
8		375/1	0.095	0.004
9		375/2	0.095	0.010
10		408	0.652	0.011
11		403	0.348	0.004
12		405	0.332	0.016
13		404/3	0.116	0.009

14		404/6	0.073	0.004
15		415/1/क	0.170	0.002
16		415/2/क	0.158	0.009
17		415/2/ख	0.188	0.004
18		415/2/घ	0.188	0.011
19		614	0.202	0.009
20		613	0.077	0.007
21		612/1	0.129	0.001
22		611/2	0.150	0.009
23		610/2	0.123	0.011
24		455	0.142	0.010
25		458	0.243	0.009
26		461	0.526	0.015
27		462	0.034	0.001
28		463/4	0.076	0.004
29		463/7	0.051	0.006
30		463/9	0.153	0.004
31		464	0.026	0.003
32		465	0.429	0.011
33		469	0.045	0.002
34		470/1	0.202	0.010
35		470/4	0.202	0.009
36		471/2	0.049	0.002
37		472/1	0.101	0.004
38		472/2	0.101	0.006
39		472/3	0.097	0.004
40		476/1	0.166	0.006
41		476/2	0.177	0.008
42		476/3	0.166	0.006
43		475	0.713	0.002
44		477	0.061	0.002
45		478/1/क	0.156	0.001
46		478/1/घ	0.156	0.006
47		478/2	0.615	0.016
48		484	0.081	0.003
49		485	0.295	0.009
50		486	0.040	0.002
51		487	0.431	0.017
52		488	0.113	0.003
53		534	2.110	0.030
54		533	0.206	0.003
55		493	0.660	0.010
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग—	55 किता	12.525	0.374
1		495	0.802	0.006
	(ब) स. प्र. शासन की भूमि का योग—	1 किता	0.802	0.006
	अ + ब का योग—	कुल 56 किता	13.327	0.380

क्र. 612-भू-अर्जन-कार्य-2019

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 374 दिनांक 29.08.2019 द्वारा, राज्य सरकार ने रामनगर सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम-बाबूपुर, तहसील-रामनगर जिला-सतना के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 02/08/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	ग्राम-बाबूपुर, पटवारी हल्का-बाबूपुर, रा.नि.मं.-बड़वार, तह.- रामनगर	411	1.011	0.042
2		410	0.061	0.003
3		409	1.073	0.045
4		408/1	0.016	0.003
5		408/2	0.016	
6		408/3/क	0.016	
7		408/3/ख/1	0.006	
8		408/3/ख/2	0.007	
9		406/502	0.526	0.029
10		397/1/क	0.284	0.006
11		397/1/ख	0.284	
12		397/2	0.575	
13		407	0.405	0.008
14		392/1	1.245	0.019
15		392/2/क	0.838	
16		392/2/ख	0.405	
17		392/3	1.243	
18		394	0.045	0.002
19		395	0.749	0.034
20		350/1/क	0.057	0.002
21		350/1/ख	0.057	
22		350/2	0.020	

23	351/1/क	0.369	0.003
24	351/1/ख	0.368	
25	351/2	0.016	
26	352/1/क	0.041	0.005
27	352/1/ख	0.040	
28	352/2	0.080	
29	353/1/क	0.720	0.031
30	353/1/ख	0.716	
31	353/2/क	0.718	
32	353/2/ख	0.719	0.005
33	330/1/क/1	0.242	
34	330/1/क/2	0.244	
35	330/1/ख	0.348	
36	330/1/ग/1	0.124	
37	330/1/ग/2	0.112	0.013
38	330/1/ग/3	0.112	
39	329/1/क/1	0.029	
40	329/1/क/2/1	0.014	
41	329/1/क/2/2	0.014	
42	329/1/क/3	0.024	
43	329/1/ख/1	0.009	
44	329/1/ख/2	0.010	
45	329/1/ख/3	0.010	
46	329/1/ग/1	0.010	
47	329/1/ग/2	0.009	
48	329/1/ग/3	0.009	
49	329/1/घ	0.024	
50	329/1/ङ/1	0.004	
51	329/1/ङ/2	0.004	
52	329/1/ङ/3	0.004	
53	329/1/च	0.012	
54	329/1/छ	0.028	
55	329/1/ज	0.029	
56	329/2	0.085	
57	329/495	0.052	0.009
58	328/1	0.356	0.018
59	328/2	0.089	
60	239/1	0.125	0.032
61	239/2	0.129	
62	239/3	0.255	
63	239/4	0.255	

64		239/5	0.259	
65		13/1	0.397	0.030
66		13/2	0.405	
67		3	0.757	0.025
68		4/1	2.740	0.028
69		4/2	0.202	
70		4/448	2.023	0.048
71		5/445	0.061	0.002
72		7	1.193	0.088
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग—	72 किता	23.534	0.530
1		238	1.668	0.026
2		47/447	1.457	0.012
3		237	0.206	0.007
	(ब) म.प्र. शासन की भूमि का योग—	3 किता	3.331	0.045
	अ + ब का योग—	75 किता	26.865	0.575

क्र. 613-भू-अर्जन-कार्य-2019

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 375 दिनांक 29.08.2019 द्वारा, राज्य सरकार ने रामनगर सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम— वेलहा, तहसील—रामनगर जिला—सतना के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 02/08/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	ग्राम—वेलहा, पटवारी हल्का—बाबूपुर, रा.नि.म.—बड़वार, तहसील—रामनगर	20/1	0.405	0.017
2		20/2	0.295	
3		15	0.644	0.019
4		12/1	0.454	0.028
5		12/2	0.450	
6		10/1	0.358	0.023
7		10/2	0.354	
8		9	0.053	0.004
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग—	8 किता	3.013	0.091
1		1	1.149	0.024
	(ब) म.प्र. शासन की भूमि का योग—	1 किता	1.149	0.024
	अ + ब का योग—	कुल 9 किता	4.162	0.115

क्र. 614-भू-अर्जन-कार्य-2019

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 379 दिनांक 29.08.2019 द्वारा, राज्य सरकार ने रामनगर सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम- कुचलेवा, तहसील-रामनगर जिला-सतना के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 02/08/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चरपा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	ग्राम-कुचलेवा, पटवारी हल्का-वाबूपुर, रा.नि.म.-बड़वार, तहसील-रामनगर	25/1/क	0.061	0.008
2		25/1/ख	0.056	
3		25/2	0.117	
4		22/1/क	0.028	0.004
5		22/1/ख	0.029	
6		22/2	0.056	
7		21/1/क	0.748	0.045
8		21/1/ख	0.474	
9		21/1/ग	0.182	
10		21/2	0.870	0.063
11		6/1/क/1	1.040	
12		6/1/क/2	0.101	
13		6/1/ख/1	0.148	
14		6/1/ख/2	0.148	
15		6/1/ख/3	0.149	
16		6/1/ग/1	0.133	
17		6/1/ग/2	0.474	
18		6/2	0.304	
19		6/3	0.121	
20		7	0.251	0.008
21		5	0.174	0.001
22		1	0.089	0.002
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	22 किता	5.753	0.131
1		27	0.405	0.007
	(ब) स.प्र. शासन की भूमि का योग-	1 किता	0.405	0.007
	अ + ब का योग-	कुल 23 किता	6.158	0.138

क्र. 615-भू-अर्जन-कार्य-2019

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 376 दिनांक 29.08.2019 द्वारा, राज्य सरकार ने रामनगर सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम- मोहनी, तहसील-रामनगर जिला-सतना के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 02/08/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	ग्राम-मोहनी, पटवारी हल्का-बाबूपुर, रा.नि.म.-बड़वार, तहसील-रामनगर	134	0.045	0.003
2		135/1/क	0.147	0.032
3		135/1/ख	0.147	
4		135/1/ग	0.147	
5		135/2	0.441	
6		136/1	0.016	0.002
7		136/2	0.024	
8		136/3	0.017	
9		137/1	0.176	0.021
10		137/2	0.175	
11		137/3	0.175	
12		138/1/क	0.201	0.032
13		138/1/ख	0.201	
14		138/1/ग	0.201	
15		138/2	0.304	0.120
16		127, 123	5.918	
17		147/1	0.376	0.005
18		147/2	0.380	
19		150/1	0.401	0.026
20		150/2	0.405	
21		151/1	0.202	0.022
22		151/2	0.202	
23		152/1	0.198	0.014
24		152/2	0.202	
25		153	0.356	0.022
26		156	1.481	0.007
27		180	1.372	0.023
28		181	0.129	0.004
29		182/1	0.085	0.002
30		182/2/क	0.077	
31		182/2/ख	0.077	
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	31 किता	14.278	0.335
	(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-		0.000	0.000
	अ + ब का योग-	कुल 31 किता	14.278	0.335

क्र. 616-भू-अर्जन-कार्य-2019

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 395 दिनांक 29.08.2019 द्वारा, राज्य सरकार ने रामनगर सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम- बटैया, तहसील-रामनगर जिला-सतना के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 02/08/2019 को प्रकाशित की गई तथा कुलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	ग्राम-बटैया, पटवारी हल्का-14 चंदवार, रा.नि.म.-बड़वार, तहसील-रामनगर	206/1	0.302	0.021
2		206/2	0.301	
3		204/1/क	0.405	0.053
4		204/1/ख	1.991	
5		204/1/ग	1.687	
6		204/2/1	2.505	
7		204/2/2	1.579	
8		213/734/1	0.603	0.004
9		213/734/2	1.202	
10		214/1/क	0.405	0.060
11		214/1/ख	0.339	
12		214/1/ग	0.024	
13		214/2 2	1.000	
14		214/3	1.001	
15		200	1.635	0.034
16		199/2	1.052	0.009
17		95/1/क/1	0.368	0.048
18		95/1/क/2	0.156	
19		95/1/ख	0.523	
20		95/1/ग	1.046	
21		95/2	0.782	
22		94	1.684	0.013

23	96/1/क	0.562	0.034
24	96/1/ख	0.562	
25	96/2	0.065	
26	108/1	0.166	0.040
27	108/2/क	0.457	
28	108/2/ख	0.457	
29	108/2/ग	0.045	0.023
30	107/1/1	0.711	
31	107/1/2/क	0.202	
32	107/1/2/ख	0.248	0.006
33	107/2	0.385	
34	111/1	0.190	
35	111/2	0.012	0.034
36	112/1	0.902	
37	112/2	0.150	
38	112/3	0.150	0.028
39	112/4	0.300	
40	140	0.761	
41	139	2.073	0.013
42	141	1.250	0.027
43	143/1	0.348	0.020
44	143/2/क	0.203	
45	143/2/ख	0.202	
46	144/1	0.202	0.010
47	144/2	0.238	
48	144/3/क	0.365	
49	144/3/ख	0.364	0.003
50	145/1	0.158	
51	145/2/क	0.040	
52	145/2/ख	0.041	0.003
53	146	0.057	
54	150/1	0.097	
55	150/2	0.020	0.486
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग—	55 किता	
1		207	
2		201	0.003
	(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग—	2 किता	0.005
	अ + ब का योग—	कूल 57 किता	0.491

क्र. 617-भू-अर्जन-कार्य-2019

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 394 दिनांक 29.08.2019 द्वारा, राज्य सरकार ने रामनगर सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम- भरतपुर, तहसील-रामनगर जिला-सतना के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 02/08/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।-

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	ग्राम-भरतपुर, पटवारी हल्का-भरतपुर, रा.नि.म.-बड़वार, तहसील-रामनगर	287	1.173	0.024
2		286	0.065	0.002
3		285	3.464	0.046
4		284	0.227	0.010
5		282	0.178	0.016
6		281	0.129	0.004
7		280/1/क	0.150	0.022
8		280/1/ख	0.150	
9		280/2	0.150	
10		306	0.247	0.006
11		308	0.162	0.011
12		307	0.214	0.012
13		339	0.421	0.017
14		340	0.692	0.002
15		338/1	0.595	0.046
16		338/2	0.591	
17		338/3	0.045	
18		338/4	0.045	
19		320	0.186	0.008
20		330	2.816	0.022
21		329/1/1/1	0.016	0.005
22		329/1/1/2	0.020	
23		329/1/2	0.036	
24		329/1/3	0.036	
25		329/2/1/1	0.024	

26		329/2/1/2	0.020	
27		329/2/2	0.044	
28		329/2/3	0.048	
29		326/1/1/1	0.160	0.044
30		326/1/1/2	0.177	
31		326/1/2	0.363	
32		326/1/3	0.363	
33		326/2/1/1	0.362	
34		326/2/1/2	0.362	
35		326/2/2	0.726	
36		326/2/3	0.725	
37		327	0.134	0.007
38		158	3.476	0.036
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	38 किता	18.792	0.340
1		290	0.251	0.003
2		321	0.162	0.012
	(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-	2 किता	0.413	0.015
	अ + ब का योग-	कुल 40 किता	19.205	0.355

क्र. 618-भू-अर्जन-कार्य-2019

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 377 दिनांक 29.08.2019 द्वारा, राज्य सरकार ने रामनगर सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम-पोड़िया, तहसील-रामनगर जिला-सतना के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 02/08/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगनों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	ग्राम-पोड़िया, पटवारी हल्का-भरतपुर, रा.नि.म.-बड़वार, तहसील-रामनगर	103/1	0.687	0.018
2		103/2	0.405	
3		104	0.437	
4		105/1/क	0.347	0.022
5		105/1/ख	0.086	
6		105/2	0.433	
7		105/3	0.867	
8		107/1/क/1/क/0001	0.092	
9		107/1/क/1/क/0002	0.202	
10		107/1/क/1/ख	0.648	

11	107/1/क/2	1.214	0.089	
12	107/1/ख/1/क	0.405		
13	107/1/ख/1/ख	0.405		
14	107/1/ख/1/ग	0.738		
15	107/1/ख/2	0.405		
16	107/1/ख/3	0.202		
17	107/2/क/1	0.938		
18	107/2/क/2	1.214		
19	107/2/ख	1.077		
20	107/2/ग	1.081		
21	134/1/क	0.070	0.017	
22	134/1/ख	0.071		
23	134/2/क	0.069		
24	134/2/ख	0.068		
25	134/3	0.137		
26	132/1	0.065	0.009	
27	132/2	0.065		
28	132/3	0.065		
29	133/1/क	0.588	0.020	
30	133/1/ख	0.588		
31	133/1/ग	0.589		
32	133/2	0.020		
33	133/3	0.020		
34	130/1	0.234	0.001	
35	130/2	0.234		
36	130/3	0.234		
37	139/1	0.971	0.053	
38	139/2	0.101		
39	139/3	1.234		
40	139/4	1.234		
41	139/5	1.238		
42	139/6	1.234		
43	41/160	1.457	0.002	
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	43 किता	22.469	0.241
1		140	0.174	0.003
	(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-	1 किता	0.174	0.003
	अ + ब का योग-	कुल 44 किता	22.643	0.244

क्र. 619-भू-अर्जन-कार्य-2019

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 392 दिनांक 29.08.2019 द्वारा, राज्य सरकार ने रामनगर सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम- रासा देवरा, तहसील-रामनगर जिला-सतना के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 02/08/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चरपा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	ग्राम-रासा देवरा, पटवारी हल्का-मसमासी, रा.नि.म.-बड़वार, तहसील-रामनगर	12/1	0.831	-
2		12/2	0.831	0.007
3		12/3	0.830	
4		11	1.558	0.050
5		2	0.652	0.002
6		3	0.539	0.028
7		4/1	0.023	0.017
8		4/2	0.023	
9		4/3	0.023	
10		4/4	0.013	
11		4/5	0.013	
12		4/6	0.013	
13		4/7	0.013	
14		4/8	0.013	
15		4/9	0.044	
16		4/10	0.022	
17		4/11	0.022	
18		4/12	0.044	
19		4/13	0.067	
20		4/14	0.066	
21		4/15	0.033	
22		4/16	0.033	
23		4/17	0.033	
24		4/18	0.033	
25		4/19/1	0.079	
26		4/19/2	0.057	
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	26 किता	5.908	0.104
1		28	0.045	0.002
	(ब) म.प्र. शासन की भूमि का योग-	1 किता	0.045	0.002
	अ + ब का योग-	कुल 27 किता	5.953	0.106

क्र. 620-भू-अर्जन-कार्य-2019

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 380 दिनांक 29.08.2019 द्वारा, राज्य सरकार ने रामनगर सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम- हरदुवा जागीर, तहसील-रामनगर जिला-सतना के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 02/08/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	ग्राम-हरदुवा जागीर, पटवारी हल्का-बम्हनाड़ी रा.नि.म.-बड़वार, तहसील-रामनगर	3/1	1.579	0.026
2		3/1/क	1.578	
3		3/1/ख	1.578	
4		3/1/ग	1.578	
5		3/1/घ	1.578	
6		3/2	1.578	
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	6 किता	9.469	0.026
1		1	0.134	0.002
	(ब) म.प्र. शासन की भूमि का योग-	1 किता	0.134	0.002
	अ + ब का योग-	कुल 7 किता	9.603	0.028

क्र. 621-भू-अर्जन-कार्य-2019

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 383 दिनांक 29.08.2019 द्वारा, राज्य सरकार ने रामनगर सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम- भिटारी, तहसील-रामनगर जिला-सतना के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 02/08/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चरप्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	4	5	6
1	ग्राम-भिटारी, पटवारी हल्का-भिटारी, रा.नि.म.-रामनगर, तहसील-रामनगर	512/1	0.530	0.014
2		512/2/क	0.506	
3		512/2/ख	0.506	
4		525/1/क	0.145	0.029
5		525/1/ख	0.225	
6		525/2	0.293	
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	6 किता	1.193	0.043
1		526	0.267	0.012
	(ब) म.प्र. शासन की भूमि का योग-	1 किता	0.267	0.012
	अ + ब का योग-	कुल 7 किता	1.460	0.055

क्र. 622-भू-अर्जन-कार्य-2019

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 381 दिनांक 29.08.2019 द्वारा, राज्य सरकार ने रामनगर सूक्ष्म, दबाव सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम- करौंदिया, तहसील-रामनगर जिला-सतना के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 02/08/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चरपा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	ग्राम-करौंदिया, पटवारी हल्का-31 भिटारी, रा.नि.म.-रामनगर, तहसील-रामनगर	64	0.233	0.027
2		64/1	0.073	
3		64/2	0.069	
4		64/3	0.073	
5		64/4	0.233	
6		64/5	0.237	0.002
7		65/1	0.008	
8		65/2	0.004	
9		65/3	0.008	
10		65/4	0.012	
11		65/5	0.008	0.018
12		66	0.922	
13		54/1/1	0.165	0.014
14		54/1/2	0.411	
15		54/2	0.576	0.011
16		55/1/1	0.044	
17		55/1/2	0.105	
18		55/2	0.150	0.002
19		51	0.069	
20		50/1	0.239	0.006
21		50/2	0.085	
22		49	0.057	0.002
23		48/1	0.941	0.025
24		48/2	0.941	
25		97/1	0.065	0.003
26		97/2	0.065	

27	98/1	0.202	0.021	
28	98/2	0.202		
29	98/3	0.202		
30	108	0.583	0.002	
31	107	0.255	0.011	
32	106	1.700	0.026	
33	109/1/क	0.101	0.015	
34	109/1/ख	0.687		
35	109/1/ग	0.081		
36	109/1/घ	0.709		
37	109/2	0.309	0.004	
38	110/1	0.045		
39	110/2	0.024		
40	110/3	0.020	0.032	
41	166/1	1.062		
42	166/2	1.064		
43	166/3	1.062		
44	166/4	1.062		
45	166/5	2.121		
46	166/6	2.121	0.009	
47	132	0.186		
48	136	0.235		
49	135	0.150	0.006	
50	138/1	1.214	0.042	
51	138/2	1.214		
52	145	0.785	0.007	
53	153/1	0.283	0.012	
54	153/2	0.283		
55	153/3	0.283		
56	153/4	0.284		
(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग—		56 किता	24.322	0.302
1		146	1.414	0.003
2		151	2.201	0.013
3		155	1.943	0.005
(ब) म.प्र. शासन की भूमि का योग—		3 किता	5.558	0.021
अ + ब का योग—		कुल 59 किता	29.880	0.323

क्र. 623-भू-अर्जन-कार्य-2019

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 389 दिनांक 29.08.2019 द्वारा, राज्य सरकार ने रामनगर सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम- गिधेली, तहसील-रामनगर जिला-सतना के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 02/08/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	ग्राम-गिधेली, पटवारी हल्का-27 गिधेला, रा.नि.मं.-रामनगर, तहसील-रामनगर	53/91	0.316	0.014
2		55/1	0.065	0.003
3		55/2	0.032	
4		55/3	0.032	
5		56/1	0.546	0.032
6		56/2	0.793	
7		56/3	0.789	
8		58/1	0.545	0.016
9		58/2	0.600	
10		59/98	0.587	0.019
11		59/1	0.664	0.047
12		59/2	0.000	
13		59/2/क	0.179	
14		59/2/ख	0.500	0.004
15		38/113	0.947	
16		38/113/1	0.463	
17		38/113/2	0.745	
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	17 किता	7.803	0.135
1		50	1.676	0.006
2		49	0.458	0.009
3		48/1	0.061	0.005
4		48/2	0.060	
5		48/3	0.028	
6		47/1	0.558	0.012
7		47/2	0.558	
8		47/3	0.604	
9		54	0.482	0.006
10		53	0.437	0.017
11		52	2.707	0.021
12		38/114/2	0.101	0.005
13		88	0.466	0.004
	(ब) म.प्र. शासन की भूमि का योग-	13 किता	8.196	0.085
	अ + ब का योग-	कुल 30 किता	15.999	0.220

क्र. 624-भू-अर्जन-कार्य-2019

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 534 दिनांक 09.10.2019 द्वारा, राज्य सरकार ने रामनगर सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना-के लिए ग्राम- गोदहा, तहसील-रामनगर जिला-सतना के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04/10/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	ग्राम-गोदहा, पटवारी हल्का-वाबूपुर, रा.नि.मं.-बड़वार, तहसील-रामनगर	84/1	0.263	0.029
2		84/2/क	0.280	
3		84/2/ख	0.286	
4		83/1/क	0.808	0.032
5		83/1/ख	0.306	
6		83	0.371	
7		86/1/क	0.404	0.021
8		86/1/ख	0.143	
9		86	0.182	
10		87	1.060	0.023
11		91/1	0.190	0.015
12		91/2	0.194	
13		90/1/क	0.234	
14		90/1/ख	0.460	0.013
15		90/1/ख/2	0.230	
16		90/2/क	0.124	
17		90/2/ख	0.124	0.046
18		94/1/क/1	0.384	
19		94/1/क/2	0.647	
20		94/1/ख	0.515	0.008
21		99/1/क	0.152	
22		99/1/ख	0.809	
23		99/2	0.480	0.006
24		95/1	0.392	
25		95/2	0.401	0.030
		67	0.963	0.025
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	26 किता	10.402	0.248
1		96	0.235	0.004
2		94/2	0.077	0.007
3		33	0.458	0.003
	(ब) म.प्र. शासन की भूमि का योग-	3 किता	0.770	0.014
	अ + ब का योग-	कुल 29 किता	11.172	0.262

क्र. 625-भू-अर्जन-कार्य-2019

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 552 दिनांक 09.10.2019 द्वारा, राज्य सरकार ने रामनगर सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम- बम्हनाड़ी, तहसील-रामनगर जिला-सतना के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04/10/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	ग्राम-बम्हनाड़ी, पटवारी हल्का-बम्हनाड़ी, रा.नि.म.-बड़वार, तहसील-रामनगर	480/1	2.833	0.124
2		480/2/क	1.416	
3		480/2/क/2	1.416	
4		480/2/क/500	1.000	
5		480/2/ख	1.417	
6		480/3/क	4.130	
7		480/3/ख	4.130	
8		480/3/ग/1	1.376	
9		480/3/ग/2	1.375	
10		480/3/ग/3	1.375	
11		484/1	0.649	0.044
12		484/2	0.650	
13		484/3	0.650	
14		484/4	0.649	
15		489	0.947	0.026
16		490/1	2.233	0.074
17		490/2	2.265	
18		490/3	2.893	
19		490/4/क	2.027	
20		490/4/ख	0.809	
21		490/4/ग	0.809	
22		469/1	3.678	0.047

23	469/2	0.405	
24	469/3/क	1.214	
25	469/3/ख	1.023	
26	469/4	4.476	
27	470/737/1	0.672	0.038
28	470/737/2	1.133	
29	467/1	0.263	
30	467/2	2.291	0.039
31	467/3	1.473	
32	467/4	0.700	
33	460/1	0.680	
34	460/3	0.064	0.032
35	460/4	0.064	
36	460/5/1	0.328	
37	460/6	0.202	
38	459	0.437	
39	459/1	0.107	0.022
40	459/2/क	0.165	
41	459/2/ख	0.161	
42	459/6/ख	0.161	
43	456/1	0.024	
44	456/3	0.176	0.005
45	456/4	0.174	
46	456/5	0.058	
47	456/6	0.404	
48	457	0.069	0.003
49	457/1	0.036	
50	458/1	0.048	
51	458/3	0.016	0.004
52	458/5/1	0.012	
53	458/5/2	0.030	
54	458/5/3	0.014	
55	458/6/क	0.036	
56	458/6/ख	0.004	
57	449/1	0.790	
58	449/2	0.790	0.060
59	449/3	0.786	
60	449/4	0.790	
61	449/5	0.786	
62	449/6	1.214	
63	505/1/1/क	0.494	
64	505/1/2/क	0.870	0.048
65	505/1/3/क/1	0.597	

66	505/1/3/क/2	0.597	
67	505/1/3/क/3	0.320	
68	505/1/5/क	1.497	
69	505/1/6/क	1.800	
70	505/1/7/क/1	1.024	
71	505/1/7/क/2	0.923	
72	505/1/7/क/3	0.923	
73	505/1/7/ख	0.129	
74	505/1/क/1	0.494	
75	505/1/क/3	1.497	
76	505/1/क/4	1.497	
77	505/1/क/5	1.497	
78	505/1/क/6	1.800	
79	505/1/क/7	2.870	
80	505/1/ख/1	0.020	
81	505/1/ख/3	0.073	
82	505/1/ख/4	0.073	
83	505/1/ख/5	0.073	
84	505/1/ख/6	0.081	
85	505/1/ख/7	0.129	
86	505/2	0.121	
87	67/1	0.065	0.004
88	67/2	0.040	
89	67/3	0.061	
90	67/4	0.040	
91	67/5	0.040	
92	69/1	0.846	0.016
93	69/1/क	0.530	
94	69/1/ख	0.316	
95	69/2	0.304	
96	69/3	0.304	
97	69/4	0.308	0.010
98	445/1	0.312	
99	445/2	0.169	
100	445/3	0.169	
101	445/4	0.169	0.003
102	70/1	0.089	
103	70/2	0.093	
104	70/3	0.089	0.003
105	71/1/क	1.335	
106	71/1/ख	0.065	
107	71/2	0.166	
108	71/3	0.166	

109	71/4	0.166	
110	72/1	0.498	
111	72/2	0.139	0.034
112	72/3	0.133	
113	72/4	0.133	
114	76/1/1	0.417	
115	76/1/2	0.262	0.028
116	76/2	0.069	
117	79	0.344	0.014
118	78/1/1/क/1	0.341	
119	78/1/1/क/2	0.101	
120	78/1/2/क/1	0.437	
121	78/1/2/क/2	0.231	0.006
122	78/1/2/क/3	0.105	
123	78/1/ख	0.148	
124	78/2	0.024	
125	123/1/1	0.040	
126	123/1/2	0.264	0.018
127	123/2	0.081	
128	125/1	0.020	0.005
129	125/2	0.020	
130	124/1	0.226	
131	124/2/क	0.121	0.002
132	124/2/ख	0.105	
133	126/1	0.263	
134	126/2	0.160	0.024
135	126/3	0.425	
136	128/1/क	0.040	
137	128/1/ख	0.036	
138	128/1/ग	0.036	0.007
139	128/1/घ	0.036	
140	128/2	0.040	
141	129/1/क	0.012	
142	129/1/ख	0.045	
143	129/1/ग	0.045	0.003
144	129/1/घ मेड	0.049	
145	129/2	0.045	
146	131/1	0.388	
147	131/2	0.141	0.018
148	131/3	0.141	
149	147/1	0.049	
150	147/2	0.121	0.004
151	132/1 मेड	0.069	0.002

152	132/2 मेड	0.028	
153	132/3	0.028	
154	145/1/क	0.097	
155	145/1/ख	0.490	
156	145/1/ग	0.490	
157	145/1/घ	0.490	0.027
158	145/2	0.390	
159	145/2/ख	0.376	
160	145/3	0.490	
161	144/1/क	0.028	
162	144/1/ख	0.028	
163	144/1/ग	0.028	0.003
164	144/2	0.024	
165	144/3	0.024	
166	180	0.866	0.030
167	179/1	0.291	
168	179/2	0.202	0.008
169	179/3	0.089	
170	181	0.223	0.004
171	183/1/क	0.352	
172	183/1/ख	0.121	0.024
173	183/2	0.353	
174	184	0.032	0.001
175	187/1	0.008	
176	187/2	0.008	0.004
177	187/3	0.008	
178	187/4	0.077	
179	188/1	0.028	
180	188/2	0.547	0.021
181	188/2/क	0.061	
182	188/2/ख	0.117	
183	207/1	0.028	
184	207/2	0.113	
185	207/3	0.032	0.004
186	207/4	0.053	
187	207/5	0.045	
188	208/1/क	0.056	
189	208/1/ख	0.104	
190	208/2	0.474	
191	208/3	0.185	0.057
192	208/4	0.181	
193	208/5	0.181	
194	208/6	0.506	

195		210/1	0.040	0.003
196		210/2	0.040	
197		210/3	0.040	
198		210/4	0.036	
199		211/1	0.113	0.021
200		211/2	0.113	
201		211/3	0.089	
202		211/4	0.073	
203		211/5	0.073	
204		211/6	0.121	
205		211/7	0.121	
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग—	205 किता	101.855	0.974
1		481	0.134	0.005
2		447	0.073	0.003
3		38	1.825	0.003
4		209	0.279	0.018
	(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग—	4 किता	2.311	0.029
	अ + ब का योग—	कुल 209 किता	104.166	1.003

क्र. 626-भू-अर्जन-कार्य-2019

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 548 दिनांक 09.10.2019 द्वारा, राज्य सरकार ने रामनगर सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम—पिपरी उत्तर, तहसील—रामनगर जिला—सतना के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04/10/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चरपा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	ग्राम—पिपरी उत्तर,	15/356/1	0.349	
2	पटवारी हल्का—गंगासागर,	15/356/2	0.182	
3	रा.नि.म.—रामनगर, तहसील—रामनगर	15/356/3/क	0.267	

4	15/356/3/क/0001	85.000	0.049	
5	15/356/3/ख	0.267		
6	15/356/3/ग	0.267		
7	15/356/3/घ	0.267		
8	15/356/4/क	0.267		
9	15/356/4/घ	0.267	0.038	
10	15/1	0.061		
11	15/2	0.226		
12	15/3	0.413		
13	15/4/क	0.351		
14	15/4/ख	0.351		
15	15/4/ग	0.350		
16	15/4/घ	0.351		
17	15/5/क	0.351		
18	15/5/ख	0.350		
(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-		18 किता	89.937	0.087
1		11	0.295	0.003
2		5	0.606	0.002
(ब) म.प्र. शासन की भूमि का योग-		2 किता	0.901	0.005
अ + ब का योग-		कुल 20 किता	90.838	0.092

क्र. 627-भू-अर्जन-कार्य-2019

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 538 दिनांक 09.10.2019 द्वारा, राज्य सरकार ने रामनगर सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम-पिपरी कोठार, तहसील-रामनगर जिला-सतना के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04/10/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

सं.क्र.	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	ग्राम-पिपरी कोठार, पटवारी हल्का-गंगासागर, रा.नि.म.-रामनगर, तहसील-रामनगर	8/1/क	0.081	0.068
2		8/1/ख	1.004	
3		8/1/ग	0.554	
4		8/2/1	0.546	
5		8/2/2	0.546	
6		8/2/3	0.546	

7	8/3/1	0.546	
8	8/3/2	0.546	
9	8/3/3	0.547	
10	7/1/क	0.418	
11	7/1/ख	0.418	
12	7/1/ग	0.419	
13	7/2/क	0.478	
14	7/2/ख	0.433	0.027
15	7/3/1	0.068	
16	7/3/2	0.067	
17	7/3/3	0.067	
18	6/1/क	0.133	
19	6/1/ख	0.065	
20	6/1/ग	0.069	
21	6/2/क	0.089	
22	6/2/ख	0.089	0.020
23	6/2/ग	0.093	
24	6/3/1	0.133	
25	6/3/2	0.134	
26	6/4	0.267	
27	5/1/1	11.306	
28	5/1/2	1.011	
29	5/1/3	1.011	
30	5/1/4	4.049	
31	5/2/क/1	0.265	
32	5/2/क/2	0.132	
33	5/2/क/3	0.133	
34	5/2/ख	0.534	
35	5/2/ग	0.530	
36	5/2/घ/1	0.265	
37	5/2/घ/2	0.265	0.023
38	5/3	0.809	
39	5/4/1/क	0.243	
40	5/4/1/ख	0.162	
41	5/4/2/क	0.244	
42	5/4/क/2	0.080	
43	5/5/क	0.671	
44	5/5/ख	0.679	
45	5/5/ग	0.676	
46	5/6	0.809	
47	5/6/क	0.486	
48	5/6/ख	0.323	
49	5/111/1	0.143	
50	5/111/2	0.143	0.001
51	5/111/3	0.143	
52	5/109	1.303	0.020
53	4/1/क	1.821	

54	4/1/ख	0.910	0.065	
55	4/1/ग	0.911		
56	4/2/1	1.086		
57	4/2/1/क	0.680		
58	4/2/1/ख	0.406		
59	4/2/2	0.227		
60	4/2/2/1	0.018		
61	4/2/2/2	0.019		
62	4/2/2/3	0.019		
63	4/2/2/4	0.057		
64	4/2/2/5	0.057		
65	4/2/2/6	0.057		
66	4/2/3/1	0.004		
67	4/2/3/2	0.015		
68	4/2/4	0.085		
69	4/2/5	0.085		
70	4/2/6	0.101		
71	4/2/7	0.202		
72	4/2/8/क	0.101		
73	4/2/8/ख	0.101		
74	4/2/8/95401	0.202		
75	4/3/1	0.873		
76	4/3/2	0.874		
77	4/4/क/1/0001/0001	0.122		
78	4/4/क/1/0001/0002	0.162		
79	4/4/क/1/0002	0.445		
80	4/4/क/2	0.080		
81	4/4/ख	0.405		
82	4/4/ग	0.405		
83	4/5/1	0.101		
84	4/5/2	0.101		
85	4/5/3	0.101		
86	4/5/4	0.202		
87	4/5/5	0.101		
88	4/6/1	0.101		
89	4/6/2	0.202		
90	4/6/3	0.101		
91	4/6/4	0.101		
92	4/6/5	0.101		
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	92 किता	46.513	0.224
1		1	0.664	0.003
	(ब) म.प्र. शासन की भूमि का योग-	1 किता	0.664	0.003
		कुल 93 किता	47.177	0.227

क्र. 628-भू-अर्जन-कार्य-2019

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 530 दिनांक 09.10.2019 द्वारा, राज्य सरकार ने रामनगर सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम- मोहरवा, तहसील-रामनगर जिला-सतना के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04/10/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चरपा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

सं.क्र.	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	ग्राम-मोहरवा, पटवारी हल्का-कर्ग, रा.नि.म.-रामनगर, तहसील-रामनगर	1/1/क	5.261	0.079
2		1/1/ख	0.749	
3		1/2/क	0.675	
4		1/2/ख	0.081	
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	4 किता	6.766	0.079
1		141/1	0.650	0.001
2		141/2	0.060	
	(ब) म.प्र. शासन की भूमि का योग-	2 किता	0.710	0.001
	अ + ब का योग-	कुल 6 किता	7.476	0.080

क्र. 629-भू-अर्जन-कार्य-2019

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 533 दिनांक 09.10.2019 द्वारा, राज्य सरकार ने रामनगर सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम- गोविन्दपुर, तहसील-रामनगर जिला-सतना के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04/10/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	ग्राम-गोविंदपुर, पटवारी हल्का-35 गोविन्दपुर, रा.नि.म.-रामनगर, तहसील-रामनगर	110/1	0.643	0.002
2		110/2	0.202	
3		25/1/क	3.742	
4		25/1/ख	2.004	0.009
5		25/2/क/1	0.032	
6		25/2/क/2	0.089	
7		25/2/ख	0.121	
8		25/2/ग/1/1	0.055	
9		25/2/ग/1/2	0.052	
10		25/2/ग/2	0.014	
11		25/2/घ/1	0.041	
12		25/2/घ/2	0.040	
13		25/2/घ/3	0.040	
14		25/2/ङ/1	0.098	
15		25/2/ङ/2	0.023	
16		25/3/क/1/1/1	0.058	
17		25/3/क/1/1/1/2	0.274	
18		25/3/क/1/1/2	0.060	

19	25/3/क/1/1/3	0.568	
20	25/3/क/1/1/4	0.040	
21	25/3/क/1/2	0.101	
22	25/3/क/2	0.202	
23	25/3/ख	0.202	
24	25/4/1	0.202	
25	25/4/2	0.202	
26	25/4/3	0.202	
27	25/4/4	0.202	
28	44/1	0.081	
29	44/2/क	0.061	0.097
30	44/2/ख	0.060	
31	6/1/क	0.223	
32	6/1/ख	0.222	
33	6/2/क/1	0.040	
34	6/2/क/2	0.041	0.001
35	6/2/ख/1/1	0.042	
36	6/2/ख/1/2	0.043	
37	6/2/ग	0.080	
38	6/2/घ	0.080	
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	38 किता 10.482	0.109
1	3/1	0.616	0.004
2	3/2	0.012	
3	1/1	0.016	0.003
4	1/2	0.048	
	(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-	4 किता 0.692	0.007
	अ + ब का योग-	कुल 42 किता 11.174	0.116

क्र. 630-भू-अर्जन-कार्य-2019

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 535 दिनांक 09.10.2019 द्वारा, राज्य सरकार ने रामनगर सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम-गौहानी, तहसील-रामनगर जिला-सतना के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04/10/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	ग्राम-गौहानी, पटवारी हल्का-35 गोविन्दपुर, रा.नि.म.-रामनगर, तहसील-रामनगर	30/1/क/1	0.288	0.036
2		30/1/क/2/1	0.072	
3		30/1/क/2/2	0.072	
4		30/1/क/2/3	0.072	
5		30/1/क/2/4	0.072	
6		30/1/क/3	0.287	
7		30/1/क/4	0.287	
8		30/1/ख	0.149	
9		30/2	0.081	
10		29/1	0.385	0.013
11		29/2	0.303	
12		26	1.275	0.030
13		23/1/क/1	0.405	0.007
14		23/1/क/2	0.070	
15		23/1/ख/1	0.349	
16		23/1/ख/2	0.121	
17		23/1/ग/1	0.190	
18		23/1/ग/2	0.284	
19		23/2/क	0.295	
20		23/2/ख	0.008	

21	22/1/क/1/क	0.101	0.048
22	22/1/क/1/ख	0.162	
23	22/1/क/2	0.506	
24	22/1/ख/1/1	0.202	
25	22/1/ख/1/2	0.202	
26	22/1/ख/1/3	0.203	
27	22/1/ख/2	0.162	
28	22/1/ग/1	0.267	
29	22/1/ग/2	0.506	
30	22/2/क	0.278	
31	22/2/ख	0.277	
32	22/3	0.202	
33	22/4/क	0.780	
34	22/4/ख	0.287	
35	16	0.178	0.005
36	15	2.012	0.004
37	18/1	0.174	0.025
38	18/2	0.174	
39	18/3	0.178	
40	20	1.061	0.025
41	19/1	0.607	0.003
42	19/2/क	0.405	
43	19/2/ख	0.202	
44	84/1/क	0.417	0.038
45	84/1/ख	0.417	
46	84/2	0.416	
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग—	46 किता 15.441	0.234
1	38/1	0.040	0.002
2	38/2	0.121	
3	33/1	0.105	0.010
4	33/2	0.680	
5	32	0.619	0.016
6	21	0.271	0.002
7	85	0.040	0.001
8	225	0.611	0.006
	(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग—	8 किता 2.487	0.037
	अ + ब का योग—	कुल 54 किता 17.928	0.271

क्र. 631-भू-अर्जन-कार्य-2019

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 529 दिनांक 09.10.2019 द्वारा, राज्य सरकार ने रामनगर सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम- मझगवां, तहसील-रामनगर जिला-सतना के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04/10/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	ग्राम-मझगवां, पटवारी हल्का-36 नारायणपुर, रा.नि.म.-रामनगर, तहसील-रामनगर	82/1	0.259	0.007
2		82/2/क	0.101	
3		82/2/ख	0.101	
4		64/1	2.412	0.006
5		64/2/क	0.505	
6		64/2/ख	0.506	
7		64/3/क	1.157	
8		64/3/ख	0.462	
9		64/4	0.024	
10		64/5	2.023	
11		64/6	0.405	
12		65/1	0.202	0.010
13		65/2	0.198	
14		65/3/क	0.081	
15		65/3/ख	0.117	
16		65/4	0.202	
17		65/5	0.198	0.018
18		81/1	0.129	
19		81/2/क	0.133	
20		81/2/ख	0.139	
21		81/2/ग	0.133	

22	81/3/क	0.664		
23	81/3/क/1	0.222		
24	81/3/क/1/ख	0.056		
25	81/3/क/2	0.218		
26	81/3/क/3/1/ख	0.056		
27	81/3/क/3/2	0.113		
28	81/3/ख	0.348		
29	81/3/घ	0.348		
30	78/1	0.182	0.022	
31	78/2/1	0.091		
32	78/2/2	0.091		
33	77/1	0.081	0.001	
34	77/2	0.085		
35	77/3	0.081		
36	77/4	0.081		
37	77/5	0.081		
38	74/1	0.180	0.012	
39	74/2/1	0.091		
40	74/2/2	0.091		
41	73/1	0.182	0.008	
42	73/2/1	0.091		
43	73/2/2	0.091		
44	72/1	0.069	0.008	
45	72/2	0.069		
46	72/3	0.068		
47	72/4	0.069		
48	72/5	0.069		
49	33/1	0.672	0.038	
50	33/2	0.672		
51	33/3/क	0.112		
52	33/3/ख	0.112		
53	33/3/ग	0.112		
54	33/3/घ	0.112		
55	33/3/ङ	0.112		
56	33/3/च	0.112		
57	33/4	0.672	0.011	
58	14/1/2	0.338		
59	14/2/ख	0.316		
60	14/2/ग	0.316		
61	14/3	0.688	0.031	
62	13/1/2	0.203		
63	13/2/ख	0.135		
64	13/2/ग	0.152		
65	13/3	0.405		
66	12	0.388	0.011	
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	66 किता	18.984	0.183

		79	0.097	0.004
1		32	0.223	0.003
	(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-	2 किता	0.320	0.007
	अ + ब का योग-	कुल 68 किता	19.304	0.190

क्र. 632-भू-अर्जन-कार्य-2019

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 540 दिनांक 09.10.2019 द्वारा, राज्य सरकार ने रामनगर सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम- नारायणपुर, तहसील-रामनगर जिला-सतना के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04/10/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चरपा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगनों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	ग्राम-नारायणपुर, पटवारी हल्का-36 नारायणपुर, रा.नि.म.-रामनगर, तहसील-रामनगर	22	0.045	0.003
2		23/1/क	0.200	0.019
3		23/1/ख	0.024	
4		23/2/क	0.081	
5		23/2/ख	0.081	
6		23/2/ग	0.142	
7		23/3	1.214	0.012
8		30/1	0.979	
9		30/2	0.121	
10		33	0.849	0.011
11		32/1/क	0.056	0.008
12		32/1/ख	0.849	
13		32/2	0.045	0.025
14		38/1	0.349	
15		38/2	0.468	0.011
16		40/1	0.559	
17		40/2	0.049	0.037
18		41/1/क	0.631	
19		41/1/ख	0.214	
20		41/2	0.635	
21		41/3	0.036	
22	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	46/321/1	0.906	0.001
23		46/321/2	0.910	
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	23 किता	9.443	0.127
1	(ब) स. प्र. शासन की भूमि का योग-	46/323/1	0.146	0.010
2		46/323/2	0.154	
3		47	1.108	0.009
4		48	0.761	0.012
	(ब) स. प्र. शासन की भूमि का योग-	4 किता	2.169	0.031
	अ + ब का योग-	कुल 27 किता	11.612	0.158

क्र. 633-भू-अर्जन-कार्य-2019

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 544 दिनांक 09.10.2019 द्वारा, राज्य सरकार ने रामनगर सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम-अराजी हटवा, तहसील-रामनगर जिला-सतना के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04/10/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	ग्राम-अराजी हटवा, पटवारी हल्का-36 नारायणपुर, रा.नि.म.-रामनगर, तहसील-रामनगर	68/1	0.174	0.006
2		68/2	0.174	
3		69/1	0.445	0.014
4		69/2	0.113	
5		69/3	0.077	
6		69/4	0.073	
7		69/5	0.073	
8		70	0.409	0.010
9		72	0.652	0.024
10		74	0.567	0.006
11		73/1	0.368	0.015
12		73/2	0.006	
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	12 किता	3.131	0.075
1		79	0.405	0.003
	(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-	1 किता	0.405	0.003
	अ + ब का योग-	कुल 13 किता	3.536	0.078

क्र. 634-भू-अर्जन-कार्य-2019

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 537 दिनांक 09.10.2019 द्वारा, राज्य सरकार ने रामनगर सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम- शहपुरा, तहसील-रामनगर जिला-सतना के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04/10/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	शहपुरा, पटवारी हल्का पदमी, रा.नि.म. रामनगर, तहसील-रामनगर	31/1	0.073	0.002
2		31/2	0.073	
3		7/1	0.447	0.017
4		7/2	0.447	
5		8	0.077	0.003
6		9	0.826	0.017
7		10	0.105	0.003
8		18	0.784	0.016
9		17/1	0.032	0.001
10		17/2	0.033	
11		52	0.340	0.007
12		15/1	0.158	0.017
13		15/2	0.405	
14		53	0.129	0.002
15		54	0.555	0.013
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	15 किता	4.484	0.098
1		33	0.336	0.004
	(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-	1 किता	0.336	0.004
	अ + ब का योग-	कुल 16 किता	4.820	0.102

क्र. 635-भू-अर्जन-कार्य-2019

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 547 दिनांक 09.10.2019 द्वारा, राज्य सरकार ने रामनगर सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम-सगौनी कलां, तहसील-रामनगर जिला-सतना के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04/10/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	ग्राम-सगौनी कलां, पटवारी हल्का-39 सगौनी खुर्द, रा.नि.म.-रामनगर, तहसील-रामनगर	147/1	0.331	0.001
2		147/2	0.235	
3		147/2/1	0.118	
4		147/2/2	0.117	
5		147/3	0.235	
6		148/1	0.236	0.015
7		148/2	0.233	
8		148/2/1	0.116	
9		148/2/2	0.117	
10		151	0.283	0.008
11		153	0.235	0.009
12		158	0.567	0.007
13		159/1	0.579	0.016
14		159/2	0.162	
15		166	0.348	0.004
16		171/1	0.644	0.015
17		171/2	0.660	
18		172	0.547	0.007
19		173	0.955	0.012
20		176	0.696	0.018
21		178	1.158	0.021
22		197/1	0.749	0.006
23		197/2	0.834	
24		197/2/क	0.181	
25		197/2/ख	0.000	
26		1	0.088	0.022
27		185/1/क	0.341	0.003
28		185/1/ख/1	0.309	
29		185/1/ख/2	0.309	
30		185/1/ग	0.263	
31		185/1/घ	0.263	
32		185/2	0.202	0.002
33		186/1	0.038	
34		186/2	0.039	
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	34 किता	12.188	0.166
	(ब) म.प्र. शासन की भूमि का योग-	0 किता	0.000	0.000
	अ + ब का योग-	कुल 34 किता	12.188	0.166

क्र. 636-भू-अर्जन-कार्य-2019

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 546 दिनांक 09.10.2019 द्वारा, राज्य सरकार ने रामनगर सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम-सगौनी खुर्द, तहसील-रामनगर जिला-सतना के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04/10/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	ग्राम-सगौनी खुर्द, पटवारी हल्का-39 सगौनी खुर्द, रा.नि.म. रामनगर, तहसील-रामनगर	212	0.049	0.002
2		211/1	0.101	0.001
3		211/2/क	0.053	
4		211/2/ख	0.048	
5		216/1	0.045	0.003
6		216/2	0.045	
7		229/1	0.161	0.010
8		229/2	0.053	
9		230	0.255	0.009
10		231/1	0.210	0.010
11		231/2	0.426	
12		232	0.045	0.001
13		233	0.045	0.002
14		224	0.036	0.004
15		225	0.376	0.001
16		223	0.040	0.008
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	16 किता	1.988	0.051
1		234	0.081	0.003
	(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-	1 किता	0.081	0.003
	अ + ब का योग-	कुल 17 किता	2.069	0.054

क्र. 637-भू-अर्जन-कार्य-2019

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 541 दिनांक 09.10.2019 द्वारा, राज्य सरकार ने रामनगर सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम- हिनौता, तहसील-रामनगर जिला-सतना के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04/10/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	ग्राम-हिनौता, पटवारी हल्का-जिगना, रा.नि.म. झिन्ना, तहसील-रामनगर	497	0.789	0.011
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	1 किता	0.789	0.011
	(ब) म.प्र. शासन की भूमि का योग-	0 किता	0.000	0.000
	अ + ब का योग-	कुल 1 किता	0.789	0.011

क्र. 638-भू-अर्जन-कार्य-2019

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 549 दिनांक 09.10.2019 द्वारा, राज्य सरकार ने रामनगर सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम- अमिलिया, तहसील-रामनगर जिला-सतना के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04/10/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	ग्राम-अमिलिया, पटवारी हल्का-37 पदमी, रा.नि.म. रामनगर, तहसील-रामनगर	153	0.053	0.003
2		154/1	0.823	0.010
3		154/2	0.568	

4	108	0.109	0.002	
5	107	0.198	0.005	
6	106	0.926	0.028	
7	105	0.061	0.002	
8	103/1	0.579	0.018	
9	103/2/क	0.243		
10	103/2/ख	0.113		
11	36	0.421	0.006	
12	37	0.328	0.009	
13	52	0.396	0.004	
14	51	0.481	0.009	
15	50	0.481	0.010	
16	49	0.243	0.007	
17	47	0.081	0.001	
18	48	0.444	0.017	
19	43	0.158	0.003	
20	60	1.081	0.002	
21	61	1.033	0.021	
22	64/1	0.582	0.016	
23	64/2	0.578		
(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-		23 किता	9.980	0.173

1		160	0.089	0.004
2		152	0.146	0.007
3		151	0.057	0.001
4		109	0.206	0.002
5		101	0.081	0.002
6		53/287	0.101	0.004
7		38	0.229	0.005
	(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-	7 किता	0.909	0.025
	अ + ब का योग-	कुल 30 किता	10.889	0.198

क्र. 639-भू-अर्जन-कार्य-2019

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 551 दिनांक 09.10.2019 द्वारा, राज्य सरकार ने रामनगर सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम-छिरहाई, तहसील-रामनगर जिला-सतना के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04/10/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	ग्राम-छिरहाई, पटवारी हल्का-41 छिरहाई, रा.नि.म.-झिन्ना, तहसील-रामनगर	943	0.283	0.006
2		947	0.571	0.006
3		952	0.332	0.006
4		951	0.352	0.007
5		950	0.336	0.007
6		884	0.510	0.008
7		966	0.397	0.011
8		850/1/क	0.148	0.005
9		850/1/ख	0.596	
10		850/1/ग	0.012	
11		850/2	0.809	
12		849	0.629	0.007
13		848	0.158	0.005
14		845	0.291	0.006
15		847/1	0.767	0.022
16		847/2	0.656	
17		847/3	0.069	
18		833/1	0.766	0.016
19		833/2	0.152	
20		833/3	0.101	
21		833/4	0.101	
22		806/1	0.931	0.002
23		806/2	0.466	
24		806/3	0.466	
25		816	0.186	0.007

26		813	0.368	0.008
27		812/1	0.117	0.006
28		812/2	0.114	
29		796/1	0.174	0.007
30		796/2	0.239	
31		796/3	0.206	
32		789/1	0.183	0.015
33		789/2	0.182	
34		789/3	0.178	
35		611/1	0.166	0.012
36		611/2	0.166	
37		611/3	0.166	
38		611/4	0.166	
39		616	0.478	0.009
40		617/1	0.251	0.001
41		617/2	0.251	
42		615/1	0.227	0.031
43		615/2	0.101	
44		615/3/क	0.304	
45		615/3/ख	0.538	
46		615/3/ग	0.506	0.032
47		634/1	0.652	
48		634/2	0.303	0.002
49		647/1	0.097	
50		647/2	0.049	
51		647/3	0.052	0.017
52		657	0.769	0.008
53		656	0.291	0.001
54		655	0.138	0.029
55		664	2.007	0.046
56		668	6.325	0.004
57		690	0.206	0.020
58		692	1.611	
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग—	58 किता	27.666	0.369
1		944/1	0.568	0.020
2		944/2	0.568	
3		815	0.348	0.006
4		814	0.534	0.006
5		797	0.198	0.003
	(ब) स. प्र. शासन की भूमि का योग—	5 किता	2.216	0.035
	अ + ब का योग—	कुल 63 किता	29.882	0.404

क्र. 640-भू-अर्जन-कार्य-2019

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 550 दिनांक 09.10.2019 द्वारा, राज्य सरकार ने रामनगर सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम-अरगट, तहसील-रामनगर जिला-सतना के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04/10/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	ग्राम-अरगट, पटवारी हल्का-43 अरगट, रा.नि.म.-झिन्ना, तहसील-रामनगर	330	0.510	0.009
2		329	1.365	0.004
3		331	0.522	0.009
4		332	0.105	0.002
5		332/2	0.008	
6		630/1	0.478	0.008
7		630/2	0.121	
8		625	0.405	0.003
9		624 शा.नं. 630 में	0.872	0.005
10		623	2.112	0.022
11		683	0.328	0.008
12		684	0.615	0.014
13		685	0.097	0.001
14		704	0.097	0.002
15		703	0.316	0.003
16		705/1	0.061	0.006
17		705/2	0.060	
18		706/1	0.026	0.001
19		706/2	0.027	
20		707/1	0.040	0.002
21		707/2	0.032	
22		726	1.125	0.013

23	727	0.214	0.004
24	729	0.073	0.003
25	730/1	0.028	0.005
26	730/2	0.162	
27	557/1	0.032	0.003
28	557/2	0.081	
29	557/3	0.099	
30	557/4	0.121	
31	558/1	0.012	0.002
32	558/2	0.049	
33	558/3	0.012	
34	539/1/1	0.105	0.005
35	539/1/2	0.104	
36	539/1/3	0.105	
37	539/2/1	0.104	
38	539/2/2	0.105	
39	539/2/3	0.105	
40	539/3/1	0.002	
41	539/3/2	0.003	
42	539/3/3	0.003	0.006
43	537/1/1	0.080	
44	537/1/2	0.080	
45	537/1/3	0.080	
46	537/2/1	0.082	
47	537/2/2	0.082	0.005
48	537/2/3	0.082	
49	536/1	0.120	
50	536/2	0.120	0.008
51	536/3	0.120	
52	534/1/क	0.134	
53	534/1/ख	0.129	0.003
54	534/2	0.129	
55	541/1/क	0.193	
56	541/1/ख	0.199	0.006
57	541/2/1	0.189	
58	541/2/2	0.202	0.003
59	533	0.263	0.006
60	532	0.162	0.003
61	530	0.174	0.003
62	529	0.219	0.004
63	520/1 शा.नं. 519 में	0.587	0.017
64	520/2 शा.नं. 519 में		
65	519/1	0.643	0.001
66	519/2	0.644	
67	523/1/1	0.072	0.002
68	523/1/2	0.069	
69	523/2/1	0.023	
70	523/2/2	0.022	
71	523/3/1	0.024	
72	523/3/2	0.020	
73	523/3/3	0.020	
(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	73 कित्ता	15.804	0.192
(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-	0 कित्ता	0.000	0.000
अ + ब का योग-	कुल 73 कित्ता	15.804	0.192

क्र. 641-भू-अर्जन-कार्य-2019

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 539 दिनांक 09.10.2019 द्वारा, राज्य सरकार ने रामनगर सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम- मतहा, तहसील-रामनगर जिला-सतना के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04/10/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चरपा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

सं.क्र.	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	ग्राम-मतहा, पटवारी हल्का-जुड़मानी, रा.नि.म. झिल्ला, तहसील-रामनगर	112/1/क/1	0.061	0.005
2		112/1/ख/2	0.060	
3		112/1/ख	0.063	
4		112/ग/1	0.064	
5		112/ग/2	0.073	
6		112/2	0.065	0.007
7		111	0.263	
8		110/1/क	0.284	0.007
9		110/1/ख	0.292	
10		110/2	0.310	
11		10/1	0.214	0.009
12		10/2	0.215	
13		12/1	0.028	0.001
14		12/2	0.028	
15		16	0.227	0.006
16		14	0.045	0.001
17		15	0.045	0.001
18		26	0.352	0.001
19		25	0.279	0.011
20		24	0.085	0.002
21		52/1	0.445	0.005
22		52/2	0.028	
23		53/1	0.526	0.009
24		53/2	0.081	
25		53/3	0.098	
26		54/1/क	0.057	0.002
27		54/1/ख	0.016	
28		54/1/ग	0.061	
29		54/1/घ	0.040	
30		54/1/ङ	0.032	
31		54/1/च	0.012	
32		54/1/छ	0.12	
33		54/2	0.255	
34		54/2/घ	0.012	
35		54/2/ज	0.012	
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	35 किता	4.848	0.067
1		70	2.112	0.004
	(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-	1 किता	2.112	0.004
	अ + ब का योग-	कुल 36 किता	6.960	0.071

क्र. 642-भू-अर्जन-कार्य-2019

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के-नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 532 दिनांक 09.10.2019 द्वारा, राज्य सरकार ने रामनगर सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम- हिनौता खुर्द, तहसील-मैहर जिला-सतना के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04/10/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	ग्राम-हिनौता खुर्द, पटवारी हल्का-94 जोवा, रा.नि.म.-भदनपुर उ.प, तहसील-मैहर	339/326/1/1	0.480	0.035
2		339/326/1/2	0.659	
3		339/326/2/क	0.293	
4		339/326/2/ख	0.836	
5		328/1	0.300	0.008
6		328/2	0.661	
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	6 किता	2.929	0.043
1		338	1.369	0.006
2		318/1	0.752	0.024
3		318/2	0.753	
4		327/1	0.180	
5		327/2	0.301	0.003
6		331/1	0.397	0.010
7		331/2	0.209	
8		332	1.338	0.022
9		333	1.400	0.026
	(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-	9 किता	6.699	0.091
	अ + ब का योग-	कुल 15 किता	9.628	0.134

क्र. 643-भू-अर्जन-कार्य-2019

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 545 दिनांक 09.10.2019 द्वारा, राज्य सरकार ने रामनगर सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम- टीकर खुर्द, तहसील-मैहर जिला-सतना के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04/10/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्या कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	ग्राम-टीकरखुर्द, पटवारी हल्का-93 बरा खुर्द, रा.नि.म. भदनपुर उ.प., तहसील-मैहर	408/1/क/1	1.045	0.026
2		408/1/क/2	1.463	
3		408/2/क	0.627	
4		408/2/ख	1.045	
5		408/2/ग	0.125	
6		408/2/घ	0.105	
7		408/3/क	0.105	
8		408/3/ख	0.105	
9		408/3/ग	0.105	
10		414/1	0.716	0.033
11		414/2/1	0.258	
12		414/2/2	0.458	
13		412/1/1	0.186	0.016
14		412/1/2	0.186	
15		412/1/3	0.023	
16		412/1/4	0.023	
17		412/2	0.146	
18		369/1	0.836	0.015
19		369/2	1.040	
20		369/3	0.486	
21		368/1	0.272	0.011
22		368/2	0.439	

23		367	0.125	0.002
24		366/1	1.254	0.005
25		366/2	0.690	
26		371	0.084	0.002
27		372	2.633	0.026
28		374	1.620	0.026
29		359	0.920	0.016
30		358	0.920	0.017
31		344/1	0.387	0.020
32		344/2	0.387	
33		344/3	0.396	
34		342	1.506	0.017
35		340	0.512	0.018
36		339/1	1.672	0.023
37		339/2/क	1.149	
38		339/2/ख	0.565	
39		331	1.515	0.002
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग—	39 किता	26.129	0.275
1		428	0.961	0.002
2		373	0.366	0.018
3		332	1.087	0.021
4		333	0.293	0.003
	(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग—	4 किता	2.707	0.044
		कुल 43 किता	28.836	0.319

क्र. 644-भू-अर्जन-कार्य-2019

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 536 दिनांक 09.10.2019 द्वारा, राज्य सरकार ने रामनगर सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम— बरा खुर्द, तहसील—मैहर जिला—सतना के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04/10/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चरपा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	ग्राम—बराखुर्द,	686	1.223	0.014
2	पटवारी हल्का—93 बराखुर्द,	286	0.700	0.009
3	रा.नि.म.—भदनपुर उ.प.	685/1	0.596	0.009
4	तहसील—मैहर	685/2/क	0.115	

5	685/2/ख	0.125	
6	292	0.805	0.001
7	683	0.355	0.014
8	681	2.080	0.018
9	676/1	1.824	0.014
10	676/2	1.510	
11	676/3	0.030	
12	679/1	0.068	0.003
13	679/2	0.068	
14	678/1	1.792	0.027
15	678/2/1	1.000	
16	678/2/2	0.793	
17	668/1	0.063	0.001
18	668/2	0.073	
19	669/1	0.784	0.020
20	669/2	0.794	
21	666/1	0.497	0.035
22	666/1/ख	0.470	
23	666/1/ग	0.470	
24	666/2	1.437	

	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	24 किता	13.422	0.165
1		660	0.157	0.005
	(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-	1 किता	0.157	0.005
	अ + ब का योग-	कुल 25 किता	13.579	0.170

क्र. 645-भू-अर्जन-कार्य-2019

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 543 दिनांक 09.10.2019 द्वारा, राज्य सरकार ने रामनगर सूक्ष्म द्रवाव सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम-बरकुला, तहसील-मैहर जिला-सतना के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04/10/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चरपा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी वित्तीयों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	ग्राम-बरकुला,	490	2.518	0.035
2	पटवारी हल्का-94 जोवा,	489	0.763	0.015
3	रा.नि.म.-भदनपुर उ.प.	487	0.428	0.002
4	तहसील-मैहर	488/1	0.285	

5		488/2	0.286	0.004
6		488/3	0.286	
7		484/1	0.491	0.024
8		484/2	0.491	
9		483/1	0.933	0.010
10		483/2	0.405	
11		446/1/क	0.688	0.009
12		446/1/ख	0.221	
13		446/2	0.920	
14		477	0.073	0.005
15		478	0.303	0.004
16		476/1	0.466	0.020
17		476/2	0.467	
18		476/3	0.467	
19		475	0.481	0.008
20		474	0.502	0.010
21		472	0.293	0.015
22		467/1/1	0.645	0.054
23		467/1/2	0.160	
24		467/2	0.804	
25		467/3	0.805	
26		465	0.125	0.005
27		462/1/क	0.433	0.018
28		462/1/ख	0.434	
29		462/2/1	0.434	
30		462/2/2	0.434	
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग—	30 किता	16.041	0.238
1		492	0.523	0.006
2		368	1.651	0.006
3		469	1.097	0.004
	(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग—	3 किता	3.271	0.016
	अ + ब का योग—	कुल 33 किता	19.312	0.254

क्र. 646-भू-अर्जन-कार्य-2019

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के आधीन जासी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 531 दिनांक 09.10.2019 द्वारा, राज्य सरकार ने रामनगर सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम- गोरईया, तहसील-मैहर जिला-सतना के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04/10/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	ग्राम-गोरईया, पटवारी हल्का-100 गोरईया, रा.नि.म.-भदनपुर उ.प., तहसील-मैहर	320/1	0.486	0.008
2		320/2/क/1	0.882	
3		320/2/क/2	0.081	
4		320/2/ख/1	0.884	
5		320/2/ख/2	0.080	
6		317/1	1.209	0.027
7		317/2	0.000	
8		316/1 316/2, 317/2	0.170	0.002
9		318/1	0.729	0.006
10		318/2/1/1	0.203	
11		318/2/1/2	0.202	
12		318/2/2	0.405	
13		318/3/1	0.748	
14		318/3/2	0.061	
15		318/4/1	0.684	
16		318/4/2	0.125	
17		318/5/1	0.150	
18		318/5/2	0.170	
19		318/6	0.849	
20		314	0.914	0.010
21		350/1/क/1/क/1	0.364	0.041
22		350/1/क/1/क/2	0.810	

23.	350/1/क/1/क/3	0.627	
24	350/1/क/1/ख	0.627	
25	350/1/क/1/ग	0.021	
26	350/1/क/2/2	0.384	
27	350/1/क/3	0.745	
28	350/1/ख	1.214	
29	350/2	1.214	
30	344/1	0.598	0.001
31	344/2	0.009	
32	355	1.424	0.020
33	362	0.737	0.003
34	361	0.587	0.006
35	365/1	0.592	
36	365/2	0.595	0.023
37	365/3	0.595	
38	364/1	0.688	0.001
39	364/2	0.688	
40	274/1	1.194	0.050
41	274/2	1.193	
42	406/1	0.737	0.008
43	406/2	0.736	
44	273		0.012
45	272/1 273/1	0.992	
46	272/2 273/2	0.991	0.020
47	272/3/1 273/3	0.465	
48	272/3/2 273/3	0.525	
49	418	0.364	0.008
50	443/1	0.211	0.006
51	443/2	0.405	
52	442/1	0.409	0.009
53	442/2	0.449	
54	440/1/क	0.510	
55	440/1/ख	0.510	0.024
56	440/1/ग	0.510	
57	440/1/घ	0.510	
58	440/2	0.000	
59	434/1	1.010	0.026
60	434/2	1.010	
61	434/3	1.011	
62	438/1	0.372	0.001
63	438/2	0.372	
64	438/3	0.372	
65	438/4	0.368	
66	435/1	0.500	0.001
67	435/2	0.500	
68	435/3	0.659	

16/11

69		437/1	0.359	0.013
70		437/2	0.359	
71		437/3	0.359	
72		437/4	0.359	
73		648/1	0.169	0.008
74		648/2	0.174	
75		648/3	0.174	
76		648/4	0.174	
77		650, 651/1	0.178	0.030
78		650/2 651/2	2.023	
79		Z12	1.668	0.010
80		Z13	3.075	0.023
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग—	80 किता	47.507	0.397
1		325 327/1	1.477	0.004
2		327/1	1.233	0.003
3		327/2/क		
4		327/2/ख		
5		298/1	4.603	0.026
6		298/2		
7		417	0.189	0.002
8		756 770,772	4.561	0.013
9		654	10.603	0.026
	(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग—	9 किता	22.666	0.074
	अ + ब का योग—	कुल 89 किता	70.173	0.471

क्र. 647-भू-अर्जन-कार्य-2019

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 542 दिनांक 09.10.2019 द्वारा, राज्य सरकार ने रामनगर सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम-रिवारा, तहसील-मैहर जिला-सतना के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04/10/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	ग्राम-रिवारा, पटवारी हल्का-97	891/1	0.408	0.010
2	रिवारा,	891/2	0.136	
3	रा.नि.म. भदनपुर उ.प. तहसील-मैहर	891/3	0.136	

4		894/1/क	1.348	0.018
5		894/1/ख	1.348	
6		894/2	0.408	
7		898/1	0.073	0.004
8		899/1	0.183	0.001
9		899/2	0.183	
10		897	0.178	0.010
11		896/1	0.675	0.005
12		896/2	0.261	
13		904/1	0.219	0.007
14		904/2	0.272	
15		909/1/क	0.272	0.015
16		909/1/ख	0.272	
17		909/2	0.533	
18		917	0.314	0.004
19		916	0.532	0.008
20		918/1/क	0.418	0.009
21		918/1/ख	0.178	
22		918/2	0.209	
23		918/3	0.554	
24		918/4	0.157	
25		919/1	0.167	0.010
26		919/2	0.637	
27		920	0.836	0.010
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	27 किता	10.907	0.111
1		926	0.115	0.006
	(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-	1 किता	0.115	0.006
	अ + ब का योग-	कुल 28 किता	11.022	0.117

जे. एल. तिवारी, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी.

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर 2019

क्र. एफ-5-21-2019-अ-तेहत्तर.—राज्य शासन, एतद्वारा, संलग्न परिशिष्ट-एक अनुसार “मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति, 2019” तथा संलग्न परिशिष्ट-दो अनुसार “मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना, 2019 जारी की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पर्वत सिंह, उपसचिव.

मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति, 2019

1. परिचय

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र देश में सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए इंजन माना जाता है और यह तेजी से भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे जीवंत और गतिशील क्षेत्र के रूप में उभर रहा है। एमएसएमई प्राथमिक क्षेत्र के बाद रोजगार का सबसे बड़ा सृजक है। जैसा कि हम जानते हैं, आज देश में सामने आने वाली मुख्य चुनौतियों में से एक रोजगार सृजन है। यह तथ्य एमएसएमई क्षेत्र के विकास को सबसे महत्वपूर्ण बना देता है। मध्यप्रदेश सरकार इस पहलू को स्वीकार करती है और तदनुसार राज्य में एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए अधिकतम जोर दिया जा रहा है।

रोजगार सृजन और आर्थिक एवं सामाजिक विकास में एमएसएमई की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को जानते हुए कि एमएसएमई क्षेत्र कृषि अर्थव्यवस्था से औद्योगिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण घटकों में से एक है, राज्य ने इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने का निर्णय लिया है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, एक समर्पित विभाग एमएसएमई के लिए बनाया गया है।

एमएसएमई विभाग राज्य की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अपनी स्थापना के बाद से एमएसएमई विभाग विभिन्न पहलों के माध्यम से एमएसएमई विकास के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध करा रहा है। एमएसएमई विभाग राज्य में एमएसएमई की स्थापना और विकास के लिए एक सहायक और उद्योग मित्र माहौल के निर्माण हेतु बहुआयामी पहल करने हेतु प्रतिबद्ध है।

एमएसएमई क्षेत्र के लिए अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय और राज्य स्तर पर मध्य प्रदेश के एमएसएमई विभाग ने नीतिगत पहल से कई कदम उठाए हैं।

व्यापार करने की आसानी में सुधार लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रगतिशील कदम उठाए गए हैं। स्टार्ट अप और इन्क्यूबेटर्स को बढ़ावा देने के लिए राज्य ने अपनी इन्क्यूबेशन एवं स्टार्टअप नीति लागू की है।

मध्य प्रदेश सरकार रोजगार सृजन और उद्यमिता के लिए सक्षम वातावरण प्रदान करके उद्यमियों/स्वरोजगार हितग्राहियों को सहयोग प्रदान कर रही है। एमएसएमई विभाग, रोजगार सृजन और संवर्धन के लिए विभिन्न फ्लेगशिप योजनाएं चला रहा है, जिसके तहत ब्याज अनुदान एवं पूंजी निवेश पर मार्जिन मनी सहायता का प्रावधान है।

विभाग भारत सरकार द्वारा की गई पहल के लिए प्रतिबद्ध है और यह विश्वास दिलाता है कि वह राज्य में एक जीवंत एमएसएमई के विकास की प्रक्रिया में सहभागी है। इस प्रतिवद्धता के साथ, विभाग ने एक समर्पित म. प्र. एमएसएमई विकास नीति 2019 को लागू करने का निर्णय लिया है। इस नीति का संपर्क राज्य में एमएसएमई क्षेत्र के केंद्रित विकास की ओर जाने वाले समस्त पहलुओं से है। नीति का मसौदा उद्योग संघों, वितीय संस्थानों, विशेषज्ञों और संबंधित सरकारी विभागों सहित सभी हितधारकों की राय एवं सुझावों को लेने के बाद परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से तैयार किया गया है।

2. एमएसएमई विकास नीति के उद्देश्य

एमएसएमई विकास नीति 2019 के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं: -

- (i) समय औद्योगिक विकास और एमएसएमई प्रतिस्पर्धा को प्राप्त करने के राज्य के लक्ष्य को प्राप्त करना;
- (ii) आधारभूत संरचना को सक्षम बनाना
- (iii) एक अनुकूल वातावरण का निर्माण करना और एमएसएमई के लिए समावेशी विकास को बढ़ावा देना।
- (iv) रोजगार सृजन के माध्यम से युवा उद्यमियों को अवसर प्रदान करना

3. नीति के निम्न क्षेत्र

उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यह नीति निम्नलिखित छः स्तंभों पर आधारित है:-

- (i) अनुकूल माहौल हेतु रूपरेखा : व्यवसाय करने में आसानी
- (ii) पात्र एमएसएमई इकाइयों को रियायतें जारी करने हेतु प्रक्रियात्मक सुधार
- (iii) निजी विकासकर्ताओं के माध्यम से बेहतर अधोसंरचना सुविधाओं का निर्माण और रखरखाव
- (iv) पीपीपी मॉडल पर अधोसंरचना का विकास
- (v) ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से प्रक्रियात्मक सहायता
- (vi) समयबद्ध सेवाओं और सहायताओं का प्रदाय।

4. नीति की प्रभावशील अवधि एवं कार्यक्षेत्र

4.1 यह नीति 01.10.2019 से लागू होगी।

4.2 यह नीति नई नीति द्वारा प्रतिस्थापित किये जाने तक जारी रहेगी।

4.3 30.09.2019 के पश्चात वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाली विनिर्माण क्षेत्र की एमएसएमई इस नीति के तहत सहायता प्राप्त करने के लिये पात्र होंगी। इस नीति के लागू होने के पश्चात् नवीन विनिर्माण इकाइयों, जो दिनांक 01.10.2019 या उसके पश्चात उत्पादन प्रारंभ करेंगी, के लिये म. प्र. एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2017 की सुविधाओं/सहायताओं का विकल्प समाप्त होगा। 01.10.2019 से पहले उत्पादन प्रारंभ करने वाली विनिर्माण क्षेत्र की एमएसएमई, एमएसएमई विकास नीति 2017 या इससे पहले की संबंधित नीतियों के तहत सहायता प्राप्त करने के लिये पात्र होंगी।

5. अनुकूल माहौल हेतु रूपरेखा : व्यवसाय करने में आसानी

5.1 व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ाकर व्यावसायिक माहौल में सुधार करना राज्य में एमएसएमई के संवर्धन और विकास हेतु मध्यप्रदेश सरकार ने विनियामक सुधारों को जारी रखने और प्रक्रियाओं को सरल बनाकर मध्यप्रदेश में कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने के लिए कई पहल की हैं। मध्यप्रदेश

सरकार राज्य में व्यापार करने के लिए एमएसएमई को सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में सुधार के लिए नई पहल करना जारी रखेगी। राज्य में एमएसएमई के लिए व्यवसायिक माहौल सुधारने हेतु एमएसएमई विभाग द्वारा निम्नलिखित कदम लिये गये हैं :-

- (i) विभागीय रियायतें अब ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही हैं। प्रक्रिया का सरल बनाया गया है।
- (ii) एमएसएमई के लिए औद्योगिक भूमि के आवंटन की प्रक्रिया ऑनलाइन की गई है।
- (iii) सरकारी विभागों के एमएसएमई आपूर्तिकर्ताओं के आधार को बढ़ाने और एमएसएमई आपूर्तिकर्ताओं से खरीद प्रक्रिया को गतिशील बनाने के लिए नए भण्डार क़य नियम बनाए जा रहे हैं।
- (iv) एमएसएमई हेतु विभिन्न लायसेंसों को नवीनीकरण की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाएगा।

5.2 एमएसएमई बिजनेस फैसिलिटेशन सेल

एमएसएमई को सहूलियत/सहयोग प्रदान करने हेतु उद्योग आयुक्त के कार्यालय में एक सेल का गठन किया गया है। एमएसएमई को हैण्ड होल्डिंग सहायता प्रदान करने हेतु इस सेल के माध्यम से सहायक सलाहकारों को राज्य भर में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों में पदस्थ किया गया है।

5.3 शिकायतों के समाधान के लिए संस्थागत उपाय

राज्य की एमएसएमई को उनके भुगतान के मुद्दों से संबंधित शिकायतों का समाधान करने के लिए, म. प्र. सरकार ने एमएसएमई विकास अधिनियम 2006 के अनुसार मध्य प्रदेश एमएसई फैसिलिटेशन काउंसिल का गठन किया है, जो अपनी सम्पूर्ण क्षमता के साथ कार्यरत है।

5.4 जिला स्तरीय सहायता समिति

इस नीति के प्रावधानों के तहत पात्र एमएसएमई को रियायतें प्रदान करने के लिए जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में निम्नलिखित समिति उत्तरदायी होगी :-

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. जिला कलेक्टर | - अध्यक्ष |
| 2. अग्रणी जिला प्रबंधक | - सदस्य |
| 3. महाप्रबंधक | - सदस्य सचिव |

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र

रियायतों का लाभ उठाने के लिए सामान्य प्रावधान

- 6.1 परिशिष्ट - I में उल्लेखित अपात्र उद्योगों को सूची में आने वाली इकाइयों हेतु रियायतें उपलब्ध नहीं होंगी।
- 6.2 इस नीति अंतर्गत लाभांशित इकाइयों को अपने कुल रोजगार का 70% मध्य प्रदेश के स्थाई निवासियों को प्रदान करना अनिवार्य होगा और उक्त 70% रोजगार में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को राज्य शासन द्वारा घोषित आरक्षण अनुसार प्रतिनिधित्व भी दिया जाना अनिवार्य होगा।
- 6.3 यदि कोई बीमार इकाई इस नीति की प्रभावशील अवधि में पुनर्जीवित होती है, तब वह साधिकार समिति द्वारा अनुमोदित पैकेज अनुसार नीति में प्रावधानित सहायताएं/सुविधाएं पात्रतानुसार प्राप्त कर सकती है।
- 6.4 इस नीति में प्रावधानित सहायताएं/सुविधाएं प्रदान करने हेतु म. प्र. एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019 जारी की जाएगी, जिसमें प्रक्रिया, पात्रता की शर्तों, अनुदान प्राप्त करने हेतु आवश्यक दस्तावेजों, कुल अनुदान की सीमा, लाभांशित इकाई के लिये नियम एवं शर्तों आदि का विस्तृत विवरण होगा। उक्त योजना इस नीति का भाग होगी।

7. रियायतें

7.1 उद्योग विकास अनुदान

- 7.1.1 नई औद्योगिक इकाई को संयंत्र एवं मशीनरी और भवन में किये गये पात्र निवेश का 40% उद्योग विकास अनुदान के रूप में प्रदान किया जाएगा। यह अनुदान 4 समान वार्षिक किश्तों में वितरित किया जाएगा।
- 7.1.2 रियायत की गणना के प्रयोजन के लिए भवन की लागत, संयंत्र और मशीनरी की लागत को 100% तक सीमित होगी।
- 7.1.3 महिला/अजा/अजजा उद्यमी(यों) द्वारा स्थापित इकाई के लिये प्रति वर्ष 2% (चार वर्षों हेतु) या अजा/अजजा श्रेणी की महिला उद्यमी(यों) द्वारा स्थापित इकाई के लिये प्रति वर्ष 2.5% (चार वर्षों हेतु) का अतिरिक्त उद्योग विकास अनुदान; और
- 7.1.4 औद्योगिक इकाईयों को कुल वार्षिक विक्रय का 25% से अधिक एवं अधिकतम 50% तक निर्यात करने के लिए 2% अतिरिक्त उद्योग विकास अनुदान (चार वर्षों हेतु);

या

औद्योगिक इकाईयों को कुल वार्षिक विक्रय का 50% से अधिक निर्यात करने के लिए 3% अतिरिक्त उद्योग विकास अनुदान (चार वर्षों हेतु)

7.2 गुणवत्ता प्रमाणन हेतु सहायता

- 7.2.1 सूक्ष्म स्तर की इकाईयों द्वारा आईएसओ/बीआयएस/बीईई प्रमाण पत्र के लिये प्रमाणीकरण हेतु किए गए व्यय का 100%, अधिकतम 5 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा की जाएगी।

7.2.2 जेड (ZED) प्रमाणन, एमएसएमई की ब्रांड पहचान में सुधार लाने और पर्यावरण पर प्रभाव को कम करने के लिए भारत सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम इकाइयों को क्रमशः 80%, 60% और 50% की दर से सहायता प्रदान करती है। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा शेष राशि की 50% प्रतिपूर्ति की जाएगी (सूक्ष्म, लघु और मध्यम इकाइयों के लिए कुल लागत का क्रमशः 10%, 20%, 25%)।

7.2.3 नीति की प्रभावशील अवधि के दौरान केवल निर्यात के लिए गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त करने हेतु किये गये व्यय का 50%, अधिकतम 25 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति की जाएगी, यदि ऐसा प्रमाणन राज्य की विनिर्माण क्षेत्र की एमएसएमई को यूएसए/यूरोपियन यूनियन/OECD के अन्य सदस्य देशों में निर्यात करने हेतु पात्र बनाए।

7.2.4 हालाँकि, ऐसी एमएसएमई, जिन्होंने इस नीति की प्रारंभ तिथि से पहले उत्पादन शुरू किया है, लेकिन इस नीति की प्रभावशील अवधि में गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त करती हैं, वे भी इस नीति के तहत प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी।

7.3 पेटेंट के लिए प्रतिपूर्ति

7.3.1 एमएसएमई इकाइयों को नीति की प्रभावशील अवधि के दौरान घरेलू पेटेंट/आईपीआर पंजीकरण कराने हेतु किये गये व्यय की 100%, अधिकतम 5 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति।

7.3.2 एमएसएमई इकाइयों को नीति की प्रभावशील अवधि के दौरान अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट/आईपीआर पंजीकरण कराने हेतु किये गये व्यय की 100%, अधिकतम 10 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति।

7.4 अधोसंरचना विकास के लिए वित्तीय सहायता

- 7.4.1 निजी या अविकसित शासकीय भूमि में स्थापित लघु और मध्यम श्रेणी की नई औद्योगिक इकाई को उसके परिसर तक अधोसंरचना विकास में किये गये व्यय का 50%, अधिकतम 25 लाख रुपये की सहायता।
- 7.4.2 औद्योगिक इकाई द्वारा अपशिष्ट उपचार संयंत्र (ETP) की स्थापना के लिये किये गये व्यय का 50%, अधिकतम 25 लाख रुपये की सहायता।
- 7.4.3 औद्योगिक इकाईयों के समूह (कम से कम 5) द्वारा सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र (CETP) की स्थापना के लिये किये गये व्यय का 50%, अधिकतम 100 लाख रुपये की सहायता।
- 7.4.4 निजी सेक्टर में औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर के विकासकर्ता को विकास में किये गये व्यय का 50%, अधिकतम 250 लाख रुपये की सहायता।
- 7.4.5 निजी भूमि पर कार्यरत एमएसएमई के क्लस्टर को सुदृढ़ बनाने के लिए अधोसंरचना विकास करने वाली एजेंसी को किये गये व्यय का 50%, अधिकतम 50 लाख रुपये की सहायता।

7.5 ऊर्जा लेखा परीक्षा (Audit) के लिए वित्तीय सहायता

एमएसएमई इकाईयों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए, मध्यप्रदेश सरकार द्वारा ऊर्जा लेखा परीक्षा की लागत का 50%, अधिकतम 50 हजार रुपये और ऑडिट में सुझाये गये उपकरण एवं मशीनरी को अपनाने के लिए हुये व्यय का 25%, अधिकतम 5 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

7.6 विशेष पैकेज

- 7.6.1 राज्य सरकार पावरलूम क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये परिशिष्ट - II अनुसार विशेष पैकेज प्रदान करेंगी।
- 7.6.2 राज्य सरकार फार्मास्युटिकल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये परिशिष्ट - III अनुसार विशेष पैकेज प्रदान करेंगी।
- 7.6.3 राज्य सरकार परिधान क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये परिशिष्ट - IV अनुसार विशेष पैकेज प्रदान करेंगी।

8. विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन

- 8.1 स्थापित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम स्तर की विद्यमान औद्योगिक इकाईयों द्वारा विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन करने पर, उन्हें उनके द्वारा किये गये अतिरिक्त पात्र निवेश पर नई औद्योगिक इकाई के समकक्ष सहायता/सुविधाओं की पात्रता होगी।
- 8.2 स्थापित सूक्ष्म स्तर की विद्यमान औद्योगिक इकाई द्वारा यंत्र एवं संयंत्र में 10 लाख रुपये या अधिक का निवेश करने पर, उसे नई औद्योगिक इकाई के समकक्ष सहायता/सुविधाओं की पात्रता होगी।
- 8.3 स्थापित लघु स्तर की विद्यमान औद्योगिक इकाई द्वारा यंत्र एवं संयंत्र में 25 लाख रुपये या अधिक का निवेश करने पर, उसे नई औद्योगिक इकाई के समकक्ष सहायता/सुविधाओं की पात्रता होगी।
- 8.4 स्थापित मध्यम स्तर की विद्यमान औद्योगिक इकाई द्वारा यंत्र एवं संयंत्र में 100 लाख रुपये या अधिक का निवेश करने पर, उसे नई औद्योगिक इकाई के समकक्ष सहायता/सुविधाओं की पात्रता होगी।
- 8.5 यदि विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन के फलस्वरूप किसी इकाई का यंत्र-संयंत्र में कुल निवेश 15 करोड़ रुपये से अधिक हो जाता है, तो वह इकाई इस नीति के अंतर्गत सहायता/सुविधाओं के लिये पात्र नहीं होगी।

बेहतर अधोसंरचना सुविधाओं का निर्माण और रखरखाव

बेहतर सुविधाओं के साथ औद्योगिक अधोसंरचना का विकास निश्चित रूप से एमएसएमई विकास को बढ़ावा देगा। एमएसएमई विभाग द्वारा इस नीति के अनुक्रम में नवीन औद्योगिक भूमि एवं भवन आवंटन नियम लाये जायेंगे, जिसमें:

- 9.1 एमएसएमई इकाइयों के लिए समर्पित औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों/संस्थानों का भविष्य में विकास करने हेतु शासकीय भूमि के 'लैंड बैंक' में विभाग द्वारा वृद्धि की जायेगी।
- 9.2 ऐसे जिलों, जहां एमएसएमई विकास के पर्याप्त अवसर हो, में राज्य शासन द्वारा समर्पित एमएसएमई पार्कों की स्थापना की जाएगी।
- 9.3 विभाग निजी क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्रों को प्रोत्साहित करेगा।
- 9.4 पीपीपी मोड में औद्योगिक क्षेत्र में बहुमजिला परिसर के निर्माण पर विशेष ध्यान और जोर दिया जाएगा।
- 9.5 भूमि हेतु ऑनलाईन आवेदन और आवंटन प्रणाली को आसान और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाया जाएगा।
- 9.6 राज्य शासन द्वारा औद्योगिक भूमि आवंटन हेतु नए नियम लाये जायेंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के स्वामित्व वाली इकाइयों के लिये विभागीय औद्योगिक क्षेत्र में 10 प्रतिशत भूखण्ड आरक्षित किये जायेंगे।

क्षमताओं का सुदृढीकरण

10.1 क्लस्टर विकास

- 10.1.1 राज्य शासन ने सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास के लिये क्लस्टर विकास के दृष्टिकोण को प्रमुख रणनीति के रूप में अपनाया है और साथ-साथ उन कारकों को भी, जो राज्य में नए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना को प्रोत्साहित करते हैं।

- 10.1.2 राज्य भर में फैले हुए एमएसएमई क्लस्टरों को सुविधाएं प्रदान करने के लिये अधोसंरचना (ID) एवं सार्वजनिक सुविधा केन्द्र (CFC) का निर्माण करने हेतु राज्य शासन द्वारा भारत सरकार के सहयोग से स्वयं की क्लस्टर विकास योजना बनाई जाएगी।
- 10.1.3 राज्य और भारत सरकार की क्लस्टर विकास योजना को सही तरीके से लागू करने हेतु एक समर्पित क्लस्टर विकास सेल बनाया जाएगा। यह सेल राज्य के एमएसएमई क्लस्टरों की जरूरतों को पूरा करने के लिये जिम्मेदार होगा।
- 10.1.4 म. प्र. लघु उद्योग निगम राज्य में क्लस्टर गतिविधियों के लिये नोडल एजेंसी होगा।

10.2 स्वरोजगार

- 10.2.1 युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु एमएसएमई विभाग वर्तमान में विभिन्न स्वरोजगार योजनाएं चला रहा है, जो युवा उद्यमियों को रियायते एवं हेण्ड-होल्डिंग सहायता प्रदान करती हैं।
- 10.2.2 अधिक प्रभावी हेण्ड-होल्डिंग समर्थन और बेहतर प्रोत्साहन के साथ एक नई स्वरोजगार योजना प्रारंभ की जाएगी।
- 10.2.3 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों/प्रदर्शनी में भाग लेने हेतु स्वरोजगार योजनाओं के लाभान्वितों को अवसर प्रदान किया जाएगा।
- 10.2.4 ऑनलाइन ईडीपी मॉड्यूल के माध्यम से युवाओं के व्यावसायिक कौशल में सुधार किया जाएगा।
- 10.2.5 जिला स्तर पर पैनाल के चार्टर्ड अकाउंटेंटों के माध्यम से तत्कालीन शुल्क पर स्वरोजगार योजनाओं के आवेदकों को प्रोजेक्ट रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाएगी।

10.2.6 अजा/अजजा वर्ग के हितग्राहियों को स्वरोजगार योजनाओं में अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जाएगा।

10.3 स्टार्टअप एवं इंक्यूबेशन

राज्य में युवा उद्यमियों के लिए नवाचार और स्टार्टअप वातावरण को परिपोषण करने हेतु मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नई "म. प्र. स्टार्टअप नीति" लायी जाएगी।

11. बीमार इकाइयों का पुनर्जीवन

11.1 व्यवहार्य बीमार/बंद इकाई के पुनर्जीवन के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थानों की सहायता से एक पैकेज बनाया जाएगा।

11.2 पुनर्जीवन पैकेज तैयार करने की प्रमुख जिम्मेदारी बैंकों/वित्तीय संस्थानों की होगी।

11.3 बैंकों/वित्तीय संस्थानों के परामर्श से बीमार इकाई द्वारा रियायतों का पैकेज प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव बनाया जाएगा और साधिकार समिति को प्रस्तुत किया जाएगा।

11.4 बीमार औद्योगिक इकाइयों के पक्ष में पुनर्जीवन पैकेज पर निर्णय लेने के लिए एमएसएमई विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में साधिकार समिति का गठन किया जाएगा। समिति का गठन निम्नानुसार होगा:

- (i) प्रमुख सचिव, एमएसएमई विभाग (अध्यक्ष)
- (ii) जिस विभाग से बीमार इकाई हेतु रियायत/राहत चाही गई है, उस विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव (सदस्य)
- (iii) उद्योग आयुक्त, एमएसएमई विभाग (सदस्य)
- (iv) संबंधित बैंक शाखा के क्षेत्रीय प्रबंधक (सदस्य)
- (v) उस बैंक/वित्तीय संस्था के शाखा प्रबंधक/प्रभारी अधिकारी, जिसके माध्यम से पुनर्जीवन पैकेज प्रस्तावित हो (सदस्य)

(vi) संयुक्त/उप संचालक, एमएसएमई विभाग (सदस्य सचिव)

11.5 बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के द्वारा पुनर्जीवन योग्य बीमार इकाइयों के लिये पुनर्जीवन पैकेज तैयार किया जाएगा। इस पुनर्वास पैकेज में बीमार इकाइयों के द्वारा राज्य शासन से सुविधाओं की मांग की जा सकेगी।

11.6 बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के द्वारा बीमार इकाइयों के पुनर्जीवन हेतु तैयार किये गये पुनर्जीवन पैकेज में राज्य शासन से चाही जा रही सुविधाओं की मांग साधिकार समिति के समक्ष प्रस्तुत की जावेगी तथा साधिकार समिति के द्वारा गुण-दोष के आधार पर बीमार इकाई के पक्ष में विभागीय सुविधाओं अथवा अन्य विभाग की सुविधायें, संबंधित विभाग की सहमति होने पर स्वीकृत की जा सकेगी।

12. संशोधन/शिथिलीकरण/निरसन

नीति के प्रावधानों में किसी बात के होते हुये भी, मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग किसी भी समय -

12.1 इस नीति को संशोधित अथवा निरस्त कर सकेगा,

12.2 इस नीति के प्रावधानों को शिथिल कर सकेगा,

12.3 नीति के प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए निर्देश/स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन जारी कर सकेगा।

13. न्यायालय क्षेत्र

किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र मध्यप्रदेश होगा।

14. शब्दावली

(i) नीति से सामान्य अभिप्रेत है, "म. प्र. एमएसएमई विकास नीति 2019"।

- (ii) एमएसएमई से अभिप्रेत है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (समय-समय पर किये गये संशोधनों सहित) के तहत परिभाषित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम।
- (iii) इकाई / औद्योगिक इकाई से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश में विनिर्माण क्षेत्र की एमएसएमई।
- (iv) संयंत्र और मशीनरी में निवेश से अभिप्रेत है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 (समय-समय पर किये गये संशोधनों सहित) के अनुसार संयंत्र और मशीनरी में निवेश।
- (v) भवन में निवेश से अभिप्रेत है, उत्पादन में उपयोग में आने वाली फॅक्टरी भवन व शेड, लेकिन इसमें आवासीय इकाइयाँ शामिल नहीं होंगी।
- (vi) नई औद्योगिक इकाई से अभिप्रेत है, इस नीति की प्रभावशील अवधि के दौरान स्थापित विनिर्माण क्षेत्र की एमएसएमई।
- (vii) विद्यमान औद्योगिक इकाई से अभिप्रेत है, ऐसी औद्योगिक इकाई, जिसमें दिनांक 01.10.2019 के पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ हुआ हो या ऐसी नई औद्योगिक इकाई जिसके द्वारा इस नीति की प्रभावशील अवधि में विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन किया गया हो।
- (viii) महिला/अजा/अजजा उद्यमी(यों) द्वारा संचालित इकाई से अभिप्रेत है, महिला/अजा/अजजा वर्ग के व्यक्ति(यों) के शत प्रतिशत स्वामित्व वाली इकाई।
- (ix) वाणिज्यिक उत्पादन की दिनांक से अभिप्रेत है, इकाई द्वारा उत्पादन प्रारंभ कर उत्पादित माल के प्रथम बार विक्रय की दिनांक अर्थात् प्रथम विक्रय के दायक की दिनांक।
- (x) गुणवत्ता प्रमाणीकरण से अभिप्रेत है, गुणवत्ता प्रमाणीकरण हेतु तीसरे पक्ष की अधिकृत एजेंसियों द्वारा प्रदाय ISO प्रमाणपत्र या BIS/BEE प्रमाणन या ZED प्रमाणन या निर्यात के लिये विशिष्ट प्रमाणन।
- (xi) पेटेंट से अभिप्रेत है, पेटेंट अधिनियम, 1970 (समय-समय पर किये गये संशोधनों सहित) में परिभाषित और या अंतर्निहित पेटेंट।
- (xii) एमएसएमई संचालनालय से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के अधीन संचालनालय।
- (xiii) राज्य सरकार/शासन से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन का सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग।
- (xiv) जिला व्यापार और उद्योग केंद्र से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के अधीन एमएसएमई संचालनालय का जिला स्तरीय कार्यालय।

परिशिष्ट -अज्ञात उद्योगों की सूची

1. व्यापार और सेवाओं से संबंधित गतिविधियाँ
2. बीयर और शराब, जिसमें एल्कोहल है
3. सभी प्रकार के पान मसाला और गुटखा विनिर्माण
4. तम्बाकू और तम्बाकू आधारित उत्पादों का विनिर्माण
5. समस्त प्रकार के पांतिथीन बैग और 40 माइक्रोन या उससे कम मोटाई के प्लास्टिक बैग का विनिर्माण
6. केंद्र या राज्य सरकार या उनके उपक्रम द्वारा स्थापित औद्योगिक इकाइयाँ
7. स्टोन क्रशर
8. खनिजों की पिसाई, केल्विनेशन (गिट्टी से बनाई जाने वाली कृत्रिम रेत के निर्माण को छोड़कर)
9. राज्य सरकार/राज्य सरकार के उपक्रम का अशोधी/चूककर्ता
10. सभी प्रकार की खनन गतिविधियाँ (जहां कोई मूल्य संवर्धन नहीं हुआ हो)
11. लकड़ी के कोयले (चारकोल) का निर्माण
12. सभी प्रकार के सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट (ऐसी खाद्य तेल एक्पैलर इकाईयाँ, जहाँ संयंत्र और मशीनरी में निवेश रु. 1 करोड़ से अधिक नहीं है, को छोड़कर)
13. समस्त प्रकार के तेलों की रिफायनरी
14. सीमेंट/क्लंकर विनिर्माण इकाईयाँ
15. सभी प्रकार के प्रदूषण और मुद्रण प्रक्रिया
16. आरा मिल और लकड़ी की प्लेनिंग
17. लोहे/स्टील स्क्रैप का दबाकर इसे ब्लॉकों एवं किसी अन्य किसी आकार में बदलना
18. विद्युत उत्पादक इकाईयाँ
19. पैकेज पीने का पानी
20. सॉर्टिंग प्लांट और फसलों/अनाज की सॉर्टिंग/ग्रेडिंग/सफाई
21. समस्त प्रकार के गैसयुक्त (Aerated)/ कार्बोनेटेड पेय
22. बूँदखाना और मांस पर आधारित उद्योग
23. म. प्र. एमएसएमई विकास नीति 2019 के संदर्भ में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा घोषित कोई उद्योग

परिशिष्ट - IIपावरलूम सेक्टर के लिये विशेष पैकेज**(अ) विशेष पैकेज**

1. प्लेन/सेमी ऑटोमेटिक शटल पावरलूम को आधुनिक शटललेस लूम में उन्नयन करने के लिए किये गये व्यय में से, भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता (यदि कोई हो, तो) के समायोजन के पश्चात् शेष राशि का शत-प्रतिशत या उन्नयन लागत का 25%, जो भी कम हो, अधिकतम 10 पावरलूम प्रति इकाई पर राज्य शासन द्वारा प्रदान किया जाएगा।
2. विद्युत प्रदाय में 20HP तक की क्षमता के पावरलूम को 1.50 रुपये प्रति यूनिट की दर से और 20HP से अधिक परंतु 150HP तक की क्षमता के पावरलूम को 1.25 रुपये प्रति यूनिट की दर से रियायत। साथ ही विद्युत प्रदाय में 150HP तक की क्षमता के पावरलूम को फिक्स चार्जस और न्यूनतम प्रभार व वास्तविक खपत के अंतर की राशि की शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति।
3. पावरलूम के लिये निजी औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर के विकासकारों को विकास में किये गये व्यय का 60%, अधिकतम 500 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति।

(ब) अन्य सहायता

1. इस नीति की कण्डिका 7.1 के अनुसार उद्योग विकास अनुदान।
2. इस नीति की कण्डिका 7.2 के अनुसार गुणवत्ता प्रमाणन हेतु सहायता।
3. इस नीति की कण्डिका 7.3 के अनुसार पेटेंट के लिए प्रतिपूर्ति।
4. इस नीति की कण्डिका 7.4 के अनुसार अर्थोसंरचना विकास के लिए वित्तीय सहायता (उप कण्डिका 7.4.4 को छोड़कर)।
5. इस नीति की कण्डिका 7.5 के अनुसार ऊर्जा लेखा परीक्षा में सहायता।

परिशिष्ट - IIIफार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए विशेष पैकेज

(अ) विशेष पैकेज

1. उद्योग विकास अनुदान
 - 1.1 नई औद्योगिक इकाई को संयंत्र एवं मशीनरी और भवन में किये गये पात्र निवेश का 40% उद्योग विकास अनुदान के रूप में प्रदान किया जाएगा। यह अनुदान 4 समान वार्षिक किश्तों में वितरित किया जाएगा।
 - 1.2 रियायत की गणना के प्रयोजन के लिए भवन की लागत, संयंत्र और मशीनरी की लागत की 200% तक सीमित होगी।
 - 1.3 महिला/अजा/अजजा उद्यमी(यों) द्वारा स्थापित इकाई के लिये प्रति वर्ष 2% (चार वर्षों हेतु) या अजा/अजजा श्रेणी की महिला उद्यमी(यों) द्वारा स्थापित इकाई के लिये प्रति वर्ष 2.5% (चार वर्षों हेतु) का अतिरिक्त उद्योग विकास अनुदान; और
 - 1.4 औद्योगिक इकाईयों को कुल विक्रय का 25% से अधिक एवं अधिकतम 50% तक निर्यात करने के लिए 2% अतिरिक्त उद्योग विकास अनुदान (चार वर्षों हेतु);

या

औद्योगिक इकाईयों को कुल विक्रय का 50% से अधिक निर्यात करने के लिए 3% अतिरिक्त उद्योग विकास अनुदान (चार वर्षों हेतु)

2. निर्यात के लिये तैयारी हेतु डब्ल्यूएचओ जीएमपी या यू.एस.-एफ.डी.ए. प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये सुविधाओं का सृजन करने में किये गये व्यय का 50%, अधिकतम 50 लाख रुपए की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
3. फार्मास्यूटिकल लैब की मशीनरी व उपकरण की स्थापना में किये गये व्यय का 50%, अधिकतम 25 लाख रुपए की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
4. फार्मास्यूटिकल इकाईयों के लिये निजी औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर के विकासकर्ता को विकास में किये गये व्यय का 60%, अधिकतम 500 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति।

(ब) अन्य सहायता

1. इस नीति की कण्डिका 7.2 के अनुसार गुणवत्ता प्रमाणन हेतु सहायता (उप कण्डिका 7.2.3 को छोड़कर)।
2. इस नीति की कण्डिका 7.3 के अनुसार पेटेंट के लिए प्रतिपूर्ति।
3. इस नीति की कण्डिका 7.4 के अनुसार अधोसंरचना विकास के लिए वित्तीय सहायता (उप कण्डिका 7.4.4 को छोड़कर)।
4. इस नीति की कण्डिका 7.5 के अनुसार ऊर्जा लेखा परीक्षा में सहायता।

परिशिष्ट - IVपरिधान क्षेत्र के लिए विशेष पैकेज

(अ) विशेष पैकेज

1. रेडीमेड गारमेंट एवं मेडअप्स (पहनने योग्य या गैर पहनने योग्य कपड़े, सिले कपड़े, जिनमें से कपड़ों के कम से कम दो सिरों की सिलाई, मशीनरी का उपयोग कर की गयी है) का निर्माण करने वाली नवीन इकाई, जिसमें यंत्र-संयंत्र में न्यूनतम 1.00 करोड़ रुपये का निवेश और न्यूनतम 25 नियमित कर्मचारी हो, के प्रत्येक नियमित कर्मचारी, जो मध्यप्रदेश का स्थाई निवासी है, के वेतन का 25%, अधिकतम 2500 रुपये प्रतिमाह, कुल 5 लाख रुपये की वार्षिक सीमा तक, 5 वर्ष तक 'वेतन अनुदान' के रूप में प्रदान किया जाएगा।
2. परिधान क्षेत्र की इकाईयों के लिये निजी औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर के विकासकर्ता को विकास में किये गये व्यय का 60%, अधिकतम 500 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति।

(ब) अन्य सहायता

1. इस नीति की कण्डिका 7.1 के अनुसार उद्योग विकास अनुदान।
2. इस नीति की कण्डिका 7.2 के अनुसार गुणवत्ता प्रमाणन हेतु सहायता।
3. इस नीति की कण्डिका 7.3 के अनुसार पेटेंट के लिए प्रतिपूर्ति।
4. इस नीति की कण्डिका 7.4 के अनुसार अर्थोसंरचना विकास के लिए वित्तीय सहायता (उप कण्डिका 7.4.4 को छोड़कर)।
5. इस नीति की कण्डिका 7.5 के अनुसार ऊर्जा लेखा परीक्षा में सहायता।

M.P. MSME Development Policy, 2019

1. Introduction

Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) sector is considered engine for socio economic growth in the country and is fast emerging as the most vibrant and dynamic sector of the Indian economy. MSMEs provide the largest share of employment after primary sector. We are aware that, employment generation is one of the main challenges faced in the country today. This makes development of MSME sector most crucial. The Government of Madhya Pradesh (GoMP) recognizes this aspect and accordingly, is giving priority to the development of the MSME sector in the state.

Considering the significant role of MSME in employment generation and economic and social development, and knowing the fact that MSME sector is one of the key drivers for transition from an agrarian economy to an industrialized economy, the state has decided to give special attention to this sector. To fulfil this objective, a dedicated department has already been created for MSMEs.

Department of MSME, GoMP is playing a pivotal role in enhancing the state's MSMEs competitiveness. MSME Department is proactive in providing conducive ecosystem for MSME development through various schemes and initiatives. MSME Department intends to take multi-pronged initiative to create a supportive and enabling ecosystem for establishment and growth of MSMEs in state.

Department of MSME, GoMP has taken several steps to derive maximum benefits for MSME sector out of the policy initiatives at the central and state level. The state government has also taken progressive steps towards improving Ease of Doing Business. The state also has its own Start Up policy for promotion of start ups and incubators.

Madhya Pradesh Government has been supporting entrepreneurs/ Self-Employment beneficiaries by providing an enabling environment for job creation and entrepreneurship. Department of MSME, Government of Madhya Pradesh run various flagship scheme for employment generation and promotion under which there is provision of interest subsidy and margin money support on capital investment.

The department stands committed to the Initiatives of GoI and assure that it is in the process of developing a vibrant MSME in the state. With this commitment, Department has decided to constitute a dedicated MP MSME Development Policy 2019. It touches upon all those aspects which leads to the focused growth of the MSME sector in the state. The policy has been drafted through a consultative process after taking opinions and suggestions of all stakeholders including Industry Associations, Financial Institutions, Experts and related Government Departments.

2. Objectives of MSME Development Policy

The key objectives of the MSME Development Policy 2019 are :-

- i. Achieving the state's goal of overall industrial development and MSME competitiveness
- ii. Creating enabling infrastructure
- iii. Providing a conducive ecosystem and promoting inclusive growth for MSMEs.
- iv. Providing an opportunity to young entrepreneurs through instilling employment generation

3. Policy Focus Area

To achieve the objectives, this policy is focused on following six pillars

- i. Enabling framework: Ease of doing business
- ii. Procedural reforms for release of concessions to eligible MSME units

- iii. Creation and maintenance of improved infrastructure facilities through private developers
- iv. Infrastructure development on PPP Model
- v. Procedural assistance through online services
- vi. Time bound delivery of services & assistance.

4. Operative period of the Policy and work areas

- 4.1 This Policy shall come into effect from 01.10.2019.
- 4.2 This policy will continue till the time replaced by the new policy.
- 4.3 The MSME units commencing commercial production after 30.09.2019 shall be eligible to avail benefits only under this policy. After the enforcement of this policy, the option of availing facilities/benefits for MSME promotion scheme 2017 will be closed for new manufacturing units which commence production on or after 01.10.2019. Units, which commence production before 01.10.2019 would eligible to avail concessions under the MSME Development Policy 2017 or any earlier relevant policies.

5. Enabling framework: Ease of doing business

5.1 Improving business climate by enhancing ease of doing business

The Government of MP has taken various initiatives to improve the business environment in state by continuing to bring in regulatory reforms and simplify procedures for the promotion and development of MSME in the State. GoMP shall continue to take new initiatives to improve the services provided by the government to MSMEs for doing business in the State. The DoMSME has taken up following steps to improve the business climate for MSMEs in the State:

- i. Departmental concessions are now being extended through online process. Procedure has been simplified.
- ii. The land allotment process for MSMEs has been made online.

iii. New Store Purchase Rules are being formed to increase the MSME supplier base of the government departments and expedite the procurement process from the MSME suppliers.

iv. The renewal process of various licenses of different departments shall be simplified for MSMEs.

5.2 MSME Business Facilitation Cell

In order to facilitate /support MSMEs, office of Industries Commissioner has constituted a cell. Through this cell support consultants have been deputed across the state at DTIC offices to extend handholding support to the MSMEs.

5.3 Institutional Measures for Grievance Resolution

In order to address the grievances of state's MSMEs regarding their payment issues, GoMP has constituted a Madhya Pradesh MSE Facilitation Council (MSEFC) as per the MSMED Act 2006, which is functional in its full spirit.

5.4 District Level Assistance Committee

Following committee at District level under the chairmanship of District Collector will be responsible to extend the concessions to the eligible MSMEs under the provisions of this policy :-

- | | | |
|--------------------------|---|------------------|
| 1. District Collector | - | Chairman |
| 2. Lead District Manager | - | Member |
| 3. General Manager | - | Member Secretary |

District Trade & Industries Centre

6. General provisions for availing concessions

6.1 The concessions is not applicable for units which comes under the category of ineligible industries as mentioned in the Annexure – I

- 6.2 Under this policy, it will be mandatory for beneficiary units to provide 70% of its total employment to the permanent residents of Madhya Pradesh and in that 70% employment, representation of SC, ST & Other Backward Classes, as per reservation declared by the State Government, will be mandatory also.
- 6.3 If any sick unit is revived during the policy period, it can avail the concession (as per eligibility) provided in the policy as per the package approved by the empowered committee.
- 6.4 The procedures for availing concessions will be detailed out in MSME Promotion Scheme 2019 in which detailed information of procedures, eligibility criteria, required documents for availing subsidy/incentive, limit of total assistance and terms & conditions for beneficiary units etc. will be included. Above scheme will be part of this policy.

7. Concessions

7.1 Industrial Development Subsidy

- 7.1.1 Industrial development assistance to the new industrial units @ 40% on the eligible investment made by them in Plant & Machinery and building. This assistance shall be disbursed in 4 equal annual installments.
- 7.1.2 The cost of building shall not be more than 100% of the cost of Plant and machinery for the purpose of calculating the assistance.
- 7.1.3 Additional Industrial Development Subsidy of 2% per year (for four years) for unit set up by women/SC/ST entrepreneur(s) or 2.5% per year (for four years) for unit set up by women entrepreneur(s) of SC/ST category; and
- 7.1.4 Additional Industrial Development Subsidy of 2% per year (for four years) to the industrial units for exporting more than 25% and upto 50% of their total sales;

Additional Industrial Development Subsidy of 3% per year (for four years) to the industrial units for exporting more than 50% of their total sales.

7.2 Support in Quality Certification

- 7.2.1 Assistance upto 100% of the cost incurred on obtaining ISO/BIS/BEE certification subject to maximum limit of Rs. 5 Lakhs to micro category unit.
- 7.2.2 For ZED Certification for improving brand recognition of MSME and reducing effect on environment : GoI provides assistance @ 80%, 60% and 50% to micro, small and medium units respectively. GoMP will provide assistance upto 50% of the balance amount (10%,20%,25% of total cost respectively to micro, small and medium units)
- 7.2.3 For obtaining quality certification exclusively for export, during policy period, which made MSMEs of manufacturing sector of the state, eligible to export in USA/European Union/Other OECD countries: Assistance upto 50% of the cost incurred on obtaining these certification subject to maximum limit of Rs. 25 Lakhs.
- 7.2.4 MSMEs, who have commenced production before this policy but obtain quality certification within this policy period, shall also be eligible to avail reimbursement under this policy.

7.3 Reimbursements for Patents

- 7.3.1 100% reimbursement to a maximum of Rs. 5 Lakhs to MSME units for domestic patents/IPR registration during the policy period.
- 7.3.2 100% reimbursement to a maximum of Rs. 10 Lakhs to MSME units for International patents/IPR registration during the policy period.

7.4 Financial Assistance for Infrastructure Development

- 7.4.1 50% assistance max Rs. 25 Lakhs to the small and medium new industrial units, established in private or undeveloped Govt. land, for developing infrastructure upto their premises .
- 7.4.2 50% reimbursement max of Rs. 25 Lakhs for the establishment of an effluent treatment plant (ETP) by the industrial unit.
- 7.4.3 50% reimbursement up to a maximum of Rs. 100 Lakhs for the establishment of an Common effluent treatment plant by a group (minimum 5) of industrial units.
- 7.4.4 50% financial assistance max of Rs. 250 Lakhs to the Developers for industrial area/flatted industrial complex in private sector.
- 7.4.5 50% financial assistance max Rs. 50 Lakhs as reimbursement towards the agency doing infrastructure development for strengthening the MSME cluster working in private land.

7.5 Financial Assistance for Energy audit

To promote energy efficiencies in MSME units, GoMP will reimburse 50% of the cost of conducting energy audit with maximum limit of Rs. 50,000 and 25% of the cost maximum Rs. 5 Lakhs for adoption of equipment and machinery

7.6 Special Packages

- 7.6.1 The State Government would give special package to Powerlooms sector as described in **Annexure - II**.
- 7.6.2 The State Government would give special package to Pharmaceutical sector as described in **Annexure - III**.
- 7.6.3 The State Government would give special package to Apparel sector as described in **Annexure - IV**.

8. Expansion/Diversification/Technical up-gradation

- 8.1 Established micro, small and medium industrial units which undertakes expansion will be eligible for assistance/facilities at par with new

industrial units on their additional eligible investment.

- 8.2 Established micro scale industrial units, which invest additional Rs. 10 Lakhs or more in plant & machinery, shall be eligible for assistance/facilities at par with new industrial units.
- 8.3 Established small scale industrial units, which invest additional Rs. 25 Lakhs or more in plant & machinery, shall be eligible for assistance/facilities at par with new industrial units.
- 8.4 Established medium scale industrial units, which invest additional Rs. 100 Lakhs or more in plant & machinery, shall be eligible for assistance/facilities at par with new industrial units.
- 8.5 If total investment in plant and machinery became more than Rs. 15 crores after expansion/diversification/technical upgradation, then the unit will not be eligible for assistance/facilities under this policy.

9. Creation and maintenance of improved infrastructure facilities

Development of industrial infrastructure with best facilities will surely boost the MSME growth. The MSME department shall come up with new industrial land and shed allotment rules in alignment with this policy. Under this:-

- 9.1 The Department will increase the "Land Bank" of Government Land for future development of Industrial Areas/Parks/Estate exclusively for MSME units.
- 9.2 GoMP shall establish dedicated MSME parks in the districts where there are ample opportunities of MSME development.
- 9.3 Department will encourage the industrial areas in private sector.
- 9.4 Special focus and thrust shall be given to creation of flatted structure in industrial area on PPP mode.
- 9.5 Online Land Application and Allocation System shall be made easier and user friendly.
- 9.6 State Govt. shall come up with new 'Industrial Land Allotment Rules'. 10 percent plots will be reserved in the Departmental industrial area

for the units owned by Scheduled Castes, Scheduled Tribes and OBC category.

10. Capacity strengthening

10.1 Cluster development

- 10.1.1 The State Government has adopted the cluster development approach as a key strategy for industrial & economic development of MSEs as well as factors which will promote in establishment of new industrial area in the State.
- 10.1.2 GoMP will formulate State's own **Cluster Development Scheme** for creating the Infrastructure (ID) and Common Facility Centre (CFC) facilities for the MSME clusters spread over across the state with support from Gol.
- 10.1.3 A dedicated cluster development cell shall be created to properly implement the Cluster Development Scheme of State & Gol. This cell shall be responsible to cater to the needs of MSME clusters of the State.
- 10.1.4 Madhya Pradesh Laghu Udyog Nigam will be the nodal agency for cluster activities in state.

10.2 Self-Employment

- 10.2.1 In order to provide the self-employment opportunities for the youth, the MSME department is presently running various self-employment schemes, which provide concessions and hand-holding support to young entrepreneurs.
- 10.2.2 A new Self employment scheme with more effective hand holding support and better incentives shall be initiated.
- 10.2.3 Beneficiaries of Self employment schemes shall be given opportunity to participate in international trade fair/exhibitions.
- 10.2.4 Business skills of youth shall be improved through online EDP module.

10.2.5 In order to support the applicants of self employment schemes, a panel of Chartered Accountants (CAs) will be made at district level.

10.2.6 Additional grant will be provided in self-employment schemes to SC/ST beneficiaries

10.3 Start-up and Incubation Support

To nurture innovation and start-up ecosystem for young entrepreneurs in the state, Government of Madhya Pradesh shall come up with new "MP Start-up Policy".

11. Revival of sick units

11.1 To revive potentially viable sick/closed unit, a package will be made with the help of Bankers/ Financial Institutions.

11.2 The key responsibilities of preparing the revival package will be Bankers/ Financial Institutions

11.3 The Sick Industrial Unit in consultation with Bankers/ Financial Institutions will prepare its proposal for seeking package of concessions and submit it to the Empowered Committee.

11.4 The empowered committee will be set up to decide on revival package in favor of sick industrial units, under the chairmanship of Principal Secretary, Department of MSME. The constitution of the Committee will be as follows:

- i. Principal Secretary, MSME Department (Chairman)
- ii. Principal Secretary/ Secretary of the departments from which concessions/ relief are sought by the sick units.
- iii. Industries Commissioner, MSME Department (Member)
- iv. Zonal Manager of the concerned bank branch (Member)
- v. Branch Manager/ In charge officer of the Bank/ Financial Institute through which revival package is proposed.

vi. Joint / Deputy Director, MSME Department (Member Secretary)

11.5 Banks/ Financial Institutions will prepare revival package in favour of viable sick industrial units, in which concession can be sought from State Govt.

11.6 The concession/relief sought under revival package will be placed before empowered committee. The empowered committee will be fully authorised to take decision on the demands/concession sought under revival package with the consent of the concerning department, on merits.

12. Amendment/Relaxation/Cancellation

Regardless of the provisions under the policy, the Madhya Pradesh government, the Micro, Small and Medium Enterprises Department at any time -

12.1 May amend or cancel this policy

12.2 May relax the provisions of this policy

12.3 May issue instructions/ clarifications/guidelines to clarify the provisions of the policy.

13. Jurisdiction

In case of any dispute, the court area will be Madhya Pradesh.

14. Glossary

- i. **Policy** means "MP MSME Development Policy 2019".
- ii. **MSME** means, micro, small and medium enterprises defines under Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (amendment from time to time Inclusive).
- iii. **Unit/industrial unit** means, manufacturing unit of MSME category in Madhya Pradesh

- iv. **Investment in plant and machinery** means as per Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (amendment from time to time Inclusive).
- v. **Investment in building** means investment in factory buildings & sheds, which is used for production but shall not include dwelling units.
- vi. **New industrial unit** means such manufacturing unit of MSME category, which are established during the policy period.
- vii. **Existing industrial unit** means, a industrial unit which commenced commercial production before 01.10.2019 or new industrial units which made expansion/ diversification/technical upgradation during the policy period.
- viii. **Women/SC/ST entrepreneur unit** means operational unit in which Women/SC/ST entrepreneur(s) have hundred percent stake.
- ix. **The date of commercial production** means after commencing production date of the first time sale of the goods produce, which means the date of the bill-date of the first sale.
- x. **Quality certification** means, ISO certification issued by third party authorized agencies for quality certification or BIS/BEE certification or ZED certification or certification exclusively for export.
- xi. **Patent** Means, The patent defined under Patent Act, 1970 (including amendments made from time to time) and or underlying patent.
- xii. **MSME Directorate** means The Directorate under the Micro, Small and Medium Enterprises Department of Government of Madhya Pradesh.
- xiii. **The State Government** means the Micro, Small and Medium Enterprises Department of Government of Madhya Pradesh.
- xiv. **District Trade & Industries Centre** means the district level office of MSME Directorate under the Micro, Small and Medium Enterprises Department of Government of Madhya Pradesh.

Annexure - I**List of ineligible industries**

1. Activities pertaining to trading and services
2. Beer and liquor which contains alcohol
3. Manufacturing of all kinds of pan masala and gutkha
4. Manufacturing of Tobacco and tobacco based products
5. Manufacturing of plastic bags of thickness 40 micron or lesser and all type of polythene bags.
6. Industrial units set up by central or state government or their undertaking
7. Stone crusher
8. Grinding of minerals, Calcination (Excluding manufacturing of artificial sand from crushed stone)
9. Defaulter of state government/state government undertaking
10. All types of mining activity (where there is no value addition)
11. Manufacturing of Charcoal
12. All type of Solvent extraction plant (Excluding edible oil expeller units, which invested Rs. 1 crore or less in plant & machinery)

13. All type of edible oil refineries
14. Cement /Clinker manufacturing
15. Publishing and Printing processes of all types
16. Saw milling & planing of wood
17. Pressing of iron/steel scrap into blocks or any other shapes
18. Electricity generation units
19. Package drinking water
20. Sortex plant and Sorting/Grading/Cleaning of crops/grain
21. All types of aerated/ carbonated drinks
22. Slaughter house and industries based on meat
23. Any industry declared by state government from time to time with reference to MP MSME Development Policy 2019

Annexure – II**Special Package to Powerlooms Sector****(A) Special Package**

1. GoMP shall provide 25% of upgradation cost or 100% remaining of GoI's financial support after adjustment (if any) whichever is less as financial assistance for upgradation of plain/semi automatic shuttle powerloom into modern shuttleless powerloom subject to a maximum of 10 looms in a unit.
2. Concession @ Rs. 1.50 per unit to the powerloom, upto 20HP capacity and @ Rs. 1.25 per unit to the powerloom for above 20HP but upto 150HP capacity in electricity supply. Also, 100% reimbursement of fixed charges and difference in minimum charges & actual consumption in electricity supply for the powerloom of upto 150HP capacity.
3. 60% financial assistance up to maximum of Rs. 500 Lakhs to the Developers for industrial area/flatted industrial complex for powerloom in private sector.

(B) Other Assistance

1. Industrial Development Subsidy as per clause 7.1 of this policy.
2. Support in quality certification as per clause 7.2 of this policy.
3. Reimbursements for Patents as per clause 7.3 of this policy.
4. Financial Assistance for infrastructure development as per clause 7.4 of this policy (excluding sub-clause 7.4.4).
5. Support in energy audit as per clause 7.5 of this policy.

Annexure - III**Special Package to Pharmaceutical Sector****A) Special Package****1. Industrial Development Subsidy**

1.1 Industrial development assistance to the new industrial units @ 40% on the eligible investment made by them in Plant & Machinery and building. This assistance shall be disbursed in 4 equal annual installments.

1.2 The cost of building shall not be more than 200% of the cost of Plant and machinery for the purpose of calculating the assistance.

1.3 Additional Industrial Development Subsidy of 2% per year (for four years) for unit set up by women/SC/ST entrepreneur(s) or 2.5% per year (for four years) for unit set up by women entrepreneur(s) of SC/ST category; and

1.4 Additional Industrial Development Subsidy of 2% per year (for four years) to the industrial units for exporting more than 25% and upto 50% of their total sales;

or

Additional Industrial Development Subsidy of 3% per year (for four years) to the industrial units for exporting more than 50% of their total sales.

2. 50% of the expenditure incurred on creating facilities for obtaining certificate of WHO-GMP or US-FDA certificate for export readiness, would be reimbursed up to a maximum limit of Rs. 50 lakhs.

3. Assistance @ 50%, maximum Rs. 25 Lakhs to extend support for establishment of lab equipments & machinery.

4. 60% financial assistance up to maximum of Rs. 500 Lakh to the Developers for industrial area/flatted industrial complex for pharmaceutical units in private sector

(B) Other Assistance

1. Support in quality certification as per clause 7.2 of this policy (excluding 7.2.3).

2. Reimbursements for Patents as per clause 7.3 of this policy.

3. Financial Assistance for infrastructure development as per clause 7.4 of this policy (excluding sub-clause 7.4.4).

4. Support in energy audit as per clause 7.5 of this policy.

Annexure - IV**Special Package to Apparel Sector****(A) Special Package**

1. New industrial Readymade garments and made-ups (wearable or non-wearable fabric, stitched fabric, in which atleast two ends of the cloth is stitched by using machinery) manufacturing units having atleast Rs. 1.00 crores invested in plant & machinery & minimum 25 regular employee, will be provided 25 percent of salary of each regular employee, which is a permanent residents of the state, maximum Rs. 2500 per month, up to an annual limit of Rs 5 lakh, for 5 years as a 'Salary grant'.
2. 60% financial assistance up to maximum of Rs. 500 Lakh to the Developers for industrial area/flatted industrial complex for Apparel units in private sector.

(B) Other Assistance

1. Industrial Development Subsidy as per clause 7.1 of this policy.
2. Support in quality certification as per clause 7.2 of this policy.
3. Reimbursements for Patents as per clause 7.3 of this policy.
4. Financial Assistance for infrastructure development as per clause 7.4 of this policy (excluding sub-clause 7.4.4).
5. Support in energy audit as per clause 7.5 of this policy.

मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना, 2019

1. प्रस्तावना :-

राज्य शासन द्वारा म. प्र. एमएसएमई विकास नीति, 2019 दिनांक 01.10.2019 से लागू की गई है। उक्त नीति में सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणी के विनिर्माण उद्यमों को सहायता हेतु किए गए प्रावधानों को क्रियान्वित करने की दृष्टि से राज्य शासन "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019" लागू करता है।

2. योजना के प्रभावशील होने की अवधि एवं कार्यक्षेत्र :-

- 2.1 यह योजना दिनांक 01.10.2019 से प्रभावशील होगी और शासन द्वारा संशोधित या अधिक्रमित किये जाने तक सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में प्रभावी रहेगी।
- 2.2 30.09.2019 के बाद वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाली विनिर्माण क्षेत्र की एमएसएमई इस योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के लिये पात्र होगी अर्थात् इस योजना के लागू होने के पश्चात नवीन विनिर्माण इकाईयों के लिये म. प्र. एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2017 की सुविधाओं/सहायताओं का विकल्प समाप्त होगा।
- 2.3 01.10.2019 से पहले उत्पादन प्रारंभ करने वाली विनिर्माण क्षेत्र की एमएसएमई, म. प्र. एमएसएमई विकास नीति 2017 या इससे पहले की नीतियाँ, जैसी भी स्थिति हो, के तहत सहायता प्राप्त करने के लिये पात्र होगी।
- 2.4 इस योजना अंतर्गत म. प्र. एमएसएमई विकास नीति 2019 की प्रभावशील अवधि में अपशिष्ट उपचार संयंत्र/सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र

स्थापित करने, गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्राप्त करने, पेटेंट प्राप्त करने और ऊर्जा लेखा परीक्षा के लिये किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति 01.10.2019 से पहले उत्पादन प्रारंभ करने वाली विनिर्माण क्षेत्र की एमएसएमई को भी प्राप्त होगी।

- 2.5 इस योजना अंतर्गत "म. प्र. एमएसएमई विकास नीति 2019" की प्रभावशील अवधि में, पॉवरलूम का उन्नयन करने पर वाली पॉवरलूम इकाई को भी पॉवरलूम उन्नयन हेतु सहायता प्रदान की जाएगी।
- 2.6 सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र हेतु सहायता औद्योगिक इकाईयों के समूह को और निजी औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर या निजी भूमि पर कार्यरत एमएसएमई के क्लस्टर को सुदृढ़ बनाने के लिए अधोसंरचना विकास हेतु सहायता विकासकर्ता को प्रदान की जाएगी।
- 2.7 पूर्व/प्रचलित नीति(यों) अंतर्गत विनिर्माण एमएसएमई को एमएसएमई विभाग द्वारा सुविधा/सहायता का लाभ प्राप्त करने हेतु गठित विभिन्न समितियों को समाप्त करते हुए, पूर्व की नीति(यों) अंतर्गत प्राप्त/स्वीकृत प्रकरणों का निराकरण "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना, 2019" में निर्धारित प्रक्रियानुसार किया जाएगा।

3. परिभाषाएँ :-

- 3.1 नीति से सामान्य अभिप्रेत है, "म. प्र. एमएसएमई विकास नीति 2019"।
- 3.2 योजना से सामान्य अभिप्रेत है, "म. प्र. एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019"।
- 3.3 एमएसएमई से अभिप्रेत है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (समय-समय पर किये गये संशोधनों सहित) के तहत परिभाषित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम।
- 3.4 इकाई/औद्योगिक इकाई से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश में विनिर्माण क्षेत्र की एमएसएमई।

- 3.5 संयंत्र और मशीनरी में निवेश से अभिप्रेत है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 (समय-समय पर किये गये संशोधनों सहित) के अनुसार संयंत्र और मशीनरी में निवेश।
- 3.6 भवन में निवेश से अभिप्रेत है, उत्पादन में उपयोग में आने वाली फैक्टरी भवन व शेड, लेकिन इसमें आवासीय इकाइयाँ शामिल नहीं होंगी।
- 3.7 स्थायी पूंजी निवेश से अभिप्रेत है, भूमि, भवन, संयंत्र व मशीनरी और अन्य स्थिर अरित्तों में किया गया कुल निवेश।
- 3.8 नई औद्योगिक इकाई से अभिप्रेत है, इस नीति की प्रभावशील अवधि के दौरान स्थापित विनिर्माण क्षेत्र की एमएसएमई।
- 3.9 विद्यमान औद्योगिक इकाई से अभिप्रेत है, ऐसी औद्योगिक इकाई, जिसमें दिनांक 01.10.2019 के पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ हुआ हो या ऐसी नई औद्योगिक इकाई जिसके द्वारा इस नीति की प्रभावशील अवधि में विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन किया गया हो।
- 3.10 वाणिज्यिक उत्पादन की दिनांक से अभिप्रेत है, इकाई द्वारा उत्पादन प्रारंभ कर उत्पादित माल के प्रथम बार विक्रय की दिनांक अर्थात् प्रथम विक्रय के देयक की दिनांक।
- 3.11 पूर्व में किये गये संयंत्र एवं मशीनरी में पूंजी निवेश से अभिप्रेत, विद्यमान औद्योगिक इकाई द्वारा, जिस वर्ष में विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन के लिए नवीन पूंजी निवेश करना प्रारम्भ किया गया हो, उस वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि की स्थिति में किया गया संयंत्र एवं मशीनरी में पूंजी निवेश अथवा विद्यमान औद्योगिक इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि की स्थिति में किया गया संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश, जो भी अधिक हो, से होगा।
- 3.12 पूर्व स्थापित क्षमता से अभिप्रेत, विद्यमान औद्योगिक इकाई द्वारा, जिस वर्ष में विस्तार/डायवर्सिफिकेशन के लिए नवीन पूंजी निवेश करना प्रारम्भ किया

गया हो, उस वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के वार्षिक उत्पादन का औसत या विद्यमान औद्योगिक इकाई की वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक के समय स्थापित क्षमता, इसमें से जो भी अधिक हो, से है।

- 3.13 जीएसटी से अभिप्रेत, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में परिभाषित 'राज्य कर' से है।
- 3.14 गुणवत्ता प्रमाणीकरण से अभिप्रेत है, गुणवत्ता प्रमाणीकरण हेतु तीसरे पक्ष की अधिकृत एजेंसियों द्वारा प्रदाय आईएसओ/बीआयएस/बीईई प्रमाणपत्र या जेड प्रमाणन या निर्यात के लिये प्रमाणन।
- 3.15 पेटेंट से अभिप्रेत है, पेटेंट अधिनियम, 1970 (समय-समय पर किये गये संशोधनों सहित) में परिभाषित और या अंतर्निहित पेटेंट।
- 3.16 महिला/अजा/अजजा उद्यमी(यों) द्वारा संचालित इकाई से अभिप्रेत है, महिला/अजा/अजजा वर्ग के व्यक्ति(यों) के शत प्रतिशत स्वामित्व वाली इकाई।
- 3.17 एमएसएमई संचालनालय से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के अधीन संचालनालय।
- 3.18 राज्य सरकार/शासन से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन का सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग।
- 3.19 उद्योग आयुक्त से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के अधीन उद्योग संचालनालय, म. प्र. के आयुक्त।
- 3.20 जिला व्यापार और उद्योग केंद्र से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के अधीन एमएसएमई संचालनालय का जिला स्तरीय कार्यालय।
- 3.21 महाप्रबंधक से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के अधीन जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक।

3.22 जिला स्तरीय सहायता समिति से अभिप्रेत निम्नानुसार गठित समिति से है:-

i.	कलेक्टर	अध्यक्ष
ii.	अग्रणी जिला प्रबंधक (LDM)	सदस्य
iii.	महाप्रबन्धक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र	सदस्यसचिव

टीप :- समिति की बैठक का कोरम न्यूनतम 2 सदस्यों से पूर्ण होगा।

4. विविध :-

- 4.1 इस योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन/रियायत संबंधी वित्तीय सहायता केवल औद्योगिक इकाई के लिए उपलब्ध होगी। इस योजना की बिंदु 11 एवं 12 में दी गई सहायता एजेन्सी/संस्था/निवेशक को तथा बिंदु 14 में दी गई सहायता पॉवरलूम इकाई को उपलब्ध होगी।
- 4.2 औद्योगिक इकाई को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 अंतर्गत उद्योग आधार जापन (UAM) फाइल करना और 'मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017' (जीएसटी अधिनियम) अंतर्गत पंजीयन कराना सहायता/सुविधा प्राप्त करने के लिये आवश्यक होगा। साथ ही जीएसटी अंतर्गत पंजीकृत इकाई को अपने बिजनेस वर्टीकल (जीएसटी अधिनियम अंतर्गत परिभाषित) के लिये इस योजना अंतर्गत सुविधा प्राप्त करने हेतु पृथक से जीएसटी अधिनियम अंतर्गत पंजीयन कराना होगा। किसी कंपनी/फर्म या संस्था का जीएसटी अधिनियम अंतर्गत पंजीयन होने पर भी उसकी इकाई को इस योजना अंतर्गत सहायता प्राप्त करने हेतु पृथक से जीएसटी अधिनियम अंतर्गत पंजीयन कराना आवश्यक होगा। परंतु किसी पॉवरलूम इकाई को जीएसटी अधिनियम अंतर्गत पंजीयन हेतु छूट की पात्रता है, तो वह इस योजना के अंतर्गत बिंदु 14 में उल्लेखित पॉवरलूम उन्नयन के लिये सहायता प्राप्त करने हेतु उस छूट का लाभ ले सकेंगी।

- 4.3 किसी भी मामले में, इकाई को रियायतों की कुल राशि इकाई द्वारा किये गये स्थायी पूंजी निवेश से अधिक नहीं होगी।
- 4.4 यदि राज्य शासन की ऐसी एक से अधिक नीतियाँ हैं, जिनके अंतर्गत इकाई प्रोत्साहन/रियायतें प्राप्त कर सकती है, तो इकाई द्वारा किसी अन्य नीति अंतर्गत प्रोत्साहन/रियायतें लेने/आवेदन करने पर इस योजना अंतर्गत सहायता हेतु अपात्र होगी।
- 4.5 कोई इकाई, जिसने स्वरोजगार योजनाओं के तहत प्रोत्साहनों का लाभ प्राप्त किया हो, वह म. प्र. एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019 के तहत प्रोत्साहन/सहायता का लाभ लेने के लिये पात्र नहीं होगी।
- 4.6 हालाँकि, यदि एक इकाई इस योजना के तहत अपनी पात्रता के अतिरिक्त भारत सरकार से वित्तीय सहायता का लाभ लेना चाहे तो, वह इस शर्त के अधीन ऐसा कर सकती है कि उसे प्राप्त होने वाला कुल अनुदान उसके द्वारा किये गये स्थायी पूंजी निवेश से अधिक न हो।
- 4.7 स्थापित सूक्ष्म स्तर की विद्यमान औद्योगिक इकाई द्वारा विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन हेतु यंत्र एवं संयंत्र में 10 लाख रुपये या अधिक का निवेश करने पर, उसे नई औद्योगिक इकाई के समकक्ष सहायता/सुविधाओं की पात्रता होगी।
- 4.8 स्थापित लघु स्तर की विद्यमान औद्योगिक इकाई द्वारा विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन हेतु यंत्र एवं संयंत्र में 25 लाख रुपये या अधिक का निवेश करने पर, उसे नई औद्योगिक इकाई के समकक्ष सहायता/सुविधाओं की पात्रता होगी।
- 4.9 स्थापित मध्यम स्तर की विद्यमान औद्योगिक इकाई द्वारा विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन हेतु यंत्र एवं संयंत्र में 100 लाख रुपये या अधिक का निवेश करने पर, उसे नई औद्योगिक इकाई के समकक्ष सहायता/सुविधाओं की पात्रता होगी।

- 4.10 यदि विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन के फलस्वरूप किसी इकाई का यंत्र-संयंत्र में कुल निवेश 15 करोड़ रुपये से अधिक हो जाता है, तो वह इकाई इस नीति के अंतर्गत सहायता/सुविधाओं के लिये पात्र नहीं होगी।
- 4.11 विस्तार/डायवर्सिफिकेशन के प्रकरणों में उपरोक्त सुविधा इकाईयों को पूर्व स्थापित क्षमता में कमी नहीं होने की शर्त के साथ प्राप्त होगी।
- 4.12 विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन अंतर्गत पात्रता का निर्धारण इकाई द्वारा उसकी विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन अंतर्गत उत्पादन दिनांक से पिछले तीन वर्ष में, परंतु विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन के पूर्व की वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक के पश्चात, संयंत्र और मशीनरी में किए गए नवीन निवेश से किया जाएगा।
- 4.13 इस योजना में उल्लेखित आवेदन की समय-सीमा में जिला स्तरीय सहायता समिति समुचित कारणों से आवेदन प्रस्तुत करने में किये गये विलम्ब को शिथिल कर सकेगी।
- 4.14 इकाई/एजेन्सी/संस्था/निवेशक द्वारा सहायता राशि हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने के दिनांक को इकाई/पॉवरलूम इकाई/निजी औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर/एमएसएमई क्लस्टर में निर्मित औद्योगिक संरचना/अपशिष्ट उपचार संयंत्र/ सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र को उत्पादनरत/कार्यरत/स्थापित रहना अनिवार्य होगा एवं इकाई/निजी औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर के वाणिज्यिक उत्पादन/प्रारंभ/स्थापित होने की दिनांक से चार वर्षों तक या सुविधा अवधि में, जो भी बाद में हो, उत्पादनरत/कार्यरत/स्थापित रखा जाना अनिवार्य होगा। इस अवधि में इकाई/निजी औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर के 6 माह से अधिक अवधि तक बंद होने की स्थिति में इकाई/निजी औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर को दी गई संपूर्ण सहायता राशि भू-राजस्व की बकाया की तरह इकाई/निजी औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक

परिसर के स्वामी/संस्था से 12 प्रतिशत दाण्डिक ब्याज सहित वसूल की जावेगी।

- 4.15 इकाई/निजी औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर/ एमएसएमई क्लस्टर में निर्मित औद्योगिक अधोसंरचना/अपशिष्ट उपचार संयंत्र/सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र को जिस पूंजी निवेश के आधार पर सहायता स्वीकृत की जायेगी, उसको वाणिज्यिक उत्पादन/प्रारंभ होने की दिनांक से चार वर्षों तक अच्छी स्थिति में रखना अनिवार्य होगा और इकाई की उत्पादन क्षमता बनाए रखनी होगी। इकाई/निजी औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर द्वारा उसके किसी भाग में परिवर्तन तथा किये गये पूंजी निवेश में कमी नहीं की जाएगी। सहायता प्राप्त इकाई/निजी औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर/ एमएसएमई क्लस्टर में निर्मित औद्योगिक अधोसंरचना/ अपशिष्ट उपचार संयंत्र/ सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र द्वारा उसके स्वामित्व में परिवर्तन, उसके वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने/स्थापना की दिनांक से चार वर्षों तक, उद्योग आयुक्त की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना, नहीं किया जाएगा। यदि अनुमति प्राप्त करने पर ऐसा परिवर्तन किया जाता है, तो मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019 के अंतर्गत पूर्व स्थापित इकाई/निजी औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर/एमएसएमई क्लस्टर में निर्मित औद्योगिक अधोसंरचना/अपशिष्ट उपचार संयंत्र/ सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र के समस्त दायित्व एवं अधिकार नवीन/परिवर्तित इकाई/निजी औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर/ एमएसएमई क्लस्टर में निर्मित औद्योगिक अधोसंरचना/ अपशिष्ट उपचार संयंत्र/ सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र के नए स्वामी पर लागू होंगे।
- 4.16 म.प्र. शासन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा जारी म. प्र. एमएसएमई विकास नीति 2019 के परिशिष्ट - I में शामिल उद्योग इस योजना अंतर्गत सुविधा/सहायता हेतु अपात्र होंगे।(परिशिष्ट-1)
- 4.17 नगर निगम की अधिसूचित सीमा में केवल राज्य शासन अथवा उसके उपक्रम द्वारा औद्योगिक प्रयोजन हेतु आवंटित की गई शासकीय भूमि और

मास्टर प्लान में उद्योगों हेतु आरक्षित भूमि में स्थापित इकाईयों को ही योजनांतर्गत अनुदान की पात्रता होगी।

- 4.18 म. प्र. एमएसएमई प्रोत्साहन योजना, 2019 के तहत लाभ लेने वाली इकाईयों को अपने कुल रोजगार का न्यूनतम 70% मध्य प्रदेश के स्थाई निवासियों को प्रदान करना अनिवार्य होगा और उक्त 70% रोजगार में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को राज्य शासन द्वारा घोषित आरक्षण अनुसार प्रतिनिधित्व भी दिया जाना अनिवार्य होगा।

5. जिला स्तरीय सहायता समिति का दायित्व

- 5.1 जिला स्तरीय सहायता समिति का यह दायित्व होगा कि वह सूक्ष्म, लघु और मध्यम विनिर्माण उद्यम का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के उपरान्त उद्यम से आवेदन प्राप्त होने से म. प्र. एमएसएमई प्रोत्साहन योजना, 2019 के अंतर्गत प्रावधानित प्रोत्साहन की स्वीकृति तथा वितरण सुनिश्चित करे।
- 5.2 योजना अंतर्गत सभी सहायताओं की प्रथम बार स्वीकृति जिला स्तरीय सहायता समिति द्वारा जारी की जायेगी। उसके बाद मिलने वाली वार्षिक/छःमाही किश्तें पात्रतानुसार स्वमेव, बिना पुनः समिति में गए, मिलेंगी।
- 5.3 वेतन अनुदान हेतु रेडीमेड गारमेंट एवं मेडअप्स का निर्माण करने वाली इकाई को प्रत्येक छःमाही (जिस हेतु सहायता चाही गई है) के पश्चात इकाई में कार्यरत नियमित कर्मचारी, जो म. प्र. के स्थाई निवासी हैं, को दिये गये वेतन की राशि एवं ऐसे कर्मचारियों की संख्या (माहवार, नामवार सूची एवं प्रदत्त वेतन एवं नियमित कर्मचारी संबंधी प्रामाणिक दस्तावेज के संलग्न सहित) संबंधी जानकारी सहायता प्राप्त करने हेतु संबंधित महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

- 5.4 समिति की बैठक माह में कम से कम एक बार होगी।
- 5.5 मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना, 2019 अंतर्गत सहायता हेतु आवेदन निर्धारित समयावधि में इकाई/संस्था के स्वामी/अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निर्धारित प्रपत्र में संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। वांछित अनुलग्नक आवेदन के साथ प्रस्तुत किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त परिशिष्ट-13 में शपथ पत्र (निर्धारित शुल्क के स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित) भी आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा। साथ ही उपलब्ध कराये गये कुल रोजगार का न्यूनतम 70 प्रतिशत रोजगार मध्यप्रदेश के स्थाई निवासियों को दिये जाने संबंधी दस्तावेजों की अभिप्रमाणित प्रति भी आवेदन के संलग्न करना अनिवार्य होगा, जिसमें अजा, अजजा एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व की जानकारी भी सम्मिलित होगी।
- 5.6 महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा आवश्यकतानुसार विभागीय अधिकारियों से इकाई का निरीक्षण तथा दी गई जानकारी का यथासंभव सत्यापन कराया जायेगा। महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र समुचित परीक्षण उपरान्त अपना प्रतिवेदन जिला स्तरीय सहायता समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करेगा। इस प्रतिवेदन में अन्य सभी सुसंगत बातों के अलावा निम्न बातों, जहाँ लागू हो, का समावेश आवश्यक होगा :-
- (i) इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक तक संयंत्र एवं मशीनरी और भवन पर किया गया निवेश।
 - (ii) वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक एवं उत्पादनरत रहने का प्रमाण।
 - (iii) महिला/अजा/अजजा उद्यमी के स्वामित्व की इकाई होने का प्रमाणन।
 - (iv) निर्यात की स्थिति में कुल विक्रय एवं किया गया निर्यात।
 - (v) अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली/सार्वजनिक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना में किया गया निवेश।
 - (vi) औद्योगिक परिसर तक अधोसंरचना विकास पर व्यय।

- (vii) गुणवत्ता प्रमाणीकरण/जेड प्रमाणन/निर्यात के लिये प्रमाणन/पेटेंट प्राप्त करने में इकाई द्वारा किया गया व्यय।
 - (viii) पॉवरलूम इकाई द्वारा पॉवरलूम को उन्नयन करने के लिए किया गया व्यय, भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता (यदि कोई हो, तो) एवं कुल परिवर्तित पॉवरलूमों की संख्या।
 - (ix) निजी औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना के प्रकरण में अधोसंरचना व्यय व कार्यरत इकाईयों की जानकारी।
 - (x) निजी भूमि पर कार्यरत एमएसएमई के क्लस्टर में औद्योगिक अधोसंरचना के विकास में किया गया व्यय।
 - (xi) ऊर्जा लेखा परीक्षा में हुआ व्यय और ऑडिट में सुझाये गये उपकरण एवं मशीनरी को अपनाने में हुआ व्यय।
 - (xii) फार्मास्यूटिकल लैब की मशीनरी व उपकरण की स्थापना में किया गया व्यय।
 - (xiii) रेडिमेड गारमेंट एवं मेडअप्स का निर्माण करने वाली इकाईयों से वेतन अनुदान हेतु प्रदत्त रोजगार एवं वेतन की जानकारी।
 - (xiv) औद्योगिक इकाई द्वारा लिये गये विद्युत कनेक्शन की जानकारी।
 - (xv) औद्योगिक इकाई में प्रदत्त कुल रोजगार में से म. प्र. के स्थाई निवासियों को प्रदत्त रोजगार और उसमें अजा, अजजा एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व की जानकारी।
- 5.7 समुचित विचारोपरान्त जिला स्तरीय सहायता समिति को यह अधिकार होगा कि वह म. प्र. एमएसएमई प्रोत्साहन योजना, 2019 अंतर्गत प्रावधानित वित्तीय सहायता स्वीकृति आदेश जारी करे। समिति की स्वीकृति प्राप्त होने पर आदेश समिति के सदस्य सचिव द्वारा स्वीकृत सहायता(सहायताएं) एवं जहां लागू हो, प्रतिवर्ष दी जाने वाली सहायता राशि का विवरण/मापदण्ड का उल्लेख करते हुये जारी किया जायेगा।

- 5.8 समिति के ध्यान में ऐसा कोई तकनीकी बिंदु आए, जिसके कारण उसे अपने निर्णय को संशोधित करना पड़े, तो वह स्वतः संज्ञान लेकर अपने निर्णय का पुनर्विलोकन कर सकेगी, किन्तु इस प्रकार लिये गये निर्णय की सूचना 30 दिवस के अन्दर संबंधित इकाई तथा उद्योग आयुक्त, मध्य प्रदेश को प्रेषित किया जाना अनिवार्य होगा।
- 5.9 समिति द्वारा पूर्व की नीति(यों) अंतर्गत प्राप्त प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।

6. उद्योग विकास अनुदान

- 6.1 नई औद्योगिक इकाई को संयंत्र एवं मशीनरी और भवन में किये गये पात्र निवेश का 40% उद्योग विकास अनुदान के रूप में प्रदान किया जाएगा। यह अनुदान 4 समान वार्षिक किश्तों में वितरित किया जाएगा।
- 6.2 रियायत की गणना के प्रयोजन के लिए भवन की लागत, संयंत्र और मशीनरी की लागत के 100% तक सीमित होगी। परंतु फार्मास्यूटिकल इकाईयों हेतु रियायत की गणना के प्रयोजन के लिए भवन की लागत, संयंत्र और मशीनरी की लागत के 200% तक सीमित होगी।
- 6.3 महिला/अजा/अजजा उद्यमी(यों) द्वारा स्थापित इकाई के लिये प्रति वर्ष 2% (चार वर्षों हेतु) या अजा/अजजा श्रेणी की महिला उद्यमी(यों) द्वारा स्थापित इकाई के लिये प्रति वर्ष 2.5% (चार वर्षों हेतु) का अतिरिक्त उद्योग विकास अनुदान; और
- 6.4 औद्योगिक इकाईयों को कुल वार्षिक विक्रय का 25% से अधिक एवं अधिकतम 50% तक निर्यात करने के लिए 2% अतिरिक्त उद्योग विकास अनुदान प्रदान किया जाएगा (चार वर्षों हेतु);

या

औद्योगिक इकाईयों को कुल वार्षिक विक्रय का 50% से अधिक निर्यात करने के लिए 3% अतिरिक्त उद्योग विकास अनुदान प्रदान किया जाएगा (चार वर्षों हेतु)

- 6.5 उद्योग विकास अनुदान की प्रथम किश्त जिला स्तरीय सहायता समिति की स्वीकृति पश्चात देय होगी और द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ किश्त की देयता इकाई की वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक के क्रमशः एक, दो व तीन वर्ष के पश्चात होगी। महिलाओं/अजा/अजजा उद्यमियों द्वारा स्थापित इकाई को अतिरिक्त अनुदान की द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ किश्त प्राप्ति हेतु इकाई के स्वामित्व संबंधी नवीनतम दस्तावेज महाप्रबंधक को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- 6.6 निर्यातक इकाई को जिस वर्ष हेतु अतिरिक्त उद्योग विकास अनुदान की सहायता चाहिए, उस वर्ष की समाप्ति दिनांक से अधिकतम 90 दिवस के अंदर निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट-14) में संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत करना होगा। प्रथम बार अतिरिक्त उद्योग विकास अनुदान जिला स्तरीय सहायता समिति द्वारा स्वीकृत होने के पश्चात शेष वर्षों हेतु महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र इसे इकाई द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों के आधार पर वितरित करने के लिए सक्षम होंगे। परंतु प्रत्येक बार इकाई को सहायता हेतु निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट-14) में संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत करना होगा। निर्यात की पुष्टि जीएसटी पोर्टल में अपलोड/से प्राप्त जानकारी, निर्यात संबंधी शिपिंग बिल, बॉण्ड, लेटर ऑफ अण्डरटेकिंग आदि के आधार पर की जाएगी।
- 6.7 वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से अधिकतम 90 दिवस के अंदर इकाई को उद्योग विकास अनुदान हेतु निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट-2) में आवेदन तथा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (परिशिष्ट-13) संबंधित जिला व्यापार एवं

उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत करना होगा। आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक होगा :-

- (i) एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत उद्योग आधार ज्ञापन (UAM) जमा करने पर प्राप्त अभिस्वीकृति की छायाप्रति
- (ii) जीएसटी अंतर्गत पंजीयन की छायाप्रति
- (iii) संयंत्र एवं मशीनरी और भवन में किये गये पात्र निवेश के प्रमाणीकरण हेतु चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र/मूल्यांकन।
- (iv) भारत सरकार के जीएसटी पोर्टल से प्राप्त इकाई द्वारा विगत माह में किये गये विक्रय का प्रमाण
- (v) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी उचित अनुमति/ अनापत्ति प्रमाण पत्र/पंजीयन प्रमाण पत्र (यदि लागू हों) की छायाप्रतियां
- (vi) वित्तीय संस्था का ऋण स्वीकृति एवं वितरण संबंधी पत्र (यदि इकाई स्थापना हेतु ऋण लिया गया हो) की छायाप्रति
- (vii) भारत सरकार की किसी योजना में सहायता हेतु आवेदन दिया हो/ प्राप्त की गई हो, की जानकारी, जहां लागू हो
- (viii) महिलाओं/अजा/अजजा उद्यमियों द्वारा स्थापित इकाई के प्रकरण में स्वामित्व के प्रमाणीकरण का दस्तावेज

7. गुणवत्ता प्रमाणन हेतु सहायता

- 7.1 सूक्ष्म स्तर की इकाई द्वारा नीति' की प्रभावशील अवधि में, आईएसओ/बीआयएस/बीईई प्रमाण पत्र के लिये प्रमाणीकरण हेतु किए गए

व्यय का 100%, अधिकतम 5 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा की जाएगी।

- 7.2 उक्त बिंदु 7.1 में उल्लेखित वित्तीय सीमा के अन्तर्गत इकाई एक से अधिक गुणवत्ता प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन कर सकेगी, किन्तु प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा, प्रत्येक इकाई के लिए रु. 5 लाख तक ही होगी।
- 7.3 जेड (ZED) प्रमाणन, एमएसएमई की ब्रांड पहचान में सुधार लाने और पर्यावरण पर प्रभाव को कम करने के लिए भारत सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम इकाइयों को क्रमशः 80%, 60% और 50% की दर से सहायता प्रदान करती है। राज्य शासन द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम इकाइयों के लिए कुल लागत का क्रमशः 10%, 20% व 25% की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
- 7.4 नीति की प्रभावशील अवधि के दौरान केवल निर्यात के लिए गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त करने हेतु किये गये व्यय का 50%, अधिकतम 25 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति की जाएगी, यदि ऐसा प्रमाणन राज्य की विनिर्माण क्षेत्र की एमएसएमई को यूएसए/यूरोपियन यूनियन/OECD के अन्य सदस्य देशों में निर्यात करने हेतु पात्र बनाए। यह सहायता वास्तविक रूप से यूएसए/यूरोपियन यूनियन/OECD के अन्य सदस्य देशों में निर्यात प्रारंभ करने पर ही प्राप्त होगी।
- 7.5 उक्त बिंदु 7.4 में उल्लेखित वित्तीय सीमा के अन्तर्गत इकाई निर्यात के लिए एक से अधिक गुणवत्ता प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन कर सकेगी, किन्तु प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा, प्रत्येक इकाई के लिए रु. 25 लाख तक ही होगी।
- 7.6 नीति की प्रभावशील अवधि के दौरान फार्मास्यूटिकल इकाई द्वारा निर्यात के लिये तैयारी हेतु डब्ल्यूएचओ जीएमपी या यू.एस.-एफ.डी.ए. प्रमाण पत्र प्राप्त

करने के लिये सुविधाओं का सृजन करने में किये गये व्यय का 50%, अधिकतम 50 लाख रुपए की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

7.7 उक्त बिंदु 7.6 में उल्लेखित वित्तीय सीमा के अन्तर्गत फार्मास्यूटिकल इकाई द्वारा निर्यात के लिए एक से अधिक गुणवत्ता प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन कर सकेगी, किन्तु प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा, प्रत्येक इकाई के लिए रू. 50 लाख तक ही होगी।

7.8 इस सहायता हेतु इकाई को गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्राप्ति दिनांक से अधिकतम 90 दिवस के अंदर निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट-3) में आवेदन तथा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (परिशिष्ट-13) संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत करना होगा। आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज, जहाँ लागू हो, संलग्न करना आवश्यक होगा :-

- (i) आईएसओ/बीआयएस/बीईई प्रमाणीकरण की अभिप्रमाणित प्रति।
- (ii) उन दस्तावेजों की अभिप्रमाणित प्रति जो आईएसओ/बीआयएस/बीईई प्रमाणीकरण प्राप्त करने के लिये किये गये व्यय को प्रमाणित करते हो।
- (iii) जेड प्रमाणीकरण की अभिप्रमाणित प्रति।
- (iv) जेड प्रमाणीकरण हेतु भारत सरकार द्वारा मान्य व्यय एवं प्रदत्त सहायता संबंधी दस्तावेजों की छायाप्रति।
- (v) निर्यात हेतु प्राप्त किये गये गुणवत्ता प्रमाणन की अभिप्रमाणित प्रति।
- (vi) उन दस्तावेजों की अभिप्रमाणित प्रति जो निर्यात हेतु गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त करने के लिये किये गये व्यय को प्रमाणित करते हो।

- (vii) एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत उद्योग आधार ज्ञापन (UAM) जमा करने पर प्राप्त अभिस्वीकृति की छायाप्रति।
- (viii) जीएसटी अंतर्गत पंजीयन की छायाप्रति।
- (ix) भारत सरकार के जीएसटी पोर्टल से प्राप्त इकाई द्वारा विगत माह में किये गये विक्रय का प्रमाण
- (x) भारत सरकार से समान स्वरूप की योजनान्तर्गत प्राप्त सहायता/किये गये आवेदन (यदि कोई हों तो) की जानकारी।

8. पेटेंट/आईपीआर के लिए प्रतिपूर्ति

- 8.1 औद्योगिक इकाई को नीति की प्रभावशील अवधि के दौरान घरेलू पेटेंट/आईपीआर पंजीकरण कराने हेतु किये गये व्यय की 100%, अधिकतम 5 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा की जाएगी।
- 8.2 औद्योगिक इकाई को नीति की प्रभावशील अवधि के दौरान अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट/आईपीआर पंजीकरण कराने हेतु किये गये व्यय की 100%, अधिकतम 10 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा की जाएगी।
- 8.3 उक्त बिंदुओं 8.1 व 8.2 में उल्लेखित वित्तीय सीमा के अन्तर्गत इकाई एक से अधिक पेटेंट/आईपीआर पंजीकरण कराने हेतु किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन कर सकेगी, किन्तु प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा, प्रत्येक इकाई के लिए घरेलू पेटेंट/आईपीआर हेतु रु. 5 लाख एवं अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट/आईपीआर हेतु रु. 10 लाख तक ही होगी।
- 8.4 विकसित किये गये उत्पाद/प्रक्रिया, जिसका पेटेंट कराया गया है, का वाणिज्यिक उत्पादन/प्रक्रिया का उपयोग इकाई द्वारा किया जाना आवश्यक होगा।
- 8.5 सहायता प्राप्त करने हेतु इकाई का मुख्यालय मध्यप्रदेश में होना आवश्यक होगा।

8.6 योजनांतर्गत प्रतिपूर्ति पेटेंट पंजीयन/बौद्धिक सम्पदा अधिकार(आईपीआर) प्राप्ति हेतु किये गये वास्तविक व्यय पर की जावेगी, जिसमें निम्न व्यय मान्य किये जाएंगे -

- (i) पेटेंट कराने हेतु प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र के साथ जमा की गई निर्धारित शुल्क की राशि।
- (ii) पेटेंट कराए गए उत्पाद के अनुसंधान एवं शोध हेतु स्थापित संयंत्र एवं साज सज्जा पर व्यय राशि।
- (iii) पेटेंट प्रक्रिया अन्तर्गत विषय विशेषज्ञ की ली गई सलाह/सेवा के लिए भुगतान किये गये व्यय की राशि।

8.7 इस सहायता हेतु इकाई को पेटेंट प्राप्ति दिनांक से अधिकतम 90 दिवस के अंदर निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट-3) में आवेदन तथा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (परिशिष्ट-13) संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत करना होगा। आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक होगा:-

- (i) पेटेंट/आईपीआर पंजीयन प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति।
- (ii) उन दस्तावेजों की अभिप्रमाणित प्रति जो पेटेंट/आईपीआर प्राप्त करने के लिये किये गये व्यय को प्रमाणित करते हों।
- (iii) एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत उद्योग आधार ज्ञापन (UAM) जमा करने पर प्राप्त अभिस्वीकृति की छायाप्रति।
- (iv) जीएसटी अंतर्गत पंजीयन की छायाप्रति।
- (v) भारत सरकार के जीएसटी पोर्टल से प्राप्त इकाई द्वारा विगत माह में किये गये विक्रय का प्रमाण

(vi) भारत सरकार से समान स्वरूप की योजनान्तर्गत प्राप्त सहायता/किये गये आवेदन (यदि कोई हों तो) की जानकारी।

9. औद्योगिक परिसर तक अधोसंरचना विकास के लिए वित्तीय सहायता :-

- 9.1 यदि निवेशक लघु और मध्यम श्रेणी के विनिर्माण उद्यम की स्थापना हेतु निजी भूमि क्रय करता है या अविकसित शासकीय भूमि प्राप्त करता है, तो ऐसी इकाइयों को इकाई परिसर तक पानी, सड़क और बिजली के अधोसंरचना विकास में किये गये व्यय का 50% वित्तीय सहायता, अधिकतम रुपये 25 लाख, राज्य शासन द्वारा प्रदान की जाएगी। यह सहायता नीति की प्रभावशील अवधि के अंतर्गत वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाली इकाइयों को ही प्राप्त होगी।
- 9.2 अधोसंरचना विकास के पूर्व उद्योग आयुक्त की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। अनुमति प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत आवेदन से तीस दिवस के भीतर निर्णय न होने पर डीमंड अनुमति मान्य की जाएगी और तदनुसार निवेशक द्वारा उद्योग आयुक्त को सूचित किया जाएगा।
- 9.3 जिस अधोसंरचना के विकास के व्यय हेतु प्रतिपूर्ति चाही गई है, उसका विकास उद्योग आयुक्त की अनुमति/डीमंड अनुमति के पश्चात हुआ हो एवं इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन के दिनांक के पश्चात् का नहीं हो।
- 9.4 इस सुविधा का लाभ उद्योग परिसर तक अधोसंरचना विकसित करने में किये गये वास्तविक व्यय पर किया जावेगा, जिसमें निम्नलिखित व्यय सम्मिलित किये जायेंगे :-
 - (i) मुख्य मार्ग से उद्योग परिसर तक सड़क निर्माण में हुआ व्यय।
 - (ii) पॉवर स्टेशन/विद्युत केन्द्र से उद्योग परिसर तक विद्युतीकरण में हुआ व्यय।
 - (iii) जल स्रोत/मुख्य पाइप लाइन से उद्योग परिसर तक जल लाने हेतु पाइप लाइन बिछाने में हुआ व्यय।

उक्त कार्यो पर हुए व्यय का सत्यापन चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र/मूल्यांकन के आधार पर किया जावेगा।

9.5 वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से अधिकतम 90 दिवस के अंदर इकाई को अधोसंरचना व्यय में दिये जाने वाले अनुदान हेतु निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट-2) में आवेदन तथा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (परिशिष्ट-13) संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत करना होगा। आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक होगा :-

- (i) उद्योग परिसर तक अधोसंरचना विकसित करने में हुए व्यय के प्रमाणीकरण हेतु चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र/मूल्यांकन।
- (ii) एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत उद्योग आधार ज्ञापन जमा करने पर प्राप्त अभिस्वीकृति की छायाप्रति
- (iii) जीएसटी अंतर्गत पंजीयन की छायाप्रति
- (iv) उद्योग आयुक्त द्वारा प्रदत्त अनुमति की छायाप्रति या डीम्ड अनुमति संबंधी सूचना पत्र।
- (v) भारत सरकार के जीएसटी पोर्टल से प्राप्त इकाई द्वारा विगत माह में किये गये विक्रय का प्रमाण

10. अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना हेतु सहायता

10.1 नई औद्योगिक इकाई को नीति की प्रभावशील अवधि में, अपशिष्ट उपचार संयंत्र (ETP) की स्थापना में निवेश के लिए 50 प्रतिशत पूंजी अनुदान अधिकतम 25 लाख रुपए प्रदान किया जाएगा।

10.2 औद्योगिक इकाईयों के समूह (कम से कम 5) द्वारा सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र (CETP) की स्थापना के लिये किये गये व्यय का 50%, अधिकतम 100 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी।

10.3 इकाई/समूह द्वारा इस सहायता हेतु अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना के 90 दिवस के भीतर निम्न दस्तावेजों सहित निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट-4) में आवेदन तथा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (परिशिष्ट-13) में संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत किया जाएगा :-

- (i) अपशिष्ट उपचार संयंत्र/सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र की स्थापना में हुए व्यय के प्रमाणीकरण हेतु चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र/मूल्यांकन। (मदवार व्यय सत्यापन सहित)।
- (ii) अपशिष्ट उपचार संयंत्र/सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र के परिप्रेक्ष्य में प्रदूषण नियंत्रण मण्डल/ औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संचालनालय का प्रमाण-पत्र।
- (iii) अपशिष्ट उपचार संयंत्र/सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र के उपयोग को प्रमाणित करने वाले दस्तावेजों की छायाप्रति।
- (iv) सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र के प्रकरण में समूह गठन संबंधी दस्तावेज/एग्रीमेंट।
- (v) इकाई/इकाईयों द्वारा एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत उद्योग आधार ज्ञापन जमा करने पर प्राप्त अभिस्वीकृति(यों) की छायाप्रति(यां)
- (vi) इकाई/इकाईयों द्वारा जीएसटी अंतर्गत पंजीयन की छायाप्रति(यां)
- (vii) भारत सरकार के जीएसटी पोर्टल से प्राप्त इकाई द्वारा विगत माह में किये गये विक्रय का प्रमाण

11. निजी औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/विकास हेतु सहायता

11.1 नीति की प्रभावशील अवधि में, निजी औद्योगिक क्षेत्रों/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/विकास हेतु उद्योग आयुक्त के अनुमति प्राप्त करने वाली संस्था/एजेन्सी/निवेशक को स्थापना/विकास में व्यय हुई राशि का 50 प्रतिशत अधिकतम रु. 250 लाख, सहायता के रूप में निजी क्षेत्रों को उपलब्ध कराया जाएगा, बशर्ते इस प्रकार विकसित औद्योगिक क्षेत्र का क्षेत्रफल कग रो कग 5 एकड़ हो या बहुमंजिला औद्योगिक परिसर का कारपेट क्षेत्र कम से कम 10000 वर्ग फीट हो और विकसित औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर में न्यूनतम पांच औद्योगिक इकाईयां कार्यरत हों।

11.2 पॉवरलूम, फार्मास्यूटिकल और परिधान क्षेत्र की इकाईयों के लिये समर्पित निजी औद्योगिक क्षेत्रों/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/विकास में व्यय हुई राशि का 60 प्रतिशत अधिकतम रु. 500 लाख, सहायता के रूप में निजी क्षेत्रों को उपलब्ध कराया जाएगा।

11.3 संस्था/एजेन्सी/निवेशक द्वारा औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/विकास की अनुमति प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट-5) में आवेदन सहपत्रों सहित उद्योग संचालनालय, म. प्र. में प्रस्तुत किया जायेगा। उद्योग आयुक्त के अनुमोदन उपरांत निम्नलिखित शर्तों के अधीन औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/विकास हेतु अनुमति जारी की जाएगी:-

11.3.1 औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/विकास अनुमति दिनांक से तीन वर्ष के भीतर होना चाहिए।

11.3.2 निर्धारित अवधि में औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/विकास न होने की दशा में उद्योग आयुक्त, म.प्र. द्वारा संबंधित संस्था/एजेन्सी/निवेशक को 60 दिवसीय सूचना पत्र जारी किया जाएगा। समाधानकारक उत्तर प्राप्त होने पर औद्योगिक

क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/विकास हेतु छःमाह का अतिरिक्त समय उद्योग आयुक्त, म.प्र. द्वारा प्रदान किया जाएगा।

- 11.3.3 अतिरिक्त समय में भी औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/विकास न होने की दशा में या 60 दिवसीय सूचना पत्र का समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/विकास हेतु जारी अनुमति निरस्त की जाएगी। उक्त निरस्तीकरण के विरुद्ध अपील तीन माह के अंदर प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन, एमएसएमई विभाग को प्रस्तुत की जा सकेगी।
- 11.3.4 प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन, एमएसएमई विभाग अपील पर विचार कर गुण दोष के आधार पर अधिकतम छःमाह का अतिरिक्त समय प्रदान कर सकेंगे।
- 11.3.5 औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर स्थापना/विकास हेतु अतिरिक्त समय को मिलाकर कुल समय, संस्था/एजेन्सी/निवेशक को औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर स्थापना/विकास हेतु जारी अनुमति की दिनांक से चार वर्ष की अवधि तक सीमित होगा।
- 11.4 औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना हेतु, सक्षम स्तर से स्वीकृत अवधि या औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर के पूर्ण होने का दिनांक जो भी पहले हो, तक स्थापना/विकास में व्यय की गई राशि सहायता हेतु गणना में ली जाएगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर के पूर्ण होने से आशय अधोसंरचना पूर्ण

होने के बाद न्यूनतम 5 औद्योगिक इकाइयों द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिये जाने से है।

11.5 औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर के पूर्ण होने के दिनांक के 90 दिवस के भीतर संस्था/एजेन्सी/निवेशक द्वारा सहायता स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट-6) में आवेदन तथा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (परिशिष्ट-13) निम्नलिखित सहपत्रों के साथ संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को प्रस्तुत किया जाएगा :-

- (i) विकसित औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर में स्थापित किन्हीं पांच औद्योगिक इकाइयों के नाम मय स्थापना को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज सहित।
- (ii) विकसित औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर के क्षेत्रफल को प्रमाणित करने वाला दस्तावेज।
- (iii) औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर विकसित करने में हुए व्यय (बिंदु 11.4 में दी गई अवधि में) के प्रमाणीकरण हेतु चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र/मूल्यांकन।
- (iv) औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर विकसित करने हेतु प्राप्त आवश्यक अनुमतियों/दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां।
- (v) औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर के स्वामित्व संबंधी दस्तावेजों की छायाप्रति।

12. निजी भूमि पर कार्यरत एमएसएमई के क्लस्टर को सुदृढ़ बनाने हेतु सहायता

12.1 निजी भूमि पर कार्यरत एमएसएमई के क्लस्टर को सुदृढ़ बनाने के लिए अधोसंरचना विकास करने वाली एजेन्सी को किये गये व्यय का 50%, अधिकतम 50 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी।

- 12.2 जिस निजी भूमि पर कार्यरत एमएसएमई के क्लस्टर को सुदृढ़ करने हेतु चयन किया गया है, वह किसी निजी कंपनी/संस्था/निवेशक का न होकर स्वाभाविक रूप से स्थापित होना चाहिए अर्थात् उसमें अलग-अलग स्वामित्व की भूमि पर कम से कम 10 इकाईयां कार्यरत होनी चाहिये।
- 12.3 एमएसएमई के क्लस्टर में जिस अधोसंरचना का विकास किया जाना है, उसकी अनुशांसा उस क्षेत्र के औद्योगिक संघ द्वारा उस एमएसएमई क्लस्टर की कम से कम पांच इकाईयों की सहमति से की जाएगी और औद्योगिक संघ की ओर से ही अधोसंरचना विकास हेतु एजेन्सी का चयन किया जाएगा।
- 12.4 विकासकर्ता एजेन्सी द्वारा अधोसंरचना विकास का विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया जाएगा, जिस पर संबंधित औद्योगिक संघ की सहमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- 12.5 एजेन्सी द्वारा निजी भूमि पर कार्यरत एमएसएमई के क्लस्टर को सुदृढ़ बनाने के लिए अधोसंरचना विकास करने के पूर्व उद्योग आयुक्त की अनुमति प्राप्त की जाएगी। इस हेतु निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट-7) में आवेदन सहपत्रों सहित उद्योग संचालनालय, म. प्र. में प्रस्तुत किया जायेगा। उद्योग आयुक्त के अनुमोदन उपरांत निम्नलिखित शर्तों के अधीन अधोसंरचना विकास हेतु अनुमति जारी की जाएगी:-
- 12.5.1 अधोसंरचना के विकास हेतु समयावधि निर्धारित की जाएगी, जो अधिकतम एक वर्ष की होगी।
- 12.5.2 निर्धारित अवधि में अधोसंरचना का विकास न होने की दशा में उद्योग आयुक्त, म.प्र. द्वारा संबंधित एजेन्सी को 60 दिवसीय सूचना पत्र जारी किया जाएगा। समाधानकारक उत्तर प्राप्त होने पर अधोसंरचना के विकास हेतु छः माह का अतिरिक्त समय उद्योग आयुक्त, म.प्र. द्वारा प्रदान किया जाएगा।

- 12.5.3 अतिरिक्त समय में भी अधोसंरचना विकास न होने की दशा में या 60 दिवसीय सूचना पत्र का समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर अधोसंरचना विकास हेतु जारी अनुमति निरस्त की जाएगी। उक्त निरस्तीकरण के विरुद्ध अपील तीन माह के अंदर प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन, एमएसएमई विभाग को प्रस्तुत की जा सकेगी।
- 12.5.4 प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन, एमएसएमई विभाग अपील पर विचार कर गुण दोष के आधार पर अधिकतम छः माह का अतिरिक्त समय प्रदान कर सकेंगे।
- 12.5.5 अधोसंरचना विकास हेतु अतिरिक्त समय को मिलाकर कुल समय, ऐजेन्सी को अधोसंरचना विकास हेतु जारी अनुमति की दिनांक से दो वर्ष की अवधि तक सीमित होगा।
- 12.6 अधोसंरचना विकास की प्रतिपूर्ति हेतु, सक्षम स्तर से स्वीकृत अवधि या औद्योगिक अधोसंरचना विकास के पूर्ण होने का दिनांक जो भी पहले हो, तक विकास में व्यय की गई राशि सहायता हेतु गणना में ली जाएगी।
- 12.7 अधोसंरचना विकास का कार्य पूर्ण होने से आशय उद्योग आयुक्त से अनुमति प्राप्त प्रस्ताव अनुसार अधोसंरचना विकास का कार्य पूर्ण होने से है।
- 12.8 अधोसंरचना विकास के पूर्ण होने के दिनांक के 90 दिवस के भीतर ऐजेन्सी द्वारा सहायता स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट-8) में आवेदन तथा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (परिशिष्ट-13) निम्नलिखित सहपत्रों के साथ संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को प्रस्तुत किया जाएगा :-
- (i) उद्योग आयुक्त से अनुमति प्राप्त प्रस्ताव।
 - (ii) विकसित अधोसंरचना को प्रमाणित करने वाला दस्तावेज।

- (iii) अधोसंरचना विकसित करने में हुए व्यय (बिंदु 12.6 में दी गई अवधि में) के प्रमाणीकरण हेतु चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र/मूल्यांकन।
- (iv) अधोसंरचना विकसित करने हेतु प्राप्त आवश्यक अनुमतियों/दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां।
- (v) विकसित अधोसंरचना हेतु संबंधित औद्योगिक संघ का संतुष्टि प्रमाण पत्र।

13. ऊर्जा लेखा परीक्षा (Audit) के लिए वित्तीय सहायता

- 13.1 एमएसएमई इकाइयों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए, मध्यप्रदेश सरकार द्वारा ऊर्जा लेखा परीक्षा की लागत का 50%, अधिकतम 50 हजार रुपये और ऑडिट में सुझाये गये उपकरण एवं मशीनरी को अपनाने के लिए हुये व्यय का 25%, अधिकतम 5 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
- 13.2 औद्योगिक इकाई द्वारा ऊर्जा लेखा परीक्षा नीति की प्रभावशील अवधि में करवाया जाना अनिवार्य होगा और ऑडिट में सुझाये गये उपकरण एवं मशीनरी का क्रय ऊर्जा लेखा परीक्षा की रिपोर्ट दिनांक से एक वर्ष के भीतर का होना चाहिये।
- 13.3 ऑडिट में सुझाये गये उपकरण एवं मशीनरी की स्थापना के पश्चात् 20 प्रतिशत ऊर्जा की बचत होना आवश्यक होगा।
- 13.4 इकाई/समूह द्वारा इस सहायता हेतु ऊर्जा लेखा परीक्षा या ऑडिट में सुझाये गये उपकरण एवं मशीनरी की स्थापना के 90 दिवस के भीतर निम्न दस्तावेजों सहित निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट-9) में आवेदन तथा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (परिशिष्ट-13) में संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत किया जाएगा :-

- (i) म. प्र. शासन, ऊर्जा विभाग द्वारा ऊर्जा लेखा परीक्षा हेतु अधिकृत ऐजेन्सी द्वारा की गई लेखा परीक्षा की अभिप्रमाणित प्रति।
- (ii) ऊर्जा लेखा परीक्षा में हुए व्यय को प्रमाणित करने वाले दस्तावेजों की छायाप्रति।
- (iii) ऊर्जा लेखा परीक्षा में सुझाये गये उपकरण एवं मशीनरी के क्रय के प्रमाणीकरण हेतु चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र/मूल्यांकन (यदि क्रय की गई हो)
- (iv) ऊर्जा लेखा परीक्षा के समय और ऊर्जा लेखा परीक्षा में सुझाये गये उपकरण एवं मशीनरी की स्थापना के पश्चात् ऊर्जा की बचत को दर्शाने वाले दस्तावेजों की छायाप्रति।
- (v) इकाई द्वारा एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत उद्योग आधार ज्ञापन जमा करने पर प्राप्त अभिस्वीकृति की छायाप्रति
- (vi) इकाई द्वारा जीएसटी अंतर्गत पंजीयन की छायाप्रति
- (vii) भारत सरकार के जीएसटी पोर्टल से प्राप्त इकाई द्वारा विगत माह में किये गये विक्रय का प्रमाण

14. पावरलूम उन्नयन हेतु सहायता

- 14.1 नीति की प्रभावशील अवधि में प्लेन/सेमी ऑटोमेटिक शटल पावरलूम को आधुनिक शटललेस लूम में उन्नयन करने के लिए किये गये व्यय में से, भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता (यदि कोई हो, तो) के समायोजन के पश्चात् शेष राशि का शत-प्रतिशत या उन्नयन लागत का 25%, जो भी कम हो, अधिकतम 10 पावरलूम प्रति इकाई पर राज्य शासन द्वारा प्रदान किया जाएगा। इस योजना का बिंदु क्रमांक 4.17 उक्त सहायता हेतु लागू नहीं होगा।

14.2 इस सहायता हेतु पॉवरलूम इकाई को उन्नयन दिनांक से अधिकतम 90 दिवस के अंदर निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट-10) में आवेदन तथा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (परिशिष्ट-13) संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत करना होगा। आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक होगा :-

- (i) पॉवरलूम के उन्नयन हेतु किये गये व्यय एवं उन्नयन किये गये पॉवरलूमों की संख्या के प्रमाणीकरण हेतु चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अयोगउन्टेंट द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र/मूल्यांकन।
- (ii) भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता के दस्तावेजों की अभिप्रमाणित प्रति। (यदि प्राप्त की गई हो, तो)।
- (iii) एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत उद्योग आधार ज्ञापन (UAM) जमा करने पर प्राप्त अभिस्वीकृति की छायाप्रति।
- (iv) जीएसटी अंतर्गत पंजीयन की छायाप्रति (यदि जीएसटी अधिनियम अंतर्गत पंजीयन अनिवार्य हो, तो)
- (v) भारत सरकार का अन्य कोई पंजीयन (यदि कोई हो, तो)।
- (vi) विद्युत देयक की प्रति।

15. फार्मास्यूटिकल लैब की मशीनरी व उपकरण की स्थापना हेतु सहायता

15.1 फार्मास्यूटिकल सेक्टर की नई औद्योगिक इकाई को फार्मास्यूटिकल लैब की मशीनरी व उपकरण की स्थापना में किये गये व्यय का 50%, अधिकतम 25 लाख रुपए की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

15.2 इकाई द्वारा इस सहायता हेतु फार्मास्यूटिकल लैब की मशीनरी व उपकरण की स्थापना के 90 दिवस के भीतर निम्न दस्तावेजों सहित निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट-11) में आवेदन तथा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (परिशिष्ट-13) में संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत किया जाएगा :-

- (i) फार्मास्यूटिकल लैब की मशीनरी व उपकरण की स्थापना में हुए व्यय के प्रमाणीकरण हेतु चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र/मूल्यांकन। (मदवार व्यय सत्यापन सहित)।
- (ii) फार्मास्यूटिकल लैब के परिप्रेक्ष्य में वांछित पंजीयन/अनुमति/प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित प्रति।
- (iii) फार्मास्यूटिकल लैब के उपयोग को प्रमाणित करने वाले दस्तावेजों की छायाप्रति।
- (iv) इकाई द्वारा एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत उद्योग आधार ज्ञापन जमा करने पर प्राप्त अभिस्वीकृति की छायाप्रति
- (v) इकाई द्वारा जीएसटी अंतर्गत पंजीयन की छायाप्रति
- (vi) भारत सरकार के जीएसटी पोर्टल से प्राप्त इकाई द्वारा विगत माह में किये गये विक्रय का प्रमाण

16. रेडीमेड गारमेंट एवं मेडअप्स का निर्माण करने वाली इकाईयों हेतु वेतन अनुदान

- 16.1 रेडीमेड गारमेंट एवं मेडअप्स (पहनने योग्य या गैर पहनने योग्य कपड़े, सिले कपड़े, जिनमें से कपड़ों के कम से कम दो सिरों की सिलाई, मशीनरी का उपयोग कर की गयी है) का निर्माण करने वाली नवीन इकाई, जिसमें यंत्र-संयंत्र में न्यूनतम 1.00 करोड़ रुपये का निवेश और न्यूनतम 25 नियमित कर्मचारी हो, के प्रत्येक नियमित कर्मचारी, जो मध्यप्रदेश का स्थाई निवासी है, के वेतन का 25%, अधिकतम 2500 रुपये प्रतिमाह, कुल 5 लाख रुपये की वार्षिक सीमा तक, 5 वर्ष तक 'वेतन अनुदान' के रूप में प्रदान किया जाएगा। वेतन अनुदान छःमाही आधार पर प्रदान किया जाएगा। अतः जिस छःमाही हेतु वेतन अनुदान चाहिए, उसके समाप्त होने के 90 दिवस के भीतर वेतन संबंधी प्रामाणिक जानकारी महाप्रबंधक को उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

16.2 प्रथम बार वेतन अनुदान हेतु इकाई को वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से अधिकतम 90 दिवस के भीतर निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट-12) में आवेदन तथा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (परिशिष्ट-13) संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत करना होगा। आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक होगा :-

- (i) इकाई की उत्पादन दिनांक से प्रथम छः माह में नियोक्ता द्वारा इकाई में कार्यरत नियमित कर्मचारी, जो म. प्र. के स्थाई निवासी हैं, को दिये गये वेतन की राशि एवं ऐसे कर्मचारियों की संख्या की पुष्टि हेतु दस्तावेज की अभिप्रमाणित प्रति।
- (ii) एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत उद्योग आधार ज्ञापन जमा करने पर प्राप्त अभिस्वीकृति की छायाप्रति।
- (iii) जीएसटी अंतर्गत पंजीयन की छायाप्रति।
- (iv) संयंत्र एवं मशीनरी और भवन में किये गये पात्र निवेश के प्रमाणीकरण हेतु चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र/मूल्यांकन।
- (v) इकाई में कार्यरत नियमित कर्मचारियों की संख्या की पुष्टि हेतु दस्तावेज की अभिप्रमाणित प्रति।
- (vi) भारत सरकार के जीएसटी पोर्टल से प्राप्त इकाई द्वारा विगत माह में किये गये विक्रय का प्रमाण
- (vii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी उचित अनुमति/ अनापति प्रमाण पत्र/पंजीयन प्रमाण पत्र (यदि लागू हों) की छायाप्रतियां

16.3 किसी इकाई को जिला स्तरीय सहायता समिति से प्रथम बार वेतन अनुदान स्वीकृत होने के बाद महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र इसे संपूर्ण

पात्रता अवधि में वितरित करने के लिए सक्षम होंगे अर्थात् किसी इकाई को प्रथम बार समिति द्वारा वेतन अनुदान स्वीकृत होने पर उसके अनुदान प्रकरण में शेष छः माहियों हेतु किसी छः माही में इकाई में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत म.प्र. के स्थायी निवासियों को प्रदत्त वेतन संबंधी प्रामाणिक जानकारी और इकाई में कार्यरत नियमित कर्मचारियों की संख्या संबंधी जानकारी, इकाई द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर उस छः माही हेतु वेतन अनुदान का वितरण महाप्रबंधक द्वारा किया जाएगा।

17. प्राप्त आवेदनों में जिला स्तरीय सहायता समिति के अनुमोदन उपरांत सदस्य सचिव (महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र) द्वारा सहायता स्वीकृति आदेश जारी किया जायेगा और उपलब्ध आवंटन अनुसार महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा इकाई को पात्रतानुसार देय सहायता राशि उपलब्ध कराई जायेगी।
18. एमएसएमई स्तर की बीमार औद्योगिक इकाईयों के पुनर्जीवन हेतु प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, एमएसएमई विभाग की अध्यक्षता में गठित साधिकार समिति (Empowered Committee) द्वारा स्वीकृत पैकेज अनुसार सहायता की स्वीकृति एवं वितरण इस योजना की प्रक्रिया अनुसार किया जाएगा। बीमार इकाई द्वारा पुनर्वास पैकेज हेतु साधिकार समिति के समक्ष निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट-15) में आवेदन किया जायेगा।

एमएसएमई विकास नीति 2019 की प्रभावशील अवधि में पुनर्जीवित बीमार इकाई साधिकार समिति द्वारा अनुमोदित पैकेज अनुसार योजना में प्रावधानित सहायताएं/सुविधाएं पात्रतानुसार प्राप्त कर सकती हैं।

19. प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने की सामान्य प्रक्रिया -

- 19.1 इकाई/एजेन्सी/संस्था/निवेशक को वित्तीय सहायता हेतु निर्धारित आवेदन पत्र समय सीमा में संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत करना होगा।
- 19.2 समिति से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त म. प्र. एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019 अंतर्गत देय वित्तीय सहायता का प्रदाय महाप्रबंधक द्वारा किया जायेगा। स्वीकृत सहायता राशि का भुगतान इकाई को ई-पेमेंट के माध्यम से इकाई के बैंक खाते में किया जायेगा।
- 19.3 इकाई के प्रकरण में ई-पेमेंट की पावती ही एमएसएमई प्रोत्साहन के रूप में प्राप्त राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र होगा।
- 19.4 जिला स्तरीय सहायता समिति द्वारा प्रोत्साहन राशि की स्वीकृति उपरांत बजट में प्रावधान के अभाव में अथवा किसी भी अन्य कारण से ई-पेमेंट वितरण में विलम्ब होने पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

20. अपील

जिला स्तरीय सहायता समिति के निर्णय के विरुद्ध प्रथम अपील उद्योग आयुक्त के समक्ष निर्णय प्राप्ति दिनांक से 90 दिवस के भीतर की जा सकेगी। विलंब से प्राप्त अपील के विलंब दोष को उद्योग आयुक्त गुण-दोष के आधार पर शिथिल कर सकेंगे। उद्योग आयुक्त के निर्णय के विरुद्ध द्वितीय अपील प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के समक्ष निर्णय प्राप्ति दिनांक से 30 दिवस के भीतर की जा सकेगी। विलंब से प्राप्त अपील के विलंब दोष को प्रमुख सचिव गुण-दोष के आधार पर शिथिल कर सकेंगे। प्रमुख सचिव का निर्णय अंतिम होगा एवं उसके विरुद्ध राज्य शासन में किसी भी स्तर पर अपील नहीं की जा सकेगी।

- 21.** योजना के क्रियान्वयन को सुगम बनाने की दृष्टि से अथवा विसंगति दूर करने एवं योजना के प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए निर्देश एवं मार्गदर्शन उद्योग आयुक्त द्वारा दिया जा सकेगा, जो अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। इस योजना एवं म. प्र. एमएसएमई विकास नीति 2019 की भाषा में विरोधाभास होने पर मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा मार्गदर्शन दिया जा सकेगा, जो अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

22. संशोधन/शिथिलीकरण/निरसन

योजनांतर्गत प्रावधानों में किसी बात के होते हुए भी मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग किसी भी समय -

- 22.1 इस योजना को संशोधित अथवा निरस्त कर सकेगा,
- 22.2 इस योजना के प्रावधानों को शिथिल कर सकेगा,

- 23.** किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र मध्यप्रदेश होगा।

परिशिष्ट-1**अपात्र उद्योगों की सूची**

1. व्यापार और सेवाओं से संबंधित गतिविधियाँ
2. बीयर और शराब, जिसमें एल्कोहल है
3. सभी प्रकार के पान मसाला और गुटखा विनिर्माण
4. तम्बाकू और तम्बाकू आधारित उत्पादों का विनिर्माण
5. समस्त प्रकार के पॉलिथीन बैग और 40 माइक्रोन या उससे कम मोटाई के प्लास्टिक बैग का विनिर्माण
6. केंद्र या राज्य सरकार या उनके उपक्रम द्वारा स्थापित औद्योगिक इकाइयाँ
7. स्टोन क्रशर
8. खनिजों की पिसाई, केल्विनेशन (गिट्टी से बनाई जाने वाली कृत्रिम रेत के निर्माण को छोड़कर)
9. राज्य सरकार/राज्य सरकार के उपक्रम का अशोधी/चूककर्ता
10. सभी प्रकार की खनन गतिविधियाँ (जहाँ कोई मूल्य संवर्धन नहीं हुआ हो)
11. लकड़ी के कोयले (चारकोल) का निर्माण
12. सभी प्रकार के सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट (ऐसी खाद्य तेल एक्पैलर इकाइयाँ, जहाँ संयंत्र और मशीनरी में निवेश रु. 1 करोड़ से अधिक नहीं है, को छोड़कर)
13. समस्त प्रकार के तेलों की रिफायनरी
14. सीमेंट/क्लिकर विनिर्माण इकाइयाँ
15. सभी प्रकार के प्रकाशन और मुद्रण प्रक्रिया
16. आरा मिल और लकड़ी की प्लेनिंग
17. लोहे/स्टील स्क्रैप को दबाकर इसे ब्लॉकों एवं किसी अन्य किसी आकार में बदलना
18. विद्युत उत्पादक इकाइयाँ
19. पैकेज पीने का पानी
20. सॉर्टेक्स प्लांट और फसलों/अनाज की सॉर्टिंग/ग्रेडिंग/सफाई
21. समस्त प्रकार के गैसयुक्त (Aerated)/ कार्बोनेटेड पेय
22. बूचड़खाना और मांस पर आधारित उद्योग
23. म. प्र. एमएसएमई विकास नीति 2019 के संदर्भ में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा घोषित कोई उद्योग

परिशिष्ट-2

**"मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019" अंतर्गत उद्योग विकास
अनुदान और इकाई परिसर तक अधोसंरचना विकास के लिये
सहायता हेतु आवेदन का प्रारूप**

प्रति,

महाप्रबंधक,
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,
....., म.प्र.।

विषय:- "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019" अंतर्गत उद्योग विकास अनुदान और इकाई परिसर तक अधोसंरचना विकास की स्थापना के लिये सहायता उपलब्ध कराने हेतु।

मेरे/हमारे द्वारा जिला(मध्यप्रदेश) में विनिर्माण इकाई स्थापित की गई है। "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019" अंतर्गत उद्योग विकास अनुदान और इकाई परिसर तक अधोसंरचना विकास के लिये सहायता उपलब्ध कराने हेतु इकाई का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 01. इकाई का नाम | : | |
| 02. इकाई का कार्यस्थल | : | |
| स्थान/नगर | | |
| विकासखण्ड | | |
| तहसील | | |
| जिला | | |
| 03. अ/ इकाई का प्रकार | : | प्रोप्रायटरी/संस्था/पार्टनरशिप/कंपनी
(पार्टनरशिप डीड/मेमोरेण्डम ऑफ
एसोसिएशन/आर्टिकल की छायाप्रति
संलग्न करें) |

ब/ यदि इकाई प्रोप्रायटरी (पूर्ण :
स्वामित्व) है तो, इकाई स्वामी का
नाम

04. एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत :
उद्योग आधार ज्ञापन फाइल करने पर
प्राप्त अभिस्वीकृति का क्रमांक व दिनांक
(छायाप्रति संलग्न करें)

05. जीएसटी अंतर्गत पंजीयन का क्रमांक व
दिनांक (छायाप्रति संलग्न करें)

06. इकाई का प्रकार (नवीन/विस्तार/ :
डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन)

07. इकाई के विद्युत संयोजन का भार, :
क्रमांक व दिनांक

08. वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का :
दिनांक

09. वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के :
दिनांक तक किये गए संयंत्र व मशीनरी
और भवन में पूंजी निवेश की राशि
(लाख रूपए में)

क्र.	मद	निवेश (रूपये में)
(i)	संयंत्र व मशीनरी	
(ii)	भवन	

10. इकाई के उत्पादों के नाम व वार्षिक :
क्षमता

क्र.	उत्पाद का नाम	वार्षिक क्षमता

11. इकाई में प्राप्त रोजगार : कुल रोजगार -
(पुष्टि हेतु प्रामाणिक दस्तावेज संलग्न करें)
कुल रोजगार में से म. प्र. के स्थाई निवासी को प्रदत्त रोजगार -
(i) कुल -
(ii) अजा -
(iii) अजजा -
(iv) अन्य पिछड़ा वर्ग -
12. जीएसटी पोर्टल अनुसार इकाई द्वारा :
विगत माह में किया गया विक्रय
(छायाप्रति संलग्न करें)
13. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुमति/ :
अनापत्ति प्रमाण पत्र/ पंजीयन प्रमाण पत्र (यदि लागू हों, तो)
14. विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकीउन्नयन :
होने पर

विवरण	विस्तार/ डायवर्सिफिकेशन/ तकनीकी उन्नयन के पूर्व	विस्तार/ डायवर्सिफिकेशन/ तकनीकी उन्नयन अंतर्गत	योग (विस्तार/ डायवर्सिफिकेशन/ तकनीकी उन्नयन पश्चात्)
संयंत्र एवं मशीनरी में पूंजी निवेश (लाख रुपये में)			
रोजगार			
उत्पाद की वार्षिक क्षमता			

(i)(उत्पाद).....			
(ii)(उत्पाद).....			
(iii)(उत्पाद).....			
(iv)(उत्पाद).....			

चाही गई सहायता का विवरण

(अ) उद्योग विकास अनुदान (नियम-6)

(i) प्रथम विक्रय के देयक का :

दिनांक (छायाप्रति संलग्न)

(ii) संयंत्र एवं मशीनरी पर किये :

(राशि लाख रुपये में)

गये व्यय की चार्टर्ड
इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट
द्वारा प्रमाणित मदवार व्यय
राशि (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

क्र.	विवरण	राशि
1		
2		
3		
योग		

(iii) वित्तीय संस्था का ऋण :

स्वीकृति एवं वितरण संबंधी
पत्र।(यदि लागू हों)

(iii) अतिरिक्त उद्योग विकास :

अनुदान हेतु इकाई स्वामी का अजा/अजजा श्रेणी की महिला
वर्ग (स्वामित्व को दर्शाने वाले
दस्तावेज की छायाप्रति संलग्न
संलग्न करें)

(ब) अधोसंरचना विकास के लिए वित्तीय सहायता (नियम-9)

(i) विकसित की गई अधोसंरचना :

का संक्षिप्त विवरण

(ii) उद्योग परिसर तक :

(राशि लाख रुपये में)

अधोसंरचना विकसित करने
हेतु, उद्योग आयुक्त द्वारा प्रदत्त
अनुमति/डीमंड अनुमति संबंधी
सूचना पत्र दिनांक से इकाई
की वाणिज्यिक उत्पादन
दिनांक तक, किये गये व्यय
की चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड
अकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित राशि
(प्रमाण पत्र संलग्न)

सड़क निर्माण हेतु
विद्युतीकरण हेतु
जल अधोसंरचना हेतु.....

कृपया "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019" अंतर्गत उक्त सहायता(ओं) को स्वीकृत करने का कष्ट करें। स्वीकृति की दशा में अनुदान वितरण के लिये इकाई के बैंक खाते, बैंक व शाखा का नाम, IFSC कोड संबंधी जानकारी संलग्न है।

संलग्न :-

दिनांक :-

स्थान :-

आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति

हस्ताक्षर

नाम.....

पद.....

(सील)

नोट- जिस सहायता के लिये आवेदन नहीं किया जाना हो, उसमें 'लागू नहीं' अंकित किया जावे।

परिशिष्ट-3

"मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019" अंतर्गत गुणवत्ता प्रमाणीकरण और पेटेंट/आईपीआर के लिए प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन का प्रारूप

प्रति,

महाप्रबंधक,

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,

....., म.प्र.।

विषय:- "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019" अंतर्गत गुणवत्ता प्रमाणीकरण और/या पेटेंट/आईपीआर के लिए प्रतिपूर्ति उपलब्ध कराने हेतु।

मेरे/हमारे द्वारा जिला(मध्यप्रदेश) में विनिर्माण इकाई स्थापित की गई है। "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019" अंतर्गत गुणवत्ता प्रमाणीकरण और/या पेटेंट/आईपीआर के लिए प्रतिपूर्ति उपलब्ध कराने हेतु इकाई का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

- | | |
|-----------------------|--|
| 01. इकाई का नाम | : |
| 02. इकाई का कार्यस्थल | : |
| स्थान/नगर | |
| विकासखण्ड | |
| तहसील | |
| जिला | |
| 03. इकाई का प्रकार | : |
| | प्रोप्रायटरी/संस्था/पार्टनरशिप/कंपनी
(पार्टनरशिप डीड/मेमोरेण्डम ऑफ
एसोसिएशन/आर्टिकल की छायाप्रति
संलग्न करें) |

04. एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत उद्योग :
आधार ज्ञापन फाइल करने पर प्राप्त
अभिस्वीकृति का क्रमांक व दिनांक
(छायाप्रति संलग्न करें)
05. जीएसटी अंतर्गत पंजीयन का क्रमांक व :
दिनांक (छायाप्रति संलग्न करें)
06. इकाई का प्रकार (नवीन/विस्तार/
डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन)
07. इकाई के विद्युत संयोजन का भार, क्रमांक व :
दिनांक
08. वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक :
09. वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक :
तक किये गए संयंत्र व मशीनरी में पूंजी
निवेश की राशि (लाख रुपए में) (चार्टर्ड
इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट का प्रमाण पत्र
संलग्न करें)

10. इकाई के उत्पादों के नाम व वार्षिक क्षमता :

क्र.	उत्पाद का नाम	वार्षिक क्षमता

11. इकाई में प्राप्त रोजगार : कुल रोजगार -
 (पुष्टि हेतु प्रामाणिक दस्तावेज
 संलग्न करें) कुल रोजगार में से म. प्र. के स्थाई
 निवासी को प्रदत्त रोजगार -
 (i) कुल -
 (ii) अजा -
 (iii) अजजा -
 (iv) अन्य पिछड़ा वर्ग -
12. जीएसटी पोर्टल अनुसार इकाई द्वारा विगत :
 माह में किया गया विक्रय (छायाप्रति संलग्न
 करें)
13. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुमति/ :
 अनापति प्रमाण पत्र/ पंजीयन प्रमाण पत्र
 (यदि लागू हों, तो)
14. चाही गई सहायता का विवरण
- (अ) गुणवत्ता प्रमाणीकरण के लिये प्रतिपूर्ति (नियम-7)
- [क] (i) आईएसओ/बीआयएस/बीईई :
 प्रमाणीकरण की
 अभिप्रमाणित प्रति (छायाप्रति
 संलग्न करें)
- (ii) उक्त प्रमाणीकरण प्राप्त करने :
 के लिये किये गये व्यय
 (दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति
 संलग्न करें)

- [ख] (i) जेड (ZED) प्रमाणन की :
अभिप्रमाणित प्रति (छायाप्रति संलग्न करें)
- (ii) उक्त प्रमाणीकरण प्राप्त करने : 1. कुल व्यय
के लिये किये गये व्यय एवं 2. भारत सरकार से प्राप्त
भारत सरकार से प्राप्त सहायता
सहायता (दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)
- [ग] (i) निर्यात के लिए गुणवत्ता :
प्रमाणन (यूएसए/यूरोपियन यूनियन/OECD के अन्य सदस्य देशों में निर्यात करने हेतु) की अभिप्रमाणित प्रति (छायाप्रति संलग्न करें)
- (ii) उक्त प्रमाणीकरण प्राप्त करने :
के लिये किये गये व्यय (दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)
- (iii) इकाई द्वारा यूएसए/यूरोपियन यूनियन/OECD के अन्य सदस्य देशों में निर्यात प्रारंभ करने संबंधी जानकारी (संबंधित दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न करें)

[घ] (i) निर्यात के लिए डब्ल्यूएचओ :
जीएमपी या यू.एस.-
एफ.डी.ए. प्रमाणन की
अभिप्रमाणित प्रति (छायाप्रति
संलग्न करें) (फार्मास्यूटिकल
इकाई हेतु लागू)

(ii) उक्त प्रमाणीकरण प्राप्त करने :
के लिये सुविधाओं का सृजन
करने में किया गया व्यय
(दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति
संलग्न करें)

(ब) पेटेंट/आईपीआर के लिए प्रतिपूर्ति (नियम-8)

(i) पेटेंट/आईपीआरका संक्षिप्त :
विवरण

(ii) पेटेंट/आईपीआर प्राप्त करने के : निर्धारित शुल्क
लिये किये गये व्यय (व्यय को अनुसंधान एवं शोध पर व्यय
प्रमाणित करने वाले दस्तावेज की
प्रमाणित प्रति संलग्न करें) सलाह/सेवा पर व्यय

(iii) इकाई के मुख्यालय का पता :

15. बिंदु 14 में उल्लेखित सहायता अन्तर्गत पूर्व में :
कुल स्वीकृत राशि एवं उसका विवरण

कृपया "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019" अंतर्गत उक्त सहायता(ओं) को स्वीकृत करने का कष्ट करें। स्वीकृति की दशा में अनुदान वितरण के लिये इकाई के बैंक खाते, बैंक व शाखा का नाम, IFSC कोड संबंधी जानकारी संलग्न है।

संलग्न :-

दिनांक :-

स्थान :-

आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति

हस्ताक्षर

नाम.....

पद.....

(सील)

नोट- जिस सहायता के लिये आवेदन नहीं किया जाना हो, उसमें 'लागू नहीं' अंकित किया जावे।

परिशिष्ट-4

**"मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019" अंतर्गत अपशिष्ट प्रबंधन
प्रणाली की स्थापना हेतु सहायता के लिये आवेदन का प्रारूप**

प्रति,

महाप्रबंधक,
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,
....., म.प्र.]

विषय:- "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019" अंतर्गत अपशिष्ट प्रबंधन
प्रणाली की स्थापना हेतु सहायता उपलब्ध कराने बाबत।

मेरे/हमारे द्वारा जिला(मध्यप्रदेश) में विनिर्माण इकाई(यां) स्थापित
की गई है। "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019" अंतर्गत अपशिष्ट उपचार
संयंत्र/सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र के लिये सहायता (नियम 10) उपलब्ध कराने हेतु
इकाई(यों) का/के विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

- | | |
|----------------------------|--|
| 01. इकाई(यों) का/के नाम | : |
| 02. इकाई(यों) का कार्यस्थल | : |
| स्थान/नगर | |
| विकासखण्ड | |
| तहसील | |
| जिला | |
| 03. अ/ इकाई का प्रकार | : प्रोप्रायटरी/संस्था/पार्टनरशिप/कंपनी
(पार्टनरशिप डीड/मेमोरेण्डम ऑफ
एसोसिएशन/आर्टिकल की छायाप्रति
संलग्न करें) |

ब/ यदि इकाई प्रोप्रायटरी (पूर्ण :
स्वामित्व) है तो, इकाई स्वामी का
नाम

04. एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत :
उद्योग आधार ज्ञापन फाइल करने पर
प्राप्त अभिस्वीकृति का क्रमांक व दिनांक
(छायाप्रति(यां) संलग्न करें)
05. जीएसटी अंतर्गत पंजीयन का क्रमांक व :
दिनांक (छायाप्रति(यां) संलग्न करें)
06. इकाई(यों) का/के प्रकार :
(नवीन/विस्तार/
डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन)
07. इकाई(यों) का/के विद्युत संयोजन का :
भार, क्रमांक व दिनांक
08. इकाई(यों) का/के वाणिज्यिक उत्पादन :
प्रारंभ करने का दिनांक
09. इकाई(यों) का/के वाणिज्यिक उत्पादन :
प्रारंभ करने के दिनांक तक किये गए
संयंत्र व मशीनरी में पूंजी निवेश की
राशि (लाख रूपए में) (चार्टर्ड
इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेंट का प्रमाण
पत्र संलग्न करें)
10. इकाई(यों) के उत्पादों के नाम व वार्षिक :
क्षमता

क्र.	उत्पाद का नाम	वार्षिक क्षमता

11. इकाई(यों) में प्राप्त रोजगार
(पुष्टि हेतु प्रामाणिक दस्तावेज
संलग्न करें)

: कुल रोजगार -

कुल रोजगार में से म. प्र. के स्थाई
निवासी को प्रदत्त रोजगार -

- (i) कुल -
(ii) अजा -
(iii) अजजा -
(iv) अन्य पिछड़ा वर्ग -

12. जीएसटी पोर्टल अनुसार इकाई द्वारा :
विगत माह में किया गया विक्रय
(छायाप्रति संलग्न करें)
13. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुमति/ :
अनापति प्रमाण पत्र/ पंजीयन प्रमाण
पत्र (यदि लागू हों, तो)

14. चाही गई सहायता का विवरण

- (i) अपशिष्ट उपचार संयंत्र/सार्वजनिक :
अपशिष्ट उपचार संयंत्र की स्थापना
में किये गये व्यय की चार्टर्ड
इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा
प्रमाणित मदवार राशि (प्रमाण पत्र
संलग्न करें)

(राशि लाख रुपये में)

क्र.	विवरण	राशि
1		
2		
3		
योग		

- (ii) स्थापित किये गये अपशिष्ट :
उपचार संयंत्र/सार्वजनिक अपशिष्ट
उपचार संयंत्र का संक्षिप्त विवरण,
उपयोगिता सहित (प्रदूषण नियंत्रण
मण्डल/ औद्योगिक स्वास्थ्य एवं

सुरक्षा संचालनालय का प्रमाण पत्र
संलग्न करें)

- (iii) सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र :
के प्रकरण में समूह गठन संबंधी
दस्तावेज/एग्रीमेंट का विवरण
(अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें)

कृपया "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019" अंतर्गत उक्त सहायता को स्वीकृत करने का कष्ट करें। स्वीकृति की दशा में अनुदान वितरण के लिये इकाई/समूह के बैंक खाते, बैंक व शाखा का नाम, IFSC कोड संबंधी जानकारी संलग्न है।

संलग्न :-

दिनांक :-

स्थान :-

आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति

हस्ताक्षर

नाम.....

पद.....

(सील)

नोट- जिस सहायता के लिये आवेदन नहीं किया जाना हो, उसमें 'लागू नहीं' अंकित किया जावे।

परिशिष्ट-5

**निजी औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/विकास
करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन का प्रारूप**

प्रति,

उद्योग आयुक्त,
मध्यप्रदेश।

विषय:- निजी औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/विकास करने की अनुमति प्रदान करने बाबत।

मेरे/हमारे द्वारा जिला (मध्यप्रदेश) में निजी औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/विकास किया जाना प्रस्तावित है। "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019" (नियम 11) अंतर्गत उक्त क्षेत्र की स्थापना/विकास करने की अनुमति बाबत विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

01. एजेंसी/संस्था/निवेशक का नाम :

02. सम्पर्क का पता :

दूरभाष
फैक्स
ई-मेल

03. पंजीकृत कार्यालय का पता :

दूरभाष
फैक्स
ई-मेल

04. औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर का स्थल :
स्थान/नगर
विकासखण्ड
तहसील
जिला
05. औद्योगिक क्षेत्र का क्षेत्रफल (एकड़ में) / :
बहुमंजिला औद्योगिक परिसर का कारपेट
क्षेत्र (वर्ग फीट में)
(क्षेत्रफल/कारपेट क्षेत्र को प्रमाणित
करने वाले दस्तावेज की प्रती)
06. औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर :
के स्वामी/लीजधारक का नाम
(दस्तावेज संलग्न करें)
07. औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर में :
प्रस्तावित उद्योगों के नाम (न्यूनतम पांच)
08. औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर :
की स्थापना/विकास में किये जाने वाले
प्रस्तावित निवेश का संक्षिप्त विवरण
(नक्शा व प्लान ले-आउट संलग्न करें)
09. औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर :
की स्थापना/विकास के पूर्ण होने की
प्रस्तावित दिनांक
(चरणबद्ध समयसीमा संलग्न करें)

कृपया औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना/विकास करने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट
करें। औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना/विकास हेतु राज्य शासन के अन्य विभागों से अनुमतियां
(आवश्यक होने पर) मेरे/हमारे द्वारा प्राप्त की जाएगी।

संलग्न :-

दिनांक :-

स्थान :-

आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति

हस्ताक्षर

नाम.....

पद.....

(सील)

परिशिष्ट-6

"मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019" अंतर्गत निजी औद्योगिक क्षेत्र/ बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना हेतु सहायता बाबत् आवेदन का प्रारूप

प्रति,

महाप्रबंधक,
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,
....., म.प्र.।

विषय:- "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019" अंतर्गत निजी औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना हेतु सहायता उपलब्ध कराने बाबत्।

मेरे/हमारे द्वारा जिला(मध्यप्रदेश) में निजी औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना की गई है। "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019" अंतर्गत की स्थापना हेतु सहायता (नियम 11) उपलब्ध कराने हेतु विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

01. एजेन्सी/संस्था/निवेशक का नाम :
(निजी औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर के स्वामित्व का प्रमाण संलग्न करें)

02. सम्पर्क का पता :

दूरभाष

ई-मेल

03. पंजीकृत कार्यालय का पता :
दूरभाष
ई-मेल
04. निजी औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक :
परिसर का स्थल का पूर्ण पता
05. औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर :
के स्वामी/लीजधारक का नाम (दस्तावेज
संलग्न करें)
06. निजी औद्योगिक क्षेत्र का क्षेत्रफल (एकड़ में)/ :
बहुमंजिला औद्योगिक परिसर का कारपेट क्षेत्र
(वर्ग फीट में) (क्षेत्रफल/कारपेट क्षेत्र को
प्रमाणित करने वाले दस्तावेज सहित)
07. निजी औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक :
परिसर में स्थापित उद्योगों के नाम -
न्यूनतम पांच (स्थापना को प्रमाणित करने
वाले दस्तावेज संलग्न)
08. उद्योग आयुक्त, म. प्र. द्वारा निजी औद्योगिक :
क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर को
स्थापित/विकसित करने हेतु प्रदाय अनुमति
की दिनांक (छायाप्रति संलग्न करें)
09. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निजी औद्योगिक :
क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर को
स्थापित/विकसित करने हेतु बढ़ाई गई समय

सीमा का विवरण, यदि कोई हो तो (आदेश की प्रति संलग्न करें)

10. औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर :
की स्थापना/विकास के पूर्ण होने की दिनांक
11. चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा :
अधोसंरचना विकास में किया गया प्रमाणित व्यय (व्यय संबंधी प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नक्शा व प्लान ले-आउट संलग्न करें)
12. औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर :
विकासित करने हेतु प्राप्त आवश्यक अनुमोदनाएं (छायाप्रति संलग्न करें)

कृपया "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019" अंतर्गत उक्त सहायता को स्वीकृत करने का कष्ट करें। स्वीकृति की दशा में अनुदान वितरण के लिये एजेन्सी के बैंक खाते, बैंक व शाखा का नाम, IFSC कोड संबंधी जानकारी संलग्न है।

संलग्न :-

दिनांक :-

स्थान :-

आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति

हस्ताक्षर

नाम.....

पद.....

(सील)

परिशिष्ट-7

**निजी भूमि पर कार्यरत एमएसएमई के क्लस्टर को सुदृढ़ बनाने के लिए
औद्योगिक अधोसंरचना के विकास करने की अनुमति
प्राप्त करने हेतु आवेदन का प्रारूप**

प्रति,

उद्योग आयुक्त,
मध्यप्रदेश।

विषय:- निजी भूमि पर कार्यरत एमएसएमई के क्लस्टर को सुदृढ़ बनाने के लिए
औद्योगिक अधोसंरचना के विकास करने की अनुमति प्रदान करने बाबत।

मेरे/हमारे द्वारा जिला (मध्यप्रदेश) में स्थापित एमएसएमई क्लस्टर
में औद्योगिक अधोसंरचना का विकास किया जाना प्रस्तावित है। "मध्यप्रदेश एमएसएमई
प्रोत्साहन योजना 2019" (नियम 12) अंतर्गत उक्त क्षेत्र में विकास कार्य करने की अनुमति
बाबत विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

01. एजेंसी/संस्था/निवेशक का नाम :

02. सम्पर्क का पता :

दूरभाष
फैक्स
ई-मेल

03. पंजीकृत कार्यालय का पता :

दूरभाष
फैक्स
ई-मेल

04. एमएसएमई क्लस्टर का पूर्ण पता:
(विकासखण्ड, तहसील व जिला सहित)
05. एमएसएमई क्लस्टर में अलग-अलग :
स्वामित्व की भूमि पर स्थापित इकाईयां
(कम से कम 10 की सूची संलग्न करें)
06. एमएसएमई क्लस्टर के औद्योगिक संघ :
का नाम (दस्तावेज संलग्न करें)
07. विकसित की जाने वाली अधोसंरचना का :
विवरण एवं उसकी उपयोगिता (न्यूनतम
पांच इकाईयों की अनुशंसा के साथ
जानकारी संलग्न करें)
08. अधोसंरचना विकास हेतु एजेंसी के चयन संबंधी :
औद्योगिक संघ का निर्णय (छायाप्रति संलग्न करें)
09. अधोसंरचना विकास कार्य के पूर्ण होने की :
प्रस्तावित दिनांक
(चरणबद्ध समयसीमा संलग्न करें)

कृपया एमएसएमई क्लस्टर में उपरोक्तानुसार औद्योगिक अधोसंरचना के विकास करने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें। अधोसंरचना के विकास हेतु राज्य शासन के अन्य विभागों से अनुमतियां (आवश्यक होने पर) मेरे/हमारे द्वारा प्राप्त की जाएगी।

संलग्न :-

दिनांक :-

स्थान :-

आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति

हस्ताक्षर

नाम.....

पद.....

(सील)

परिशिष्ट-8

**"मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019" अंतर्गत निजी भूमि पर
कार्यरत एमएसएमई के क्लस्टर में औद्योगिक अधोसंरचना के विकास हेतु
सहायता बाबत आवेदन का प्रारूप**

प्रति,

महाप्रबंधक,
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,
....., म.प्र.।

विषय:- "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019" अंतर्गत निजी भूमि पर
कार्यरत एमएसएमई के क्लस्टर को सुदृढ़ बनाने के लिए औद्योगिक अधोसंरचना
के विकास हेतु सहायता उपलब्ध कराने बाबत।

मेरे/हमारे द्वारा जिला(मध्यप्रदेश) में स्थित निजी भूमि पर
कार्यरत एमएसएमई के क्लस्टर को सुदृढ़ बनाने के लिए औद्योगिक अधोसंरचना का विकास
किया गया है। "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019" अंतर्गत निजी भूमि पर
कार्यरत एमएसएमई के क्लस्टर को सुदृढ़ बनाने के लिए औद्योगिक अधोसंरचना के विकास
हेतु सहायता (नियम 12) उपलब्ध कराने बाबत विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

01. एजेन्सी का नाम :
(एजेन्सी के चयन संबंधी औद्योगिक संघ के
निर्णय की छायाप्रति संलग्न करें)

02. सम्पर्क का पता :
दूरभाष
ई-मेल

03. पंजीकृत कार्यालय का पता :
दूरभाष
ई-मेल
04. सार्वजनिक औद्योगिक क्षेत्र का पूर्ण पता :
(विकासखण्ड, तहसील व जिला सहित)
05. एमएसएमई क्लस्टर के औद्योगिक संघ का :
नाम (दस्तावेज संलग्न करें)
06. विकसित की गई अधोसंरचना का विवरण एवं :
उसकी उपयोगिता (विवरण संलग्न करें)
07. उद्योग आयुक्त, म. प्र. द्वारा अधोसंरचना :
विकसित करने हेतु प्रदाय अनुमति की दिनांक
(छायाप्रति संलग्न करें)
08. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधोसंरचना विकसित :
करने हेतु बढ़ाई गई समय सीमा का विवरण,
यदि कोई हो तो (आदेश की प्रति संलग्न करें)
09. औद्योगिक अधोसंरचना विकास कार्य के पूर्ण :
होने की दिनांक (विकसित अधोसंरचना को
प्रमाणित करने वाला दस्तावेज संलग्न करें)
10. चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा :
अधोसंरचना विकास में किया गया प्रमाणित
व्यय (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
11. विकसित अधोसंरचना हेतु संबंधित :
एमएसएमई क्लस्टर के औद्योगिक संघ का
संतुष्टि संबंधी प्रमाण (प्रमाण पत्र संलग्न
करें)
12. औद्योगिक अधोसंरचना विकसित करने हेतु :
प्राप्त आवश्यक अनुमतियां (छायाप्रति संलग्न
करें)

कृपया "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019" अंतर्गत उक्त सहायता को स्वीकृत करने का कष्ट करें। स्वीकृति की दशा में अनुदान वितरण के लिये एजेन्सी के बैंक खाते, बैंक व शाखा का नाम, IFSC कोड संबंधी जानकारी संलग्न है।

संलग्न :-

दिनांक :-

स्थान :-

आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति

हस्ताक्षर

नाम.....

पद.....

(सील)

परिशिष्ट-9

**"मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019" अंतर्गत ऊर्जा लेखा परीक्षा
(Audit) के लिए प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन का प्रारूप**

प्रति,

महाप्रबंधक,
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,
....., म.प्र.।

विषय:- "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019" अंतर्गत ऊर्जा लेखा परीक्षा
(Audit) के लिए प्रतिपूर्ति उपलब्ध कराने हेतु।

मेरे/हमारे द्वारा जिला(मध्यप्रदेश) में विनिर्माण इकाई स्थापित की गई है। "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019" अंतर्गत ऊर्जा लेखा परीक्षा (Audit) के लिए प्रतिपूर्ति (नियम 13) उपलब्ध कराने हेतु इकाई का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

- | | |
|-----------------------|--|
| 01. इकाई का नाम | : |
| 02. इकाई का कार्यस्थल | : |
| स्थान/नगर | |
| विकासखण्ड | |
| तहसील | |
| जिला | |
| 03. इकाई का प्रकार | : प्रोप्रायटरी/संस्था/पार्टनरशिप/कंपनी
(पार्टनरशिप डीड/मेमोरेण्डम ऑफ
एसोसिएशन/आर्टिकल की छायाप्रति
संलग्न करें) |

04. एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत उद्योग :
आधार ज्ञापन फाइल करने पर प्राप्त
अभिस्वीकृति का क्रमांक व दिनांक
(छायाप्रति संलग्न करें)

05. जीएसटी अंतर्गत पंजीयन का क्रमांक व :
दिनांक (छायाप्रति संलग्न करें)

06. इकाई का प्रकार (नवीन/विस्तार/ :
डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन)

07. इकाई के विद्युत संयोजन का भार, क्रमांक व :
दिनांक

08. वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक :

09. वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक :
तक किये गए संयंत्र व मशीनरी में पूंजी
निवेश की राशि (लाख रूपए में)

10. इकाई के उत्पादों के नाम व वार्षिक क्षमता :

क्र.	उत्पाद का नाम	वार्षिक क्षमता

11. इकाई में प्राप्त रोजगार :
(पुष्टि हेतु प्रामाणिक दस्तावेज
संलग्न करें)

: कुल रोजगार -

कुल रोजगार में से म. प्र. के स्थाई
निवासी को प्रदत्त रोजगार -

(i) कुल -

(ii) अजा -

(iii) अजजा -

(iv) अन्य पिछड़ा वर्ग -

12. जीएसटी पोर्टल अनुसार इकाई द्वारा विगत :
माह में किया गया विक्रय (छायाप्रति संलग्न
करें)

13. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुमति/ :
अनापति प्रमाण पत्र/ पंजीयन प्रमाण पत्र
(यदि लागू हों, तो)

14. ऊर्जा लेखा परीक्षा हेतु अधिकृत एजेन्सी द्वारा :
की गई लेखा परीक्षा की दिनांक
(लेखा परीक्षा की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें)
15. ऊर्जा लेखा परीक्षा में हुआ व्यय :
(व्यय को प्रमाणित करने वाले दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न करें)
16. ऊर्जा लेखा परीक्षा में सुझाये गये उपकरण :
एवं मशीनरी के क्रय में हुआ व्यय (चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र/मूल्यांकन की छायाप्रति संलग्न करें)
17. उक्त बिंदु 16 में उल्लेखित उपकरण एवं :
मशीनरी के क्रय से ऊर्जा में हुई बचत का विवरण (दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न करें)

कृपया "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019" अंतर्गत उक्त सहायता को स्वीकृत करने का कष्ट करें। स्वीकृति की दशा में अनुदान वितरण के लिये इकाई के बैंक खाते, बैंक व शाखा का नाम, IFSC कोड संबंधी जानकारी संलग्न है।

संलग्न :-

दिनांक :-

स्थान :-

आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति

हस्ताक्षर

नाम.....

पद.....

(सील)

नोट- जिस सहायता के लिये आवेदन नहीं किया जाना हो, उसमें 'लागू नहीं' अंकित किया जावे।

परिशिष्ट-10

**"मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019" अंतर्गत पॉवरलूम के
उन्नयन हेतु सहायता के लिये आवेदन का प्रारूप**

प्रति,

महाप्रबंधक,

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,

....., म.प्र.।

विषय:- "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019" अंतर्गत पॉवरलूम उन्नयन के लिये सहायता उपलब्ध कराने हेतु।

मेरे/हमारे द्वारा जिला(मध्यप्रदेश) में पॉवरलूम इकाई स्थापित की गई है और "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019" अंतर्गत उक्त उन्नयन हेतु सहायता (नियम 14) उपलब्ध कराने बाबत पॉवरलूम इकाई का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

- | | |
|-----------------------|--|
| 01. इकाई का नाम | : |
| 02. इकाई का कार्यस्थल | : |
| स्थान/नगर | |
| विकासखण्ड | |
| तहसील | |
| जिला | |
| 03. इकाई का प्रकार | : प्रोप्रायटरी/संस्था/पार्टनरशिप/कंपनी
(पार्टनरशिप डीड/मेमोरेण्डम ऑफ
एसोसिएशन/आर्टिकल की छायाप्रति
संलग्न करें) |

04. एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत उद्योग :
आधार ज्ञापन फाइल करने पर प्राप्त
अभिस्वीकृति का क्रमांक व दिनांक
(छायाप्रति संलग्न करें)
05. जीएसटी अंतर्गत पंजीयन की छायाप्रति (यदि :
जीएसटी अधिनियम अंतर्गत पंजीयन अनिवार्य
हो, तो)
06. भारत सरकार का अन्य कोई पंजीयन (यदि :
हो तो) का क्रमांक व दिनांक (छायाप्रति
संलग्न करें)
07. इकाई के विद्युत संयोजन का भार, क्रमांक व :
दिनांक (नवीनतम विद्युत देयक की छायाप्रति
संलग्न करें)
08. वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक :
09. वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक :
तक किये गए संयंत्र एवं मशीनरी में पूंजी
निवेश की राशि (लाख रूपए में) (चार्टर्ड
इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट का प्रमाण पत्र
संलग्न करें)

10. इकाई के उत्पादों के नाम व वार्षिक क्षमता :

क्र.	उत्पाद का नाम	वार्षिक क्षमता

11. इकाई में प्राप्त कुल रोजगार : कुल रोजगार -
(पुष्टि हेतु प्रामाणिक दस्तावेज)

संलग्न करें)

कुल रोजगार में से म. प्र. के स्थाई
निवासी को प्रदत्त रोजगार -

- (i) कुल -
- (ii) अजा -
- (iii) अजजा -
- (iv) अन्य पिछड़ा वर्ग -

12. उन्नयन पूर्व पॉवरलूम का प्रकार एवं संख्या : प्लेन या सेमी ऑटोमेटिक -
कुल संख्या -

13. प्लेन/सेमी ऑटोमेटिक पॉवरलूम से आधुनिक :
शटललेस लूम में उन्नयन किये गये पॉवरलूम
की संख्या एवं उनमें हुआ व्यय
(चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा
प्रदत्त प्रमाण पत्र/मूल्यांकन संलग्न करें)

14. भारत सरकार की INSITU अपग्रेडेशन योजना :
के तहत परिवर्तित पॉवरलूमों की संख्या,
उन्नयन का प्रकार एवं प्राप्त सहायता (यदि
कोई हो, तो)

कृपया "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019" अंतर्गत उक्त सहायता को स्वीकृत
करने का कष्ट करें। स्वीकृति की दशा में अनुदान वितरण के लिये इकाई के बैंक खाते,
बैंक व शाखा का नाम, IFSC कोड संबंधी जानकारी संलग्न है।

संलग्न :-

दिनांक :-

स्थान :-

आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति

हस्ताक्षर

नाम.....

पद.....

(सील)

परिशिष्ट-11

**"मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019" अंतर्गत फार्मास्यूटिकल
इकाई द्वारा फार्मास्यूटिकल लैब की मशीनरी व उपकरण की स्थापना
हेतु सहायता के लिये आवेदन का प्रारूप**

प्रति,

महाप्रबंधक,
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,
....., म.प्र.।

विषय:- "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019" अंतर्गत फार्मास्यूटिकल लैब की मशीनरी व उपकरण की स्थापना हेतु सहायता उपलब्ध कराने बाबत।

मेरे/हमारे द्वारा जिला(मध्यप्रदेश) में विनिर्माण इकाई स्थापित की गई है। "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019" अंतर्गत फार्मास्यूटिकल लैब की मशीनरी व उपकरण की स्थापना के लिये सहायता (नियम 10) उपलब्ध कराने हेतु इकाई का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

- | | |
|----------------------------|--|
| 01. इकाई का नाम | : |
| 02. इकाई(यों) का कार्यस्थल | : |
| स्थान/नगर | |
| विकासखण्ड | |
| तहसील | |
| जिला | |
| 03. अ/ इकाई का प्रकार | : प्रोप्रायटरी/संस्था/पार्टनरशिप/कंपनी
(पार्टनरशिप डीड/मेमोरेण्डम ऑफ
एसोसिएशन/आर्टिकल की छायाप्रति
संलग्न करें) |

ब/ यदि इकाई प्रोप्रायटरी (पूर्ण :
स्वामित्व) है तो, इकाई स्वामी का
नाम

04. एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत :
उद्योग आधार जापन फाइल करने पर
प्राप्त अभिस्वीकृति का क्रमांक व दिनांक
(छायाप्रति संलग्न करें)

05. जीएसटी अंतर्गत पंजीयन का क्रमांक व :
दिनांक (छायाप्रति संलग्न करें)

06. इकाई का प्रकार (नवीन/विस्तार/ :
डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन)

07. इकाई का विद्युत संयोजन का भार, :
क्रमांक व दिनांक

08. इकाई का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ :
करने का दिनांक

09. वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के :
दिनांक तक किये गए संयंत्र व मशीनरी
में पूंजी निवेश की राशि (लाख रुपये में)
(चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट का
प्रमाण पत्र संलग्न करें)

10. इकाई के उत्पादों के नाम व वार्षिक :
क्षमता

क्र.	उत्पाद का नाम	वार्षिक क्षमता

11. इकाई में प्राप्त रोजगार :
(पुष्टि हेतु प्रामाणिक दस्तावेज
संलग्न करें)

: कुल रोजगार -

कुल रोजगार में से म. प्र. के स्थाई
निवासी को प्रदत्त रोजगार -

(i) कुल -

(ii) अजा -

(iii) अजजा -

(iv) अन्य पिछड़ा वर्ग -

12. जीएसटी पोर्टल अनुसार इकाई द्वारा :
विगत माह में किया गया विक्रय
(छायाप्रति संलग्न करें)

13. फार्मास्यूटिकल इकाई की स्थापना हेतु :
सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुमति/
अनापत्ति प्रमाण पत्र/ पंजीयन प्रमाण
पत्र (यदि लागू हों, तो)

14. फार्मास्यूटिकल लैब की मशीनरी व :
उपकरण की स्थापना में हुये व्यय की
चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा
प्रमाणित मदवार राशि (प्रमाण पत्र
संलग्न करें)

(राशि लाख रुपये में)

क्र.	विवरण	राशि
1		
2		
3		
योग		

15. फार्मास्यूटिकल लैब के परिप्रेक्ष्य में :
वांछित पंजीयन/अनुमति/प्रमाण-पत्र की
जानकारी
(अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करे)

16. फार्मास्यूटिकल लैब की उपयोगिता :
संबंधी विवरण (दस्तावेज संलग्न करें)

कृपया "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019" अंतर्गत उक्त सहायता को स्वीकृत करने का कष्ट करें। स्वीकृति की दशा में अनुदान वितरण के लिये इकाई/समूह के बैंक खाते, बैंक व शाखा का नाम, IFSC कोड संबंधी जानकारी संलग्न है।

संलग्न :-

दिनांक :-

स्थान :-

आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति

हस्ताक्षर

नाम.....

पद.....

(सील)

परिशिष्ट-12

**"मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019" अंतर्गत रेडीमेड गारमेंट
एवं मेडअप्स का निर्माण करने वाली इकाईयों को
वेतन अनुदान हेतु आवेदन का प्रारूप**

प्रति,

महाप्रबंधक,
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,
....., म.प्र।

विषय:- "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019" अंतर्गत रेडीमेड गारमेंट एवं मेडअप्स का निर्माण करने वाली इकाईयों को वेतन अनुदान उपलब्ध कराने हेतु।

मेरे/हमारे द्वारा जिला(मध्यप्रदेश) में विनिर्माण इकाई स्थापित की गई है। "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019" अंतर्गत रेडीमेड गारमेंट एवं मेडअप्स का निर्माण करने वाली इकाईयों को वेतन अनुदान (नियम 16) उपलब्ध कराने हेतु इकाई का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

- | | |
|-----------------------|---|
| 01. इकाई का नाम | : |
| 02. इकाई का कार्यस्थल | : |
| स्थान/नगर | |
| विकासखण्ड | |
| तहसील | |
| जिला | |

03. इकाई का प्रकार : प्रोप्रायटरी/संस्था/पार्टनरशिप/कंपनी
(पार्टनरशिप डीड/मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन/आर्टिकल की छायाप्रति संलग्न करें)
04. एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत :
उद्योग आधार ज्ञापन फाइल करने पर प्राप्त अभिस्वीकृति का क्रमांक व दिनांक (छायाप्रति संलग्न करें)
05. जीएसटी अंतर्गत पंजीयन का क्रमांक व दिनांक (छायाप्रति संलग्न करें)
06. इकाई का प्रकार (नवीन/विस्तार/ :
डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन)
07. इकाई के विद्युत संयोजन का भार, क्रमांक :
व दिनांक
08. वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का :
दिनांक
09. इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ :
करने के दिनांक तक किये गए संयंत्र व मशीनरी में पूंजी निवेश की राशि (लाख रूपए में) (चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट का प्रमाण पत्र संलग्न करें)
10. इकाई के उत्पादों के नाम व वार्षिक क्षमता :
- | क्र. | उत्पाद का नाम | वार्षिक क्षमता |
|------|---------------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
11. इकाई में प्राप्त रोजगार : कुल रोजगार -
(पुष्टि हेतु प्रामाणिक दस्तावेज संलग्न करें) कुल नियमित कर्मचारी -
कुल रोजगार में से म. प्र. के स्थाई निवासी को प्रदत्त रोजगार -
(i) कुल -
(ii) अजा -
(iii) अजजा -
(iv) अन्य पिछड़ा वर्ग -
12. जीएसटी पोर्टल अनुसार इकाई द्वारा :
विगत माह में किया गया विक्रय (छायाप्रति संलग्न करें)
13. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुमति/ :
अनापत्ति प्रमाण पत्र/ पंजीयन प्रमाण पत्र (यदि लागू हों, तो)

14. विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन :
होने पर

विवरण	विस्तार/ डायवर्सिफिकेशन/ तकनीकी उन्नयन के पूर्व	विस्तार/ डायवर्सिफिकेशन/ तकनीकी उन्नयन अंतर्गत	योग (विस्तार/ डायवर्सिफिकेशन/ तकनीकी उन्नयन पश्चात्)
संयंत्र एवं मशीनरी में पूंजी निवेश (लाख रुपये में)			
रोजगार			
उत्पाद की वार्षिक क्षमता			
(i)(उत्पाद).....			
(ii)(उत्पाद).....			

15. इकाई में कार्यरत नियमित कर्मचारी, जो म. :
प्र. के स्थाई निवासी है, को दिये गये वेतन
की राशि एवं ऐसे कर्मचारियों की संख्या
(इकाई की उत्पादन दिनांक से प्रथम छः माह
की नियमित कर्मचारियों को प्रदत्त वेतन की
माहवार व नामवार सूची संलग्न करें एवं
प्रदत्त वेतन एवं नियमित कर्मचारी संबंधी
प्रामाणिक दस्तावेज भी संलग्न करें)

कृपया "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019" अंतर्गत उक्त सहायता को स्वीकृत करने का कष्ट करें। स्वीकृति की दशा में अनुदान वितरण के लिये इकाई/समूह के बैंक खाते, बैंक व शाखा का नाम, IFSC कोड संबंधी जानकारी संलग्न है

संलग्न :-

दिनांक :-

स्थान :-

आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति

हस्ताक्षर

नाम.....

पद.....

(सील)

परिशिष्ट-13

**"मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019" अंतर्गत दिए जाने वाला शपथ पत्र
(निर्धारित शुल्क के स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित)**

मैं/हम एतद् द्वारा यह शपथपूर्वक कथन करता हूँ/करते हैं कि :-

1. मेरे/हमारे द्वारा जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019" अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन दिनांक में दी गई जानकारी सत्य है।
2. मैं/हम राज्य शासन अथवा राज्य शासन के किसी उपक्रम की घोषित चूककर्ता/अशोधी नहीं हूँ/हैं।
3. मैं/हम यह वचन देता/देते हूँ/हैं कि यदि उपरोक्त उल्लेखित योजना में उल्लेखित किसी भी शर्त/प्रावधान का मेरे/हमारे द्वारा उल्लंघन किया जाता है, तो विभाग को नियमानुसार सुविधा को निरस्त करने/वापस लेने का पूर्ण अधिकार होगा तथा मैं/हम 12 प्रतिशत ब्याज दर से सुविधा/सहायता राशि वापस करने के लिये उत्तरदायी रहूँगा/रहेंगे।
4. मैं/हम इकाई/उन्नयन किये गये पॉवरलूमों/औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर/अपशिष्ट उपचार संयंत्र/सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र/एमएसएमई क्लस्टर में निर्मित औद्योगिक अधोसंरचना को प्रारंभ/उन्नयन दिनांक से कम से कम 4 वर्षों तक या सुविधा अवधि जो भी बाद में हो, उत्पादनरत/कार्यरत रखूँगा/रखेंगे।
5. मेरी/हमारी इकाई में कुल रोजगार का न्यूनतम 70 प्रतिशत मध्यप्रदेश के स्थाई निवासियों को प्रदान किया जा रहा है और उक्त 70% रोजगार में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को राज्य शासन द्वारा घोषित आरक्षण अनुसार प्रतिनिधित्व भी दिया जा रहा है।
6. मेरे/हमारे द्वारा इकाई हेतु मध्यप्रदेश की किसी अन्य नीति अंतर्गत अनुदान प्राप्त/ हेतु आवेदन नहीं किया गया है।

7. मेरे/हमारे द्वारा इकाई हेतु भारत सरकार से समान स्वरूप की योजनान्तर्गत प्राप्त सहायता/किये गये आवेदन (यदि कोई हों तो) की जानकारी आवेदन के साथ पृथक से संलग्न की गई है।
8. औद्योगिक परिसर तक विकसित की गई अधोसंरचना आवेदन में उल्लेखित इकाई हेतु विकसित की गई है तथा अच्छी गुणवत्ता की है। (यदि लागू हो तो)

या

स्थापित की गई अपशिष्ट उपचार संयंत्र/सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र आवेदन में उल्लेखित इकाई(यों) हेतु स्थापित किया गया है तथा मानकों के अनुरूप है। (यदि लागू हो तो)

या

एमएसएमई क्लस्टर में निर्मित अधोसंरचना अच्छी गुणवत्ता की है। (यदि लागू हो तो)

स्थान :-

दिनांक :-

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

नाम :-

(सील)

परिशिष्ट-14

**"मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019" अंतर्गत निर्यातक इकाई द्वारा
अतिरिक्त उद्योग विकास अनुदान के लिये आवेदन का प्रारूप**

प्रति,

महाप्रबंधक,
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,
....., म.प्र.।

विषय:- "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019" अंतर्गत निर्यातक इकाई के
लिये अतिरिक्त उद्योग विकास अनुदान सहायता उपलब्ध कराने हेतु।

मेरे/हमारे द्वारा जिला(मध्यप्रदेश) में विनिर्माण इकाई स्थापित की
गई है। "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019" अंतर्गत निर्यातक इकाई के लिये
अतिरिक्त उद्योग विकास अनुदान उपलब्ध कराने हेतु इकाई का विवरण निम्नानुसार है:-

01. इकाई का नाम :
02. इकाई का कार्यस्थल :
स्थान/नगर
विकासखण्ड
तहसील
जिला
03. बाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक :
04. जीएसटी अंतर्गत पंजीयन का क्रमांक व
दिनांक
05. स्वीकृत उद्योग विकास अनुदान की दिनांक :
व कुल राशि (आदेश की प्रति संलग्न करें)
06. इकाई द्वारा जिस अवधि (वर्ष) हेतु :
अतिरिक्त अनुदान चाहा गया है, उस वर्ष में
जीएसटी पोर्टल अनुसार इकाई द्वारा निर्मित
माल के विक्रय की कुल राशि (छायाप्रति
संलग्न करें)
07. इकाई द्वारा जिस अवधि (वर्ष) हेतु :
अतिरिक्त अनुदान चाहा गया है, उस वर्ष में
इकाई द्वारा किये गये कुल निर्यात की राशि
(संबंधित दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न
करें)

कृपया "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019" अंतर्गत अतिरिक्त उद्योग विकास
अनुदान को स्वीकृत करने का कष्ट करें।

संलग्न :-

दिनांक :-

स्थान :-

आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति

हस्ताक्षर

नाम.....

पद.....

(सील)

परिशिष्ट-15

**"मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति 2019" अंतर्गत बीमार इकाई द्वारा
राहत एवं अनुदान के लिये आवेदन का प्रारूप**

(तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जाय)

1. इकाई का नाम _____
 इकाई के कार्यस्थल का पता _____
 इकाई का पत्राचार का पता _____

मुख्य अधिकारी
 नाम _____
 पता _____

 दूरभाष क्र. (कार्या.) _____ (नि.) _____
 ई-मेल _____
2. वाणिज्यिक उत्पादन की दिनांक _____
3. लघु उद्योग पंजीयन/ ईएम पार्ट-2/ _____
 यू.ए.एम. क्रमांक एवं दिनांक _____
 और जारीकर्ता प्राधिकारी _____
 (संबंधित दस्तावेज की सत्यापित
 छायाप्रति संलग्न करें)
4. आवेदन शुल्क '1000.00' (एक हजार रुपये मात्र), की पावती संलग्न करें :
 चालान क्रमांक _____, दिनांक _____

5. निर्मित उत्पाद एवं उनकी वार्षिक क्षमता (कृपया शिफ्ट की संख्या का उल्लेख करें)

उत्पाद का नाम : _____

वार्षिक क्षमता : _____

6. विगत तीन वर्षों में इकाई प्रदर्शन (सी.ए./ऑडिटर द्वारा सत्यापित)

(वर्ष) (वर्ष) (वर्ष)
(_____) (_____) (_____)

- (i) उत्पादन :

(विगत तीन वर्षों में)

मात्रा : _____

मूल्य : _____

- (ii) विक्रय :

(विगत तीन वर्षों में)

मात्रा : _____

मूल्य : _____

- (iii) सकल लाभ/हानि _____

- (iv) निवल (नेट) लाभ/हानि _____

(कटौती एवं कर पश्चात)

- (v) संचित हानि _____

7. बैलेंस शीट (चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट/वैधानिक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित)

पूंजी के स्रोत

प्रदत्त पूंजी _____

रिजर्व एवं सरप्लस _____

टर्म लोन _____

जमा पूंजी _____

कोई अन्य ऋण/ _____
 असुरक्षित ऋण _____
 योग _____

8. घटायें
 देनदारियों _____
 प्रावधान _____
 नेट चालू अस्तियां _____
 निवेश, यदि कोई हो _____
 हानि _____
 योग _____

9. नेट मूल्य (worth)

	(वर्ष)	(वर्ष)	(वर्ष)
	(_____)	(_____)	(_____)
प्रदत्त पूंजी	_____	_____	_____
रिजर्व एवं सरप्लस	_____	_____	_____
(पूनर्मूल्यांकन को छोड़कर)			
योग	_____	_____	_____

10. लेनदारों द्वारा क्या कोई विधिक _____
 कार्यवाही प्रारंभ की गई है?
 यदि हाँ, तो कृपया विवरण दें _____

11. निवेश, यदि कोई हो तो, विवरण दें :
- (अ) कंपनियों में _____
- (ब) सावधि जमा _____
- (स) अन्य _____
12. सांविधिक देनदारी:
- (अ) वाणिज्यिक कर/वैट/जीएसटी _____
- (ब) विद्युत शुल्क _____
- (स) आबकारी शुल्क (आज तक) _____
- (द) भविष्य निधि (आज तक) _____
- (इ) ESI _____
- (फ) कोई अन्य देनदारियां _____
- (कृपया स्पष्ट करें)
13. (अ) यदि इकाई उत्पादनरत हो तो, कृपया _____
- माहवार उत्पादन एवं विगत एक वर्ष में _____
- विद्युत खपत (आखिरी विद्युत देयक की _____
- छायाप्रति संलग्न करें)
- (ब) पुनर्जीवन के लिये प्रमोटर का अंश _____
14. (अ) यदि इकाई बंद है, तो कृपया _____
- बंद होने की दिनांक एवं बंद _____
- होने का कारण बतायें _____
- (ब) क्या विद्युत कनेक्शन विच्छेद _____
- हुआ है?

(स) क्या श्रमिक/मजदूर की छटनी
की गई है? _____

(द) इकाई कैसे पुनर्जीवित की जाएगी?
इकाई को पुनः आरंभ करने के लिये
आवश्यक पूंजी की व्यवस्था कहां से
होगी? _____

(इ) इकाई को पुनर्जीवित करने के लिये
क्या नये प्रमोटर को शामिल करने
का प्रस्ताव है?, यदि हां, तो किन
शर्तों पर? _____

(फ) उत्पाद के विपणन की व्यवस्था _____

15. बैंक/वित्तीय संस्था/शासन के विभागों से प्रस्तावित सहायता/राहत :

स. क्र.	बैंक/वित्तीय संस्था/शासकीय विभाग का नाम	प्रस्तावित सहायता/राहत
1.	बैंक/MPFC (वित्तीय संस्था)	_____
2.	वाणिज्यिक कर विभाग	_____
3.	म. प्र. विद्युत वितरण कंपनी	_____
4.	कोई अन्य संस्था/विभाग	_____

16. पुनर्जीवन हेतु प्रस्तावित विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन का विवरण :
- (i) विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/ _____
तकनीकी उन्नयन में से किसके _____
द्वारा पुनर्जीवन किया जायेगा _____
- (ii) आयटम का नाम _____
- (iii) परियोजना लागत _____
- (iv) पूंजी के स्रोत _____
- (v) ऑयटम का पंजीयन, यदि कोई हो _____
- (vi) विनिर्माण प्रक्रिया _____
- (vii) कीमत सहित प्रस्तावित मशीनों _____
का विस्तृत लिस्ट _____
- (viii) उत्पादन में प्रस्तावित बढ़ोतरी एवं _____
लाभप्रदता _____
17. पुनर्जीवन पैकेज तैयार करने वाली बैंक _____
की शाखा का नाम व पता _____
(सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

नोट :-

आवेदन पूर्ववर्ती दो वर्षों के लिए लेखा परीक्षण खातों के साथ होना चाहिए। खातों के साथ लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों को पूरी तरह से निपटाया और अनुपालन किया जाना है। आवेदन एक प्रस्तावित पुनर्वास योजना के साथ होना चाहिए जिसमें, बैंक/वित्तीय संस्थान के ऋण और ब्याज की पूर्ण वापसी के साथ-साथ राज्य सरकार/वाणिज्यिक कर/वैट/जीएसटी के बकाया को चुकाने की भी व्यवस्था की गई हो। इस हेतु पृथक से जानकारी/प्रस्ताव संलग्न करें।

दिनांक :

स्थान :

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
(सील)

घोषणा

मैं, _____ एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि
उपरोक्त दी गई जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास से सही, पूर्ण एवं मेरे द्वारा दी गई है।

दिनांक :

स्थान :

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
(सील)

प्राधिकृत व्यक्ति :

घोषणा करने वाले व्यक्ति का नाम _____

धारित पद _____

इकाई का नाम _____

कार्यालय का पता _____

(सी.ए./ऑडिटर/बैंक शाखा प्रबंधक द्वारा सत्यापित)

नोट : पूर्णतः भरा हुआ आवेदन उद्योग आयुक्त. म. प्र., उद्योग संचालनालय, म. प्र.
भोपाल में प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

पर्यटन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 अक्टूबर 2019

क्र. एफ-10-05-2018-तैंतीस.—राज्य शासन, एतद्वारा, पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के अवसर निर्मित करने एवं पर्यटकों को विभिन्न अनुभवों सहित आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नवीन योजनाओं के प्रवर्तन हेतु विभागीय संक्षेपिका दिनांक 9 अक्टूबर 2019 के साथ परिशिष्ट 1, 2 एवं 3 पर संलग्न पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के अवसर निर्मित करने एवं पर्यटकों को विभिन्न अनुभवों सहित आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नवीन योजनाओं के प्रवर्तन को अनुमोदित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
फैज अहमद किदवई, सचिव.

परिशिष्ट-1

मध्यप्रदेश बेड एण्ड ब्रेकफ़ास्ट स्थापना (पंजीयन तथा नियमन)
योजना, 2019

विषय- मध्यप्रदेश बेड एण्ड ब्रेकफ़ास्ट स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना अंतर्गत पंजीकृत किये जाने वाले भवन को "इकाई" से संबोधित किया जायेगा, मध्यप्रदेश बेड एण्ड ब्रेकफ़ास्ट स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना अंतर्गत "इकाई" भूमि/भवन के स्वामी (पंजीकृत/लीजग्राहीता) को "संपत्तिधारक" से संबोधित किया जायेगा एवं मध्यप्रदेश बेड एण्ड ब्रेकफ़ास्ट स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना अंतर्गत "संपत्तिधारक" द्वारा "इकाई" की देखभाल करने हेतु अधिकृत व्यक्ति जो सदैव इकाई में निवासरत हो, को "केयर टेकर" से संबोधित किया जायेगा।

1. योजना का संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा लागू करना :-

1.1 यह योजना मध्यप्रदेश बेड एण्ड ब्रेकफ़ास्ट स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना 2019 कहलायेगी।

1.2 इस योजना का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश होगा।

1.3 यह योजना शासन द्वारा जारी शिर्षक से लागू होगी।

1.4 इस योजना का उद्देश्य -

(अ) देशी-विदेशी पर्यटकों को किरायायती दर्जे पर आवास एवं नाश्ता/भोजन आदि सुविधा प्रदाय करना।

(ब) देशी-विदेशी पर्यटकों को भारतीय संस्कृति एवं आतिथ्य से परिचित कराना।

(स) नागरिकों को अपने आवास में उपलब्ध अतिरिक्त क्षमता से आय अर्जन एवं रोजगार सृजन के अवसर प्रदान करना।

(द) स्थानीय स्तर पर पर्यटकों हेतु आवासीय सुविधाओं का विकास एवं अभिवृद्धि।

(इ) प्रदेश में निजी क्षेत्र के माध्यम से पर्यटक आवासीय सुविधाओं का विस्तार।

1.5 होटल, मोटल, गेस्ट हाउस आदि इस योजनांतर्गत पंजीकृत नहीं किए जायेंगे।

1.6 योजना संचालन के दिशा निर्देश जारी करने हेतु प्रबंध संचालक, म.प्र.टूरिज्म बोर्ड अधिकृत होंगे।

पंजीयन :-

2.1 इकाई में न्यूनतम 01 तथा अधिकतम 06 कक्ष(12 शैय्या) पर्यटक/ अतिथि रहवास के लिये उपलब्ध रहेंगे।

2.2 बेड एण्ड ब्रेकफ़ास्ट इकाई पंजीयन हेतु शुल्क रु. 2000/- एवं जीएसटी होगा।

2.3 इकाई पंजीयन परिशिष्ट 'एक' में निर्धारित मापदंड/ चेकलिस्ट के आधार पर किया जायेगा।

- 2.4 पंजीयन तीन (3) साल तक वैध रहेगा।
- 2.5 तीन वर्ष पश्चात पंजीयन नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र के साथ रु. 2000/- + जी.एस.टी. शुल्क एवं निर्धारित दस्तावेज, वैधता की अंतिम तिथि के तीन माह पूर्व जमा कर नवीनीकरण कराया जा सकेगा।
- 2.6 इस योजना अंतर्गत पंजीकरण कराने के इच्छुक संपत्तिधारक को, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड (जिसे आगे बोर्ड कहा जायेगा) के प्रबंध संचालक को निर्धारित प्रारूप 'अ' में पंजीयन फीस के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा। पंजीयन फीस का भुगतान डिमाण्ड ड्राफ्ट/ RTGS/ NEFT अथवा बैंकर्स चैक से करना होगा। डिमाण्ड ड्राफ्ट/ बैंकर्स चैक प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड, भोपाल के नाम पर बनाये जाये। आवेदन पत्र अमान्य होने पर यह फीस वापसी योग्य नहीं होगी। आवेदन के साथ चेक लिस्ट अनुसार जानकारी संलग्न करनी होगी।
- 2.7 इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत होने के लिये 'इकाई' को निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति करना आवश्यक होगा, अर्थात्-
- (1) यह कि इकाई विशुद्धतः आवासीय हो। इकाई स्वामी अथवा उसके द्वारा नियुक्त किया गया केयरटेकर (देखभाल करने वाला) भौतिक रूप से उसमें सतत निवासरत हो। इकाई में किचन का संचालन किया जाता हो।
 - (2) यह कि सम्पत्तिधारक/ केयरटेकर उसके आवासीय भवन के अधिकतम दो तिहाई शयन कक्षों को ही किराये पर दे सके। जिसकी संख्या कम से कम 01 तथा अधिकतम 06 होगी, जिसमें अधिकतम 12 शैय्या होंगी।
 - (3) यह कि इकाई में स्नानागार, शौचालय, जल, उर्जा/ विद्युत आपूर्ति, फर्नीचर आदि सुविधाएँ उपयुक्त एवं आरामदायक होगी। कक्षों में हवा आने- जाने के लिये खिड़की अथवा वेन्टीलेटर हो।
 - (4) यह कि परिसर अच्छी अवस्था में हो। परिसर में साफ-सफाई की उत्तम व्यवस्था हो। अग्नि सुरक्षा सहित अन्य सुरक्षा का पर्याप्त प्रबंध हो।
 - (5) किसी एक संपत्तिधारक द्वारा एक ही परिसर/ कॉलोनी/ भवन में पृथक-पृथक बेड एण्ड ब्रेकफ़ास्ट इकाईयों का पंजीयन नहीं कराया जा सकेगा।
 - (6) इकाई तक विधिवत पहुंच मार्ग हो एवं इकाई के आसपास कोई अस्वच्छ/ प्रदूषणकारी गतिविधि संचालित नहीं हो।
 - (7) अन्य कोई शर्तें जो राज्य सरकार या 'बोर्ड' द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जावें।
- 2.8 उप कंडिका (2.6) में प्राप्त आवेदन पत्रों पर प्रबंध संचालक, पंजीयन के निमित्त निरीक्षणकर्ता नियुक्त कर उसकी स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त करेगा।

- 2.9 परिसर का निरीक्षण करने पर पायी गयी कमियों को निर्धारित समयावधि में निरीक्षणकर्ता की संतुष्टि स्तर तक सुधार का अवसर आवेदक को दिया जायेगा। आवेदक द्वारा ऐसे पत्र के जारी होने के 60 दिवस में सुधार न कर पाने पर आवेदन अमान्य कर दिया जायेगा।
- 2.10 निरीक्षणकर्ता नियुक्ति के अधिकतम 15 दिवस में ऐसी जांच अथवा निरीक्षण जैसा कि वह उपयुक्त समझे करने के पश्चात, परिसर के पंजीयन की अर्हता के संबंध में अपना दृष्टिकोण तय करेगा एवं अपनी अनुशंसाएँ देते समय सम्पत्तिधारक द्वारा उपलब्ध करायी जा रही भोजन सुविधा एवं सेवाओं पर भी विचार करेगा।
- 2.11 निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्रबंध संचालक प्रतिवेदन से संतुष्ट होने पर अधिकतम 15 दिवस में इकाई का पंजीयन करने के लिए विहित प्रारूप 'ब' में प्रमाण पत्र जारी करेगा। यह प्रमाण पत्र 3 वर्ष के लिये वैध होगा, बशर्ते उसे पहले निरस्त न कर दिया जाये। इकाई के सफल संचालन पर पंजीयन का नवीनीकरण, विहित शुल्क अदा करने पर किया जा सकेगा।
- 2.12 'इकाई' के पंजीयन की संपूर्ण प्रक्रिया आवेदन प्राप्ति के 45 दिवस के भीतर पूर्ण की जायेगी तथा परिणाम से आवेदक को अवगत कराया जावेगा।
- 2.13 इस योजना के अंतर्गत स्थापित इकाईयों की एक डायरेक्ट्री विहित प्रारूप 'स' में संधारित की जायेगी।
- 2.14 पंजीयन प्रमाण पत्र की एक प्रति निकटस्थ पुलिस थाना प्रभारी को सूचनार्थ प्रेषित की जायेगी।
3. **योजना अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण कार्य :-**
- प्रबंध संचालक द्वारा अधिकृत प्राधिकारी अथवा योजना प्रभारी अधिकारी तथा एक मान्यक अशासकीय सदस्य द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों का पर्यवेक्षण अथवा निरीक्षण कार्य किया जायेगा। अशासकीय सदस्यों को मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा द्वितीय श्रेणी अधिकारियों हेतु निर्धारित यात्रा/आवास/भोजन भत्ते की पात्रता तथा रुपये एक हजार प्रतिदिवस के मान से मानदेय भुगतान योग्य होगा।
4. **इस योजना के अंतर्गत पंजीयन के लिए कोई 'इकाई' निर्हर होगी:-**
- (क) यदि सम्पत्तिधारक पर किसी आपराधिक मामले में चालान प्रस्तुत किया गया हो अथवा दंडित होकर जेल में निरुद्ध रहा हो, या
- (ख) यदि सम्पत्तिधारक/ केयरटेकर दिवालिया हो गया हो, या
- (ग) यदि इकाई का नाम इस योजना की कंडिका-9 के अधीन डायरेक्ट्री से हटा दिया गया हो।
5. **सम्पत्तिधारक का दायित्व होगा कि वह:-**
- 5.1 अतिथि/पर्यटक को स्वच्छ एवं सुविधाजनक आवास एवं नाश्ता (ब्रेकफास्ट) उपलब्ध कराये।

- 5.2 अतिथि के आगमन तथा प्रस्थान व उनके विवरण की विहित प्रारूप 'द' में एक पंजी संधारित करे, जो निरीक्षण के लिये सभी अवसरों पर उपलब्ध रहेगी। ऐसी पंजी प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में नवीनीकृत की जावेगी एवं उसे पाँच वर्ष तक सुरक्षित रखा जाना होगा।
 - 5.3 बेड एण्ड ब्रेकफास्ट इकाई में रुकने वाले अतिथियों का विवरण स्थानीय पुलिस को मासिक आधार पर प्रेषित करना होगा। विदेशी अतिथियों का ब्योरा स्थानीय पुलिस को उनके आगमन के 24 घंटे के अंदर देना होगा।
 - 5.4 इकाई में कार्यरत केयरटेकर/कर्मचारियों का सत्यापन स्थानीय पुलिस से कराया जाना होगा।
 - 5.5 इकाई को अच्छी हालत में संधारित रखना होगा। भवन की साफ-सफाई, सुरक्षा (जिसमें अग्नि सुरक्षा भी शामिल है) का प्रबंध करना होगा।
 - 5.6 'इकाई' के पंजीयन प्रमाण पत्र, कक्षों का किराया, खाद्य पदार्थों की दरों के साथ, चेक इन/आउट का समय तथा इकाई में कार्यरत कर्मचारियों के नामों की सूची सहज दिखाई देने वाले स्थान पर प्रदर्शित करना होगा।
 - 5.7 खाद्य पदार्थ स्वच्छ, ताजा एवं पौष्टिक तैयार कर उपलब्ध कराना होगा।
 - 5.8 अतिथियों को ठहरने तथा खान-पान की सुविधा उनकी दरों, इकाई में चेक इन तथा चेक आउट का समय आदि की समस्त जानकारी पूर्व में उपलब्ध करानी होगी।
 - 5.9 अतिथियों को खान-पान तथा अन्य सुविधाएँ जैसा कि वादा किया जाये उपलब्ध कराना होगा।
 - 5.10 कर्मचारियों के लिए वर्दी निधारित करना होगा। वर्दी में दिखाई देने वाले स्थान पर नाम प्रदर्शित लगानी होगी।
 - 5.11 इकाई के विरुद्ध शिकायत करने के लिए बोर्ड द्वारा नामांकित अधिकारी का नाम, पद, पता, दूरभाष क्रमांक, ई-मेल आई.डी. को सहज दृष्टिगोचर रूप से प्रदर्शित करना होगा।
 - 5.12 इकाई द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं में यदि कोई परिवर्तन हो तो प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड को उसके अनुरूप प्रतिवेदन एक सप्ताह के भीतर भेजना होगा।
 - 5.13 अतिथियों की सुरक्षा संपत्तिधारक/केयरटेकर की जिम्मेदारी होगी।
6. सम्पत्तिधारक/केयर टेकर :-
- 6.1 पृथक फ्रंट आफिस/स्वागतकक्ष संधारित नहीं करेगा तथा इकाई को सामान्य आवासीय भवन की तरह रखेगा।
 - 6.2 ऐसी किसी गतिविधि में संलग्न नहीं होगा अथवा उसकी अनुमति नहीं देगा, जो पड़ोसियों तथा मोहल्ले/कॉलोनी के निवासियों की निजता या अधिकारों को विपरीत रूप से प्रभावित करता हो।
 - 6.3 किसी भी व्यक्ति को इकाई की स्थापना/सुविधाओं के संबंध में गलत जानकारी नहीं देगा।

- 6.4 अतिथि के द्वारा दी गई जानकारी को गोपनीय रखेगा, जब तक कि ऐसी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए विधि सम्मत निर्देश न दिये गये हों।
- 6.5 अतिथि की निजता का सम्मान करेगा।
- 6.6 अतिथि को स्थान, पर्यटक स्थलों, बाजारों, परिवहन आदि के संबंध में सही व प्रामाणिक जानकारी देगा।
- 6.7 अतिथि के साथ सौम्य, नम्र एवं शिष्ट व्यवहार एवं सभ्य आचरण करेगा।
- 6.8 संपत्तिधारक द्वारा आय-व्यय का संपूर्ण ब्यौरा संधारित किया जायेगा जो कि मांगे जाने पर मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।
- 6.9 संपत्तिधारक गुणवत्ता एवं सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना सुनिश्चित करेगा। मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा छः माही आधार पर उक्त व्यवस्था/ प्रक्रिया का प्रमाणीकरण किया जायेगा।
- 6.10 सम्पत्तिधारक/ केयरटेकर/ इकाई में संलग्न कर्मचारियों का पुलिस प्रमाणीकरण करवाकर प्रतिवेदन एवं इनके विरुद्ध लंबित आपराधिक प्रकरणों की जानकारी मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त व्यक्ति/यों में परिवर्तन होने की दशा में नवीन व्यक्ति/यों का पुलिस प्रमाणीकरण कराया जाना आवश्यक होगा।

7. अतिथि के दायित्व :-

अतिथि अपने अन्य सामान्य दायित्व के साथ निम्न दायित्वों का पालन करेगा, अर्थात् :-

- 7.1 वह स्वयं के संबंध में सही विवरण बतलाकर निर्धारित पंजी में उसकी प्रविष्टि करेगा।
- 7.2 वह उत्तम आचरण तथा व्यवहार रखेगा। वह ऐसी किसी गतिविधियों में संलग्न नहीं होगा जो शांति भंग करने वाली हो अथवा जिससे पड़ोसी/मोहल्ले/कॉलोनी में बाधा(nuisance) उत्पन्न होता हो।
- 7.3 उसकी गतिविधियों से अन्य अतिथियों की निजता अथवा अधिकार प्रभावित नहीं करेगा।
- 7.4 वह स्वतंत्र किचन संचालित नहीं करेगा।
- 7.5 जानबूझकर या असावधानीवश उसके या ऐसे व्यक्ति जिसे उसने अनुमति दी हो, द्वारा इकाई में यदि कोई क्षति पहुंचे तो उसकी क्षतिपूर्ति करेगा। ऐसी क्षति में सामान्य टूट-फूट शामिल नहीं है।
- 7.6 परिसर को साफ एवं स्वच्छ रखने में वह संपत्तिधारक/केयरटेकर को पूर्ण सहयोग करेगा, समय पर देय राशि का भुगतान करेगा और बेड एण्ड ब्रेकफ़ास्ट इकाई के नियमों का पालन करेगा।
- 7.7 वह आगन्तुक पंजी में दर्ज कराये अतिथि से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति को निजी तौर पर रात्रि में स्वयं के साथ इकाई में रुकने की अनुमति नहीं देगा/रुकने की अनुमति हेतु संपत्तिधारक को बाध्य नहीं करेगा।
- 7.8 आवास छोड़ते समय विधिवत चेक आउट करायेगा एवं अतिथि पंजी में प्रस्थान दर्ज करेगा।

7.9 परिसर के सुचारु संचालन के लिए बनाये गये नियम निर्देशों का पालन करेगा।

7.10 विदेशी अतिथि आगमन/ चेक इन के 24 घण्टे के अन्दर स्थानीय पुलिस अधिकारी को अपने आगमन की सूचना देंगे।

8. अतिथियों के सुझाव/फीडबैक एवं शिकायत का निराकरण

- 8.1 सम्पत्तिधारक द्वारा प्रदान की गई सेवाओं एवं सुविधाओं के आधार पर फीडबैक देने हेतु सम्पत्तिधारक द्वारा फीडबैक/ सुझाव रजिस्टर का संधारण किया जायेगा।
- 8.2 समस्त अतिथियों द्वारा चेक आउट करते समय फीडबैक रजिस्टर में फीडबैक/ सुझाव देने हेतु अनुरोध किया जाये।
- 8.3 नवीनीकरण के समय उक्त फीडबैक/ सुझाव रजिस्टर की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न की जाये।
- 8.4 उक्त फीडबैक/ सुझाव के आधार पर सम्पत्तिधारक को पुरस्कार/ दण्ड लगाये जाने हेतु प्रक्रिया निर्धारित की जायेगी।
- 8.5 उत्कृष्ट सेवाओं एवं सुविधाओं का फीडबैक/ सुझाव प्राप्त होने पर सम्पत्तिधारक को पुरस्कार श्रेणी में पृथक से अंकों का प्रावधान किया जायेगा।
- 8.6 खराब सेवाओं एवं सुविधाओं का फीडबैक प्राप्त होने पर सम्पत्तिधारक को सुधार हेतु चेतावनी दी जायेगी। सम्पत्तिधारक द्वारा 03 बार चेतावनी देने के उपरांत भी सुधार न करने पर पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संपादित की जायेगी।
- 8.7 जब कोई सम्पत्तिधारक/ कर्मचारी अतिथि को गलत जानकारी देता है या कोई पदार्थ या अन्य सुविधाएँ जैसा कि वह वचन देता है, उपलब्ध कराने में असमर्थ रहता है, तो अतिथि इस बारे में एक लिखित शिकायत ऐसे दस्तावेज या सामग्री जिन पर वह विश्वास करता है, के साथ प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड को प्रस्तुत कर सकेगा। ऐसी शिकायत ई-मेल (md@mptourism.com) या पोस्ट से भेजी जा सकती है। शिकायत पत्र में अतिथि का पूरा स्थाई पता, दूरभाष/मोबाइल क्रमांक, ई-मेल आई.डी. होना चाहिये।
- 8.8 अतिथियों द्वारा मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा निर्धारित दूरभाष क्रमांक पर शिकायतें पंजीकृत की जा सकती हैं। उक्त शिकायतों के निराकरण हेतु बोर्ड द्वारा पंजी का संधारण किया जायेगा, जिसमें की गई कार्यवाही की पूर्ण जानकारी होगी।
- 8.9 प्रबंध संचालक ऐसी शिकायत को जांच तथा सम्पत्तिधारक को पक्ष प्रस्तुति का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात या तो समाधान कारक रूप से निरस्त करेगा अथवा शिकायत सत्य प्रमाणित होने पर इकाई का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका नाम डायरेक्ट्री से हटा देगा।
- 8.10 प्रकरण में निराकरण से संतुष्ट न होने की स्थिति में मंत्री, पर्यटन, मध्यप्रदेश शासन, को अपील की जा सकती है। जिनका निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

9. पंजीयन निरस्तीकरण एवं डायरेक्ट्री से नाम हटाया जाना :-

9.1 प्रबंध संचालक एक लिखित आदेश के जरिये इकाई का नाम डायरेक्ट्री से हटाते हुए उसका पंजीयन प्रमाण-पत्र निम्न आधारों पर निरस्त कर सकेगा, अर्थात्-

- (क) यदि संपत्तिधारक/केयरटेकर में बिना अनुमति परिवर्तन कर दिया गया हो,
- (ख) यदि सम्पत्तिधारक/केयर टेकर के विरुद्ध आपराधिक मामले में चालान पेश हुआ हो अथवा दंडित किया गया हो अथवा वह जेल में रहा हो,
- (ग) यदि सम्पत्तिधारक/केयर टेकर दिवालिया घोषित हो गया हो,
- (घ) यदि सम्पत्तिधारक/केयर टेकर ने योजना के प्रावधानों का उल्लंघन किया हो,
- (च) यदि इकाई से पड़ोसी, मोहल्ले/कॉलोनी निवासियों की निजता अथवा अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ना पाया गया हो,
- (ड) अन्य कोई उपयुक्त कारण,

9.2 उप कंडिका (1) में की गयी कार्रवाई से प्रचलित विधि के अंतर्गत सम्पत्तिधारक को अभियोजित करने की कार्रवाई अथवा उसके सिविल दायित्वों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

9.3 इकाई का नाम डायरेक्ट्री से हटाने के पूर्व प्रबंध संचालक सम्पत्तिधारक को उन कारणों को बतलाते हुए 15 दिवस अवधि युक्त कारण बताओ सूचना पत्र जारी करेगा जिसके आधार पर स्थापना का नाम डायरेक्ट्री से हटाया जाना प्रस्तावित हो। सम्पत्तिधारक को पक्ष प्रस्तुति का अवसर देने के पर्याप्त प्रबंध संचालक मामले में नीति अनुरूप निर्णय लेंगे।

9.4 अतिथि शिकायत पर निरस्त पंजीयन को छोड़कर अन्य नियम पालन संबंधी कारणों से इकाई का पंजीयन निरस्त होने पर, वांछित सुधार के बाद पुनः पंजीयन के लिए आवेदन ग्राह्य किया जा सकेगा। ऐसे आवेदन पत्रों पर कंडिका-2 के प्रावधानों के अनुसार पुनः परीक्षण उपरांत प्रबंध संचालक द्वारा यथोचित निर्णय लिया जा सकेगा।

10. इकाई को प्राप्त सुविधाएँ:-

10.1 इकाई जल कर तथा सम्पत्ति कर का आवासीय दर से संबंधित स्थानीय नगरीय/ग्रामीण निकाय को भुगतान करेगा।

10.2 बेड एण्ड ब्रेकफास्ट इकाई पर प्रचलित प्रावधान अनुसार गुड्स एवं सर्विसेस टैक्स (जी.एस.टी.) लागू होगा।

10.3 इकाई को विद्युत प्रभार म.प्र. विद्युत मंडल द्वारा संबंधित प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रचलित आवासीय दर पर नियमानुसार भुगतान करना होगा।

10.4 योजना के अंतर्गत प्रचलित नियमों के अंतर्गत करों, फीस आदि, अगर कोई देय हो तो उसका भुगतान करने का दायित्व इकाई का होगा।

10.5 इकाई को फूड तथा रेस्टोरेन्ट लायसेंस लेना आवश्यक नहीं होगा।

11. निरीक्षण की शक्तियाँ :-

11.1 प्रबंध संचालक या उनके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा यथा आवश्यकता पर पंजीकृत इकाईयों के परिसर का निरीक्षण किया जा सकेगा।

12. प्रचार-प्रसार:-

12.1 मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड ऐसी पंजीकृत इकाईयों का प्रचार-प्रसार अपनी वेबसाइट तथा अन्य माध्यम से करेगा।

12.2 योजना अंतर्गत पंजीकृत बेड एण्ड ब्रेकफास्ट इकाईयों की डायरेक्ट्री/प्रोफाइल समय-समय पर (आनलाईन एवं ऑफलाईन) प्रकाशित की जायेगी।

13. प्रोत्साहन:-

13.1 मध्यप्रदेश टूरिज्म पुरस्कार (अवार्ड्स) अंतर्गत प्रतिवर्ष श्रेष्ठ बेड एण्ड ब्रेकफास्ट इकाई को अवार्ड दिया जायेगा।

13.2 पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित/ भाग लिये जाने वाले मार्केटिंग रोड शो/राशि में भाग ले सकेगा।

13.3 होम स्टे का ब्रोशर / वेबसाइट बनाने हेतु व्यय का 100% (सौ फीसदी) अथवा अधिकतम रु. 10,000/- सम्पत्तिधारक को एक बार (One time) देय होगा। संबंधित प्रोत्साहन हेतु प्रपत्र -1 में आवेदन किया जा सकेगा।

13.4 सम्पत्तिधारक को वेबसाइट निर्माण हेतु एक बार व्यय राशि का 100 प्रतिशत या अधिकतम राशि रुपये 10,000/- अनुदान दिया जाएगा।

13.5 राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्केटिंग शो/रोड शो/बायर सेलर मीट में भाग लेने पर एक व्यक्ति के परिवहन व्यय (रेल द्वारा एसी-11 श्रेणी देश में/विदेश भ्रमण हेतु इकनॉमी क्लास का) एवं स्टॉल शुल्क की 50 प्रतिशत राशि अधिकतम रुपये 50,000/- का अनुदान दिया जाएगा।

13.6 बेड एण्ड ब्रेकफास्ट इकाई को निम्नानुसार प्रोत्साहन अनुदान दिया जायेगा:-

(अ) प्रथम वर्ष उपरांत न्यूनतम 50 पर्यटक/अतिथि आवास दिवस होने पर रुपये 15,000/- अनुदान

(ब) द्वितीय वर्ष उपरांत न्यूनतम 75 पर्यटक/अतिथि आवास दिवस होने पर रुपये 20,000/- अनुदान

(स) तृतीय वर्ष उपरांत न्यूनतम 100 पर्यटक/अतिथि आवास दिवस होने पर रुपये 25,000/- अनुदान

न्यूनतम पर्यटक/अतिथि आवास दिवस की शर्त पूर्ण न होने पर नवीनीकरण तो किया जा सकेगा किंतु अनुदान देय नहीं होगा।

13.7 उपरोक्त अनुदान क्लेम हेतु आवेदन प्रपत्र-1 में किया जायेगा। आवेदन निराकरण प्रक्रिया प्रपत्र-2 अनुसार होगी।

14. प्रशिक्षण:-

संभावित बेड एण्ड ब्रेकफ़ास्ट धारकों/पंजीकृत बेड एण्ड ब्रेकफ़ास्ट धारकों को सामान्य संचालन संबंधी प्रशिक्षण मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड की प्रशिक्षण संस्थाओं से प्राप्त करने की सुविधा यथा मांग/आवश्यकता उपलब्ध करायी जायेगी। पंजीकृत संपत्तिधारकों की मांग के अनुरूप हाउसकीपिंग, फूड प्रोडक्शन, व्यवहार कुशलता, सुरक्षा प्रावधान जैसे आवश्यक प्रशिक्षणों का आयोजन मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा कराया जायेगा।

15. बेड एण्ड ब्रेकफ़ास्ट विकास में निजी क्षेत्र/पर्यटन हेतु गठित पंजीकृत सहकारी समिति की भूमिका:-

15.1 प्रदेश में बेड एण्ड ब्रेकफ़ास्ट स्थापना हेतु पर्यटन हेतु गठित पंजीकृत सहकारी समितियों एवं अलाभकारी संस्थाओं/ सहकारी समितियों आदि को प्रोत्साहित किया जायेगा।

15.2 ऐसी संस्थायें जो पर्यटन विभाग/ बोर्ड द्वारा ग्राम स्टे एवं इससे संबंधित गतिविधियों के संचालन में चयनित/ सूचीबद्ध संस्थाओं को विभाग/ मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अंतर्गत सहायता प्रदान की जायेगी।

16. योजना को लागू करना :-

इस योजना को लागू करने एवं प्रक्रिया आदि निर्धारण हेतु प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड अधिकृत होंगे।

17. योजना की व्याख्या/स्पष्टीकरण/संशोधन :

इस योजना की व्याख्या/स्पष्टीकरण/संशोधन हेतु मध्यप्रदेश शासन पर्यटन विभाग अधिकृत होगा।

परिशिष्ट-2

मध्यप्रदेश ग्राम स्टे स्थापना (पंजीयन तथा नियमन)**योजना, 2019**

विषय- ग्राम स्टे से आशय ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित ऐसे आवासीय भवन है जिसमें गृहस्वामी स्वयं निवास करता हो अथवा पर्यटक आवास के लिए पर्यटन हेतु गठित पंजीकृत सहकारी समिति अथवा पंजीकृत स्व-सहायता समूह द्वारा निर्मित किया गया हो तथा ऐसे आवास में न्यूनतम 1 व अधिकतम 6 कक्ष (12 शैय्या) पर्यटक आवास हेतु संधारित एवं उपलब्ध हो एवं खान-पान सुविधा उपलब्ध हो, गृह स्वामी से भिन्न पर्यटन हेतु गठित पंजीकृत सहकारी समिति/पंजीकृत स्व-सहायता समूह द्वारा निर्मित ग्राम स्टे में संबंधितों द्वारा नियमित व्यवस्थापक रखा जाना जरूरी होगा।

1. योजना का संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा लागू करना :-

1.1 यह योजना मध्यप्रदेश ग्राम स्टे स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना, 2019 कहलायेगी।

1.2 इस योजना का विस्तार सम्पूर्ण ग्रामीण मध्यप्रदेश होगा।

1.3 यह योजना शासन द्वारा जारी दिनांक से लागू होगी।

1.4 इस योजना का उद्देश्य ---

(अ) देशी-विदेशी पर्यटकों को ग्रामीण आवास में आवास, भोजन सुविधा एवं ग्राम्य जीवन अनुभव प्रदाय करना,

(ब) देशी/विदेशी पर्यटकों को भारतीय ग्रामीण संस्कृति, खान पान एवं आतिथ्य से परिचित कराना,

(स) ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटक आवास सुविधाएँ विकसित करना,

(द) ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को अपने आवास में उपलब्ध अतिरिक्त क्षमता को पर्यटन व्यवसाय से जोड़ने एवं अतिरिक्त आय अर्जन हेतु प्रोत्साहित करना एवं

(इ) पर्यटन हेतु गठित पंजीकृत सहकारी समिति अथवा पंजीकृत स्व-सहायता समूहों को ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटक आवास निर्माण हेतु प्रोत्साहित करना है।

1.5 इस योजना हेतु संपत्तिधारक से आशय आवासीय भवन के स्वामी अथवा पर्यटन हेतु गठित पंजीकृत सहकारी समिति अथवा पंजीकृत स्व-सहायता समूह से है, जिसके द्वारा पर्यटक आवास निर्मित किये गये हों, से है।

2. पंजीयन :-

- 2.1 सम्पत्तिधारक के आवासीय भवन के कक्षों को जिनकी न्यूनतम संख्या 01 तथा अधिकतम संख्या 06 (12 शैय्या) हो, को पर्यटक/ अतिथि रहवास के लिये उपलब्ध रहेंगे।
- 2.2 ग्राम स्टे इकाई का पंजीयन हेतु शुल्क रु. 1000/- एवं जीएसटी होगा।
- 2.3 इकाइयों का पंजीयन **परिशिष्ट 'एक'** में निर्धारित मापदंड चेकलिस्ट के आधार पर किया जायेगा।
- 2.4 पंजीयन तीन (3) साल तक वैध रहेगा।
- 2.5 तीन वर्ष पश्चात पंजीयन नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र के साथ रु. 1000/- + जी.एस.टी. शुल्क, निर्धारित दस्तावेज एवं गत वर्षों की पर्यटक पंजी की प्रतिलिपि के साथ आवेदन वैधता की अंतिम तिथि के तीन माह पूर्व जमा कर नवीनीकरण कराया जा सकेगा।
- 2.6 इस योजना अंतर्गत पंजीकरण कराने के इच्छुक संपत्तिधारक को, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड (जिसे आगे बोर्ड कहा जायेगा) के प्रबंध संचालक को निर्धारित **प्रारूप 'अ'** में पंजीयन फीस के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा। पंजीयन फीस का भुगतान डिमाण्ड ड्राफ्ट/**RTGS/NEFT** अथवा बैंकर्स चेक से करना होगा। डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड, भोपाल के नाम पर बनाये जाये। आवेदन पत्र अमान्य होने पर यह फीस वापसी योग्य नहीं होगी। आवेदन के साथ चेक लिस्ट (परिशिष्ट-1) अनुसार जानकारी प्रदान करनी होगी।
- 2.7 इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत होने के लिये 'ग्राम स्टे' को निम्न शर्तों की पूर्ति करना आवश्यक होगा, अर्थात् -
 - (1) यह कि 'ग्राम स्टे' विशुद्धतः आवासीय भवन हो। भवन स्वामी भौतिक रूप से उसमें सतत निवासरत हो एवं किचन का संचालन किया जाता हो/संपत्तिधारक द्वारा आवासीय भवन एवं किचन के संचालन/संधारण की उपयुक्त व्यवस्था की गई हो।
 - (2) यह कि सम्पत्ति धारक उसके आवासीय भवन के ऐसे आवासीय भाग को ही किराये पर दे सकेगा जिसमें शयन कक्षों की संख्या कम से कम 01 तथा अधिकतम 06 होगी, (अधिकतम 12 शैय्या होगी)।
 - (3) यह कि 'ग्राम स्टे' में स्नानागार, शौचालय, जल, ऊर्जा आपूर्ति, सामान्य फर्नीचर आदि सुविधाएँ उपलब्ध होगी। कक्षों में हवा आने-जाने के लिये खिड़की अथवा वेंटिलेटर हो। प्रत्येक कक्ष का बाथरूम सहित क्षेत्रफल कम से कम 100 वर्गफीट होगा।
 - (4) यह कि परिसर अच्छी अवस्था में हो। परिसर में साफ-सफाई की नियमित व्यवस्था हो। अग्नि सुरक्षा एवं पर्यटक सुरक्षा सहित अन्य सुरक्षा का पर्याप्त प्रबंध हो।
 - (5) अन्य कोई शर्तें जो राज्य सरकार या 'बोर्ड' द्वारा निर्धारित की जावें।

- 2.8 उप कंडिका (2.6) में प्राप्त आवेदन पत्रों पर प्रबंध संचालक, पंजीयन के निमित्त निरीक्षणकर्ता नियुक्त कर स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त करेगा।
- 2.9 परिसर का निरीक्षण करने पर पायी गयी कमीयों को निर्धारित समयावधि में निरीक्षणकर्ता की संतुष्टि स्तर तक सुधार का अवसर आवेदक को दिया जायेगा। आवेदक द्वारा ऐसे पत्र के जारी होने के 60 दिवस में सुधार न कर पाने पर आवेदन अनान्य किया जायेगा।
- 2.10 निरीक्षणकर्ता, नियुक्ति के अधिकतम 15 दिवस में ऐसी जांच अथवा निरीक्षण जैसा कि वह उपयुक्त समझे करने के पश्चात, परिसर के पंजीयन की अहंता के संबंध में अपना दृष्टिकोण तय करेगा एवं अपनी अनुशंसाएं देते समय सम्पत्तिधारक द्वारा उपलब्ध करायी जा रही भौतन आदि सुविधा एवं सेवाओं पर भी विचार करेगा।
- 2.11 निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्रबंध संचालक, प्रतिवेदन से संतुष्ट होने पर अधिकतम 15 दिवस में इकाई का पंजीयन करने के लिए विहित प्रारूप 'ब' में प्रमाण पत्र जारी करेगा। यह प्रमाण पत्र 3 वर्ष के लिये वैध होगा, बशर्ते उसे पहले निरस्त न कर दिया जाये। ग्राम स्टे के सफल संचालन पर पंजीयन का नवीनीकरण, विहित शुल्क अदा करने पर किया जा सकेगा।
- 2.12 ग्राम स्टे के पंजीयन की संपूर्ण प्रक्रिया आवेदन प्राप्ति के 45 दिवस के भीतर पूर्ण की जावेगी तथा परिणाम से आवेदक को अवगत कराया जावेगा।
- 2.13 इस योजना के अंतर्गत स्थापित ग्राम स्टे की एक डायरेक्ट्री विहित प्रारूप 'स' में बोर्ड में संघारित की जायेगी।

3. योजना अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण:-

प्रबंध संचालक द्वारा अधिकृत प्राधिकारी अथवा योजना प्रभारी अधिकारी तथा एक नामांकित अशासकीय सदस्य, द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों का पर्यवेक्षण अथवा निरीक्षण कार्य किया जायेगा। अशासकीय सदस्यों को मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा द्वितीय श्रेणी अधिकारियों हेतु निर्धारित यात्रा/आवास/भोजन भत्ते की पात्रता तथा रुपये एक हजार प्रतिदिवस के मान से मानदेय भुगतान योग्य होगा।

4. इस योजना के अंतर्गत पंजीयन के लिए कोई 'ग्राम स्टे' निर्हर होगी-

- 4.1 यदि सम्पत्तिधारक पर किसी आपराधिक मामले में चालान प्रस्तुत किया गया हो अथवा दंडित होकर जेल में निरुद्ध रहा हो, या
- 4.2 यदि ग्राम स्टे का नाम इस योजना की कंडिका-9 के अधीन डायरेक्ट्री से हटा दिया गया हो।

5. सम्पत्तिधारक/व्यवस्थापक का दायित्व होगा कि वह:-

- 5.1 पर्यटक/अतिथियों को निर्धारित सुविधा युक्त आवास एवं भोजन उपलब्ध करायेगा।

- 5.2 अतिथि के आगमन तथा प्रस्थान व उनके विवरण की विहित प्रारूप 'द' में एक पंजी संधारित करना होगा, जो निरीक्षण के लिये सभी अवसरों पर उपलब्ध रहेगी। ऐसी पंजी प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में नवीनीकृत की जावेगी एवं उसे दो वर्ष तक सुरक्षित रखा जाना होगा।
 - 5.3 ग्राम स्टे में रुकने वाले विदेशी अतिथियों का विवरण स्थानीय पुलिस को 24 घण्टे में प्रेषित करना होगा।
 - 5.4 ग्राम स्टे में रुकने वाले सभी अतिथियों की जानकारी संबंधित सरपंच को प्रेषित करना होगा।
 - 5.5 ग्राम स्टे के समुचित संधारण, उत्तम साफ-सफाई, सुरक्षा, जिसमें अग्नि सुरक्षा भी शामिल है, का प्रबंध करना होगा।
 - 5.6 'ग्राम स्टे' के पंजीयन प्रमाण पत्र, कमरों का किराया, खाद्यपदार्थों की दरों के साथ, चेक इन/चेक आउट का समय तथा कर्मचारियों के नाम की सूची सहज दिखाई देने वाले स्थान पर प्रदर्शित करना होगा।
 - 5.7 खाद्य पदार्थ स्वच्छ, ताजा एवं पौष्टिक तैयार कर उपलब्ध कराना होगा।
 - 5.8 अतिथियों को आवास तथा खान-पान की दरों, चेक इन/चेक आउट की जानकारी पूर्व में उपलब्ध करानी होगी।
 - 5.9 अतिथि समस्या निराकरण/शिकायत के लिए बोर्ड द्वारा नामांकित अधिकारी का नाम, पद, पता, दूरभाष क्रमांक की जानकारी संपत्तिधारक द्वारा, चाहे जाने पर अतिथि को उपलब्ध करायी जायेगी।
6. **सम्पत्तिधारक :-**
- 6.1 सम्पूर्ण ग्राम स्टे भवन सामान्य आवासीय भवन की तरह संधारित रखेगा।
 - 6.2 संपत्तिधारक अतिथियों की आवास एवं खान-पान की व्यवस्था के साथ ग्रामीण पर्यटन अनुभव संबंधित गतिविधियाँ जैसे बैलगाड़ी की सवारी, पशुपालन, स्थानीय पेड़-पौधों का परिचय, वानिकी, कृषि कार्य, कृषि उपकरणों का निर्माण, माटीकला, स्थानीय उपज से तैयार वस्तु/पदार्थ का प्रदर्शन तथा ग्रामीण परिवेश से संबंधित नृत्य, संगीत, खान-पान आदि पर्यटकों को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा।
 - 6.3 ऐसी किसी गतिविधि में संलग्न नहीं होगा अथवा उसकी अनुमति नहीं देगा, जो स्थानीय ग्रामीणों में असंतोष उत्पन्न करे अथवा जिससे अतिथियों को असुविधा हो।
 - 6.4 अतिथि के साथ सौम्य, नम्र एवं शिष्ट व्यवहार एवं सभ्य आचरण करेगा।
 - 6.5 अतिथि की सुरक्षा एवं सुरक्षित व निरापद आवास सुनिश्चित करेगा।
 - 6.6 संपत्तिधारक द्वारा आय-व्यय का संपूर्ण ब्यौरा संधारित किया जायेगा जो कि मांगे जाने पर मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।

- 6.7 संपत्तिधारक गुणवत्ता एवं सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना सुनिश्चित करेगा। मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा छ:माही आधार पर उक्त व्यवस्था/ प्रक्रिया का प्रमाणीकरण किया जायेगा।
- 6.8 सम्पत्तिधारक/ केयरटेकर/ इकाई में संलग्न कर्मचारियों का पुलिस प्रमाणीकरण करवाकर प्रतिवेदन एवं इनके विरुद्ध लंबित आपराधिक प्रकरणों की जानकारी मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त व्यक्ति/यों में परिवर्तन होने की दशा में नवीन व्यक्ति/यों का पुलिस प्रमाणीकरण कराया जाना आवश्यक होगा।

7. अतिथि के दायित्व:-

- 7.1 अतिथि स्वयं के संबंध में सही विवरण बतलाकर निर्धारित पंजी में उसकी प्रविष्टि करेगा।
- 7.2 वह उत्तम आचरण तथा व्यवहार रखेगा। वह ऐसी किसी गतिविधियों में संलग्न नहीं होगा जो स्थानीय ग्राम वासियों में असंतोष उत्पन्न करे।
- 7.3 परिसर को साफ एवं स्वच्छ रखने में वह ग्राम स्टे स्वामी को पूर्ण सहयोग करेगा, समय पर देय राशि का भुगतान करेगा और संपत्तिधारक द्वारा तय नियमों का पालन करेगा एवं परिसर को क्षति नहीं पहुंचायेगा।
- 7.4 आगन्तुक पंजी में दर्ज व्यक्तियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को रात्रि में स्वयं के साथ ग्राम स्टे में रुकने की अनुमति नहीं देगा।
- 7.5 विदेशी अतिथि अपने आगमन के 24 घण्टे में स्थानीय पुलिस अधिकारी को सूचित करेगा।

8. अतिथियों के सुझाव/फीडबैक एवं शिकायत का निराकरण

- 8.1 सम्पत्तिधारक द्वारा प्रदान की गई सेवाओं एवं सुविधाओं के आधार पर फीडबैक देने हेतु सम्पत्तिधारक द्वारा फीडबैक/ सुझाव रजिस्टर का संधारण किया जायेगा।
- 8.2 समस्त अतिथियों द्वारा चेक आउट करते समय फीडबैक रजिस्टर में फीडबैक/ सुझाव देने हेतु अनुरोध किया जाये।
- 8.3 नवीनीकरण के समय उक्त फीडबैक/ सुझाव रजिस्टर की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न की जाये।
- 8.4 उक्त फीडबैक/ सुझाव के आधार पर सम्पत्तिधारक को पुरस्कार/ दण्ड लगाये जाने हेतु प्रक्रिया निर्धारित की जायेगी।
- 8.5 उत्कृष्ट सेवाओं एवं सुविधाओं का फीडबैक/ सुझाव प्राप्त होने पर सम्पत्तिधारक को पुरस्कार श्रेणी में पृथक से अंकों का प्रावधान किया जायेगा।

- 8.6 खराब सेवाओं एवं सुविधाओं का फीडबैक प्राप्त होने पर सम्पत्तिधारक को सुधार हेतु चेतावनी दी जायेगी। सम्पत्तिधारक द्वारा 03 बार चेतावनी देने के उपरान्त भी सुधार न करने पर पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संपादित की जायेगी।
- 8.7 जब कोई ग्राम स्टे सम्पत्तिधारक अतिथि को गलत जानकारी देता है या खाद्य पदार्थ या अन्य सुविधाएं जैसा कि वह वचन देता है, उपलब्ध कराने में असमर्थ रहता है, तो अतिथि इस बारे में एक लिखित शिकायत ऐसे दस्तावेज या सामग्री जिन पर वह विश्वास करता है, के साथ प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड को प्रस्तुत कर सकेगा। ऐसी शिकायत ई-मेल (md@mptourism.com) या पोस्ट से भेजी जा सकती है। शिकायत पत्र में अतिथि का पूरा स्थाई पता, दूरभाष/मोबाइल क्रमांक, ई-मेल आई.डी. होना चाहिये।
- 8.8 अतिथियों द्वारा मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा निर्धारित दूरभाष क्रमांक पर शिकायतें पंजीकृत की जा सकती हैं। उक्त शिकायतों के निराकरण हेतु बोर्ड द्वारा पंजी का संधारण किया जायेगा, जिसमें की गई कार्यवाही की पूर्ण जानकारी होगी।
- 8.9 प्रबंध संचालक ऐसी शिकायत की जांच तथा ग्राम स्टे सम्पत्तिधारक को सुनवाई का व्यक्तिगत अवसर देने के पश्चात शिकायत को या तो निरस्त करेगा अथवा यदि यह पाया जाता है कि शिकायत में सत्यता है तो उस ग्राम स्टे का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका नाम डायरेक्ट्री से हटा देगा।
- 8.10 प्रकरण में निराकरण से संतुष्ट न होने की स्थिति में मंत्री, पर्यटन, मध्यप्रदेश शासन, को अपील की जा सकती है। जिनका निर्णय अंतिम एवं बाध्य होगा।

9. पंजीयन निरस्तीकरण एवं डायरेक्ट्री से नाम हटाया जाना :-

- 9.1 प्रबंध संचालक एक लिखित आदेश के जरिये ग्राम स्टे का नाम डायरेक्ट्री से हटाते हुए उसका पंजीयन प्रमाण-पत्र निम्न आधारों पर निरस्त कर सकेगा, अर्थात्-
 - (क) यदि ग्राम स्टे संपत्तिधारक परिवर्तित हो गया हो एवं नवीन संपत्तिधारक ग्राम स्टे संचालन हेतु अनिच्छुक हो।
 - (ख) यदि ग्राम स्टे सम्पत्तिधारक के विरुद्ध आपराधिक मामले में चालान पेश हुआ हो अथवा दंडित किया गया हो अथवा वह जेल में रहा हो,
 - (ग) यदि ग्राम स्टे सम्पत्ति धारक ने योजना के प्रावधानों का उल्लंघन किया हो।
 - (घ) अन्य कोई उपयुक्त कारण।
- 9.2 उप कंडिका (1) में की गयी कार्यवाही से प्रचलित विधि के अंतर्गत सम्पत्तिधारक को अभियोजित करने की कार्यवाही अथवा उसके सिविल दायित्वों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- 9.3 ग्राम स्टे का नाम डायरेक्ट्री से हटाने के पूर्व प्रबंध संचालक ग्राम स्टे सम्पत्तिधारक को उन कारणों को बतलाते हुए 15 दिवस अवधि युक्त कारण बताओ सूचना पत्र जारी करेगा जिसके आधार पर ग्राम

स्टे का नाम डायरेक्ट्री से हटाया जाना प्रस्तावित हो। ग्राम स्टे सम्पत्ति धारक को पक्ष प्रस्तुति का अवसर देने के पश्चात प्रबंध संचालक, मामले में नीति अनुरूप निर्णय लेंगे।

- 9.4 जिस ग्राम स्टे का पंजीयन निरस्त किया गया हो, वह वांछित सुधार के बाद पुनः पंजीयन के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। ऐसे आवेदन पत्र का कंडिका-2 के प्रावधानों के अनुसार पुनः परीक्षण कर यथोचित निर्णय प्रबंध संचालक द्वारा लिया जा सकेगा।

10. देयताएं :-

- 10.1 ग्राम स्टे सम्पत्तिधारक जल कर तथा सम्पत्ति कर का आवासीय दर से संबंधित स्थानीय नगरीय/ग्रामीण निकाय को भुगतान करेगा।
- 10.2 ग्राम स्टे पर प्रचलित प्रावधान अनुसार गुड्स एवं सर्विसेस टैक्स (जी.एस.टी) लागू होगा।
- 10.3 ग्राम स्टे सम्पत्तिधारक को विद्युत प्रभार म.प्र. विद्युत मंडल द्वारा संबंधित प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रचलित आवासीय दर पर नियमानुसार भुगतान करना होगा।

11. निरीक्षण की शक्तियाँ :-

- 11.1 प्रबंध संचालक या उनके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा यथा आवश्यकता पंजीकृत ग्राम स्टे का निरीक्षण किया जा सकेगा।

12. प्रचार-प्रसार:-

- 12.1 मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड/मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम ऐसी पंजीकृत ग्राम स्टे का प्रचार-प्रसार अपनी वेबसाइट तथा अन्य माध्यमों से करेगा।
- 12.2 योजना अंतर्गत पंजीकृत ग्राम स्टे की डायरेक्ट्री समय-समय पर (आनलाईन एवं ऑफलाईन) प्रकाशित की जायेगी।

13. प्रोत्साहन:-

- 13.1 ग्राम स्टे सम्पत्तिधारक को फूड तथा रेस्टोरेंट लायसेंस लेना आवश्यक नहीं होगा।
- 13.2 मध्यप्रदेश टूरिज्म अवार्ड्स अंतर्गत प्रतिवर्ष श्रेष्ठ ग्राम स्टे को अवार्ड दिया जायेगा।
- 13.3 पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित/भाग लिये जाने वाले मार्केटिंग रोड शो आदि में ग्राम स्टे सम्पत्तिधारक निःशुल्क भाग ले सकेगा।
- 13.4 सम्पत्तिधारक को ब्रोशर प्रिंटिंग हेतु एक बार व्यय राशि का 100 प्रतिशत अधिकतम राशि रुपये 10,000/- अनुदान दिया जाएगा।
- 13.5 सम्पत्तिधारक को वेबसाइट निर्माण हेतु एक बार व्यय राशि का 100 प्रतिशत या अधिकतम राशि रुपये 10,000/- अनुदान दिया जाएगा।

13.6 राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्केटिंग शो/रोड शो/बायर संस्तर मीट में भाग लेने पर एक व्यक्ति के परिवहन व्यय (रेल द्वारा एसी-II श्रेणी देश में/विदेश भ्रमण हेतु इकनॉमी क्लास का) एवं स्टॉल शुल्क की 50 प्रतिशत राशि अधिकतम रुपये 50,000/- का अनुदान दिया जाएगा।

13.7 ग्राम स्टे को प्रोत्साहन अनुदान दिया जायेगा :-

(अ) प्रथम वर्ष उपरांत न्यूनतम 50 पर्यटक/अतिथि आवास दिवस होने पर रुपये 15,000/- अनुदान

(ब) द्वितीय वर्ष उपरांत न्यूनतम 75 पर्यटक/अतिथि आवास दिवस होने पर रुपये 20,000/- अनुदान

(स) तृतीय वर्ष उपरांत न्यूनतम 100 पर्यटक/अतिथि आवास दिवस होने पर रुपये 25,000/- अनुदान

न्यूनतम पर्यटक/अतिथि आवास दिवस की शर्त पूर्ण न होने पर नवीनीकरण तो किया जा सकेगा किंतु अनुदान देय नहीं होगा।

13.8 उपरोक्त अनुदान क्लेम हेतु आवेदन प्रपत्र -1 में किया जायेगा। आवेदन निराकरण प्रक्रिया प्रपत्र-2 अनुसार होगी।

14. प्रशिक्षण :-

संभावित ग्राम स्टे धारकों/पंजीकृत ग्राम स्टे धारकों को सामान्य संचालन संबंधी प्रशिक्षण मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड की प्रशिक्षण संस्थाओं से प्राप्त करने की सुविधा यथा मांग/आवश्यकता उपलब्ध करायी जायेगी। पंजीकृत संपत्तिधारकों की मांग के अनुसार इन्हें प्रशिक्षण प्रोत्साहन व्यवहार कुशलता, सुरक्षा, सवधान जैसे आवश्यक प्रशिक्षणों का आयोजन मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा कराया जायेगा।

15. ग्राम स्टे विकास में निजी क्षेत्र/ पंजीकृत स्व-सहायता समूह/पर्यटन हेतु गठित पंजीकृत सहकारी समिति की भूमिका :-

15.1 प्रदेश में ग्राम स्टे स्थापना हेतु पंजीकृत स्व सहायता समूह, पर्यटन हेतु गठित पंजीकृत सहकारी समितियों एवं अलाभकारी संस्थाओं/ सहकारी समितियों आदि को प्रोत्साहित किया जायेगा।

15.2 ऐसी संस्थाएँ जो पर्यटन विभाग/ बोर्ड द्वारा ग्राम स्टे एवं इससे संबंधित गतिविधियों के संचालन में चर्यान्त/ सूचीबद्ध संस्थाओं को विभाग/ मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अंतर्गत सहायता प्रदान की जायेगी।

16. योजना को लागू करना :-

इस योजना को लागू करने, निर्देश जारी करने एवं प्रक्रिया आदि निर्धारण हेतु प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड अधिकृत होंगे।

17. योजना की व्याख्या/स्पष्टीकरण/संशोधन :-

इस योजना की व्याख्या/स्पष्टीकरण/संशोधन हेतु मध्यप्रदेश शासन पर्यटन विभाग अधिकृत होगा।

परिशिष्ट-3मध्यप्रदेश फार्म स्टे स्थापना (पंजीयन तथा नियमन)योजना, 2019

विषय - फार्म स्टे से आशय नगरीय निकायों (नगरपालिका, नगर निगम) की सीमा से बाहर स्थित ऐसे आवासीय भवन से होगा जिसमें संपत्तिधारक/ केयर टेकर स्वयं निवास करता हो, ऐसे भवन में कम से कम 01 तथा अधिकतम 06 कक्ष (12 शैय्या तक) पर्यटक आवास हेतु संधारित एवं उपलब्ध हो, खानपान सुविधा उपलब्ध हो तथा प्राकृतिक पर्यावरणीय अनुभव एवं इनडोर-आउटडोर मनोरंजक गतिविधियाँ उपलब्ध हों। ऐसे मध्यप्रदेश फार्म स्टे स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना अंतर्गत पंजीकृत किये जाने वाले भवन को "फार्म स्टे" से संबोधित किया जायेगा, मध्यप्रदेश फार्म स्टे स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना अंतर्गत "फार्म स्टे" जिस भूमि पर स्थित है वह भूमि जिस व्यक्ति के नाम से पंजीकृत, नामांकित अथवा मालिकाना हक की है, उसे "संपत्तिधारक" से संबोधित किया जायेगा एवं मध्यप्रदेश फार्म स्टे स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना अंतर्गत "संपत्तिधारक" द्वारा "फार्म स्टे" की देखभाल करने हेतु अधिकृत किये गये व्यक्ति को "केयर टेकर" से संबोधित किया जायेगा जो इकाई में सदैव निवासरत होगा।

1. योजना का संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा लागू करना :-

- 1.1 यह योजना मध्यप्रदेश फार्म स्टे स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना 2019 कहलायेगी।
- 1.2 इस योजना का विस्तार नगरीय निकाय की सीमा को छोड़कर सम्पूर्ण मध्यप्रदेश होगा।
- 1.3 यह योजना शासन द्वारा जारी दिनांक से लागू होगी।
- 1.4 इस योजना का उद्देश्य -
 - (अ) देशी-विदेशी पर्यटकों को प्राकृतिक परिवेश में आवास एवं भोजन सुविधा एवं फार्म जीवन अनुभव प्रदाय करना,
 - (ब) देशी-विदेशी पर्यटकों को भारतीय ग्रामीण संस्कृति, खान पान, आतिथ्य, कृषि एवं साहसिक पर्यटन का अनुभव प्रदान करना एवं
 - (स) गैर शहरी क्षेत्र के संपत्तिधारकों को अपने आवास में उपलब्ध अतिरिक्त क्षमता से आय के साथ पर्यटन संवर्धन एवं विकास तथा स्थानीय रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु प्रोत्साहित करना है।
- 1.5 योजना संचालन के विस्तृत दिशा निर्देश जारी करने हेतु प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड अधिकृत होगा।

2. पंजीयन :-

- 2.1 सम्पत्तिधारक/ केयर टेकर न्यूनतम 01 तथा अधिकतम 06 कक्ष (12 शैय्या) को पर्यटक रहवास के लिये उपलब्ध करा सकेगा।
- 2.2 फार्म स्टे का पंजीयन शुल्क - रु. 5000/- एवं जीएसटी होगा।
(इकाइयों का पंजीयन परिशिष्ट 'एक' में निर्धारित मापदंड चेकलिस्ट के आधार पर किया जायेगा)
- 2.3 पंजीयन तीन (3) साल तक वैध रहेगा।

- 2.4 तीन वर्ष पश्चात पंजीयन के नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र के साथ रु. 5000/- एवं जीएसटी एवं पूर्व संचालन संबंधी जानकारी सहित वैधता की अंतिम तिथि के तीन माह पूर्व जमा कर नवीनीकरण कराया जा सकेगा।
- 2.5 जो सम्पत्तिधारक इस योजना अंतर्गत पंजीकरण कराने का इच्छुक हो, उसे मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड (जिसे आगे बोर्ड कहा जायेगा) के प्रबंध संचालक को प्रारूप 'अ' में विहित पंजीयन फीस के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा। पंजीयन फीस का भुगतान डिमाण्ड ड्राफ्ट/ RTGS/ NEFT अथवा बैंकर्स चैक से करना होगा। डिमाण्ड ड्राफ्ट/ बैंकर्स चैक प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड, भोपाल के नाम पर बनाये जाये। आवेदन पत्र अमान्य होने पर यह फीस वापसी योग्य नहीं होगी। आवेदन के साथ चेक लिस्ट अनुसार जानकारी संलग्न करनी होगी।
6. इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत होने के लिये फार्म स्टे को निम्न शर्तों की पूर्ति करना आवश्यक होगा, अर्थात्-
- (1) यह कि फार्म स्टे विशुद्धतः आवासीय इकाई हो। इकाई स्वामी अथवा उसके द्वारा नियुक्त किया गया केयर टेकर (देखभाल करने वाला) मौलिक रूप से उसमें निवासरत हो एवं इकाई में किचन का संधारण/ संचालन हो।
 - (2) यह कि सम्पत्ति धारक/ केयर टेकर उसके आवासीय भवन के अधिकतम दो तिहाई शयन कक्षों की यथा मांग किराये पर दे सकता है जिसकी संख्या कम से कम 01 तथा अधिकतम 06 होगी जिसमें अधिकतम 12 शैथ्या होगी।
 - (3) यह कि इकाई में स्नानागार, संचालय, जल, उर्जा आपूर्ति, फर्नीचर, व अन्य सुविधाएं उपयुक्त/ आरामदायक होंगी। कक्षों में हवा आने-जाने के लिये खिड़की अथवा वेन्टीलेटर हो।
 - (4) यह कि परिसर अच्छी अवस्था में हो। परिसर में साफ-सफाई की उत्तम व्यवस्था हो। अग्नि सुरक्षा सहित अन्य सुरक्षा का पर्याप्त प्रबंध हो।
 - (5) संपत्तिधारक/ केयर टेकर द्वारा एक ही परिसर/ भवन/ कॉलोनी में पृथक-पृथक फार्म स्टे का पंजीयन नहीं कराया जा सकेगा।
 - (6) अन्य कोई शर्तें जो राज्य सरकार या 'बोर्ड' द्वारा समय समय पर निर्धारित की जावें।
- 2.7 उप कंडिका (2.5) में प्राप्त आवेदन पत्रों को प्रबंध संचालक, पंजीयन के निमित्त निरीक्षणकर्ता नियुक्त कर स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त करेगा।
- 2.8 परिसर का निरीक्षण करने पर पायी गयी कमियों को निर्धारित समयावधि में निरीक्षणकर्ता की संतुष्टि स्तर तक सुधार का अवसर आवेदक को दिया जायेगा। आवेदक ऐसा करने में यदि असफल रहता है तो उसका आवेदन अमान्य किया जायेगा।
- 2.9 निरीक्षणकर्ता, ऐसी जांच अथवा निरीक्षण जैसा कि वह उपयुक्त समझे करने के पश्चात, परिसर के पंजीयन की अर्हता के संबंध में अपना दृष्टिकोण तय करेगा। निरीक्षणकर्ता अपनी अनुशंसाएं देते समय सम्पत्तिधारक द्वारा उपलब्ध करायी जा रही भोजन सुविधा एवं सेवाओं पर भी विचार करेगा।
- 2.10 निरीक्षणकर्ता प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्रबंध संचालक, प्रतिवेदन से संतुष्ट होने पर इकाई का पंजीयन करने के लिए विहित प्रारूप 'ब' में प्रमाण पत्र जारी करेगा। यह प्रमाण पत्र 3 वर्ष के लिये होगा, बशर्ते उसे पहले निरस्त न कर दिया जाये। फार्म स्टे के सफल संचालन पर पंजीयन का नवीनीकरण, विहित शुल्क अदा करने पर किया जा सकेगा।

- 2.11 फार्म स्टे के पंजीयन की संपूर्ण प्रक्रिया आवेदन प्राप्ति से 45 दिवस में पूर्ण की जावेगी तथा परिणाम से आवेदक को अवगत कराया जावेगा।
- 2.12 इस योजना के अंतर्गत स्थापित फार्म स्टे की एक डायरेक्ट्री विहित प्रारूप 'स' में संधारित की जायेगी।

योजना अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण कार्य :-

प्रबंध संचालक द्वारा अधिकृत प्राधिकारी अथवा योजना प्रभारी अधिकारी तथा एक नामांकित अशासकीय सदस्य द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों का पर्यवेक्षण अथवा निरीक्षण कार्य किया जायेगा। अशासकीय सदस्यों को मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा द्वितीय श्रेणी अधिकारियों हेतु निर्धारित यात्रा/आवास/भोजन भत्ते की पात्रता तथा रुपये एक हजार प्रतिदिवस के मान से मानदेय भुगतान योग्य होगा।

इस योजना के अंतर्गत पंजीयन के लिए कोई फार्म स्टे निर्हर होगा -

- (क) यदि सम्पत्तिधारक/ केयर टेकर किसी आपराधिक मामले में चालान प्रस्तुत किया गया हो अथवा दंडित होकर जेल में निरुद्ध रहा हो, या
- (ख) यदि फार्म स्टे का नाम इस योजना की कंडिका -9 के अधीन डायरेक्ट्री से हटा दिया गया हो।

सम्पत्तिधारक का दायित्व होगा कि वह:-

- 5.1 अतिथि के आगमन तथा प्रस्थान व उनके विवरण की विहित प्रारूप 'द' में एक पंजी संधारित करे, जो निरीक्षण के लिये सभी अगसरों पर उपलब्ध रहेगी। ऐसी पंजी प्रत्येक वर्ष नवीनीकृत की जावेगी एवं उसे पाँच वर्ष तक सुरक्षित रखा जाना होगा।
- 5.2 फार्म स्टे में रुकने वाले विदेशी अतिथियों का निगरान स्थानीय पुलिस को 24 घण्टे में फेरित करना होगा।
- 5.3 फार्म स्टे में रुकने वाले सभी अतिथियों की जानकारी संबंधित सरपंच को प्रेषित करना होगा।
- 5.4 फार्म स्टे के समुचित संधारण, उत्तम साफ सफाई, सुरक्षा जिसमें अग्नि सुरक्षा भी शामिल है, का प्रबंध करना होगा।
- 5.5 'फार्म स्टे' के पंजीयन प्रमाण पत्र, कक्षों का किराया, खाद्य पदार्थों की दरों के साथ, चेक इन/आउट का समय तथा फार्म स्टे में कार्यरत कर्मचारियों के नामों की सूची सहज दिखाई देने वाले स्थान पर प्रदर्शित करना होगा।
- 5.6 खाद्य पदार्थ स्वच्छ, ताजा एवं पौष्टिक तैयार कर उपलब्ध कराना होगा।
- 5.7 अतिथियों को ठहरने तथा खान-पान की सुविधा उनकी दरों, फार्म स्टे के खुलने एवं बंद होने आदि की समस्त जानकारी पूर्व में उपलब्ध करानी होगी।
- 5.8 अतिथि समस्या निराकरण/शिकायत के लिए बोर्ड द्वारा नामांकित अधिकारी का नाम, पद, पता, दूरभाष क्रमांक, ई-मेल आई.डी. को सहज दृष्टिगोचर रूप से प्रदर्शित करना होगा।

सम्पत्तिधारक/केयर टेकर

- 6.1 सम्पूर्ण फार्म स्टे इकाई सामान्य आवासीय भवन की तरह संधारित रखेगा।

- 6.2 संपत्तिधारक अतिथियों की आवास/खानपान की व्यवस्था के साथ मनोरंजक गतिविधियाँ जैसे इनडोर/आउटडोर गेम्स, स्विमिंग पुल, किचन गार्डन, लान, बगीचा, फलोद्यान आदि अनुभव उपलब्ध करायेगा।
- 6.3 ऐसी किसी गतिविधि में संलग्न नहीं होगा अथवा उसकी अनुमति नहीं देगा, जो पड़ोसियों तथा मोहल्ले/कॉलोनी के निवासियों की निजता अथवा अधिकारों को विपरीत रूप से प्रभावित करता हो।
- 6.4 किसी भी व्यक्ति को इकाई की स्थापना के संबंध में गलत जानकारी नहीं देगा।
- 6.5 अतिथि के साथ सौम्य, नम्र एवं शिष्ट व्यवहार एवं सभ्य आचरण करेगा एवं अतिथि की सुरक्षा एवं सुरक्षित व निरापद आवास सुनिश्चित करेगा।
- 6.6 संपत्तिधारक द्वारा आय-व्यय का संपूर्ण व्यौरा संधारित किया जायेगा जो कि मांगे जाने पर मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।
- 6.7 संपत्तिधारक गुणवत्ता एवं सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना सुनिश्चित करेगा। मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा छ:माही आधार पर उक्त व्यवस्था/प्रक्रिया का प्रमाणीकरण किया जायेगा।
- 6.8 सम्पत्तिधारक/ केयरटेकर/ इकाई में संलग्न कर्मचारियों का पुलिस प्रमाणीकरण करवाकर प्रतिवेदन एवं इनके विरुद्ध लंबित आपराधिक प्रकरणों की जानकारी मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त व्यक्ति/यों में परिवर्तन होने की दशा में नवीन व्यक्ति/यों का पुलिस प्रमाणीकरण कराया जाना आवश्यक होगा।

7. अतिथि के दायित्व:-

अतिथि अपने अन्य सामान्य दायित्व के साथ निम्न दायित्वों का पालन करेगा, अर्थात :-

- 7.1 वह स्वयं के संबंध में सही विवरण बतलाकर निर्धारित पंजी में उसकी प्रविष्टि करेगा।
- 7.2 वह उत्तम आचरण तथा व्यवहार रखेगा। वह ऐसी किसी गतिविधियों में संलग्न नहीं होगा जो शांति भंग करने वाली हो अथवा जिससे पड़ोसी/ मोहल्ले/ कॉलोनी में बाधा(nuisance) उत्पन्न होता हो।
- 7.3 उसकी गतिविधियों से अन्य अतिथियों की निजता अथवा अधिकार प्रभावित नहीं करेगा।
- 7.4 परिसर को साफ एवं स्वच्छ रखने में वह भवन स्वामी/ केयर टेकर को पूर्ण सहयोग करेगा, समय पर देय राशि का भुगतान करेगा और संपत्तिधारक द्वारा तय नियमों का पालन करेगा एवं परिसर को क्षति नहीं पहुंचायेगा।
- 7.5 आगंतुक पंजी में दर्ज व्यक्तियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को रात्रि में स्वयं के साथ फार्म स्टे में रुकने की अनुमति नहीं देगा।
- 7.6 विदेशी अतिथि अपने आगमन के 24 घण्टे में स्थानीय पुलिस अधिकारी को सूचित करेगा।

8. अतिथियों के सुझाव/फीडबैक एवं शिकायत का निराकरण

- 8.1 सम्पत्तिधारक द्वारा प्रदान की गई सेवाओं एवं सुविधाओं के आधार पर फीडबैक देने हेतु सम्पत्तिधारक द्वारा फीडबैक/ सुझाव रजिस्टर का संधारण किया जायेगा।

- 8.2 समस्त अतिथियों द्वारा चेक आउट करते समय फीडबैक रजिस्टर में फीडबैक/ सुझाव देने हेतु अनुरोध किया जाये।
- 8.3 नवीनीकरण के समय उक्त फीडबैक/ सुझाव रजिस्टर की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न की जाये।
- 8.4 उक्त फीडबैक/ सुझाव के आधार पर सम्पत्तिधारक को पुरस्कार/ दण्ड लगाये जाने हेतु प्रक्रिया निर्धारित की जायेगी।
- 8.5 उत्कृष्ट सेवाओं एवं सुविधाओं का फीडबैक/ सुझाव प्राप्त होने पर सम्पत्तिधारक को पुरस्कार श्रेणी में पृथक से अंकों का प्रावधान किया जायेगा।
- 8.6 खराब सेवाओं एवं सुविधाओं का फीडबैक प्राप्त होने पर सम्पत्तिधारक को सुधार हेतु चेतावनी दी जायेगी। सम्पत्तिधारक द्वारा 03 बार चेतावनी देने के उपरांत भी सुधार न करने पर पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संपादित की जायेगी।
- 8.7 जब कोई सम्पत्तिधारक/ केयर टेकर अतिथि को गलत जानकारी देता है या खाद्य पदार्थ या अन्य सुविधाएँ जैसा कि वह वचन देता है, उपलब्ध कराने में असमर्थ रहता है, तो अतिथि इस बारे में एक लिखित शिकायत ऐसे दस्तावेज या सामग्री जिन पर वह विश्वास करता है, के साथ प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड को प्रस्तुत कर सकेगा। ऐसी शिकायत ई-मेल (md@mptourism.com) या पोस्ट से भेजी जा सकती है। शिकायत पत्र में अतिथि का पूरा स्थाई पता, दूरभाष/मोबाइल क्रमांक, ई-मेल आई.डी. होना चाहिये।
- 8.8 अतिथियों द्वारा मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा निर्धारित दूरभाष क्रमांक पर शिकायत पंजीकृत की जा सकती है। उक्त शिकायतों के निराकरण हेतु बोर्ड द्वारा पंजी का संचालन किया जायेगा, जिसमें की गई कार्यवाही की पूर्ण जानकारी होगी।
- 8.9 प्रबंध संचालक ऐसी शिकायत की जांच तथा सम्पत्तिधारक को सुझाव का व्यक्तिगत अवसर देने के पश्चात् यदि शिकायत को निरस्त करेगा अथवा यदि यह पता चले कि शिकायत सत्य है तो उस इकाई का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका नाम डायरेक्ट्री से हटा देगा।
- 8.10 प्रकरण में निराकरण से संतुष्ट न होने की स्थिति में मंत्री, पर्यटन, मध्यप्रदेश शासन, को अपील की जा सकती है। जिनका निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

9. डायरेक्ट्री से नाम हटाया जाना

- 9.1 प्रबंध संचालक एक लिखित आदेश के जरिये फार्म स्टे का नाम डायरेक्ट्री से हटाते हुए उसका पंजीयन प्रमाण-पत्र निम्न आधारों पर निरस्त कर सकेगा, अर्थात्-
 - (क) यदि सम्पत्तिधारक परिवर्तित हो गया हो एवं नवीन सम्पत्तिधारक फार्म स्टे संचालन का अनिच्छुक हो,
 - (ख) यदि सम्पत्तिधारक/ केयर टेकर को आपराधिक मामले में चलन पेश हुआ हो अथवा दंडित किया गया हो अथवा वह जेल में रहा हो,
 - (ग) यदि सम्पत्तिधारक/ केयर टेकर ने योजना के प्रावधानों का उल्लंघन किया हो।
 - (घ) अन्य कोई उपयुक्त कारण।
- 9.2 उप कंडिका (1) में की गयी कार्यवाही से प्रचलित विधि के अंतर्गत सम्पत्तिधारक को अभियोजित करने की कार्यवाही अथवा उसके सिविल दायित्वों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

- 9.3 इकाई का नाम डायरेक्ट्री से हटाने के पूर्व प्रबंध संचालक सम्पत्तिधारक को उन कारणों को बतलाते हुए कारण बताओ सूचना पत्र जारी करेगा जिसके आधार पर स्थापना का नाम डायरेक्ट्री से व्यक्तिगत हटाया जाना प्रस्तावित हो। सम्पत्तिधारक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात प्रबंध संचालक मामले में नीति अनुरूप निर्णय लेंगे।
- 9.4 जिस इकाई का पंजीयन निरस्त किया गया हो, वह वांछित सुधार के बाद पुनः पंजीयन के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। ऐसे आवेदन पत्र का कंडिका-2 के प्रावधानों के अनुसार पुनः परीक्षण कर यथोचित निर्णय प्रबंध संचालक द्वारा लिया जा सकेगा।

10. देयताएं :-

- 10.1 फार्म स्टे जल कर तथा सम्पत्ति कर का आवासीय दर से संबंधित स्थानीय नगरीय/ ग्रामीण निकाय को भुगतान करेगा।
- 10.2 फार्म स्टे पर प्रचलित प्रावधान अनुसार गुड्स एवं सर्विसेस टैक्स (जी.एस.टी) लागू होगा।
- 10.3 फार्म स्टे को विद्युत प्रभार म.प्र. विद्युत मंडल द्वारा संबंधित प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रचलित आवासीय दर पर नियमानुसार भुगतान करना होगा।
- 10.4 योजना के अंतर्गत प्रचलित नियमों के अंतर्गत करों, फीस आदि, अगर कोई देय हो तो उसका भुगतान करने का दायित्व फार्म स्टे का होगा।

11. निरीक्षण की शक्तियां :-

प्रबंध संचालक या उनके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा यथा आवश्यकता पंजीकृत इकाईयों के परिसर का निरीक्षण किया जा सकेगा।

12. प्रचार-प्रसार:-

- 12.1 मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड/मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम ऐसी पंजीकृत इकाईयों का प्रचार-प्रसार अपनी वेबसाइट तथा अन्य माध्यम से करेगा।
- 12.2 योजना अंतर्गत पंजीकृत फार्म स्टे की डायरेक्ट्री समय-समय पर (आनलाईन एवं ऑफलाईन) प्रकाशित की जायेगी।

13. प्रोत्साहन:-

- 13.1 फार्म स्टे सम्पत्तिधारक को फूड तथा रेस्टोरेंट लायसेंस लेना आवश्यक नहीं होगा।
- 13.2 मध्यप्रदेश टूरिज्म अवार्ड्स अंतर्गत प्रतिवर्ष श्रेष्ठ फार्म स्टे को अवार्ड दिया जायेगा।
- 13.3 पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित/भाग लिये जाने वाले मार्केटिंग रोड शो आदि में फार्म स्टे संपत्तिधारक निःशुल्क भाग ले सकेगा।
- 13.4 संपत्तिधारक को ब्रोशर प्रिंटिंग हेतु एक बार व्यय राशि का 100 प्रतिशत अधिकतम राशि रुपये 10,000/- अनुदान दिया जाएगा।
- 13.5 संपत्तिधारक को वेबसाइट निर्माण हेतु एक बार व्यय राशि का 100 प्रतिशत या अधिकतम राशि रुपये 10,000/- अनुदान दिया जाएगा।

13.6 राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्केटिंग शो/रोड शो/बायर सेलर मीट में भाग लेने पर एक व्यक्ति के परिवहन व्यय (रेल द्वारा एसी-11 श्रेणी देश में/विदेश भ्रमण हेतु इकोनॉमी क्लास का) एवं स्टॉल शुल्क की 50 प्रतिशत राशि अधिकतम रुपये 50,000/- का अनुदान दिया जाएगा।

13.7 फार्म स्टे सम्पत्तिधारक को निम्नानुसार प्रोत्साहन अनुदान दिया जायेगा:-

(अ) प्रथम वर्ष उपरांत न्यूनतम 50 पर्यटक/अतिथि आवास दिवस होने पर रुपये 15,000/- अनुदान

(ब) द्वितीय वर्ष उपरांत न्यूनतम 75 पर्यटक/अतिथि आवास दिवस होने पर रुपये 20,000/- अनुदान

(स) तृतीय वर्ष उपरांत न्यूनतम 100 पर्यटक/अतिथि आवास दिवस होने पर रुपये 25,000/- अनुदान

न्यूनतम पर्यटक/अतिथि आवास दिवस की शर्त पूर्ण न होने पर नवीनीकरण तो किया जा सकेगा किंतु अनुदान देय नहीं होगा।

13.8 उपरोक्त अनुदान क्लेम हेतु आवेदन प्रपत्र -1 में किया जायेगा। आवेदन निराकरण प्रक्रिया प्रपत्र-2 अनुसार होगी।

14. प्रशिक्षण :-

संभावित फार्म स्टे धारकों/पंजीकृत फार्म स्टे धारकों को संचालन संबंधी प्रशिक्षण मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड की प्रशिक्षण संस्थाओं से प्राप्त करने की सुविधा यथा मांग/आवश्यकता उपलब्ध करायी जायेगी। पंजीकृत सम्पत्तिधारकों की मांग के अनुरूप हाउसकीपिंग, फूड प्रोडक्शन, व्यवहार कुशलता, सुरक्षा प्रावधान जैसे आवश्यक प्रशिक्षणों का आयोजन मध्यप्रदेश-टूरिज्म बोर्ड द्वारा कराया जायेगा।

15. फार्म स्टे विकास में निजी क्षेत्र/पंजीकृत स्व-सहायता समूह/पर्यटन हेतु गठित पंजीकृत सहकारी समिति की भूमिका :-

15.1 प्रदेश में फार्म स्टे स्थापना हेतु पंजीकृत स्व सहायता समूह, पर्यटन हेतु गठित पंजीकृत सहकारी समितियों एवं अलाभकारी संस्थाओं/ सहकारी समितियों आदि को प्रोत्साहित किया जायेगा।

15.2 ऐसी संस्थायें जो पर्यटन विभाग/ बोर्ड द्वारा फार्म स्टे एवं इससे संबंधित गतिविधियों के संचालन में चयनित/ सूचीबद्ध संस्थाओं को विभाग/ मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अंतर्गत सहायता प्रदान की जायेगी।

16. योजना को लागू करना :-

इस योजना को लागू करने, निर्देश जारी करने एवं प्रक्रिया आदि निर्धारण हेतु प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड अधिकृत होंगे।

17. योजना की व्याख्या/स्पष्टीकरण/संशोधन :-

इस योजना की व्याख्या/ स्पष्टीकरण/ संशोधन हेतु मध्यप्रदेश शासन पर्यटन विभाग अधिकृत होगा।

भोपाल, दिनांक 31 अक्टूबर 2019

क्रमांक एफ 10-41/2019/तैंतीस, राज्य शासन एनद् द्वारा राज्य की पर्यटन नीति (2016) संशोधित 2019 की कंडिका क्र. 9.12 में अल्ट्रा, मेगा परियोजना हेतु पर्यटन विभाग/राजस्व विभाग की लैंड बैंक की शासकीय भूमि कलेक्टर गाइड लाईन रेट पर आवेदन करने के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान किये गये हैं -

कंडिका क्र. 9.12

"अल्ट्रा मेगा परियोजना हेतु प्रस्ताव प्राप्त होंगे पर राजस्व/पर्यटन विभाग के लैंड बैंक में से प्रस्तावक द्वारा चिन्हित शासकीय भूमि निवेशक को विभाग द्वारा उस स्थान के तत्समय प्रचलित कलेक्टर गाइड लाईन रेट पर 90 वर्ष की लीज पर 1% वार्षिक लीज रेंट पर आवंटित की जा सकेगी। प्रत्येक 30 वर्ष के उपरांत लीज रेंट में 6 गुना वृद्धि की जायेगी। यदि प्रस्तावक द्वारा राजस्व विभाग के शासकीय भूमि के लैंड बैंक की भूमि चिन्हित की जायेगी तो ऐसी भूमि प्रथमतः पर्यटन विभाग को हस्तांतरित की जायेगी। यह आवंटन प्रथम आओ प्रथम गये के आधार पर किया जायेगा। ऐसे प्रस्ताव का अनुमोदन पर्यटन नीति अंतर्गत गठित साधिकार समिति द्वारा किया जायेगा।"

उपरोक्त कंडिका के क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार नियम एवं प्रक्रिया निर्धारित की जाती है -

1. आवेदन हेतु पात्रता- उपरोक्त नीति के अंतर्गत आवेदन की पात्रता निम्नानुसार होगी -

1.1 कोई व्यक्ति, फर्म, कम्पनी अथवा कंसोर्शियम (जिसे आगे आवेदक कहा जायेगा) जिनकी नेटवर्थ आवेदन दिनांक को प्रचलित वित्तीय वर्ष अथवा उसके पूर्व के वित्तीय वर्ष में रु. 100 करोड़ से अधिक हो।

1.2 आवेदक का व्यवसायिक ग्रास टर्न ओवर विगत 3 वित्तीय वर्षों में न्यूनतम रु. 150 करोड़ हो।

1.3 नेटवर्थ की पुष्टि हेतु चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा जारी प्रमाण पत्र आवश्यक होगा।

1.4 टर्न ओवर के प्रमाणीकरण हेतु चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित बैलेंस शीट की प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी।

1.5 कंसोर्शियम की स्थिति में कंसोर्शियम के सदस्यों की संयुक्त नेटवर्थ रु. 100 करोड़ होना आवश्यक होगी।

1.6 आवेदक को पर्यटन नीति में उल्लेखित पर्यटन परियोजनाओं का एकल परियोजना अथवा एकाधिक परियोजनाओं का 5 वर्षीय संचालन अनुभव आवश्यक होगा तथा प्रति वर्ष विगत 3 वर्षों में रु. 50 करोड़ का न्यूनतम ग्रास टर्न ओवर आवश्यक होगा।

1.7 भूमि का आवंटन पर्यटन नीति में घोषित पर्यटन परियोजनाओं के लिये ही किया जायेगा।

1.8 आवेदक को भूमि पूर, भूमि का मूल्य छह लाख रुपये 100 करोड़ से अधिक की परियोजना स्थापित करनी होगी।

2 भूमि आवंटन हेतु आवेदन -

2.1 आवेदक द्वारा परिशिष्ट-1 पर निर्धारित प्रपत्र में आवेदन, परिशिष्ट-2 में निर्धारित चेकलिस्ट अनुसार सहपत्रों सहित आवेदक अथवा उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित कर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड को प्रस्तुत किया जायेगा।

2.2 आवेदन पत्र टूरिज्म बोर्ड की वेबसाइट पर आन लाईन प्राप्त किये जायेंगे। आनलाईन व्यवस्था प्रारंभ होने तक ऑफ लाईन आवेदन प्रबंध संचालक के कार्यालय में प्रस्तुत कर पावती प्राप्त की जा सकेगी। आवेदन ईमेल/कोरियर/पंजीकृत डाक के माध्यम से भी आनलाईन व्यवस्था होने तक प्राप्त किये जा सकते हैं।

2.3 आवेदन अपूर्ण होने पर एक सप्ताह में त्रुटि पूर्ति हेतु संबंधित आवेदक को प्रबंध संचालक द्वारा सूचित किया जायेगा। त्रुटि पूर्ति हेतु 15 दिवस की समय सीमा दी जायेगी, तदोपरांत आवेदन निरस्त किया जायेगा।

2.4 आवेदन की वरियता पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के दिनांक से की जायेगी ।

2.5 आवंटन प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर किया जायेगा । एक से अधिक आवेदन होने की स्थिति में यदि प्रथम आवेदक द्वारा आवेदन वापिस किया जाता है तो ऐसी दशा में क्रमशः उसके बाद वाले आवेदक को वरियता दी जायेगी ।

3. आवंटन प्रक्रिया -

3.1 आवेदन पत्र प्राप्त होने के 10 दिनों में आवेदन हेतु संक्षेपिका तैयार कर आवेदन नीति की कंति 1 क. 20 में प्रावधित मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित साधिकार समिति के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी ।

3.2 साधिकार समिति द्वारा प्रस्ताव मान्य किये जाने की दशा में कलेक्टर गाईड लाईन रेट पर 5 वर्ष हेतु लीज पर भूमि आवंटन के संबंध में लेटर आफ अलाटमेंट (LOA) जारी किया जायेगा ।

3.3 आवंटित भूमि हेतु तत्समय प्रचलित गाईड लाईन रेट को एक मुश्त प्रीमियम माना जायेगा तथा इसके 1% के तुल्य राशि, वार्षिक लीज रेंट के रूप में ली जायेगी । प्रति 30 वर्ष उपरान्त लीज रेंट में 6 गुना वृद्धि की जायेगी ।

3.4 लेटर आफ अलाटमेंट (LOA) जारी होने के उपरान्त लीज निष्पादन, लीज पंजीयन एवं कब्जा सौंपना आदि संबंधी कार्यवाही पर्यटन नीति (2016) संशोधित 2019 में वर्णित प्रावधानों एवं प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा ।

4. परियोजना क्रियान्वयन एवं भूमि का आधिपत्य -

4.1 भूमि का आधिपत्य भूमि जहां जैसी है उसी रूप में किया जायेगा ।

4.2 भूमि तक सड़क/विद्युत/जल प्रदाय आदि मूल अधोसंरचनाएँ आवंटी आवेदक द्वारा विकसित की जायेगी ।

4.3 अतिक्रमण रहित भूमि का आधिपत्य आवंटी आवेदक को दिया जायेगा ।

4.4 परियोजना क्रियान्वयन एवं निर्माण कार्य आधिपत्य देने के एक वर्ष में सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त आवेदक आवंटी द्वारा किया जायेगा ।

4.5 परियोजना क्रियान्वयन हेतु आधिपत्य दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष की अवधि प्रदान की जायेगी ।

4.6 उपरोक्त अवधि में न्यूनतम 75% तक कार्य पूर्ण होने की दशा में दिये गये कार्य के आंकलन उपरान्त गुण दोष के आधार पर प्रबंधक संचालक मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा अधिकतम एक वर्ष की अवधि बढ़ायी जा सकेगी ।

4.7 भूमि के आधिपत्य के उपरान्त कार्य प्रारंभ करने के पूर्व विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन सहित प्राप्त अनुमतियां एवं अनुमोदित नक्शे आदि की प्रतियां प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड को प्रस्तुत की जायेगी ।

5. विविध -

5.1 राजस्व विभाग की शासकीय भूमि यदि आवेदक द्वारा चयनित की जाती है तो प्रथमतः ऐसी भूमियों का हस्तांतरण पर्यटन विभाग के नाम पर कराया जायेगा । तदोपरांत उपरोक्त प्रक्रिया अनुसार आवंटन किया जायेगा ।

5.2 उपरोक्त प्रक्रिया के अनुपालन हेतु प्रपत्र आदि निर्धारण तथा मार्गदर्शन एवं निर्देशन हेतु प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड अधिकृत होंगे ।

5.3 उपरोक्त नियम एवं प्रक्रिया में संशोधन अथवा स्पष्टीकरण हेतु पर्यटन विभाग मध्यप्रदेश शासन अधिकृत होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

फैज अहमद किदवाई, सचिव.

Annexure-1

Application Form for Land Allotment, Proposal for Ultra-Mega (Rs.100 crore +) Tourism Project

General Information and Address					
1	Name of the proposed project				
2	Applicant Name				
3	Constitution Type				
	Address Type	Address	Mobile / Phone	Fax	Email
4	Correspondence				
Contact Details					
5	Directors / MD / Project Head				
	Name (Designation)	Member	Mobile / Phone	Fax	Email
6	Authorized signatory details				
	Name	Address	Mobile / Phone	Fax	Email
7	Local Contact Person details				
	Name	Address	Mobile / Phone	Fax	Email
Project Information					
8	Proposal in brief				
9	Land required (details & area of land applied for)				
10	Power required		Type: Load Required (in KW):		
11	Water required				

12	Employment Details (In Numbers)	Type	Total	From M.P.	Outside M.P.
		Managerial			
		Supervisory			
		Skilled			
		Semi-Skilled			
		Unskilled			
		Grand Total			
13	Probable Date of starting work				
14	Probable date of starting operation				

Cost of project		
15	Land (In Rs.)	
16	Building & other construction (In Rs.)	
17	Plant & Machinery/Equipment (In Rs.)	
18	Other investment	
	Total	
19	Working capital	
	Grand Total	
Means of finance		
20	Total cost of project	
21	Loan from Bank/Financial Institution (Please specify name)	
22	Own funds	
23	Funds from Other sources (Please specify)	
	Total	
24	Financial Capability	
	S.No.	Name of the Applicant - Proprietor/ Firm/Company/Consortium Members
	1	Net worth as on date of application/as on last financial year (in Rs.)
	2	
	3	
	4	
	Total	

25	Technical capability (Operation of Tourism Project as detailed in Tourism Policy) of the Applicant - Proprietor/Firm/Company/ Consortium Member	Experience field	Experience years	Last 3 year Turn over		
				Year 1	Year 2	Year 3

26	Brief profile of the Applicant - Proprietor/Firm/ Company/Consortium Member	
27	Vendor information in prescribed format is attached	
28	Benefits to the State by this Project in terms of Employment, Destination Promotion, Investment and Tourism Promotion.	

Declaration

I/We hereby undertake that

I/We abide by the conditions stipulated by the Government of M.P.

I/We hereby declare that above statements and enclosed documents are true and correct to the best of my/our knowledge and belief. I/We fully understand that the government may take any action, if it is found that any of the statements/documents, therein are incorrect or false.

Date :

Place:

Signature

Name

Post

Seal of the Applicant



Madhya Pradesh Tourism Board

6th Floor Lily Trade Wings, Jehangirabad, Bhopal - 462008

Vendor Registration Form

1	Vendor Name (in Capital Letters)	
2	Vendor Type (Govt./Private/Individual)	
3	Contact Person	
4	Address	
5	State	
6	Mobile No.	
7	Email ID	
8	Bank Details	
9	Bank & Branch Name	
10	Account No.	
11	IFSC Code	
12	PAN	
13	GST No. (Certificate to be attached)	

Date :

Signature with Company Seal

Name :..

DECLARATION

- I hereby declare that our firm has not registered under GST Act.
- I hereby declare that our firm has not allotted PAN from Income Tax Dept.

Signature with Company Seal

Name :..

Annexure-2**Check list for Land Allotment, Proposal for Ultra-Mega
(Rs.100 crore +) Tourism Project.**

1. Applicant - Proprietor/ Firm/Company/Consortium Members profile.
2. Project profile of the Proposed activity.
3. Applicant, Proprietor/ Firm/Company/Consortium Members balance sheet for the last 3 years (CA certified).
4. Memorandum and Article of Association and certification of Incorporation.
5. Net worth of the Applicant - Proprietor/ Firm/Company/Consortium Members for the current/preceding financial year (CA certified in format-1)
6. Turn over of the Applicant - Proprietor/ Firm/Company/Consortium Members for the last 3 years certified by CA in format-2
7. Time schedule for implementation of the project.
8. A brief note on Applicant, Proprietor/Firm/Company/Consortium Members profile, business performance etc.
9. A brief note on company's corporate social responsibility.
10. Board resolution -
 - (a) To take up the project
 - (b) Authorized signatory appointment
11. GST Registration Number (GSTN)//Tax Equivalent of Particular Country.
12. PAN No./Equivalent of Particular country.
13. Any other information, applicant wants to provide about Project/Firm/Company/Specified achievements/benefits to the State etc.

Format - 1

**FORMAT FOR NET WORTH CERTIFICATE
ON THE LETTER HEAD OF THE CHARTERED ACCOUNTANT
NET WORTH CERTIFICATE (AS ON 31st MARCH**

We statutory auditor of M/s/Mr./Mrs..... Hereby certify that the Net Worth of M/s/Mr./Mrs.....S/o / D/o Shri (Address)as on 31st March is Rs. (Rs..... only).

The methodology adopted for calculating net worth is as follows :

S.No.	Particulars	Methodology	Amount
1.	Fixed Assets	At purchasing price Registry value (As per collector guideline rates of the preceding year)	
2.	Investment & other assets	As per audited balance sheet	
3.	Cash and bank balances	As per audited balance sheet	
		Total Assets (A) Rs.	
4.	Current liabilities, salary, Expenses payable, Loans and Advances	As per audited balance sheet	
		Total liabilities (B) Rs.	
	Net worth calculation	Total Assets (A) Rs. Less : Total liabilities (B) Rs.	
		Total Net Worth (A-B) Rs.	

(Rupees only)

Above Net Worth Certificate is issued on the basis of books of account and documents produced before us.

Place :

Name, Seal and Signature of the Chartered Accountant

Date :

Format - 2

FORMAT FOR TURNOVER CERTIFICATE
ON THE LETTER HEAD OF THE CHARTERED ACCOUNTANT

CERTIFICATE**TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN**

We statutory auditor of M/s/Mr./Mrs..... hereby certify that the annual turnover of M/s / Mr./ Mrs..... (address)for the past three years are given below .

S.No.	Year	Turnover in lakh (Rs.)
1.		
2.		
3.		

The above turnover certificate is issued on the basis of books of accounts and documents produced before us.

Name, Seal and signature of the Chartered Accountant

Place :

Date :

संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्यप्रदेश, भोपाल

क-गन्ना-एस-3-क्षे.आर-जवाहरलाल-2019-20-768

भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2019

मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं कय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं मुकेश कुमार शुक्ल, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल, गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2019-20 हेतु जवाहरलाल नेहरू सहकारी एग्रीकल्चर प्रोड्युस प्रोसेसिंग सोसायटी लि0, शक्कर कारखाना यूनिट, सरवरदेवला, तहसील-कसरावद, जिला-खरगोन (म. प्र.) के लिये नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करता हूँ :-

क्र.	जिला/विकास खण्ड	कय केन्द्र	ग्रामों की संख्या	क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1	खरगोन/कसरावद	फैक्ट्री गेट	58	1339.757
2	खरगोन/खरगोन	फैक्ट्री गेट	07	102.429
3	खरगोन/गोगावा	फैक्ट्री गेट	13	75.611
4	खरगोन/सेगावा	फैक्ट्री गेट	00	00
5	खरगोन/भीकनगांव	फैक्ट्री गेट	13	93.619
6	खरगोन/झिरन्या	फैक्ट्री गेट	02	11.243
7	खरगोन/भगवानपुरा	फैक्ट्री गेट	02	5.964
8	खरगोन/महेश्वर	फैक्ट्री गेट	40	390.64
9	खरगोन/बड़वाह	फैक्ट्री गेट	27	228.368
10	खण्डवा/पुनासा	फैक्ट्री गेट	14	56.97
11	धार/धरमपुरी	फैक्ट्री गेट	18	303.089
	कुल		194	2607.69

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किये गये हैं, उनकी सूची संलग्न है। यह आदेश जब तक इस हेतु समयपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा।

मुकेश कुमार शुक्ल, गन्ना आयुक्त.

पेरार्ड सत्र 2019-20 में विकास खण्ड कसरावद जिला खरगोन में उपलब्ध गन्ने की जानकारी

क.	गन्ना ग्राम का नाम	गन्ना क्षेत्र (हेक्टर)				मिल से ग्राम की रोड दूरी
		रोपा	जडी	तडी	योग	
पिछले पेज का योग		225.798	195.166	135.372	556.336	
22	खलटाका	22.393	16.417	0.000	38.810	29
23	खलसाटक	0.000	1.012	0.000	1.012	29
24	निमरानी	6.040	15.028	0.000	21.069	32
25	चिचली	53.757	64.935	12.235	130.927	37
26	भोइन्दा	101.498	50.045	32.603	184.146	44
27	कठोरा भोइन्दा	27.381	8.121	12.931	48.433	46
28	जरोली	30.976	13.049	7.340	51.364	39
29	पानवा	1.822	3.591	9.032	14.445	24
30	मालपुरा	5.429	4.089	2.964	12.482	32
31	सरवरदेवला	14.555	16.049	1.741	32.344	2
32	बहाइरपुरा	0.709	0.960	0.000	1.668	1
33	पिपलई	1.429	0.000	0.000	1.429	2
34	गोरावा	6.502	2.522	4.462	13.486	4
35	अहिल्यापुरा	0.939	0.000	0.000	0.939	5
36	गोपालपुरा	1.312	1.960	0.000	3.271	6
37	चंदनपुरी	6.093	3.972	0.000	13.065	18
38	उटावद	2.389	10.101	0.000	12.490	7
39	उमरिया	0.000	1.709	0.000	1.709	7
40	रामपुरा	0.551	0.000	0.000	0.551	19
41	भुलगांव	3.583	0.211	0.000	3.794	19
42	सीपटान	2.219	0.000	0.000	2.219	22
43	खेडी सेलानी	0.000	0.239	0.000	0.239	15
44	भनगाव	2.271	19.490	1.360	23.121	6
45	कवडी	3.935	9.761	0.000	13.696	9
46	मुलटान	4.543	1.919	0.000	6.462	15
योग		526.122	443.344	220.040	1189.506	

पेरार्ड सत्र 2019-20 में विकास खण्ड कसरावद जिला खरगोन में उपलब्ध गन्ने की जानकारी

क.	गन्ना ग्राम का नाम	गन्ना क्षेत्र (हेक्टर)				मिल से ग्राम की रोड दूरी
		रोपा	जडी	तडी	योग	
पिछले पेज का योग		526.122	443.344	220.040	1189.506	
47	डावरी	0.000	0.000	1.680	1.680	78
48	मलतार	2.429	0.360	0.000	2.789	75
49	हतोला	0.000	0.000	3.073	3.073	78
50	बलकवाडा	0.000	0.000	1.077	1.077	40
51	सामेडा	4.879	1.429	0.000	6.308	15
52	टिगरियाव	0.000	0.000	0.000	0.000	18
53	लेपा	1.000	0.000	0.000	1.000	19
54	मलगांव	3.911	0.960	0.000	4.871	31
55	तेलियाव	0.761	0.291	0.000	1.053	28
56	कोगावा	4.830	2.709	0.000	7.538	13
57	अमलाथा	41.55	30.121	31.611	103.287	27
58	नहारखेडी	5.061	5.032	1.619	11.713	27
59	ससावड	1.599	4.263	0.000	5.862	30
योग		592.148	488.509	259.101	1339.757	

जवाहरलाल नेहरू सहकारी एग्री. प्रो. प्राप्ते. सोसायटि लि० खरगोन

यूनिट सरवर देवला तेह कसरावद जिला खरगोन

पेराई सत्र 2019-20 मे विकास खण्ड खरगोन जिला खरगोन में उपलब्ध गन्ने की जानकारी

क्र.	गन्ना ग्राम का नाम	गन्ना क्षेत्र (हेक्टर)				मिल से ग्राम की रोड दूरी
		रोपा	जडी	तडी	योग	
1	खरगोन	7.328	0.000	0.000	7.328	30
2	डेहरी	35.721	22.498	9.211	67.429	65
3	डोगरगांव (लोनारा)	0.000	2.271	0.000	2.271	64
4	साईखेडा	1.700	0.000	0.000	1.700	90
5	दामखेडा	2.121	2.089	0.000	4.211	34
6	भाडली	8.611	0.000	0.000	8.611	34
7	बीड बुजुर्ग	10.879	0.000	0.000	10.879	32
	योग	66.360	26.858	9.211	102.429	

मुख्य गन्ना प्रबंधक

जवाहरलाल नेहरू सहकारी एग्री. प्रो. प्राप्ते. सोसायटि लि० खरगोन

यूनिट सरवर देवला तेह कसरावद जिला खरगोन

पेराई सत्र 2019-20 मे विकास खण्ड गोगावां जिला खरगोन में उपलब्ध गन्ने की जानकारी

क्र.	गन्ना ग्राम का नाम	गन्ना क्षेत्र (हेक्टर)				मिल से ग्राम की रोड दूरी
		रोपा	जडी	तडी	योग	
1	बेलापुर	10.061	10.632	0.000	20.692	54
2	बिलखेडा बुजुर्ग	1.858	5.089	0.518	7.466	57
3	बनगांव	1.300	4.672	0.000	5.972	35
4	मोहम्मदपुर	0.000	5.992	0.000	5.992	57
5	गोगावां	4.089	4.619	0.789	9.498	53
6	दयालपुरा	1.000	1.040	0.000	2.040	54
7	लाखी	0.000	1.020	0.000	1.020	57
8	खारदा	0.000	1.960	0.000	1.960	47
9	टिबगांव	0.000	3.170	0.000	3.170	45
10	कुकडील	1.895	7.401	0.000	9.296	46
11	उमरखली	1.883	4.340	0.000	6.223	51
12	बिस्टान	0.000	0.992	0.000	0.992	51
13	बिलाली	0.000	1.291	0.000	1.291	56
	योग	22.085	52.219	1.308	75.611	

जवाहरलाल नेहरू सहकारी एग्री. प्रो. प्राप्ते. सोसायटि लि० खरगोन
यूनिट सरवर देवला तेह कसरावद जिला खरगोन
पेराई सत्र 2019-20 मे विकास खण्ड सेगावां जिला खरगोन में उपलब्ध गन्ने की जानकारी

क.	गन्ना ग्राम का नाम	गन्ना क्षेत्र (हेक्टयर)				मिल से ग्राम की रोड दूरी
		रोपा	जडी	तडी	योग	
1	श्रीखण्डी	0.000			0.000	50
2	डालकी	0.000			0.000	60
3	गंधावड	0.000			0.000	58
	योग	0.000	0.000		0.000	

जवाहरलाल नेहरू सहकारी एग्री. प्रो. प्राप्ते. सोसायटि लि० खरगोन
यूनिट सरवर देवला तेह कसरावद जिला खरगोन
पेराई सत्र 2019-20 मे विकास खण्ड भीकनगांव जिला खरगोन में उपलब्ध गन्ने की जानकारी

क.	गन्ना ग्राम का नाम	गन्ना क्षेत्र (हेक्टयर)				मिल से ग्राम की रोड दूरी
		रोपा	जडी	तडी	योग	
1	सगुर भगुर	10.502	13.931	0.000	24.433	76
2	पिपरी	3.482	0.000	0.000	3.482	79
3	सेल्दा	0.822	4.182	0.000	5.004	67
4	कोयडा सर्वा	2.709	2.943	0.000	5.652	73
5	गोहनादह	0.000	1.660	0.000	1.660	73
6	शकरखेडी	1.538	2.830	0.000	4.368	72
7	भभनाला	5.810	12.020	6.721	23.551	64
8	बोववाडा	1.040	2.049	0.000	3.089	67
9	बडिया	0.360	0.652	0.000	1.012	56
10	बिटनेरा	3.538	6.951	0.000	10.490	58
11	रेहगांव	0.490	0.000	0.000	0.490	65
12	बिलखेड खुर्द	5.190	0.709	0.000	5.899	56
13	खुडगांव	1.409	3.081	0.000	4.490	70
	योग	36.891	51.008	5.721	93.619	

जवाहरलाल नेहरू सहकारी एग्री. प्रो. ग्रा.से. सोसायटि लि० खरगोन :

यूनिट सरवर देवला तेह कसरावद जिला खरगोन

पेराई सत्र 2019-20 मे विकास खण्ड झिरन्या जिला खरगोन में उपलब्ध गन्ने की जानकारी

क.	गन्ना ग्राम का नाम	गन्ना क्षेत्र (हेक्टर)				मिल से ग्राम की रोड दूरी
		रोपा	जडी	तडी	योग	
1	गोराडिया	3.429	5.300	1.332	10.061	86
2	नेमित	1.000	0.182	0.000	1.182	90
3	देवित बुजुर्ग	0.000	0.000	0.000	0.000	90
	योग	4.429	5.482	1.332	11.243	

62

मुख्य गन्ना प्रबंधक

जवाहरलाल नेहरू सहकारी एग्री. प्रो. ग्रा.से. सोसायटि लि० खरगोन

यूनिट सरवर देवला तेह कसरावद जिला खरगोन

पेराई सत्र 2019-20 मे विकास खण्ड भगवानपुरा जिला खरगोन में उपलब्ध गन्ने की जानकारी

क.	गन्ना ग्राम का नाम	गन्ना क्षेत्र (हेक्टर)				मिल से ग्राम की रोड दूरी
		रोपा	जडी	तडी	योग	
1	भगवानपुरा	0.000	0.000	2.012	2.012	70
2	वाडी	0.000	3.951	0.000	3.951	69
	योग	0.000	3.951	2.012	5.964	

जवाहरलाल नेहरू सहकारी एग्री. प्रो. प्रा. सोसायटि लि० खरगोन

यूनिट सरवर देवला तेह कसराबद जिला खरगोन

पेराई सत्र 2019-20 में विकास खण्ड महेश्वर जिला खरगोन में उपलब्ध गन्ने की जानकारी

क्र.	गन्ना ग्राम का नाम	गन्ना क्षेत्र (हेक्टर)				मिल से ग्राम की रोड दूरी
		रोपा	जडी	तडी	योग	
1	जलकोटा	8.41	5.82	5.66	19.89	32
2	खराडी	11.99	6.48	1.74	20.21	35
3	मोला	7.38	5.54	1.92	14.84	35
4	लालपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	35
5	कुडियां	0.00	0.00	0.00	0.00	40
6	माचंदा	6.34	4.11	0.00	10.45	38
7	महेश्वर	22.74	3.70	1.97	28.41	29
8	दहीवर	0.00	0.00	0.42	0.42	32
9	सुब्बाखेडी	0.00	0.00	0.00	0.00	40
10	मोहना	6.58	6.53	4.18	17.29	44
11	राजपुरा (मण्ड)	0.00	3.64	0.00	3.64	29
12	मातगूर	7.22	5.07	0.00	12.29	32
13	उरवाय	8.30	0.00	0.00	8.30	49
14	बडवी	5.62	9.80	1.99	17.41	32
15	केरियाखेडी	4.83	1.25	0.30	6.38	39
16	मिर्जापुर	5.54	0.00	0.00	5.54	45
17	काकरिया महेश्वर	1.32	0.00	0.00	1.32	47
18	लाडवी	2.29	0.59	1.34	4.22	25
19	मण्डलेश्वर	5.13	8.09	3.66	16.88	21
20	जलूद	3.83	4.10	0.00	7.93	25
21	ठनगांव	1.58	0.00	3.61	5.19	27
22	समराज	8.05	0.00	1.04	9.09	29
23	करोदिया	14.92	2.31	0.00	17.23	29
24	छोटी खरगोन	2.86	1.08	1.11	5.05	25
	योग	134.92	68.12	28.64	231.68	

पेराई सत्र 2019-20 में विकसित खण्ड महेश्वर जिला खरगोन में उपलब्ध आने की जानकारी

क्र.	गन्ना ग्राम का नाम	गन्ना क्षेत्र (हेक्टर)				मिल से ग्राम की रोड दूरी
		रोपा	जडी	तडी	योग	
	पिछले पेज का योग	134.919	68.121	28.644	231.684	
25	चोली	3.72	0.74	0.00	4.46	30
26	धरगांव	2.31	0.00	0.89	3.20	28
27	सुलगांव	18.38	7.76	6.28	32.42	33
28	गोगावा(मण्डलेश्वर)	12.00	5.02	4.81	21.83	33
29	चुंदडिया	0.44	0.00	0.00	0.44	36
30	नान्दा	0.00	0.91	0.00	0.91	30
31	डोजर	8.55	5.44	0.92	14.91	32
32	डीगार	14.33	14.48	9.35	38.16	40
33	चौगावां	4.87	0.00	2.40	7.27	35
34	रामदह	0.87	1.41	4.18	6.46	33
35	खारिया	5.65	0.00	0.00	5.65	33
36	मोरीपुरा	0.00	1.19	1.19	2.38	30
37	हरसगांव	1.78	1.73	0.00	3.51	32
38	देव पिपल्या	0.00	1.94	1.00	2.94	34
39	पथराड	3.49	0.00	0.00	3.49	34
40	सोमखेडी	0.37	0.00	0.00	0.37	34
41	बंडेरा	0.00	1.46	0.00	1.46	38
42	भूदरी	6.85	0.00	0.00	6.85	45
43	वेरफड	2.15	0.00	0.00	2.15	42
	योग	220.68	110.20	59.75	390.64	

जवाहरलाल नेहरू सहकारी एग्री. प्रो. प्रासे. सोसायटि लि० खरगोन

यूनिट सरवर देवला तेह कसरावद जिला खरगोन

पेराई सत्र 2019-20 मे विकास खण्ड बडवाह जिला खरगोन में उपलब्ध गन्ने की जानकारी

क.	गन्ना ग्राम का नाम	गन्ना क्षेत्र (हेक्टर)				मिल से ग्राम की रोड दूरी
		रोपा	जडी	तडी	योग	
1	बफलगांव	0.000	0.000	0.000	0.000	62
2	अमलाथा	3.498	2.429	0.000	5.927	62
3	मुरला	9.449	11.854	3.709	25.012	68
4	बावडी खेडा	0.000	0.858	0.000	0.858	66
5	अस्तुरिया	14.150	11.470	5.607	31.227	61
6	टोकी	1.028	3.903	0.000	4.931	70
7	सिरलाय	7.089	4.130	0.000	11.219	67
8	नादिया	0.000	0.822	0.000	0.822	69
9	रामगढ (बडवाह)	1.571	0.000	0.000	1.571	86
10	बडवाह	0.000	0.000	0.000	0.000	65
11	फटखडा	1.822	1.891	0.000	3.713	67
12	रतनपुरा	7.749	21.530	3.190	32.470	64
13	भोगापुरा	0.000	0.000	0.000	0.000	50
14	पिंडाय	0.470	0.000	0.000	0.470	72
15	बेलम	3.190	0.000	0.000	3.190	63
16	गिणलूद (जगतपुरा)	0.000	0.000	0.000	0.000	57
17	भोकर नाला	0.960	0.000	0.000	0.960	68
18	कानापुर	2.919	1.510	0.000	4.429	32
19	मर्दाना	5.032	2.510	0.000	7.543	39
20	नगावा	13.623	5.777	0.000	19.401	41
21	रावेरखेडी	2.664	5.109	3.858	11.632	45
22	रूपखेडा	2.389	0.000	0.000	2.389	58
23	बेडिया	0.000	1.320	0.000	1.320	45
24	राहटकोड	1.162	0.000	0.000	1.162	59
	योग	78.765	75.113	16.364	170.243	

पेराई सत्र 2019-20 मे विकास खण्ड बडवाह जिला खरगोन में उपलब्ध गन्ने की जानकारी

क.	गन्ना ग्राम का नाम	गन्ना क्षेत्र (हेक्टर)				मिल से ग्राम की रोड दूरी
		रोपा	जडी	तडी	योग	
	पिछले पेज का योग	78.765	75.113	16.364	170.243	
25	बडूद	0.000	6.660	0.000	6.660	56
26	पीतनगर	9.312	12.449	0.000	21.761	65
27	वासवा	1.688	0.000	0.000	1.688	66
28	जुनापानी (बेडिया)	2.802	0.000	0.000	2.802	64
29	खनगांवखेडी	2.470	2.421	1.502	6.393	64
30	सनावद	3.543	0.632	0.000	4.174	60
31	सिवना	0.000	10.178	4.470	14.648	67
	योग	98.579	107.453	22.336	228.368	

जवाहरलाल नेहरू सहकारी एग्री. प्रो. प्रासे. सोसायंटी लि० खरगोन

यूनिट सरवर देवला तेह कसंरावद जिला खरगोन

पेंसाई सत्र 2019-20 में विकास खण्ड पुनासा जिला खण्डवा में उपलब्ध गन्ने की जानकारी

क्र.	गन्ना ग्राम का नाम	गन्ना क्षेत्र (हेक्टेयर)				मिल से ग्राम की रोड दूरी
		रोपा	जडी	तडी	योग	
1	रिच्छफल	5.073	2.162	0.340	7.575	94
2	जूनापानी	0.000	2.109	1.911	4.020	94
3	मोहना	0.000	0.352	0.000	0.352	86
4	अट्टट	0.000	4.672	1.219	5.891	86
5	कोठी	0.000	0.000	0.000	0.000	73
6	कालिया खेडी	1.381	0.000	0.000	1.381	94
7	गोल	0.802	0.000	0.000	0.802	80
8	दयानतपुरा	0.000	2.012	0.000	2.012	85
9	निमारखेडी	0.000	0.000	0.000	0.000	74
10	थापना	0.000	1.470	5.551	7.020	68
11	नादियाखेडी	0.000	0.000	0.000	0.000	97
12	जमलापानी	1.259	0.632	0.000	1.891	95
13	डुडगांव (मोहना)	0.000	1.061	2.150	3.211	93
14	नरलाय	5.401	0.000	0.000	5.401	81
15	कामनखेडा	0.721	7.741	0.000	8.462	82
16	गुजरखेडी	1.780	1.741	0.000	3.521	92
17	लाल्याखेडी	5.433	0.000	0.000	5.433	81
	योग	21.849	23.951	11.170	56.970	

जवाहरलाल नेहरू सहकारी ए.पी. प्रो. प्रा.सो. सोसायटि लि० खरगोन
यूनिट सरवर देवला तह कसरावद जिला खरगोन
पैराई सत्र 2019-20 मे विकास खण्ड धरमपुरी जिला धार में उपलब्ध गन्ने की जानकारी

क्र.	गन्ना ग्राम का नाम	गन्ना क्षेत्र (हेक्टेयर में)				मिल से ग्राम की रोड दूरी
		रोपा	जडी	तिरी	योग	
1	गुलाटी	1.810	2.911	0.000	4.721	36
2	निमोला	12.696	14.583	2.571	29.850	34
3	पिपल्दागडी	14.150	18.632	5.911	38.692	33
4	लुन्हेरा	5.320	1.939	0.441	7.700	31
5	शाला	1.332	0.000	0.000	1.332	30
6	खलघाट	7.482	2.571	2.660	12.713	29
7	बगडीपुरा	12.360	7.478	4.061	23.899	37
8	सुन्देल	16.287	11.462	1.700	29.449	39
9	पटलावद	0.000	2.891	0.000	2.891	40
10	धामनोद	2.623	4.530	0.000	7.154	36
11	बलवाडा	0.000	0.870	0.000	0.870	35
12	गोरगडी	0.000	1.304	0.000	1.304	32
13	भाटपुरा	32.818	10.283	3.202	46.303	40
14	डोंगरी	0.700	0.632	0.239	1.571	42
15	देगावां	2.850	2.170	0.518	5.538	42
16	भोगावा	2.514	3.599	0.000	6.113	36
17	खुजावा	6.328	2.571	2.891	11.789	39
18	हतनावर	25.599	37.648	7.951	71.198	42
	योग	144.870	126.073	32.146	303.089	

क-गन्ना-एस-3-क्षे.आर-एन.पंजाब-2019-20-769

भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर 2019

मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं कय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं मुकेश कुमार शुक्ल, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल, गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2019-20 हेतु मे. एन. पंजाब शुगर मिल प्रा.लि., ग्राम- हिनाखेड़ी, तहसील-चांद, वि.ख.-चौरई, जिला- छिंदवाड़ा (म. प्र.) के लिये नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करता हूँ :-

क्र.	जिला/तहसील	कय केन्द्र	ग्रामों की संख्या	क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1	छिंदवाड़ा	फैक्ट्री गेट	165	2979.545
	कुल		165	2979.545

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किये गये हैं, उनकी सूची संलग्न है। यह आदेश जब तक इस हेतु समय परिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा।
संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

मुकेश कुमार शुक्ल, गन्ना आयुक्त.

एन० पंजाब शुगर्स प्रा० लि०
हरनाखेडी (चांद) छिंदवाडा म० प्र०
गन्ना क्षेत्र आरक्षण विवरण (हेक्टेयर में) पेराई सीजन 2019-20
जिला छिंदवाडा के ग्राम

क्रमांक	ग्राम का नाम	रोपा	जडी	तिरी	योग
1	चांद	3.44	26.11	15.59	45.142
2	भांडपिपरिया	3.64	8.91	5.47	18.016
3	विकला	7.49	19.03	7.89	34.413
4	रानीखैरी	4.05	16.40	9.51	29.960
5	कौआखेड़ा	13.97	25.30	26.72	65.992
6	बेलगांव	8.70	12.55	11.13	32.389
7	मोघर	9.11	10.93	18.42	38.462
8	गुमगांव	1.82	2.23	0.00	4.049
9	खापाबिहारी	3.24	11.34	5.47	20.040
10	दिलावर मोहगांव	18.22	20.24	20.24	58.704
11	पखड़िया	0.40	1.21	2.43	4.049
12	खभरा बड़ा	0.00	0.81	0.00	0.810
13	किशनपुर	3.24	3.64	4.86	11.741
14	सटोटी	9.92	8.10	6.07	24.089
15	विष्णु कला	2.07	0.81	2.63	5.466
16	हिवरा जयसिंग	3.04	11.13	14.37	28.543
17	बतरी	2.83	4.25	0.00	7.085
18	चांदढाना	0.00	3.64	0.40	4.049
19	घोघरी हरहर	0.81	0.00	1.21	2.024
20	मालीखैरी	2.43	2.23	0.81	5.466
21	बंधान	5.67	15.99	8.91	30.567
22	शेरपापडा	1.62	2.02	1.21	4.858
23	मोया	0.00	1.62	0.00	1.619
24	जमनिया	0.81	3.24	0.81	4.858
25	डोकली	0.81	1.62	0.00	2.429
26	मोया मोहगांव	2.02	0.40	0.40	2.834
27	सिंगोड़ी	8.30	12.55	13.36	34.211
28	सिरस	8.10	25.30	21.46	54.858
29	कुकरई	0.00	1.21	1.21	2.429
30	धमनिया सिरस	3.44	14.78	20.65	38.866
31	बम्हनी लाला	5.67	18.62	22.87	47.166
32	बर्वा	7.49	15.38	19.64	42.510
33	बर्वा खेड़ा	1.62	4.25	3.85	9.717

34	बर्सा मनियाटोला	0.00	0.81	0.81	1.619
35	बर्सा रामाटोला	0.81	3.64	0.40	4.858
36	पंजरा	8.50	29.96	24.90	63.360
37	नोनी खुर्द	2.63	12.55	19.84	35.020
38	नांदना	4.25	10.53	13.16	27.935
39	परसोली	3.44	5.47	5.67	14.575
40	पटिया	0.00	7.49	2.63	10.121
41	डोंगरी टोला	1.62	6.68	4.66	12.955
42	सिंगोड़ी टोला	4.66	18.22	18.22	41.093
43	जामुन टोला	2.83	5.26	7.69	15.789
44	बाड़ीबाड़ा	10.53	29.15	23.68	63.360
45	कुम्पानी	0.00	0.40	0.00	0.405
46	देवरी माल	0.00	0.00	0.61	0.607
47	नोनी कला	5.47	27.73	23.28	56.478
48	दुटमर	0.81	2.23	4.66	7.692
49	चौरई	0.81	2.83	1.42	5.061
50	हरनाखेड़ी	7.89	38.06	25.10	71.053
51	राजलबाड़ी	2.23	4.66	5.67	12.551
52	चिखली खुर्द	0.81	8.10	7.69	16.599
53	मोहगांव कला	0.81	2.43	2.02	5.263
54	टिधरा	2.83	8.10	22.67	33.602
55	झिरिया	1.21	0.00	7.69	8.907
56	बांका नागनपुर	1.62	6.48	12.96	21.053
57	केरिया	2.43	8.91	8.10	19.433
58	पाल्हरी	1.21	1.21	1.62	4.049
59	पालादोन	3.24	9.72	4.86	17.814
60	बडडाढाना	0.00	0.40	0.81	1.215
61	मडकाहान्डी	0.00	0.40	0.00	0.405
62	खुटिया	0.00	0.00	1.62	1.619
63	मुआरी	0.00	0.40	0.00	0.405
64	मेड़ाबानी	0.00	0.00	0.61	0.607
65	खुटपिपरिया	2.83	2.23	3.04	8.097
66	तांडे	0.00	0.00	0.40	0.405
67	तेन्दनी	1.21	2.43	5.87	9.514
68	आमाझिरी	0.00	0.40	0.00	0.405
69	लुंगसी	0.00	0.40	0.81	1.215
70	कुन्डा	0.00	1.62	4.45	6.073
71	थावरी कुन्डा	0.81	6.28	1.21	8.300
72	खिरखिरी	0.00	0.40	0.00	0.405

73	गोपालपुर	0.00	0.40	0.00	0.405
74	किरंगीपार	0.00	0.81	1.21	2.024
75	कपुर्दा	0.00	1.62	0.00	1.619
76	गुरैया (चौरई)	0.00	1.62	0.40	2.024
77	लिखड़ी	1.21	0.00	0.00	1.215
78	हिवरा	0.20	0.81	0.81	1.822
79	पिंडरई कला	1.62	4.86	3.24	9.717
80	शहपुरा	7.69	33.60	21.05	62.348
81	खमरा	19.43	39.68	34.41	93.522
82	धमनिया खमरा	0.81	0.81	0.81	2.429
83	सोनापिपरी	8.50	24.29	14.57	47.368
84	सलैया	6.48	23.89	15.38	45.749
85	सुसरई	2.02	3.85	2.02	7.895
86	खेड़ा	0.81	4.86	4.45	10.121
87	पुलपुलडोह	0.00	7.69	6.48	14.170
88	थावरी (भाजीपानी)	2.02	6.07	4.05	12.146
89	कुहिया	8.50	35.63	22.67	66.802
90	सुनारी मोहगांव	10.53	30.36	25.10	65.992
91	भाजीपानी	0.00	2.02	0.40	2.429
92	खापा कला भाजीपानी	0.00	4.05	3.24	7.287
93	जताम्हा	0.00	2.02	0.40	2.429
94	धगाडिया	1.21	2.43	1.62	5.263
95	सालईछिन्दी	4.86	16.40	12.35	33.602
96	गोहरगांव	1.62	4.45	6.88	12.955
97	परसगांव	0.40	5.26	4.05	9.717
98	मुड़िया खेड़ा	4.25	12.75	13.97	30.972
99	बम्हनीतुरा	1.82	4.45	4.86	11.134
100	कोड़रखापा	3.24	5.26	9.51	18.016
101	नोलाझिर	4.45	7.29	8.91	20.648
102	राजना	1.21	0.00	5.06	6.275
103	केकड़ा	0.00	2.02	1.62	3.644
104	नवलगांव	2.02	4.66	4.66	11.336
105	दीमरमेटा	2.43	4.25	2.02	8.704
106	माताखैरी	4.86	12.15	13.16	30.162
107	उलावाड़ी	0.00	0.00	0.40	0.405
108	पिन्डरई खुर्द	0.00	0.61	0.00	0.607
109	करेल विछुआ	0.81	0.61	0.00	1.417
110	पचगांव	14.57	30.16	30.97	75.709
111	आमगांव	1.21	8.91	5.06	15.182

112	खाती पिपरिया	1.21	7.49	6.48	15.182
113	टाप	5.67	25.51	30.36	61.538
114	पोनिया	0.40	4.66	2.63	7.692
115	खैरघाट	0.40	7.29	4.86	12.551
116	बासखेड़ा	5.67	19.03	12.15	36.842
117	मेघदोन	0.61	3.64	3.44	7.692
118	पतलोन	0.00	1.42	0.40	1.822
119	थोटा	0.00	1.21	1.21	2.429
120	रमपुरी	16.19	45.34	38.26	99.798
121	घोड़पुर	2.02	1.21	1.62	4.858
122	डोला पांजरा	1.21	0.00	0.81	2.024
123	बारी	0.40	2.02	1.62	4.049
124	तीतरी	0.81	9.72	6.88	17.409
125	चंदनगांव	25.10	79.35	37.25	141.700
126	बादगांव	7.09	28.95	13.97	50.000
127	लालगांव	3.24	8.30	6.07	17.611
128	जमुनिया	0.00	5.87	4.05	9.919
129	डोंगरगांव	0.00	0.81	0.40	1.215
130	दावाझिर	2.43	4.86	2.43	9.717
131	गुमारावा	0.40	5.06	6.68	12.146
132	गाथरी	0.00	0.40	0.00	0.405
133	ओरिया	0.81	2.63	4.05	7.490
134	सीताझिर	1.42	5.67	4.66	11.741
135	फुटेरा	1.82	7.69	5.67	15.182
136	श्यामटोला	1.42	3.44	4.05	8.907
137	साजपानी	2.43	16.19	4.66	23.279
138	हलाल	0.81	4.25	2.02	7.085
139	मंदरिया	3.85	10.93	11.94	26.721
140	ग्रेहटिया	2.02	13.36	12.96	28.340
141	खैरराझी	0.00	6.07	1.62	7.692
142	सीदप	0.00	0.40	0.40	0.810
143	छापर	2.02	9.31	7.09	18.421
144	फुटेरा मोहगांव	0.81	7.49	5.26	13.563
145	खैरी टोला	1.21	3.64	1.21	6.073
146	खैरी खुर्द	0.00	1.21	0.40	1.619
147	डुंगरिया	0.40	1.21	0.00	1.619
148	करलई	5.87	12.15	15.38	33.401
149	कोना पिंडरई	0.00	1.62	1.62	3.239
150	हरदुआ	0.00	2.43	2.23	4.656

151	हलाल खुर्द	7.69	5.26	4.86	17.814
152	हतनापुर	7.217	3.026	3.957	14.200
153	मडवा	11.407	2.794	9.545	23.745
154	सिमरिया	0.931	0.000	0.931	1.862
155	सुरजना	0.931	0.466	1.397	2.794
156	चक्की खमरिया	10.243	3.725	1.862	15.830
157	ग्वारीमाल	2.328	0.000	1.862	4.190
158	बुडडी	12.105	2.794	4.190	19.089
159	आमटपानी	5.587	0.000	3.725	9.312
160	शुकवाहा	2.328	0.000	1.397	3.725
161	उमरेट	4.656	0.931	3.725	9.312
162	सिहोरा मडका	2.328	1.862	2.794	6.984
163	ठरकाखेडा	8.846	1.397	5.121	15.364
164	कारीरात	1.862	1.862	1.862	5.587
165	भालीवाडा	4.656	5.121	0.931	10.709
कुल योग					2,979.545

क-गन्ना-एस-3-क्षे.आर-श्रीजी-2019-20-772

भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर 2019

मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं कय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं मुकेश कुमार शुक्ल, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल, गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2019-20 हेतु श्रीजी शुगर एण्ड पावर प्रा0 लि0, ग्राम-सोहागपुर, तहसील एवं जिला- बैतूल (म. प्र.) के लिये नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करता हूँ :-

क्र.	जिला/तहसील	कय केन्द्र	ग्रामों की संख्या	क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1	बैतूल/बैतूल	फैक्ट्री गेट	101	4438.28
2	बैतूल/आमला	फैक्ट्री गेट	16	1191.85
3	बैतूल/मुलताई	फैक्ट्री गेट	20	323.91
4	बैतूल/आठनेर	फैक्ट्री गेट	03	38.50
		कुल	140	5992.54

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किये गये हैं, उनकी सूची संलग्न है। यह आदेश जब तक इस हेतु समयपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा।

मुकेश कुमार शुक्ल, गन्ना आयुक्त.

श्री जी शुगर एण्ड पॉवर प्रा. लि. सोहागपुर, जिला - बैतूल
बैतूल की तहसीलों का ग्रामवार गन्ना सर्वेक्षण रिपोर्ट सत्र - 2019-20
तहसील बैतूल के सुरक्षित क्षेत्र के गन्ना क्षेत्रफल की सूची
(गन्ना क्षेत्रफल हेक्टेयर में).

क्र.	गांव का नाम	पौधा	पेड़ी का योग	पौधा + पेड़ी योग	कृषक संख्या	चीनी मिल से दूरी
1	आरुल	22.33	179.78	202.11	114	4
2	बाजपुर	8.98	99.60	108.58	68	8
3	चकोरा	4.98	61.24	66.22	35	16
4	परसोड़ी बुजुर्ग	2.37	43.18	45.55	18	14
5	बागदा	5.93	58.41	64.34	35	3
6	बघवाड़	4.64	31.03	35.67	35	16
7	बरसाली	8.85	62.98	71.83	54	16
8	भीलावाड़ी	7.04	52.98	60.02	50	12
9	ग्यारसपुर	6.53	46.05	52.58	44	14
10	जैतापुर	0.83	23.38	24.21	15	4
11	काजी जामठी	12.94	63.36	76.30	64	15
12	मडूस	2.92	83.21	86.13	62	22
13	दुनोरा	2.56	49.55	52.11	17	18
14	करजगाव	0.30	2.32	2.32	3	27
15	खडला	0.00	4.79	4.79	5	22
16	मयेगांव	1.67	6.34	8.01	4	26
17	रोड़ा	2.87	26.81	29.68	28	24
18	भैसदेही	23.74	56.88	80.62	61	9
19	केलापुर	14.49	30.92	45.42	36	8
20	खण्डारा	0.76	52.66	53.42	36	12
21	किल्लौद	11.53	35.46	46.98	27	9
22	मलकापुर	25.73	115.71	141.44	85	9
23	उमरी	9.66	56.17	65.83	48	11
24	अमंदर	0.00	5.08	5.08	5	24
25	बघोली	0.62	13.87	14.49	20	18
26	भरकावाड़ी	0.79	92.95	93.74	52	15
27	गोराखार	0.00	2.97	2.97	3	30
28	जोड़क्या	0.52	8.26	8.78	8	18
29	कोलगांव	0.00	11.33	11.33	9	32
30	लोहारिया	0.00	22.44	22.44	22	16
31	सरण्डई (बघोली)	0.00	5.80	5.80	3	25
32	सेहरा	0.70	33.54	34.25	46	26
33	सुरगांव	0.00	2.91	2.91	2	21
34	बजारीढाल (ठानी)	1.02	48.12	49.14	24	45
35	गौठाना (बैतूल)	6.51	24.13	30.64	11	26
36	जामठी	3.11	47.40	50.51	38	23

कड़ाई	1.10	16.46	17.55	16	26
मोनाघाटी	2.40	19.79	22.19	16	19
टिगरिया	0.93	23.22	24.15	37	26
टिकारी	7.20	42.79	49.99	23	25
खडद	1.78	25.66	27.44	31	25
खेड़ा	2.21	29.99	32.20	30	17
अर्जुनवाडी	0.36	6.28	6.64	10	15
जावरा	7.56	101.18	108.74	113	12
खेडीकोट	5.71	34.67	40.38	34	27
जागझिरी	1.72	10.16	11.89	16	16
भीमनवाड़ा	0.70	10.55	11.25	19	32
खोडा सोहागपुर	2.07	6.63	8.70	11	10
सोनखेड़ी	7.33	26.89	34.22	32	21
सोपई	0.00	7.81	7.81	10	20
बोडी	0.23	30.26	30.49	18	16
हमलापुर	1.02	61.70	62.72	26	11
खेडली	9.90	142.90	152.80	39	9
कन्हारटेक	2.28	19.12	21.40	21	13
शबनवाडी	0.00	20.97	20.97	12	15
राठीपुर	2.82	39.42	42.23	36	13
सोमदरीपेठ	2.22	25.28	27.51	11	12
बड़ोरा	18.45	110.15	128.65	95	16
भवानीतेड़ा	3.91	29.97	33.88	16	21
भोगीतेड़ा	4.66	58.14	62.80	46	21
कोसमी	10.30	81.38	91.68	63	19
मालीतेड़ा	0.00	2.88	2.88	5	20
टेमनी	6.21	53.68	59.88	46	22
बोडना	2.24	11.11	13.34	13	32
जैतापुर	1.77	7.23	9.00	7	4
कन्हड़गांव	12.87	60.62	73.50	54	30
लाखापुर	15.89	113.61	129.49	95	19
मोरडोगरी	4.65	61.79	66.44	37	21
मोवाड़	17.79	54.64	72.44	40	28
नीमझिरी	4.84	17.04	21.87	19	26
ठानीमाल	0.00	3.08	3.08	4	24
ठानीरैयत	6.90	8.51	15.41	10	26
डोलहन	0.84	12.84	13.68	18	56
हिवरखेड़	0.00	1.76	1.76	6	65
झीटापाटी	0.00	1.68	1.68	4	18
खिड़की	0.00	0.53	0.53	2	37
मोहरखेड़ा	0.62	14.55	15.17	15	31
नादीखेड़ा	3.51	41.61	45.12	29	35
परसोड़ा	1.60	12.87	14.47	9	38
परसोड़ा आमला	0.00	8.62	8.62	19	42

82	तिरमहु	1.21	0.00	1.21	3	62
83	बारव्ही	2.45	21.79	24.24	30	30
84	बयावाडी	1.51	19.85	21.36	29	13
85	गोंडीगौला	9.51	15.43	24.94	36	17
86	हथनोरा	6.60	37.62	44.22	43	9
87	जगधर	8.29	24.99	33.28	46	13
88	खानापुर	0.67	12.06	12.72	27	14
89	परसोड़ी	7.56	28.41	35.97	45	7
90	रेडवा	2.81	9.13	11.94	15	22
91	सेलगाव	0.00	4.67	4.67	6	30
92	बुण्डाला	6.64	45.83	52.47	66	6
93	जुनावानी	0.00	4.34	4.34	1	4
94	रतनपुर	25.18	117.15	142.33	159	2
95	सोहागपुर	24.78	114.27	139.05	226	4
96	अनकावाडी	2.37	50.83	53.19	37	8
97	खापा	0.91	4.87	5.78	10	8
98	मदानीद्वाना	0.00	2.56	2.56	6	7
99	मिलानपुर	2.82	46.64	49.47	36	8
100	परतापुर	1.02	19.20	20.22	19	4
101	साईखण्डारा	1.39	9.06	10.45	12	7
102	सोपन	2.81	41.25	43.75	27	2
103	वटामा	0.93	42.72	43.66	22	15
104	बैतूलबाजार	5.83	106.73	112.55	90	10
105	चिखल्या 1	0.98	122.19	123.18	39	15
106	चिखल्या 2	0.00	0.72	0.72	4	23
107	हनोल्या	1.12	4.13	5.26	9	12
108	सिंगावाडी	9.67	124.02	133.69	63	14
TOTAL		498.08	4062.09	4560.17	3539	

101

4436.28

श्री जी शुगर एण्ड पॉवर प्रा. लि. सोहागपुर, जिला - बैतूल
 बैतूल की तहसीलों का ग्रामवार गन्ना सर्वेक्षण रिपोर्ट सत्र - 2019-20
 तहसील मुलताई के सुरक्षित क्षेत्र के गन्ना क्षेत्रफल की सूची
 (गन्ना क्षेत्रफल हेक्टेयर में)

क्रमांक	गांव का नाम	पौधा	पेड़ी का योग	पौधा + पेड़ी योग	कृषक संख्या	चीनी मिल से दूरी
1	बानुर	0.71	29.43	30.14	32	35
2	बिहरगांव	0.77	11.25	12.02	17	37
3	देहगुड़	2.62	30.16	32.78	27	33
4	धारणी	0.00	11.59	11.59	10	51
5	गौला	0.00	11.13	11.13	14	43
6	जम्बाड़ी	0.00	0.81	0.81	1	48
7	जामगांव साईखेड़ा	0.00	9.21	9.21	9	31
8	लीदा	0.00	2.18	2.18	4	35
9	प्रोहर	2.85	36.24	39.09	53	29
10	पौनी	2.36	9.13	11.49	12	42
11	साईखेड़ा	6.00	60.63	66.63	67	26
12	तावला	0.00	9.57	9.57	11	33
13	उमईग	0.00	3.44	3.44	4	29
14	ऐनस	0.79	4.35	5.14	6	34
15	भुताईखेडी	1.06	4.00	5.06	9	21
16	जौलखेड़ा	0.00	9.20	9.20	6	41
17	सोनोरी	0.00	2.87	2.87	3	26
18	कान्हाखापा	0.00	4.02	4.02	5	28
19	नगरकोर्ट	6.55	28.75	35.30	38	35
20	पाठाखेड़ा	5.33	16.91	22.24	17	31
TOTAL		29.04	294.87	323.91	345	

श्री जी शुगर एण्ड पावर प्रा. लि. सोहागपुर, जिला - बैतूल
 बैतूल की तहसीलों का ग्रामवार गन्ना सर्वेक्षण रिपोर्ट सत्र - 2019-20
 तहसील आमला के सुरक्षित क्षेत्र के गन्ना क्षेत्रफल की सूची
 (गन्ना क्षेत्रफल हेक्टेयर में)

क्र	गांव का नाम	पौधा	पेड़ी का योग	पौधा + पेड़ी योग	कृषक संख्या	चीनी मिल से दूरी
1	अम्बाडा	0.00	5.62	5.62	3	16
2	आमला	10.04	38.93	48.97	8	32
3	अन्धारिया	9.45	98.66	108.11	65	26
4	आंवरिया	25.91	134.39	160.30	80	41
5	बल्लाचाल	12.83	57.17	70.00	30	33
6	बेलमण्डई	2.36	5.60	7.96	4	18
7	बोड़खी	23.06	66.35	89.41	22	28
8	बोचनवाड़ी	10.21	61.34	71.55	30	46
9	धोसरा	16.56	60.45	77.01	35	36
10	खिड़कीकला	41.05	110.77	151.82	51	39
11	खिड़कीखूँद (आमला)	39.01	114.35	153.36	69	41
12	नाहिया	3.97	61.48	65.45	40	21
13	नरेश नयेगंव	2.05	9.22	11.27	8	14
14	देवठान	16.88	43.58	60.46	49	23
15	नांदपुर	19.27	50.45	69.72	65	25
16	रमली	4.81	24.93	29.74	35	28
17	ससुन्द्रा	17.64	42.43	60.07	72	19
TOTAL		255.10	985.72	1240.82	666	

16

1191.85

श्री जी शुगर एण्ड पॉवर प्रा. लि. सोहागपुर, जिला - बैतूल
बैतूल की तहसीलों का ग्रामवार गन्ना सर्वेक्षण रिपोर्ट सत्र - 2019-20
तहसील आठनेर के सुरक्षित क्षेत्र के गन्ना क्षेत्रफल की सूची
(गन्ना क्षेत्रफल हेक्टेयर में)

क्रमांक	गांव का नाम	पौधा	पेड़ी का योग	पौधा + पेड़ी योग	कृषक संख्या	चीनी मिल से दूरी
1	गुनखेड	0.00	0.00	0.00	0	53
2	प्रांदुना	0.00	0.00	0.00	0	62
3	जावरा आउट	0.00	9.00	9.00	10	54
4	धनोरा	0.00	5.50	5.50	4	57
	गैहूँबारसा	0.00	17.00	17.00	5	60
5	विसनुर	0.00	7.00	7.00	3	53
6	चंदकुडी	0.00	0.00	0.00	0	41
	TOTAL	0.00	38.50	38.50	22	

क-गन्ना-एस-3-क्षे.आर-हनुमंत-2019-20-775

भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर 2019

मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं कय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं मुकेश कुमार शुक्ल, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल, गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2019-20 हेतु हनुमंत शुगर प्रा.लि., जीन जोड़-दनोरा, जिला- बैतूल (म. प्र.) के लिये नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करता हूँ :-

क.	जिला/तहसील	कय केन्द्र	ग्रामों की संख्या	क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1	बैतूल/चिचोली	फैक्ट्री गेट	52	784.11
2	बैतूल/बैतूल	फैक्ट्री गेट	63	1032.39
3	बैतूल/भैसदेही	फैक्ट्री गेट	58	119.25
4	बैतूल/शाहपुर	फैक्ट्री गेट	22	104.44
5	बैतूल/घोडाडोगरी	फैक्ट्री गेट	38	150.36
6	बैतूल/आठनेर	फैक्ट्री गेट	02	2.8
		कुल	235	2193.35

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किये गये हैं, उनकी सूची संलग्न है। यह आदेश जब तक इस हेतु समयपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा।

मुकेश कुमार शुक्ल, गन्ना आयुक्त.

हनुमंत शुगरर्स प्रा. लि. जीन जोड़ दनोरा (बैतूल)

गांव का नाम	पौधा	खोडवा	कुल योग	किस्तान संख्या	मिल से गांव की दूरी
मिर्पुर	0.17	0.30	0.47	3	23
डो	0.85	3.50	4.35	6	19
डो	0.15	0.04	0.19	2	5
खोडवा	2.12	7.36	9.48	9	15
खोडवा	10.12	23.56	33.68	25	13
खोडवा	0.30	0.10	0.40	1	32
खोडवा	9.84	12.82	22.66	32	12
खोडवा	0.82	1.03	1.85	3	14
खोडवा	35.35	42.10	77.45	45	12
खोडवा	5.32	5.32	10.64	11	35
खोडवा	32.15	42.10	74.25	78	18
खोडवा	0.51	0.89	1.40	5	25
खोडवा	9.02	9.02	18.04	22	28
खोडवा	0.10	0.20	0.30	1	34
खोडवा	4.31	3.52	7.83	31	11
खोडवा	1.02	2.10	3.12	16	23
खोडवा	0.15	0.15	0.30	1	26
खोडवा	1.12	3.10	4.22	9	17
खोडवा	0.23	10.35	10.58	15	23
खोडवा	0.89	0.89	1.78	3	23
खोडवा	4.32	4.32	8.64	15	15
खोडवा	9.47	21.78	31.25	42	20
खोडवा	39.23	42.30	81.53	72	15
खोडवा	0.52	0.10	0.62	3	15
खोडवा	0.00	0.00	0.00	0	32
खोडवा	0.00	0.63	0.63	1	20
खोडवा	1.30	3.12	4.42	2	7
खोडवा	25.63	33.21	58.84	31	5
खोडवा	0.56	1.40	1.96	3	27
खोडवा	0.23	1.36	1.59	4	31
खोडवा	0.00	2.30	2.30	4	26
खोडवा	1.06	1.32	2.38	15	7
खोडवा	0.54	0.00	0.54	2	17
खोडवा	0.00	0.62	0.62	1	22
खोडवा	0.00	1.02	1.02	2	21
खोडवा	1.40	1.65	3.05	5	15
खोडवा	15.05	12.12	27.17	46	13
खोडवा	5.69	9.21	14.90	30	7
खोडवा	0.21	0.35	0.56	4	27
खोडवा	9.35	12.14	21.49	26	20
खोडवा	0.62	0.20	0.82	2	20
खोडवा	2.65	0.95	3.60	6	26
खोडवा	3.65	16.21	19.86	23	6
खोडवा	15.30	19.20	34.50	48	14
खोडवा	28.32	36.23	64.55	50	15
खोडवा	0.35	1.50	1.85	9	24
खोडवा	1.36	22.10	23.46	16	27
खोडवा	5.73	28.30	33.53	38	15
खोडवा	0.62	0.62	1.24	13	17
खोडवा	0.35	2.30	2.65	10	29
खोडवा	0.00	2.00	2.00	1	20
खोडवा	0.31	0.31	0.62	1	22
खोडवा	46.76	46.76	93.52	47	15
खोडवा	30.40	30.40	60.80	30	15

हनुमंत शुगर प्रा. लि. जौन जोड़ दनौरा (बैतुल)

गांव का नाम	पंथा	खोइवा	कुल योग	किसान संख्या	मिल से गांव की दूरी
आनंदवाड़ा	3.56	9.54	13.10	28	17
आठवांमिल	0.00	3.02	3.02	7	35
आमला	0.30	0.00	0.30	2	12
आमला	0.45	0.12	0.57	6	7
आमला	0.32	0.51	0.83	2	9
आमला	0.21	5.32	5.53	19	18
आमला	7.32	31.21	38.53	40	23
आमला	1.00	2.41	3.41	5	3
आमला	40.31	10.58	51.30	85	13
आमला	3.00	8.95	11.95	15	8
आमला	1.32	2.31	3.63	5	31
आमला	5.21	9.35	14.56	22	15
आमला	0.00	0.50	0.50	1	18
आमला	1.20	8.74	9.94	18	46
आमला	0.36	8.65	9.01	12	37
आमला	0.50	0.50	1.00	2	26
आमला	5.32	23.87	29.19	39	50
आमला	3.21	30.21	33.42	41	26
आमला	2.12	2.20	4.32	7	8
आमला	5.65	15.65	21.30	23	29
आमला	3.65	9.32	12.97	31	16
आमला	4.98	8.95	13.93	19	46
आमला	21.32	69.74	91.06	36	11
आमला	2.14	28.79	30.93	25	29
आमला	2.39	1.00	3.39	9	3
आमला	7.35	29.72	37.07	56	28
आमला	8.65	35.14	43.79	61	24
आमला	0.65	0.95	1.60	10	46
आमला	0.00	0.00	0.00	0	47
आमला	2.55	4.20	6.75	11	21
आमला	0.00	1.02	1.02	1	44
आमला	0.89	10.51	11.40	27	29
आमला	3.12	0.62	3.74	9	11
आमला	3.78	15.87	19.65	27	29
आमला	3.21	14.09	17.30	17	18
आमला	0.00	3.21	3.21	8	19
आमला	19.54	51.65	71.19	39	13
आमला	1.17	2.14	3.31	5	18
आमला	0.60	4.08	4.68	12	8
आमला	8.12	20.65	28.77	46	31
आमला	7.32	8.98	16.30	29	15
आमला	10.58	72.65	83.23	59	22
आमला	8.32	31.08	39.40	39	17
आमला	7.35	35.41	42.76	51	28
आमला	4.12	0.87	4.99	9	13
आमला	0.98	0.25	1.23	3	17
आमला	0.95	6.98	7.93	12	24
आमला	4.92	10.65	15.57	25	25
आमला	1.32	1.65	2.97	6	23
आमला	5.35	20.65	26.00	39	14
आमला	4.12	15.46	19.58	29	47
आमला	0.45	0.25	0.70	3	48
आमला	2.91	12.87	15.78	26	9
आमला	3.54	10.98	14.52	29	14
आमला	2.35	23.26	25.61	41	47
आमला	0.14	0.95	1.09	6	22
आमला	2.54	10.65	13.19	29	34
आमला	1.06	1.65	2.71	6	23
आमला	0.95	8.25	9.20	28	21
आमला	1.00	1.65	2.65	3	11
आमला	0.65	0.65	1.30	6	8
आमला	1.04	2.13	3.17	6	39
आमला	2.65	7.65	10.30	15	40
आमला	0.91	5.03	5.94	9	36
आमला	251.10	781.29	1032.39	1340	

हनुमंत शुगर प्रा. लि. जीन जोड़ दनोरा (बैतूल)

तहसील-भैसदेही					
गांव का नाम	पौधा	खोडवा	कुल योग	किसान संख्या	मिल से गांव की दूरी
खिन्नर	0.25	0.95	1.2	3	48
रहापुर	0	0.38	0.38	2	60
सिन्नर खेद	0	0.87	0.87	1	47
सिन्नर कला	0.65	1.65	2.3	4	47
सिदेही	0.35	1.86	2.21	3	60
सिन्नर	0.65	0.98	1.63	2	29
बकई खेड़ा	0.15	0.95	1.1	1	30
भाड़वा	0	0.74	0.74	2	34
बकाजूर	0.65	0.25	0.9	1	35
बोरगाव डेम	0.67	0.41	1.08	2	48
बकई चिखली	1	0.65	1.65	3	28
चनलोमा	2.31	2.35	4.66	5	31
दोदरा	0.1	0.74	0.84	1	45
डोरी	0.25	0.45	0.7	1	29
डोकिया	5.37	0.68	6.05	9	38
दोदरा	0	0.14	0.14	2	45
गवाडी	0.61	0.78	1.39	2	29
घोघामा	0.37	0.64	1.01	3	54
गुदगाव	0.86	0.65	1.51	4	56
गुल्तादाना	1.29	1.02	2.31	5	53
गोरखोदाना	2.14	2.65	4.79	8	55
गोगाझीरी	0.14	0.98	1.12	4	56
गधाखार	0.06	0.74	0.8	1	48
हिडली	0.54	0.64	1.18	5	22
जाम		0.25	0.25	1	55
जामोरा	0.25	0.74	0.99	2	49
झांखल	0.2	0.35	0.55	4	38
काटोल	1	0.54	1.54	2	55
कोथलासी	0.25	1.19	1.44	3	52
कनखेड़ा	0	0.9	0.9	1	70
कटगा	0.14	1.25	1.39	2	30
काजरी	0.5	0.91	1.41	4	28
कांडोदाना	0.32	0.77	1.09	3	64
कालडोगरी	0	0.98	0.98	1	56
कोडिया	0	0.74	0.74	1	71
कृण्ड	0.35	0.98	1.33	3	32
लक्कड़जाम	1.13	1	2.13	3	28
मच्छी	0.36	0.75	1.11	4	37
महारपानी	0	0.87	0.87	1	35
मान्कदंड	0	0.47	0.47	1	31
मालेगाव	0.31	0.65	0.96	3	53
निपालिया	0	0.35	0.35	1	58
नकटोदाना	0	0.47	0.47	1	43
पलासिया	0	1	1	2	61
पिपरिया	1.61	2.35	3.96	6	32
पोहर	0.12	1.32	1.44	5	60
पातरी	0.54	0.65	1.19	3	43
रतनपुर	0	0.74	0.74	4	23
राटमाटी कला	1.1	1	2.1	8	19
रुनोखेड़ा	0	25	25	15	37
समलडोल	0.81	12	12.81	7	45
सिंहार	0.41	0.65	1.06	3	26
सिरजगाव	0.21	0.69	0.9	4	53
सिवनी	1.47	1	2.47	4	63
सीनाझार	0.56	0.87	1.43	3	30
उटी	1.1	0.87	1.97	7	57
उमरी	0	0.17	0.17	1	65
विजयगाम	0	2.98	2.98	6	46
	31.15	88.1	119.25	193	

हनुमंत शुगर प्रा. लि. जीन जोड़ दनोरा (बैतूल)

तहसील-शाहपुर

गांव का नाम	पौधा	खोडवा	कुल योग	किसान संख्या	मिल से गांव की दूरी
आवरिया	0.00	5.31	5.31	5	19
बल्लभपुर	0.35	0.65	1.00	3	50
बरोडा	0.00	5.00	5.00	11	42
बयावाडी	0.35	2.65	3.00	5	28
बोदरी	0.10	1.32	1.42	3	26
भगवदना	0.65	1.12	1.77	2	23
चिखलीमाल	15.35	30.21	45.56	65	52
घिसीबाघला	0.14	0.65	0.79	2	27
हाथीकुण्ड	2.35	5.14	7.49	14	55
कान्हेगाँव	0.65	1.32	1.97	3	22
कसिया	0.34	1.65	1.99	7	21
कोटमी	0.32	0.87	1.19	5	67
कप्पा	0.24	1.00	1.24	4	72
कासिया	0.00	1.32	1.32	2	21
मंजीरादना	0.00	2.32	2.32	3	21
मंडई	0.35	1.65	2.00	3	16
पलासपानी	0.28	0.87	1.15	3	47
पाडर	0.35	3.21	3.56	5	41
रामपुर	0.84	1.65	2.49	4	58
शाहपुर	1.32	6.35	7.67	12	62
टप्पा	0.21	2.22	2.43	5	29
तारा	0.12	3.65	3.77	4	24
	24.31	80.13	104.44	170	

हनुमंत शुगर प्रा. लि. जीन जोड़ दनोरा (बैतूल)

तहसील-थोड़ाडोगरी

गांव का नाम	पौधा	खोडवा	कुल योग	किसान संख्या	मिल से गांव की दूरी
आगीहन	1.03	5.68	6.71	5	47
मादना	1	3.12	4.12	4	47
नकावाडी	0.1	0.95	1.05	3	50
जरावाडा	0.95	1.84	2.79	4	42
डकी पचामा	2.45	3.5	5.95	3	48
गारगाव	0.21	0.87	1.08	1	70
दूरी	0.65	5.61	6.26	10	45

झरी(रानीपुर)	2.95	8.98	11.93	13	25
चोपना	0.14	1.54	1.68	2	69
डोलीढाना	5.32	10.47	15.79	24	44
दधावाणी	0.64	0.14	0.78	3	70
दलारा	0	0.32	0.32	1	62
घोड़ाडोंगरी	0.35	5.65	6	2	75
हिरावाडी	0.45	0.47	0.92	5	65
जाखली	1.12	4.32	5.44	14	45
जवाडी(रानीपुर)	4.21	6.21	10.42	12	28
जांगना	0.14	3	3.14	2	74
कोयलारी	1.6	4.09	5.74	7	70
कौटखेड़ा	0	0.65	0.65	1	46
खारी	0.78	1.14	1.92	3	47
खारडोंगरी	0.35	2.65	3	2	72
खदारा	0.47	5.09	5.56	5	50
कूहीजोड़	0.74	4.87	5.61	3	57
केरिया	0.15	0.54	0.69	3	58
मायावनी	0.65	0.98	1.63	3	66
मर्दवाणी	0.45	0.47	0.92	4	43
माथनी	0.24	0.88	1.12	3	78
मेहकार	0.41	1.05	1.46	18	67
मालशिवनी	0.28	1.04	1.32	8	46
मैंडापानी	0.65	0.66	1.31	2	48
नीमपानी	1.12	5.98	7.1	5	45
पांडरा	0.78	4.87	5.65	7	75
फाडका	0.65	3.65	4.3	5	80
पिसाजोडी	1.19	1.3	2.49	3	42
रानीपुर	3.25	5.87	9.12	5	60
सलैया	0.3	1.24	1.54	6	80
सीतलझिरी	0.12	0.77	0.89	2	31
सीताकामठ	0.31	3.65	3.96	1	77
कुल योग-	36.25	114.11	150.36	200	

हनुमंत शुगर्स प्रा. लि. जीन जोड़ दनोरा (बैतूल)

तहसील-आठनेर

गाँव का नाम	पौधा	खोडवा	कुल योग	किसान संख्या	मिल से गाँव की दूरी
अनकलवाडी	0.95	0.54	1.49	2	52
सातनेर	0.35	0.96	1.31	1	61
कुल योग-	1.3	1.5	2.8	3	

गृह (सामान्य) विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 नवम्बर 2019

क्र. एफ-15-06/2019/दो-ए(3) : जनगणना अधिनियम 1948 (1948 का 37) की धारा 4 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं पूर्व में इस सम्बन्ध में प्रसारित समस्त अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए, राज्य शासन नीचे दर्शाई गई अनुसूची के कॉलम (2) में निर्दिष्ट अधिकारियों को कॉलम (3) में दर्शाये प्राधिकार के अनुरूप कॉलम (4) में दर्शाये क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत जनगणना 2021 के लिये जनगणना अधिकारी के रूप में नियुक्त करता है :-

अनुसूची

स. क्र.	पदाधिकारी	प्राधिकार	क्षेत्राधिकार	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	संभागायुक्त	संभागीय जनगणना अधिकारी	उनके सम्बन्धित संभाग के अन्तर्गत	
2	जिलाध्यक्ष	प्रमुख जनगणना अधिकारी	उनके सम्बन्धित जिले के अन्तर्गत	
3	मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जिला पंचायत)	अतिरिक्त प्रमुख जनगणना अधिकारी	उनके सम्बन्धित जिले के अन्तर्गत	
4	जिलाध्यक्ष द्वारा नामांकित अपर / संयुक्त / उप जिलाध्यक्ष	जिला जनगणना अधिकारी	उनके सम्बन्धित जिले के अन्तर्गत	प्रमुख जनगणना अधिकारी द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जायेगा।
5	जिला सांख्यिकी अधिकारी/ जिला योजना अधिकारी/ जिला शिक्षा अधिकारी/ जिला सूचना-विज्ञान अधिकारी (DIO-NIC),	अतिरिक्त जिला जनगणना अधिकारी	उनके सम्बन्धित जिले के अन्तर्गत	
6	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	अनुविभागीय जनगणना अधिकारी	उनके सम्बन्धित क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत	
7	तहसीलदार	चार्ज जनगणना अधिकारी	उनके सम्बन्धित क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत (नगरीय निकायों एवं छावनी बोर्ड के भीतर के क्षेत्र को छोड़कर)	
8	अतिरिक्त तहसीलदार / मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जनपद पंचायत)/ विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी / नायब तहसीलदार	अतिरिक्त चार्ज जनगणना अधिकारी	उनके सम्बन्धित क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत (नगरीय निकायों एवं छावनी बोर्ड के भीतर के क्षेत्र को छोड़कर)	
9	(अ) प्रशासक नगर निगम (अधिक्रमण किये गये नगर निगमों में)	प्रमुख जनगणना अधिकारी	उनके सम्बन्धित नगर निगम की सीमा एवं बाह्य वृद्धि क्षेत्र (यदि कोई हो) के अन्तर्गत	
	(ब) आयुक्त नगर निगम (निर्वाचित नगर निगमों में)	प्रमुख जनगणना अधिकारी	उनके सम्बन्धित नगर निगम की सीमा एवं बाह्य वृद्धि क्षेत्र (यदि कोई हो) के अन्तर्गत	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	प्रशासक, नगर निगम / आयुक्त नगर निगम द्वारा नामांकित उपायुक्त / अन्य वरिष्ठ अधिकारी	नगर चार्ज जनगणना अधिकारी	उनके सम्बन्धित नगर निगम की सीमा एवं बाह्य वृद्धि क्षेत्र (यदि कोई हो) के अन्तर्गत	प्रमुख जनगणना अधिकारी द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जायेगा।
11	नगर पालिका एवं नगर परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी / मुख्य कार्यपालन अधिकारी / औद्योगिक टाउनशिप के मुख्य प्रशासक अधिकारी	चार्ज जनगणना अधिकारी	उनके संबंधित नगर / औद्योगिक टाउनशिप की सीमा एवं बाह्य वृद्धि क्षेत्र (यदि कोई हो) के अन्तर्गत	
12	छवनी अधिशासी अधिकारी, केन्टोनमेंट बोर्ड	चार्ज जनगणना अधिकारी	उनके सम्बन्धित केन्टोनमेंट बोर्ड एरिया की सीमा एवं बाह्य वृद्धि क्षेत्र (यदि कोई हो) के अन्तर्गत	
13	नगर निगमों के जोनल अधिकारी	जोनल चार्ज जनगणना अधिकारी	नगर निगमों एवं बाह्य वृद्धि क्षेत्र (यदि कोई हो) के भीतर उनके संबंधित जोन के अन्तर्गत	प्रमुख जनगणना अधिकारी द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जायेगा
14	मुख्य कार्यपालन अधिकारी (विशेष क्षेत्र)	विशेष चार्ज जनगणना अधिकारी	उनके सम्बन्धित विशेष क्षेत्र के अन्तर्गत	

2. वर्णित अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन उपरोक्त दर्शाई अनुसूची के कॉलम (2) में निर्दिष्ट पदाधिकारियों को उक्त धारा की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उनके सम्मुख कॉलम (4) में दर्शाए क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जनगणना पदाधिकारियों को नियुक्त करने का एतद्द्वारा अधिकार प्रदाय करता है।

3. वर्णित अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन उपरोक्त दर्शाई अनुसूची के कॉलम (2) में निर्दिष्ट पदाधिकारियों को उनके समक्ष कॉलम (4) में दर्शाए गये क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उनके द्वारा नियुक्त जनगणना पदाधिकारियों के लिये लिखित में घोषणा-पत्र प्रसारित करने के लिए एतद्द्वारा प्राधिकृत करता है।

4. जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 11 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार, कोई भी जनगणना अधिकारी अथवा ऐसा व्यक्ति जो जनगणना का कार्य करने में सहायता करने हेतु विधिवत् अपेक्षित हो एवं जो वर्णित अधिनियम के अंतर्गत अथवा इसके अंतर्गत निर्दिष्ट नियम के अंतर्गत आवंटित कार्य निर्वहन करने हेतु मना करता हो, अथवा कोई भी व्यक्ति जो ऐसे कार्य निर्वहन में अन्य व्यक्ति को बाधा उत्पन्न करता हो अथवा रोकता हो, को रुपये 1000/- तक का दण्ड एवं दोष सिद्ध होने पर तीन वर्षों तक का कारावास से दण्डित किया जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नरेश पाल, सचिव.

भोपाल, दिनांक 11 नवम्बर 2019

क्र. एफ-15-06-2019-दो-ए (3).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना दिनांक 11 नवम्बर 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नरेश पाल, सचिव.

Bhopal, the 11th November 2019

F.No F-15-06/2019/2-A(3) - In exercise of powers conferred by sub-section (2) of Section-4 of the Census Act, 1948 (37 of 1948) and in supersession of all Previous Notifications issued in this regard, the State Government hereby appoints the authorities specified in Column (2) of the Schedule below as Census Officers designated in column (3) for the Census 2021 within their respective jurisdiction as specified in Column (4) thereof:-

SCHEDULE

S.No.	Authorities	Designation	Jurisdiction	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Divisional Commissioner	Divisional Census Officer	Within the limits of their respective Division	
2	District Collector	Principal Census Officer	Within the limits of their respective District	
3	Chief Executive Officer (Zila Panchayat)	Additional Principal Census Officer	Within the limits of their respective District	
4	Additional Collector / Joint Collector / Deputy Collector nominated by the Collector	District Census Officer	Within the limits of their respective District	Appointment Order to be issued by Principal Census Officer.
5	District Statistical Officer/ District Planning Officer / District Education Officer/ District Informatics Officer (NIC)	Additional District Census Officer	Within the limits of their respective District	
6	Sub-Divisional Officer (Revenue)	Sub-Divisional Census Officer	Within the limits of their respective jurisdiction	
7	Tahsildar	Charge Census Officer	Within the limits of their respective jurisdiction (Except areas within the jurisdiction of Urban Local Bodies and Cantonment Boards)	
8	Additional Tahsildar/ Chief Executive Officer (Janpad Panchayat) / Block Education Officer / Naib Tahsildar	Additional Charge Census Officer	Within the limits of their respective jurisdiction (Except areas within the jurisdiction of Urban Local Bodies and Cantonment Boards)	
9	(A) Administrator in superceded Municipal Corporations (B) Commissioner in elected Municipal Corporations	Principal Census Officer Principal Census Officer	Within the limits of their respective Municipal Corporation and Outgrowth areas (if any) Within the limits of their respective Municipal Corporation and Outgrowth areas (if any)	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	Deputy Commissioner / Other Senior Officer nominated by Administrator / Commissioner in Municipal Corporations	City Charge Census Officer	Within the limits of their respective Municipal Corporation and Outgrowth areas (if any)	Appointment Order to be issued by Principal Census Officer.
11	Chief Municipal Officer / Chief Executive Officer of Municipalities and Nagar Parishad / Chief Administrative Officer of Industrial Townships	Charge Census Officer	Within the limits of their respective Town / Industrial Townships and Outgrowth areas (if any)	
12	Chief Executive Officer of Cantonment Board	Charge Census Officer	Within the limits of their respective Cantonment Board area and Outgrowth areas (if any)	
13	Zonal Officer of Municipal Corporations	Zonal Charge Census Officer	Within the limits of their respective Zone in the Municipal Corporation and Outgrowth areas (if any)	Appointment Letter to be issued by Principal Census Officer
14	Chief Executive Officer (Special Areas)	Special Charge Census Officer	Within the limits of their respective Special Areas	

2. In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 4 of the said Act, the State Government hereby delegates the powers of appointing Census Officers conferred upon it by sub-section (2) of the said section to the authorities specified in column (2) of the above Schedule within the area specified in column (4) thereof.

3. In exercise of powers conferred by sub-section (3) of Section 4 of the said Act, the State Government hereby authorises the authorities specified in column (2) of the above Schedule to sign declaration regarding the appointment of Census Officers within the areas specified in column (4) thereof.

4. As per the provisions of Section 11 of the Census Act 1948, any Census-officer or any person lawfully required to give assistance towards the taking of census and who refuses to perform any duty allotted to him/her under this Act or any rule made thereunder or any person who hinders or obstructs another person in performing any such duty, shall be punishable with fine up to one thousand rupees and in case of a conviction shall also be punishable with imprisonment which may extend to three years.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
NARESH PAL, Secy.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा, दिनांक 16 अक्टूबर 2019

क्र. 8125-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—चौरई
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-समसवाड़ा, प.ह.नं.-30,
ब. नं.-266, रा. नि. मं.-चौरई.
(घ) अर्जित किये जाने वाला कुल रकबा-01.197
प्रस्तावित क्षेत्रफल—हेक्टेयर एवं प्रस्तावित
क्षेत्रफल पर आने
वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
602/1	0.056
604/2	0.160
590/1, 614/3	0.065
590/2, 614/14	0.056
619/2, 621/1	0.096
617/1, 618/1, 622/1	0.080
617/2, 618/2, 622/2	0.140
633/3, 634/3	0.149
633/2, 634/2	0.032
633/1, 634/1	0.045
637/1, 641/2	0.074
637/2, 641/3	0.060
636/3	0.056
636/2	0.68
636/4	0.060

योग. . 01.197 हेक्टेयर एवं
प्रस्तावित
क्षेत्रफल पर
आने वाली
संपत्तियां.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत हरदुआ वितरक नहर की माईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-2 छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

छिन्दवाड़ा, दिनांक 21 अक्टूबर 2019

क्र. 8276-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—चौरई

- (ग) नगर/ग्राम—ग्राम-मेढ़ावानी,, प.ह.नं.-37,
ब. नं.-233, रा. नि. मं.-चौरई.
- (घ) अर्जित किये जाने वाला कुल रकबा-01.889
प्रस्तावित क्षेत्रफल— हेक्टेयर एवं प्रस्तावित
क्षेत्रफल पर आने
वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
280/2, 281/2	0.120
280/3, 282/2	0.120
285/1, 286/1, 2, 3, 289/1, 290/1, 291/1, 291/2	0.171
297/2	0.072
15	0.123
298	0.060
31	0.135
30/1	0.086
29/1	0.010
38/1, 38/2	0.120
38/3	0.082
39, 40	0.082
16	0.106
14	0.072
11/1, 11/2	0.120
340	0.040
393/1	0.060
393/2	0.028
396/3	0.042
356/4, 397/2	0.054
107	0.033
108/1, 109/1	0.033
139/1, 139/4	0.120
योग .	01.889 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत नांदना वितरक नहर से निकलने वाली 4 आर माईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-2 छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

क्र. 8277-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
- (ख) तहसील—चौद

- (ग) नगर/ग्राम—ग्राम-चिखली खुर्द, प.ह.नं.-29/17,
ब. नं.-86, रा. नि. मं.-चौद.
- (घ) अर्जित किये जाने वाला कुल रकबा-0.040
प्रस्तावित क्षेत्रफल— हेक्टेयर एवं प्रस्तावित
क्षेत्रफल पर आने
वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
379	0.040
योग. . 0.040 हेक्टेयर एवं	
	प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत दांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली धमनिया वितरक नहर की 5 एल माईनर की 1 एल सब माईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, बांध जल संसाधन संभाग क्र. -1 चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-1 चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

क्र. 8278-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
- (ख) तहसील—चौरई
- (ग) नगर/ग्राम—ग्राम-सिरेगांव, प.ह.नं.-16,
ब. नं.-288, रा. नि. मं.-चौरई.
- (घ) अर्जित किये जाने वाला कुल रकबा-01.757
प्रस्तावित क्षेत्रफल— हेक्टेयर एवं प्रस्तावित
क्षेत्रफल पर आने
वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
759/12	0.102
759/11	0.156
759/16	0.040
767/1, 768, 770, 771	0.030
527/8	0.024
765	0.048
637/2	0.040
759/2, 759/6, 833, 834, 835	0.084
846	0.060
763/2, 836/1, 837/1	0.072
716/1, 717/1,	0.060
697/2	0.040
841/3	0.107
841/1	0.110
841/2/1	0.024
841/2/2	0.024
841/2/3	0.024
841/2/4	0.024

(1)	(2)
731, 842/1	0.040
727/1, 730/1	0.190
843/2	0.030
729	0.020
728/2	0.100
720	0.040
715	0.060
716/2, 717/2	0.060
697/3	0.032
697/4	0.032
697/5	0.032
697/6	0.032
733/3	0.020
योग. . 01.757 हेक्टर एवं	
प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.	
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत बायीं तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना वितरक नहर की 1 आर, 2 आर एवं 3 आर सब माईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.	
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.	
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.	
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.	

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-2 छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

क्र. 8279-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—चौरई

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-मुआरी, प.ह.नं.-37, ब. नं.-231, रा. नि. मं.-चौरई.

(घ) अर्जित किये जाने वाला कुल रकबा-03.226 हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल—हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
93/6	0.046
93/9	0.016
93/10	0.024
93/11	0.016
93/12	0.117
148/2	0.014
144/2क	0.010
149/3	0.117
149/2	0.072
88/4, 88/5च, 152/7, 153/2	0.060
104/2	0.064
152/1क, 153/1 क	0.024

(1)	(2)	(1)	(2)
152/1ख, 153/1 ख	0.050	372/5, 372/6, 372/7	0.040
158/2	0.045	372/8	0.053
167/2, 167/9	0.118	373/6	0.004
182/3, 4, 5, 6	0.062	373/7	0.006
183/2	0.063	373/8	0.005
183/1	0.064	374, 375, 376/1	0.028
183/3	0.062	338/2, 338/3, 339,	0.208
189	0.155	340, 343, 344/4	
195	0.026	376/2	0.005
37/1	0.024	386/8	0.142
95/4	0.100	344/19	0.003
95/6	0.028	344/1	0.106
95/9, 10	0.020	337/1, 337/2	0.032
191	0.080	336/2	0.060
95/8, 99/2	0.040	329	0.102
377/2	0.005	386/2	0.022
188/2, 192/2	0.057	योग. .	03.226 हेक्टर एवं
188/1, 194/2	0.060		प्रस्तावित
37/2	0.064		क्षेत्रफल पर
194/1	0.045		आने वाली
194/3	0.028		संपत्तियां.
196/1, 196/2	0.042	(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक	
196/3, 196/4	0.042	प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता	
197/1, 197/4	0.021	है—पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत नांदना	
199/4, 200/4	0.009	वितरक नहर से निकलने वाली 4 आर माईनर निर्माण के	
199/3, 200/3	0.022	लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.	
377/1	0.005	(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में	
199/2, 200/2	0.042	हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी	
201/4	0.012	वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं	
201/5	0.015	म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट	
249/3	0.022	http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा	
95/1, 95/5	0.024	सकता है.	
101/1, 101/3,	0.134	(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का	
102/1, 102/3		नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.	
309/2, 309/3, 309/4	0.046	(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे	
101/2, 102/1, 102/4	0.076	(प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन	
103/2	0.108	परियोजना, नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर	
104/1	0.014	किया जा सकता है.	

- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-2 छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

क्र. 8280-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—चांद
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-तिघरा बिसाला, प.ह.नं.-29, ब. नं.-177, रा. नि. मं.-चांद.
(घ) अर्जित किये जाने वाला कुल रकबा-0.060 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल—क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां।

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
58/2, 59/2, 61/1, 61/2	0.060
योग कुल रकबा.	0.060 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां।

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत दांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली धमनिया वितरक नहर की 5 एल माईनर की 1 एल सब माईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है।

- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पंच व्यपवर्तन परियोजना, बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक-01 चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-1 चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

क्र. 8281-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—चांद
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-तिघरा चम्पत, प.ह.नं.-29, ब. नं.-116, रा. नि. मं.-चांद.
(घ) अर्जित किये जाने वाला कुल रकबा-01.289 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल—क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां।

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
52/1	0.030
27/2	0.018
53	0.015
48/4	0.050
48/1	0.060
39/1	0.048
39/2	0.072

(1)	(2)
38/3	0.012
38/5	0.012
33	0.060
27/1	0.018
26/1	0.009
26/2	0.009
28/1	0.024
28/2	0.014
111/1, 111/12	0.014
155/6	0.032
111/2	0.013
111/3	0.034
112/1	0.040
112/2	0.010
147/8	0.024
112/3	0.017
147/4	0.084
112/4	0.017
112/5	0.012
112/6	0.010
151/1क	0.100
149/4क/2, 152/1-22	0.038
149/4 ख/2, 152/1-2ख	0.082
147/5	0.034
147/7	0.025
147/6	0.034
155/2	0.074
155/4	0.038
155/7	0.032
155/35	0.074

योग कुल रकबा . . 01.289 हेक्टर एवं
प्रस्तावित
क्षेत्रफल पर
आने वाली
संपत्तियां.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत दांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली धमनिया वितरक नहर की

5 एल माईनर की 1 एल सब माईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पंच व्यपवर्तन परियोजना, बांध जल संसाधन संभाग क्र.-1 चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-1 चौरई, के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 21 अक्टूबर 2019

पत्र क्र. 312-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम (1) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम (2) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद्द्वारा घोषित किया जाता है. निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है. चूंकि ग्राम कोनी, पटवारी हल्का-कोनी राजस्व निरीक्षक मण्डल अंतर्गता, तहसील जवा, जदुआ अंतर्गता मार्ग में निर्माणाधीन जिरोंध नदी पर पुल के पहुंच मार्ग कार्य पूर्ण करने हेतु. इस कारण

अधिनियम के उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा (म. प्र.)

(ख) तहसील—जवा

(ग) नगर/ग्राम—कोनी

(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.550 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
2015/1	0.388
2021/2	0.162
कुल योग.	0.550

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—जुदुआ अंतरेला मार्ग में निर्माणाधीन जिरोंध नदी पर पुल के पहुंच मार्ग कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. सेतु रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 313-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम (1) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम (2) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है. चूंकि ग्राम देवरा-247, पटवारी हल्का-देवरा-18 राजस्व निरीक्षक मण्डल सूरा-02, तहसील मनगवां, महमूदपुर देवरा मार्ग में पकड़ियार नदी पर पुल के पहुंच मार्ग कार्य पूर्ण करने हेतु. इस कारण अधिनियम के उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा (म. प्र.)

(ख) तहसील—मनगवां

(ग) नगर/ग्राम—देवरा-247

(घ) लगभग क्षेत्रफल —1.686 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
1007/3	0.088
1007/5	0.058
1011/1	0.056
1011/5	0.016
1011/3	0.024
1011/3/1	0.024
1011/4/ख	0.024
1011/4/ग	0.024
1011/7	0.024
1006	0.059
1012/2	0.025
1004/3	0.083
762/1	0.196
760/2	0.064
760/1	0.064
792/2	0.044
760/3	0.036
768/3	0.032
764/1	0.032
764/2	0.028
764/3	0.032
770/1	0.108
770/2	0.102
769/1	0.128
769/2	0.096
750	0.065
742/1	0.004
742/2	0.059
742/3	0.060
1005/2	0.016
1005/4	0.015
योग . .	1.686

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—महमूदपुर देवरा मार्ग में पकड़ियार नदी पर पुल के पहुंच मार्ग कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. सेतु रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 314-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम (1) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम (2) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है. चूंकि ग्राम महमूदपुर राजस्व निरीक्षण मण्डल सूरा, तहसील मनगवां, महमूदपुर देवरा मार्ग में पकडियार नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग कार्य पूर्ण करने हेतु. इस कारण अधिनियम के उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा (म. प्र.)
(ख) तहसील—मनगवां

(ग) नगर/ग्राम—मेहमूदपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.039 हेक्टेयर.

पूर्व प्रकाशित खसरा एवं रकबा का विवरण		प्रकाशन हेतु संशोधित खसरा एवं रकबा का विवरण	
(1)		(2)	
खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में.)	खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में.)
1593/1/1	0.039	1596/1/1	0.039
कुल योग . .		कुल योग . .	0.039

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—महमूदपुर देवरा मार्ग में पकडियार नदी पर निर्माणाधीन पुल के पहुंच मार्ग कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. सेतु रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओमप्रकाश श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.